राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 211

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, बुधवार, 8 जनवरी 2020

www.jagran.com

पृष्ठ 16

सैनी के सहारे भारत ने ली सीरीज में बढ़त

>> 14

22 को फांसी पर लटकाए जाएंगे निर्भया के गुनहगार

मिला न्याय ▶ दिल्ली की अदालत ने जारी किया डेथ वारंट, तिहाड़ की जेल नंबर-3 में सुबह 7 बजे चारों को दी जाएगी फांसी

जज ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी के दौरान दोषियों के सामने ही दिया आदेश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

निर्भया के सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड में दिल्ली की अदालत ने आखिरकार मंगलवार को चारों दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी कर दिए। चारों को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दे दी जाएगी। कोर्ट के आदेश के बाद निर्भया की मां ने कहा-'22 जनवरी का दिन हमारे लिए बड़ा है। हमारा न्याय में विश्वास है। हम दोषियों को फांसी पर लटका अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं।'

हालांकि दोषियों के पास उपचारात्मक याचिका (क्यूरेटिव पिटिशन) दायर करने का विकल्प खुला है। यह याचिका फांसी की सजा देने से एक दिन पहले तक सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है। दोषी पक्ष के अधिवक्ता एपी सिंह ने कहा है कि 22 जनवरी से पहले ही हम क्यूरेटिव पीटिशन दायर करेंगे। सूत्रों की मानें तो चारों को फांसी जेल नंबर-3 में दी जाएगी। हालांकि चार में से तीन को अभी जेल नंबर-2 में और एक को जेल-4 रखा गया है। जेल प्रशासन दोषियों को फांसी पर चढ़ाने के लिए मेरठ के जल्लाद से संपर्क करेगा।

ऊपर बाएं से, अक्षय और विनय शर्मा। नीचे बाएं से, मुकेश तथा पवन गुप्ता। फाइल फोटो (प्रेट्र)

और कितना समय दें : जब अदालत में पीड़िता की मां की अर्जी पर बहस शुरू हुई तो दोषियों के वकील ने कहा कि कुछ समय दिया जाए। दोषियों की तरफ से क्यूरेटिव पीटिशन (उपचारात्मक याचिका) दायर करने की प्रक्रिया जारी है। इस पर जज ने कहा-'और कितना समय दिया जाए आपको? मामला पहले ही काफी लटक चुका है।' वहीं पीड़िता के वकीलों ने अदालत में सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि दोषियों को डेथ वारंट जारी होना चाहिए। इसके बाद भी उनके पास 14 दिन का समय है, जिसमें बचे हुए कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

तकनीकी खराबी से हुई कुछ देरी : फैसला दोषियों के सामने सुनाया जाना था, दोषी मुकेश (32), पवन गुप्ता (25), विनय शर्मा (26) और अक्षय कुमार सिंह (31) को वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) के जरिये जेल से अदालत में पेश किया गया। हालांकि कुछ तकनीकी खराबी के चलते वीसी करीब 4 बजे शुरू हो सकी और करीब 40 मिनट की सुनवाई के बाद डेथ वारंट का आदेश दिया गया। इससे पहले करीब एक घंटे तक दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस हुई, जबकि डेथ वारंट जारी करने का आदेश सिर्फ इस केस से जुड़े लोगों की मौजूदगी में सुनाया गया। मीडिया को इस दौरान कोर्ट रूम में रहने की अनुमति नहीं थी।

निर्भया को न्याय पेज>>5

कब किस अदालत से सजा

सितंबर, 2013 : ट्रायल कोर्ट ने चारों को फांसी की सजा सुनाई।

मार्च, 2014 : हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले की पुष्टि की।

मई, 2017 : सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा बरकरार रखी।

> इस मामले में अब तक के रिकॉर्ड को देखने से यह स्पष्ट होता है कि दोषियों को कानून के तहत उपलब्ध सभी उपायों का इस्तेमाल करने का मौका दिया गया। दोषियों ने कुछ उपायों का प्रयोग किया है और कुछ समाप्त हो गए हैं या फिर उनका सहारा नहीं लिया गया। लिहाजा अब डेथ वारंट (ब्लैक वारंट) जारी करने में देरी करने जैसा कुछ नहीं है। दोषियों की ओर से दाखिल याचिका का निपटान करते हुए संबंधित जेल अधीक्षक को निर्देश जारी किए जाते हैं कि 22 जनवरी 2020 को सुबह 7 बजे दोषियों की मौत की सजा दी जाए।
>
> -सतीश कुमार अरोड़ा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पटियाला हाउस कोर्ट

वारदात से हिल गया था देश

दिल्ली में 16-17 दिसंबर, 2012 की रात एक चलती बस में 23 वर्षीय पैरामेडिकल छात्रा से 6 लोगों ने बर्बर सामूहिक दुष्कर्म किया और उसे बुरी तरह घायल करने के बाद बस से बाहर फेंक दिया था। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। 90 दिन बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। हालांकि 29 दिसंबर, 2012 को पीड़िता की इलाज के दौरान सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में मौत हो गई थी। मुख्य आरोपित राम सिंह ने ट्रायल के दौरान ही जेल में फांसी लगा ली थी। एक नाबालिग साबित होने के कारण तीन साल सुधार गृह में रखे जाने के बाद रिहा किया जा चुका है। 2014 में हाई कोर्ट व 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को बरकरार रखा। दोषियों की रिव्यू पिटिशन भी खारिज हो गई थी।

सरोकार

मुरादाबाद से इंडोनेशिया तक पहुंची शायरा की बनाई टोपी

मुरादाबाद : शायरा का हुनर करीब सौ परिवारों की खुशहाली का वाहक बन गया है। इनकी बनाई टोपी विदेश में भी आमद दर्ज करा चुकी है। गांधी-नेहरू की टोपी, नमाजी टोपी बनाने वाली शायरा दूसरों के लिए नजीर बन गई हैं। (पेज-11)

जागरण विशेष

करंट भरी बौछार से होगा स्मॉग का खात्मा

चंडीगढ़ : केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन ने स्मॉग से निपटने को स्वदेशी मशीन तैयार की है। एक निजी कंपनी को तकनीकी हस्तांतरित की जा रही है, जो जल्द ही व्यावसायिक उत्पादन शुरू करेगी। (पेज-11)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

विदेशी राजदूतों को कश्मीर ले जाएगा भारत

नई दिल्ली : कश्मीर की स्थिति से दुनिया को अवगत कराने के लिए भारत ने 9-10 जनवरी को यूरोपीय संघ, आसियान, दक्षिण अमेरिकी और कुछ अफ्रीकी देशों के राजदूतों को कश्मीर दौरे पर ले जाने का फैसला किया गया है। विदेशी राजनयिकों को जनता से मिलने, सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने का पूरा मौका दिया जाएगा।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

बारिश और बर्फबारी से फिर ठिठुरने लगा उत्तर भारत

नई दिल्ली : उत्तर भारत में ठंडी हवाओं का दौर लौट आया है। पहाड़ों पर लगातार जारी बर्फबारी और बारिश के चलते दिल्ली-एनसीआर समेत मैदानी इलाकों में भी ठंड महसूस की गई। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज लगातार तल्ख बना हुआ है। दिल्ली में मंगलवार को पूरे दिन रुक-रुक का बारिश होती रही।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

स्पीड ब्रेकर से मुक्त होंगे राष्ट्रीय राजमार्ग

नई दिल्ली: आने वाले दिनों में आपको स्पीड ब्रेकर मुक्त राष्ट्रीय राजमार्ग देखने को मिल सकते हैं। सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों से स्पीड ब्रेकर हटाने के लिए विशेष अभियान चला रही है। हाइवे पर बाधा रहित यातायात के लिए यह फैसला किया गया है। इस अभियान में टोल प्लाजा को विशेष रूप से ध्यान में रखा जा रहा है।

आजकल ▶ पृष्ठ 16

गगनयान में अंतरिक्ष यात्रियों को मिलेगा देसी खाना

मैसुरु : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के महात्वाकांक्षी गगनयान मिशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को खाने के लिए भारतीय भोजन ही मिलेगा। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्वादिष्ट, पौष्टिक और हल्के भोजन के रूप में विशेष रूप से एग रोल, वेज रोल, इडली, मूंग की दाल का हलवा और वेज पुलाव भी तैयार किया जाएगा।

इस वर्ष पांच फीसद पर सिमटेगी विकास दर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार ने जारी किए विकास दर के अग्रिम अनुमान
- अनुमानों से अर्थव्यवस्था में सुस्ती और गहराने के दिख रहे संकेत

केंद्र सरकार की तरफ से अर्थव्यवस्था के लिए इस वर्ष जारी पहले अग्रिम अनुमान में जो तस्वीर पेश की गई है वह उम्मीद जगाने वाली नहीं है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, देश की आर्थिक विकास दर पांच फीसद रहेगी। आरबीआइ समेत कई निजी संस्थान भी विकास दर इसी के आस पास रहने की बात कर चुके हैं। अगर जीडीपी की विकास दर पांच फीसद ही रहती है तो यह न सिर्फ पिछले आठ वर्षों की सबसे न्यूनतम विकास दर होगी बल्कि यह चौथा साल होगा जब अर्थव्यवस्था में गिरावट का रुख रहेगा। ये आंकड़े विपक्ष को सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने का फिर मौका देंगे।

सीएसओ के फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2019-20 में देश की जीडीपी (स्थिर मूल्यों पर) 147.79 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जबकि 2018-19 में यह 140.78 लाख करोड़ था। इस तरह चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर पांच फीसद रहेगी। पिछले साल यह 6.8 फीसद थी। राजग सरकार जब सत्ता (2014-15) में आई थी तब आर्थिक विकास की रफ्तार 7.4 फीसद थी जो बाद के दो वर्षों में क्रमशः आठ और 8.2 फीसद हो गई थी। वर्ष 2017-18 में यह 7.2 फीसद थी।

सरकार की तरफ से जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें विकास दर में गिरावट के पीछे तीन अहम वजहों की तरफ इशारा किया गया है। पहला कारण मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर है जिसकी विकास दर 6.9 से घटकर दो फीसद रहने का अनुमान है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ रेट 8.7 से घटकर 3.2 फीसद पर आने की आशंका है। एग्रीकल्चर सेक्टर की स्थिति कमोबेश पहले जैसी है। इसकी ग्रोथ रेट 2.9 फीसद से 2.8 फीसद रहने का अनुमान लगाया गया है। जीडीपी ग्रोथ रेट में अहम हिस्सा निभाने वाले उत्पादों पर टैक्स की ग्रोथ रेट 8.8 से घटकर 5.8 फीसद पर आने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष के पहले 9-10 माह में जीएसटी वसूली की स्थिति को देखते हुए यह बात समझी जा सकती है। जहां तक सर्विस सेक्टर की स्थिति है, उसमें बहुत गिरावट नहीं है। ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट जैसे सेवा सेक्टर की वृद्धि दर 6.9 से घटकर 5.9 फीसद, वित्तीय सेवा सेक्टर की ग्रोथ रेट 7.4 से 6.4 फीसद रहने का अनुमान लगाया गया है। मैन्यूफैक्चरिंग व कंस्ट्रक्शन रोजगार देने वाला सबसे बड़ा सेक्टर है लेकिन उनकी विकास दर में बड़ी गिरावट देश में रोजगार की स्थिति भी बताती है।

प्रतीकात्मक

गिरावट के अहम कारण

- मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र की वृद्धि दर 6.9 से घटकर दो फीसद पर आई
- कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ रेट 8.7 फीसद से घटकर 3.2 पर सिमटी
- उत्पादों पर कर वसूली की वृद्धि दर 8.8 फीसद से घटकर 4.8 फीसद पर आई

और भी गिर सकती है दर : आरबीआइ ने पहले ही विकास दर के पांच फीसद पर आने की बात कही है। जब वित्त वर्ष की शुरुआत हुई थी तब विकास दर सात फीसद रहने का अनुमान था। निजी एजेंसियों का कहना है कि अंतिम आंकड़ा आने तक विकास दर 4.5 फीसद पर सिमट सकती है। इस आशंका की वजह यह है कि ईरान-अमेरिका तनाव की वजह से कच्चा तेल महंगा हो रहा है जिसका असर चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च, 2020) पर पड़ेगा।

पुलिस की लापरवाही से जेएनयू में बढ़ा विवाद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- 3 और 4 जनवरी को दी गई शिकायतों पर दो दिन बाद दर्ज की एफआइआर
- नकाबपोश लोगों ने रविवार को परिसर में छात्रों और शिक्षकों पर लाठी-डंडों से किया था हमला

रविवार को जेएनयू में हुई हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की घोर लापरवाही उजागर हुई है। 5 जनवरी को हुए बवाल से पहले वामपंथी छात्र संगठनों के सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने तीन और चार जनवरी को लगातार दो दिनों तक प्रशासनिक ब्लॉक स्थित सर्वर रूम में जबरन घुसकर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को नुकसान पहुंचाया था। कर्मचारियों से मारपीट की थी। यहां तक कर्मचारियों के अंदर होते हुए भी सर्वर रूम में बाहर से ताला जड़ दिया गया था। दोनों ही दिन जेएनयू के मुख्य सुरक्षा अधिकारी श्याम सिंह ने थाने में लिखित शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। नतीजन हंगामा करने वाले छात्र संगठनों को बल मिलता गया और अंततः 5 जनवरी को लाठी-डंडे और रॉड से लैस नकाबपोश लोगों ने पूरे परिसर में जमकर उत्पात किया। छात्रों-शिक्षकों को पीटा और संपत्ति को भी खासा नुकसान पहुंचाया।

नई दिल्ली स्थित जेएनयू में हिंसा के बाद मंगलवार को फॉरेंसिक टीम ने विश्वविद्यालय के साबरमती छात्रावास में छानबीन की। एएनआइ

सर्वर रूम में जड़ दिया था ताला : जेएनयू की तरफ से तीन जनवरी को पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया कि एक जनवरी से विंटर सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। तीन तारीख की दोपहर 1 बजे सैकड़ों की संख्या में नकाब पहने विद्यार्थी प्रशासनिक ब्लॉक स्थित सेंटर ऑफ इंफोर्मेशन सिस्टम के कार्यालय में घुस गए और सिस्टम की बिजली काट दी। विरोध जताने पर कर्मचारियों को बाहर निकालकर सर्वर रूम में ताला जड़ दिया। इससे बायोमीट्रिक और सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम का काम ठप हो गया। इस दौरान छात्रसंघ अध्यक्ष आईशी घोष अन्य कई छात्रों के साथ मौजूद थीं। अन्य की पहचान नहीं की जा सकी। इस शिकायत पर पुलिस ने दो दिन बाद पांच जनवरी को बवाल के बाद रात 8.44 बजे मुकदमा दर्ज किया।

दूसरी शिकायत पर भी नहीं खुली नींद : चार जनवरी को मुख्य सुरक्षा अधिकारी श्याम सिंह ने थाने में दूसरी शिकायत देकर बताया कि सुबह 6 बजे सुरक्षा गार्डों ने जब सर्वर रूम को खुलवाने का प्रयास किया, तब छात्रों ने गार्डों से मारपीट की। यही नहीं कर्मियों को सर्वर रूम खोलने पर बुरा परिणाम भुगतने की धमकी दी। उस मौके पर भी आईशी घोष अन्य छात्रों के साथ मौजूद थीं। जेएनयू प्रशासन ने जब दोबारा से सर्वर रूम को खोलने की कोशिश की तो छात्रों ने फिर कर्मियों और सुरक्षा गार्ड को पीटा। हालांकि कुछ कर्मी सर्वर रूम में प्रवेश कर गए और सिस्टम को ठीक कर दिया। कुछ देर बाद काफी छात्र कार्यालय में प्रवेश कर गए। उन्होंने गाली-गलौज करते हुए कर्मियों को सर्वर रूम से निकाल दिया। बवाल बढ़ने पर जेएनयू प्रशासन ने इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी। थानेदार ने मौके का मुआयना किया। उनके जाने के बाद दोपहर एक बजे कुछ छात्र पिछले गेट से फिर सर्वर रूम में घुस गए और तोड़फोड़ की। इस मामले में भी पुलिस ने पांच जनवरी की रात 8.49 बजे केस दर्ज किया।

जेएनयू पहुंचीं दीपिका पादुकोण पेज>>5

कर्मचारी यूनियनों का बंद आज, प्रभावित हो सकती हैं सेवाएं

नई दिल्ली, प्रेट्र : श्रम सुधारों समेत सरकार की आर्थिक नीतियों को कथित तौर पर जनविरोधी करार देते हुए इंटक और सीटू समेत कई कर्मचारी यूनियनों ने बुधवार को देशव्यापी बंद बुलाया है। इससे बैंकिंग, यातायात व अन्य सेवाओं पर असर पड़ सकता है। इस बीच केंद्र सरकार ने सभी पीएसयू को निर्देश दिया है कि वे अपने कर्मियों को 'भारत बंद' में जाने से रोकें। बंद में किसी भी रूप में हिस्सा लेने वाले कर्मचारियों को दंडित किया जा सकता है। वेतन में कटौती भी की जा सकती है। पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्य सरकारों ने भी कर्मियों को बंद से दूर रहने को कहा है।

यूनियनों ने संयुक्त बयान में कहा है कि दो जनवरी की बैठक में श्रम मंत्रालय कर्मचारियों की किसी मांग पर भरोसा दिलाने में विफल रहा है। बंद के दौरान बैंकों में डिपॉजिट, विड्रॉल और चेक क्लियरेंस जैसे कार्य प्रभावित होने की आशंका है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, बीईएफआइ, आइएनबीओसी और बैंक कर्मचारी सेना महासंघ जैसे संगठनों ने इस बंद में हिस्सा लेने की बात कही है।

खाड़ी तनाव के बीच मोदी-ट्रंप में बातचीत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- ईरानी जनरल की हत्या के बाद ट्रंप की पहली बार किसी अंतरराष्ट्रीय नेता से बात
- कई देशों के साथ संपर्क में है भारत, विदेश मंत्री जयशंकर ने संभाली कमान

ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर भारत की कूटनीतिक सक्रियता भी चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की। वैसे दोनों नेताओं के बीच आपसी रणनीतिक रिश्तों पर ज्यादा बात हुई, लेकिन खाड़ी के हालात पर भी अच्छी खासी चर्चा हुई है। नव वर्ष की छुट्टी से लौटने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने पहली बार किसी अंतरराष्ट्रीय नेता से बात की है। ईरान के जनरल सुलेमानी की हत्या के बाद दुनिया के कई प्रमुख देशों ने अमेरिकी कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई है। उधर, विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी लगातार दूसरे देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। विदेश मंत्री खासतौर पर खाड़ी के हालात और इससे उपजी स्थिति में देश की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बातचीत कर रहे हैं।

भारतीय विदेश मंत्रालय और अमेरिकी राष्ट्रपति भवन की तरफ से बताया गया है कि मोदी और ट्रंप के बीच हुई बातचीत में द्विपक्षीय रिश्तों की समीक्षा की गई। मोदी ने अपनी तरफ से अमेरिका के साथ रिश्तों में लगातार मजबूती आने पर संतोष जताया।

नरेंद्र मोदी। फाइल

डोनाल्ड ट्रंप। फाइल

दोनों नेताओं ने हाल ही में संपन्न हुई दोनों देशों के विदेश व रक्षा मंत्रियों की बैठक को लेकर भी चर्चा की और रणनीतिक रिश्तों को आगे बढ़ाने पर संतोष जताया। मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मिलकर आगे भी काम करने की अपनी इच्छा जताई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के देश की जनता को नववर्ष की शुभकामनाएं भी दीं।

ट्रंप और मोदी के बीच हुई इस वार्ता से पहले विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोंपियो से बात की थी। दरअसल, जयशंकर भी लगातार दूसरे देशों के विदेश मंत्रियों के साथ संपर्क में हैं। पहले दौर में ईरान, ओमान, यूएई के विदेश मंत्रियों से संपर्क साधने के बाद जयशंकर ने सोमवार को कतर और जॉर्डन के विदेश मंत्रियों से भी बात की। जानकारों के मुताबिक, उक्त सभी देश न सिर्फ ऊर्जा के लिहाज से भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं बल्कि वहां लाखों भारतीय लोग रहते हैं जिन्हें युद्ध की स्थिति में निकालने का इंतजाम भी करना पड़ सकता है।

फैसला

केंद्रीय सिविल सेवाओं में अभी तक था 50 फीसद कोटा, अब होगा 33 फीसद, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटने के मद्देनजर उठाया गया है यह कदम

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में घटेगा स्थानीय अफसरों का कोटा

नई दिल्ली, प्रेट्र: केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में सिविल सेवाओं आइएएस, आइपीएस और आइएफओएस में राज्य के स्थानीय अधिकारियों का कोटा 50 से घटाकर 33 फीसद करने का फैसला किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में औपचारिकताओं को अंतिम रूप दे दिया है और जल्द ही सरकार आदेश जारी कर देगी। केंद्र सरकार का यह कदम जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटने के मद्देनजर उठाया गया है।

इससे पहले नियमों के मुताबिक राज्य में तीनों सिविल सेवाओं भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) और भारतीय वन सेवा (आइएफओएस) में 50-50 का फॉर्मूला लागू था। इसका मतलब है कि राज्य में इन सेवाओं के कुल पदों के 50 फीसद पर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा चयनित अधिकारी नियुक्त किए जाते थे जबकि बाकी 50 फीसद पदों को राज्य सिविल सेवा के स्थानीय अधिकारियों की पदोन्नति के जरिये भरा जाता था। जम्मू-कश्मीर राज्य के दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठन के बाद विशेष कोटे का यह प्रावधान खत्म हो गया है। अधिकारियों के मुताबिक, 'अब दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में पूरे देश में लागू होने वाला 67:33 (67 फीसद यूपीएससी द्वारा सीधे चयनित अधिकारी और 33 फीसद राज्य सेवाओं से प्रोन्नत अधिकारी) का नियम प्रभावी होगा।'

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम-2019 के मुताबिक, सिविल सेवा परीक्षा के जरिये चयनित अधिकारियों को अब जम्मू-कश्मीर के बजाय अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-केंद्र शासित प्रदेश (एजीएमयूटी) कैडर आवंटित किया जाएगा। मालूम हो कि आइएएस, आइपीएस और आइएफओएस अधिकारियों को राज्य अथवा राज्यों के समूह अथवा केंद्र शासित प्रदेश का कैडर आवंटित किया जाता है।

10 वर्ष में कितने आइएएस ने अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना किया : सीआइसी

नई दिल्ली, प्रेट्र : उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों को ऐसे कार्यों से बचना चाहिए जो संदेह पैदा करते हों, यह टिप्पणी करते हुए केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने केंद्र सरकार को उन आइएएस अधिकारियों के नाम उजागर करने को कहा है जिन्होंने पिछले 10 साल में अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना किया हो।

सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून के तहत लखनऊ निवासी नूतन ठाकुर की अपील पर फैसला सुनाते हुए सूचना आयुक्त दिव्य प्रकाश सिन्हा ने कहा, यह सूचना उजागर किया जाना व्यापक जनहित में है क्योंकि ये अधिकारी उच्च सरकारी पदों पर आसीन हैं। नूतन ठाकुर ने आवेदन में उन आइएएस अफसरों की सूची मांगी थी जिनके खिलाफ एक जनवरी, 2008 के बाद अखिल भारतीय सेवाओं के नियम-8 के तहत अनुशासनात्मक जांच शुरू की गई थी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात 14 ऐसे अफसरों की सूची दी थी जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी।

इस पर सूचना आयुक्त ने कहा, नूतन ठाकुर ने तैनाती के आधार पर सिर्फ किसी खास वर्ग के आइएएस अधिकारियों की सूची नहीं मांगी थी। लिहाजा केंद्रीय जनसूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वे उन सभी संबंधित अफसरों की सूची हासिल करें जिनके नाम आरटीआइ आवेदन में मांगे गए हैं और उसे अपीलकर्ता को उपलब्ध कराएं। इनमें राज्यों के कैडर के साथ-साथ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की प्रशासनिक सतर्कता विभाग डेस्क में कार्यरत अधिकारी शामिल हैं।

ऐसा प्रदर्शन सही नहीं जो दूसरों के अधिकारों का हनन करे : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

- उप्र में उपद्रवियों पर हो रही कार्रवाई में हाई कोर्ट का हस्तक्षेप से इन्कार
- कानूनी प्रतिबंध तोड़ना अवैध, सरकार को कार्रवाई का अधिकार

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में प्रदर्शन व हिंसा के बाद उपद्रवियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर उत्तर प्रदेश सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने सरकारी कार्रवाई के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची यह बताने में विफल रहा है कि सरकारी कार्रवाई उसके या ग्रुप (समूह) के मूल अधिकारों के विपरीत रही है।

न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और राजीव मिश्र की खंडपीठ ने लखनऊ के अधिवक्ता रजत गंगवार की याचिका खारिज करते हुए यह फैसला दिया। खंडपीठ ने कहा, जनतंत्र में सरकार के विरोध में आवाज उठाने व प्रदर्शन का नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है, लेकिन, यह दूसरों के मूल अधिकारों के विपरीत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लोगों को सड़क पर जुलूस निकाल विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन उन्हें यातायात में व्यवधान डालने का अधिकार नहीं है। प्रदर्शन के दौरान एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि जरूरी सेवाओं को रोका नहीं जा सकता। साथ ही कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए राज्य सरकार को कानूनी कार्रवाई का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई ग्रुप प्रदर्शन पर निकालता है और उस दौरान हिंसा होती है तो यह उसकी जिम्मेदारी है। हर घटना के लिए विरोध मार्च निकालने वालों की जवाबदेही होगी।

उत्तर प्रदेश के 34 जिलों में अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं 1022 लोग पेज>>6

35 हजार अवैध पोस्टर-होर्डिंग्स उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने मंगलवार को हटाया। चुनाव आयोग के निर्देश पर निगम ने यह कार्रवाई की है। विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता सोमवार को ही लागू हो गई है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 8 जनवरी 2020

तैयारी ▸ घोषणापत्र तैयार करने के लिए आतिशी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का किया गया गठन

जनता के सुझावों से आप तय करेगी चुनावी मुद्दे

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही आम आदमी पार्टी (आप) ने अपने घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी के घोषणापत्र में भी आम जनता के सुझावों की झलक दिखाई देगी, लोगों से मिले सुझाव पर मंथन कर घोषणापत्र तैयार करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया है। समिति की अध्यक्ष आप की राष्ट्रीय प्रवक्ता आतिशी होंगी, जबकि दिल्ली डायलॉग कमीशन के उपाध्यक्ष जस्मिन शाह व पार्टी प्रवक्ता डॉ. अजय कुमार इसके सदस्य होंगे। उम्मीद है कि एक सप्ताह में समिति घोषणापत्र को अंतिम रूप दे देगी जिसे 15 से 20 जनवरी के बीच जारी कर दिया जाए। घोषणापत्र में दिल्ली की सफाई व्यवस्था, यमुना की सफाई, प्रदूषण और यातायात की समस्या के मुद्दे को प्रमुखता दी जाएगी।

आप के प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि 10 जनवरी को द्वितीय चरण के कैंपेन की समाप्ति के बाद पार्टी का घोषणापत्र तैयार किया जाएगा। इसके लिए टाउन हॉल मीटिंग और डोर टू डोर कैंपेन से जो सुझाव मिले हैं, उनमें से महत्वपूर्ण सुझावों की सूची तैयार की जा रही है। इन सुझावों के आधार पर ही पार्टी का घोषणापत्र तैयार किया जाएगा। इसे तैयार करने के लिए आतिशी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति जनता से मिले महत्वपूर्ण सुझावों पर विचार कर रही है। इसके आधार पर भविष्य में आप की सरकार की क्या प्राथमिकताएं होंगी, उसको तय करेगी। 15 से 20 जनवरी के बीच में आप अपना घोषणापत्र जनता के समक्ष रखेगी। गोपाल राय ने कहा कि अगर संक्षेप में कहा जाए तो पार्टी का चुनाव घोषणापत्र इस तरह से होगा कि पिछले काम रहेंगे जारी, नए काम की है तैयारी।

ये हैं समिति के सदस्य

अध्यक्ष-आतिशी : आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आम आदमी पार्टी के 2015 विधानसभा चुनाव का घोषणापत्र भी इन्हीं के नेतृत्व में बना था। दिल्ली सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए तमाम कार्यों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आतिशी 2019 का लोकसभा चुनाव भी पूर्वी दिल्ली सीट से लड़ी थीं।

सदस्य- जस्मिन शाह : दिल्ली संवाद आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में दिल्ली सरकार की प्लानिंग में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

सदस्य-डा.अजय कुमार : पूर्व आइपीएस अधिकारी हैं। झारखंड के जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं। अभी आप के प्रवक्ता हैं।

आप के सर्वे में 12 विधायक फेल, 10 की कट सकती है टिकट

राज्य ब्यूरो,नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी के सर्वे में 12 विधायक फेल हो गए हैं। इनमें दस विधायकों की टिकट काटी जा सकती है। हालांकि अंतिम फैसला करने से पहले पार्टी एक बार फिर इन सीटों पर सर्वे करा रही है। पार्टी चाहती है कि जिन विधायकों की खराब रिपोर्ट आई है। उस बारे में पूरी तरह जांच करा ली जाए। 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीती थीं। तीन सीटों पर भाजपा जीती थी। इसके बाद हुए उप चुनाव में आप एक सीट हार गई थी। इसके बाद पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते आप ने 5 विधायकों की सदस्यता निरस्त करा दी है। अब कुल मिलाकर आप के 61 विधायक हैं। पार्टी नेतृत्व साफ तौर पर कह चुका है कि टिकट उसे मिलेगा, जनता में जिसकी छवि अच्छी होगी।हालांकि पार्टी नेतृत्व इस बारे में बात करने से कतरा रहा है कि कितने विधायकों के टिकट कटेंगे। लेकिन, कुछ विधायकों के टिकट काटे जाने से इन्कार भी नहीं कर रहा है। वहीं पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस बार 12 विधायकों की सर्वे रिपोर्ट ठीक नहीं आई है। इसमें दस विधायकों की टिकट काटे जाने की पूरी उम्मीद है। पार्टी अब फिर से अंतिम सर्वे करा रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय का कहना है कि 14 जनवरी तक आप के सभी प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे।

फिर नई दिल्ली सीट से चुनावी अखाड़े में उतरेंगे केजरीवाल

वी.के.शुक्ला, नई दिल्ली

आम आदमी पार्टी के मुखिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिर से नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनावी अखाड़े में उतरेंगे। इससे पहले वह दो बार इस सीट से विधायक चुने जा चुके हैं। वह तीसरी बार यहां से अपनी जीत पक्की करने के लिए मैदान में होंगे।

2012 में आम आदमी पार्टी के गठन के बाद पार्टी के मुखिया के तौर पर पहली बार 2013 के विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के सामने चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। उस समय दिल्ली की राजनीति में शीला दीक्षित बड़ा नाम थीं। वह तीन बार लगातार दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी थीं। चुनावी इतिहास में नई दिल्ली सीट पर यह सबसे दिलचस्प मुकाबला था। अन्ना आंदोलन के बाद बनी आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरकर उन्हें 25,864 मतों से पराजित कर दिया। उस समय केजरीवाल ने कांग्रेस के ही आठ विधायकों के सहयोग से दिल्ली में सरकार बनाई। 49 दिन तक सरकार में रहने के बाद केजरीवाल जब दिल्ली विधानसभा में जनलोकपाल बिल लेकर आए तो कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया। यह बिल पास नहीं हुआ। इसके बाद केजरीवाल ने सरकार से इस्तीफा दे दिया। 2015 में फिर से विधानसभा चुनाव हुए। 2015 में इस सीट से एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़ा। उनके सामने कांग्रेस ने इस बार पूर्व मंत्री प्रो. किरण वालिया को चुनाव मैदान में उतारा। वहीं भाजपा ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ की पूर्व अध्यक्ष नुपुर शर्मा को टिकट दिया। इस मुकाबले में भी अरविंद केजरीवाल विजयी रहे और लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 31 हजार से ज्यादा मतों से नुपुर शर्मा को पराजित किया।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, इस बार विरोधी दलों द्वारा इस तरह की चर्चा फैलाई जा रही थी कि केजरीवाल इस बार अपना विधानसभा क्षेत्र बदल सकते हैं या दो विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल न अपनी सीट बदलेंगे और न ही दो सीटों से चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात की पुष्टि की है कि वह नई दिल्ली सीट से ही चुनाव लड़ेंगे।

अरविंद केजरीवाल। फाइल

2013 के विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को 25,864 मतों से पराजित किया

2014 के विस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी नुपुर शर्मा और कांग्रेस प्रत्याशी किरण वालिया को हराया था

▸ वह लगातार तीसरी बार यहां से अपनी जीत पक्की करने के लिए होंगे मैदान में

नई दिल्ली सीट पर एक नजर

मुख्य निर्वाचन कार्यालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, नई दिल्ली सीट पर 1 लाख 44 हजार 509 मतदाता हैं। इनमें 79047 पुरुष और 65461 महिलाएं हैं। 2301 मतदाता 80 साल से ऊपर के हैं और 344 दिव्यांग मतदाता हैं। इनमें से करीब 10 हजारमतदाता झुग्गी-झोपड़ी वाले हैं। यहां केंद्र सरकार में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या अधिक है।

'एक माह के लिए पुलिस हमें दे दो, परिणाम सामने होगा'

राज्य ब्यूरो,नई दिल्ली

▸ टाउन हॉल मीटिंग में अरविंद केजरीवाल ने दिए जनता के सवालों का जवाब

▸ कहा, 49 दिन में जिस तरह भ्रष्टाचार खत्म किया था, कानून व्यवस्था भी सुधार दूंगा

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली की खराब कानून व्यवस्था के लिए दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। पुलिस वही करती है, उन्हें जो ऊपर से आदेश मिलता है। एक माह के लिए दिल्ली की पुलिस अगर उन्हें दे दी जाए तो परिणाम सामने होंगे। जिस तरह 49 दिन में भ्रष्टाचार को खत्म किया था, उसी तरह दिल्ली की कानून व्यवस्था को सुधार देंगे। मुख्यमंत्री मंगलवार को कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में आयोजित टाउन हॉल में सवालों के जवाब दे रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार उनकी 49 दिन की सरकार बनी थी। इसमें भ्रष्टाचार निरोधक शाखा उनके पास थी तो 49 दिन में ही भ्रष्टाचार खत्म हो गया था। आप दिल्ली पुलिस को देकर देख लो, महीने भर के अंदर नतीजे आ जाएंगे। मैं दिल्ली पुलिस को दोष नहीं देता है। दिल्ली पुलिस सक्षम हैं। उनके पास आधुनिक तकनीक है। उन्हें खुली छूट देकर देखो, वो अच्छे से अच्छा काम करके दिखाएंगे। आज शिक्षा के अंदर वही शिक्षक और प्रधानाचार्य हैं। हमने किसी को नहीं बदला। इस मौके पर उन्होंने पांच साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने रखा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस बार दिल्ली की जनता काम के नाम पर वोट देगी। धर्म और राजनीति करने वालों को वोट नहीं देगी।

जनता के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पांच साल काम किया। शुरू में तेजी से काम किया। इसके बाद एलजी साहब के पास फाइलें अटकने लगीं तो धरना देना पड़ा। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसके बाद से फाइलें तेजी से चल रही हैं। वहीं कन्हैया कुमार के मामले में उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट तैयार करने में तीन साल लगाए। दिल्ली सरकार के अधिकारी और कानूनी विशेषज्ञ उस चार्जशीट का परीक्षण कर रहे हैं। अभी एक साल भी नहीं हुआ है। सरकार, अधिकारी और वकील निर्णय लेंगे। हम नहीं चाहते कि जल्दबाजी और राजनीति के स्तर पर फैसला होना चाहिए। गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। हम इस पर सेवानिवृत्त जजों, वकीलों से राय ले रहे हैं। इस बीच उन्होंने अनधिकृत कॉलोनियों के मामले पर एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला और कहा कि भाजपा वाले कच्ची कॉलोनियों के नाम पर जो कर रहे हैं, वो सही नहीं कर रहे हैं। जिनको रजिस्ट्री दी है, वह फर्जी है। यह लोग कह रहे हैं कि खेती की जमीन पर रजिस्ट्री दे रहे हैं। इससे बड़ा फर्जीवाड़ा क्या हो सकता है। पहले उन्हें लैंडयूज बदल कर खेती की जमीन को आवासीय बनाना था। ग्राम सभा की जमीन को भी आवासीय बनाने के बाद नक्शे पास कराते और रजिस्ट्री करते, रहा सवाल आयुष्मान भारत योजना का तो दिल्ली सरकार ने जो योजना शुरू की है उसके तहत दिल्ली में सभी सरकारी अस्पताल व मोहल्ला क्लीनिक में सभी तरह का इलाज मुफ्त है।

महिला सुरक्षा को लेकर हैं चिंतित : महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हम चिंतित हैं। इसमें सभी को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। दिल्ली सरकार की तरफ से हम लोग सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं। कई इलाकों में युवतियां इसकी वजह से खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं।

एमसीडी को फंड जारी नहीं किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आरोप गलत है। कर्मचारियों को सारा रिकॉर्ड दिखाया था। 2014 में शीला जी की सरकार थी। 2014 में राष्ट्रपति शासन था। उसके बाद हमारी सरकार आई। एमसीडी को 2013 और 2014 में जितने पैसे दिल्ली सरकार ने दिए थे। उससे तीन गुना ज्यादा पैसा आज मेरी सरकार दे रही है।

चुनावी हलचल

1.5 करोड़ लोगों तक पहुंचा आप का रिपोर्ट कार्ड

नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने दावा किया है कि आप का रिपोर्ट कार्ड 30 लाख घरों तक पहुंचाया जा चुका है। इसके माध्यम से दिल्ली के 1.5 करोड़ लोगों को सरकार द्वारा कराए गए कार्यों की जानकारी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जनता खुद तय करेगी कि पार्टी दे दिल्ली में क्या काम किया है। जनता तक रिपोर्ट कार्ड पहुंचाने का काम 60 हजार वालंटियर्स ने डोर टू डोर अभियान के तहत किया है। यही नहीं 10 दिनों में पूरी दिल्ली में 650 मोहल्ला सभा के माध्यम से 13 लाख लोगों के साथ पार्टी ने सीधा संवाद किया है। गुरुवार तक 50 मोहल्ला सभा और करके 5 लाख घरों में कार्यकर्ता दस्तक देंगे। देश में पहली बार कोई सरकार अपने पांच सालों के कार्यों के रिपोर्ट कार्ड को घर-घर पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद 7 टाउन हाल मीटिंग के अंतर्गत जनता के समक्ष रिपोर्ट कार्ड पर हजारों लोगों से चर्चा कर चुके हैं। उनके विभिन्न सवालों का जवाब उन्होंने दिया है। (जासं)

कई नेता आम आदमी पार्टी में शामिल

नई दिल्ली : विभिन्न दलों के कई नेता मंगलवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वे लोग पांच साल में केजरीवाल सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों से प्रभावित होकर आप में आए हैं। इन सभी ने आप से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता, विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी आदि की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। आप में शामिल होने वालों में बीएसपी से पूर्व पार्षद प्रत्याशी फरीद शाह, जहांगीरपुरी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हाजी रफत अली शामिल हैं। (जासं)

दिल्ली के नतीजे हरियाणा से बेहतर होंगे : सुभाष चोपड़ा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में टिकट के लिए आवेदन करने वालों का तांता लगा रहा। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ खासी संख्या में लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा से मुलाकात करके विभिन्न सीटों के लिए दावेदारी जताई।

चोपड़ा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में पार्टी की मजबूत स्थिति को देखते हुए आज दूसरे दलों के लोग भी कांग्रेस में शामिल होने के इच्छुक हैं। उन्होंने चुनावी सर्वेक्षणों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले जो सर्वेक्षण आया था, उसमें कांग्रेस को तीन सीट दी जा रही थी, जबकि बाद में परिणाम कुछ और ही रहा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के नतीजे न केवल हरियाणा की तर्ज पर आएंगे बल्कि उससे बेहतर होंगे। उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस दिल्ली में अपने दम पर सरकार बनाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वो घर-घर पार्टी की नीतियों को पहुंचाएं व भाजपा व आप की विफलताओं को भी सामने लाएं। वहीं मुख्य प्रवक्ता मुकेश शर्मा ने कहा कि सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में हर सीट पर संभावित दावेदारों की लंबी कतार है। पार्टी जीतने वाले मजबूत व पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारेगी।

सुभाष चोपड़ा। फाइल

भाजपा के संभावित उम्मीदवारों के लिए आज होगी रायशुमारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही भाजपा में प्रत्याशी तय करने की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। बुधवार को सभी विधानसभा क्षेत्रों के संभावित प्रत्याशियों के नाम पर रायशुमारी होगी, जिसमें विस्तारक, प्रभारी, संयोजक के साथ ही विधायक व पार्षद भी शामिल होंगे। सभी उम्मीदवार को लेकर लिखित राय देंगे। उनकी राय एक पेटी में बंद की जाएगी जिसके आधार पर केंद्रीय नेतृत्व अंतिम फैसला लेगा।

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के कई नेता टिकट की दौड़ में शामिल हैं। इनमें से योग्य उम्मीदवार के चयन और इस काम में पारदर्शिता लाने के लिए इस बार यह तरीका अपनाया गया है। बुधवार को सभी 14 संगठनात्मक जिलों में इसके लिए बैठकें होंगी जिसमें प्रदेश के दो नेता पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल होंगे। उनकी उपस्थिति में संबंधित जिला में आने वाले सभी विस क्षेत्रों के प्रत्याशियों के नाम पर कार्यकर्ता राय देंगे।

जजपा भी उतरेगी मैदान में, 12 सीटों पर फीडबैक ले रहे दुष्यंत

अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़

हरियाणा में भाजपा की सहयोगी जननायक जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में ताल ठोंकने का निर्णय लिया है। इसके लिए वह करीब एक दर्जन विधानसभा सीटों पर सर्वे करा रही है। इसी सप्ताह सर्वे पूरा हो जाएगा। जजपा यह फीडबैक जुटाने में लगी है कि किन सीटों पर उसकी स्थिति मजबूत हो सकती है और किन सीटों पर मेहनत करनी पड़ेगी।

दिल्ली में जजपा अकेले ताल ठोंकेगी या भाजपा के साथ गठबंधन करेगी, इसका फैसला भी पार्टी ने भाजपा के रणनीतिकारों पर छोड़ दिया है। जजपा चाहती है कि दिल्ली विस चुनाव में भाजपा उससे गठबंधन करे, जिसका फायदा दोनों को मिल सकता है। अगर भाजपा तैयार नहीं होती तो वह अकेले चुनाव लड़ेगी। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली चुनाव के मद्देनजर 11 जनवरी को बैठक बुलाई है। चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए 10 नेताओं की एक कमेटी भी बनाई गई है, जिसमें एनसीआर के जिलों के पार्टी अध्यक्ष और दिल्ली यूनिट के नेता शामिल हैं।

जजपा को दिल्ली में जाट बाहुल्य सीटों पर अधिक समर्थन मिलने की आस है। नजफगढ़, बिजवासन, महिपालपुर, मुंडका, बवाना, नरेला, मटियाला, पालम, महरौली, नांगलोई जाट, बदरपुर, देवली और चकरपुर सीटें ऐसी हैं, जहां दुष्यंत चौटाला को लगता है कि उनकी पार्टी को बढ़त मिल सकती है।

दुष्यंत चौटाला। फाइल

शाह को ढूंढने की जरूरत नहीं, गलियों में देखें कैमरे : सिसोदिया

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : सियासी संग्राम में सीसीटीवी कैमरे पर सियासत गरमाने लगी है। भाजपा अध्यक्ष व गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीसीटीवी कैमरे को लेकर उठाए गए सवाल पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि शाह को कैमरे ढूंढने की जरूरत नहीं है, जहां वह घूम रहे हैं, उन्हीं गलियों में देखें मिल जाएंगे कैमरे। प्रचार के लिए वह जहां भी गए वहां कैमरे में कैद हुए हैं। इसे लेकर उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है। उन्होंने कहा कि तीन दिन से शाह जनता के बीच एक सवाल उठा रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे कहां लगे हैं। उन्होंने कहा कि मैं शाह को बता देना चाहता हूं कि अभी दो दिन पहले वह लाजपत नगर की जिस गली में डोर टू डोर प्रचार करने गए थे उस गली में 16 कैमरे लगाए गए हैं। यहां तक कि जिस घर में वह गए थे, उसके बाहर भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मीडिया के सामने पेश कीं।

11 विस क्षेत्रों में मिलेगी क्यूआर कोड वाली मतदाता पर्ची

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

क्यूआर कोड वाली मतदाता पर्ची से मतदान करने का मौका इस बार सिर्फ 11 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं को ही मिलेगा। दरअसल सोमवार को चुनाव आयोग ने इतने विधानसभा क्षेत्रों में इस तरह की पर्ची के इस्तेमाल की स्वीकृति दी है। हालांकि दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में इसे लागू करने की तैयारी की गई थी।

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) डॉ. रणबीर सिंह ने कहा कि क्यूआर कोड का इस्तेमाल अभी ट्रायल के चरण में है। झारखंड में पांच विधानसभा क्षेत्रों में इस्तेमाल किया गया था। अब दिल्ली में चुनाव आयोग ने हर जिले में एक विधानसभा क्षेत्र में इसे लागू करने का निर्देश दिया है। इस तरह आने वाले समय में चुनाव आयोग इसका इस्तेमाल बढ़ाएगा।

उन्होंने कहा कि सभी जिले के निर्वाचन अधिकारी क्यूआर कोड के इस्तेमाल के लिए एक-एक विधानसभा क्षेत्र का नाम प्रस्तावित करेंगे। इसके आधार पर 11 विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर इसका इस्तेमाल होगा। इन केंद्रों के प्रवेश द्वार पर हेल्प डेस्क की व्यवस्था होगी, वहीं पर मोबाइल लॉकर की भी सुविधा दी जाएगी। हेल्प डेस्क पर बीएलओ (बूथ लेबल अधिकारी) मौजूद रहेंगे, जो बूथ एप से क्यूआर कोड को स्कैन कर मतदाता को बूथ के अंदर भेजेंगे। जिनके पास पर्ची उपलब्ध नहीं होगी वे डिजिटल फोटो मतदाता पर्ची का इस्तेमाल कर सकेंगे। वोटर हेल्पलाइन एप की मदद से डिजिटल फोटो मतदाता पर्ची मोबाइल पर उपलब्ध हो सकती है। उन्होंने बताया कि जिन केंद्रों पर क्यूआर कोड वाली पर्ची दी जाएगी। उन्हीं केंद्रों पर मतदाताओं को मोबाइल अंदर ले जाने की इजाजत होगी, क्योंकि क्यूआर कोड बूथ के अंदर भी स्कैन किया जाएगा। हालांकि, ईवीएम तक मोबाइल ले जाने की सुविधा नहीं होगी। डिजिटल पर्ची का जो लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनके लिए बेहतर होगा कि वे मतदान केंद्र पर मोबाइल फोन लेकर न जाएं। इससे उनके समय की बचत होगी। साथ ही उन्हें परेशानी भी नहीं झेलनी पड़ेगी।

11 जनवरी तक मतदाता सूची में जुड़ सकता है नाम : मतदाता सूची में जिन लोगों का नाम नहीं है, वे 11 जनवरी तक सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन करने वाले इस बार मतदान नहीं कर पाएंगे।

सुरक्षा व्यवस्था से संतुष्ट : जेएनयू की घटना के मद्देनजर पूछे गए सवाल पर सीईओ ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पुलिस का मामला है। चुनाव आयोग ने उसकी समीक्षा भी की है। आयोग कानून व्यवस्था से अवगत है। इसके बाद ही चुनाव की तिथि घोषित की गई है। दिल्ली में कोई परेशानी नहीं है। विशेष परिस्थिति में चुनाव आयोग को सुरक्षा व्यवस्था पर संशय महसूस होता है तब इस पर विचार हो सकता है।

नेशनल कैपिटल

अब सीबीआइ कोर्ट में होगी यमुना विकास प्राधिकरण घोटाले की सुनवाई

जासं, गाजियाबाद : सीबीआइ की विशेष अदालत में अब यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में हुए 126 करोड़ के जमीन घोटाले की सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर केस अब मेरठ से गाजियाबाद ट्रांसफर हुआ है। इसके चलते ही मंगलवार को सीबीआइ ने प्राधिकरण के आरोपित एवं एसीओ समेत दो आरोपितों को मेरठ की जेल से लाकर गाजियाबाद की सीबीआइ की विशेष अदालत में पेश किया, जहां से विशेष न्यायाधीश अमित वीर सिंह की अदालत ने दोनों आरोपितों को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेज दिया है। अब दोनों डासना जेल में रहेंगे। अदालत ने केस की अगली सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तारीख नियत की है।

तकनीकी खराबी का पता चलने पर गो एयर की उड़ान को वापस उतारा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

आइजीआइ से वाराणसी जा रहे गो एयर की उड़ान में तकनीकी खराबी आ गई। जिसके कारण बीच रास्ते से ही उसे वापस आइजीआइ एयरपोर्ट पर उतारा गया। आपातकालीन लैंडिंग सफल रही। जिसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। विमान में 50 यात्री सवार थे।

एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक गो एयर की उड़ान संख्या जी8-186 ने मंगलवार की शाम करीब छह बजे आइजीआइ के टर्मिनल-2 से वाराणसी के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के कुछ देर बाद विमान के पायलट को उसमें तकनीकी खराबी का पता चला। जिसके बाद पायलट ने उसे वापस आइजीआइ एयरपोर्ट पर उतारने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) से संपर्क किया। खराबी की बात का पता चलने पर एटीसी अधिकारी ने विमान को एयरपोर्ट पर उतारे जाने की इजाजत दे दी। वहीं, एहतियात के तौर पर रनवे पर आपातकालीन वाहन, दमकल और बचाव कर्मियों की तैनाती कर दी गई। अधिकारियों के मुताबिक विमान के राइट इंजन में खराबी की सूचना थी। बाद में करीब 7.30 बजे उड़ान को सुरक्षित उतार लिया गया। कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि उनके लिए यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। लिहाजा तकनीकी खराबी का पता चलने पर उड़ान को वापस उतारने का निर्णय लिया गया था।

सख्त रुख

चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सख्ती शुरू कर दी है

डीटीसी बसों में पिंक टिकट से हटेगी सीएम की फोटो

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

चुनाव आचार संहिता लागू होने व चुनाव आयोग से निगरानी का निर्देश मिलने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने सख्ती शुरू कर दी है। उन्होंने सिविक एजेंसियों व चुनाव खर्च पर निगरानी रखने वाले विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकर कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। साथ ही विभागों की वेबसाइट व सरकारी भवनों से राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं का फोटो हटाने का निर्देश दिया है। दिल्ली चुनाव कार्यालय के सीईओ डॉ. रणबीर सिंह ने कहा कि विभागों की वेबसाइट पर फोटो होना चुनाव आचार संहिता के दायरे में आता है। डीटीसी बसों में महिलाओं को दिए जाने वाले पिंक टिकट से भी मुख्यमंत्री (सीएम) का फोटो हटाना होगा। चुनाव के दौरान फोटो युक्त टिकट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

डीटीसी बसों व क्लस्टर बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर के लिए पिंक टिकट दिया जाता है। हर महिला यात्री को यह टिकट लेना अनिवार्य है। टिकट के पीछे फोटो छपा होता है। सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर भी रोग लगा दी गई है। डॉ. रणबीर सिंह ने कहा कि विभागों के सोशल मीडिया एकाउंट पर किसी राजनीतिक दल के नेता का फोटो नहीं होना चाहिए। विभागों को बता दिया गया है कि आचार संहिता के उल्लंघन पर अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है।

संपत्तियों से बैनर, पोस्टर हटाने का निर्देश : मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने तीनों नगर निगम, एनडीएमसी व दिल्ली कैंट बोर्ड, सभी 11 जिलों के निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने निर्देश दिया कि आचार संहिता लागू होने के 24 घंटे में सरकारी भवन, 48 घंटे के अंदर सार्वजनिक संपत्तियों व 72 घंटे में निजी संपत्तियों से भी बैनर व पोस्टर हट जाना चाहिए।

चुनाव खर्च पर रहेगी नजर : सीईओ ने पुलिस, आयकर विभाग, नारकोटिक्स विभाग, जीएसटी, आबकारी विभाग सहित चुनाव खर्च पर निगरानी रखने वाले सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ भी बैठक की गई। उन्हें भी कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए।

राजनीतिक दलों को दी नामांकन प्रक्रिया की जानकारी : राजनीतिक दलों को भी चुनाव आचार संहिता को लेकर सचेत कर दिया गया है। साथ ही उन्हें नामांकन के दौरान फार्म-26 के साथ शपथ पत्र भरने की प्रक्रिया की भी जानकारी दी गई।

सिंगल विंडो सुविधा : चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों को कई तरह की स्वीकृति की जरूरत होती है। इसके लिए हर जिले के निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में व्यवस्था की गई है। पुलिस, फायर सहित सभी विभागों से संबंधित अनापत्ति प्रमाणपत्र एक ही जगह से मिल सकेगा।

एम-3 मॉडल का ईवीएम : सीईओ का कहना है कि एम-3 मॉडल की ईवीएम इस्तेमाल की जाएगी। पर्याप्त संख्या में ईवीएम व वीवीपैट मशीन उपलब्ध है जिसका पहले चरण का ट्रायल भी हो चुका है। मतगणना केंद्र भी चिह्नित हो चुके हैं।

नोएडा में रीजनल मैनेजर की हत्या कर कार लूटी

जागरण संवाददाता, नोएडा

सर्जिकल उपकरण बनाने वाली गुरुग्राम स्थित 3एम इंडिया लिमिटेड कंपनी के रीजनल मैनेजर गौरव चंदेल की सोमवार रात बदमाशों ने हत्या कर कार लूट ली।

रात करीब 10 बजे उनकी पत्नी से फोन पर अंतिम बार बात हुई थी। तब गौरव ने पांच मिनट में घर पहुंचने की बात कही थी, लेकिन वह घर नहीं पहुंचे। पत्नी लगातार फोन लगाती रहीं लेकिन गौरव का फोन नहीं उठा। पत्नी व सोसायटी के लोग पुलिस चौकी व थाने के चक्कर लगाते रहे, लेकिन मदद नहीं मिली। मंगलवार तड़के करीब सवा चार बजे गौरव का शव हरनंदी किनारे स्टेडियम के पास सर्विस रोड पर मिला।

हत्यारे दो माह पहले खरीदी गई उनकी कार, दो मोबाइल, पर्स, लैपटॉप सहित अन्य सामान लूट ले गए। कोतवाली फेज तीन पुलिस एफआइआर दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। एसएसपी वैभव कृष्ण के निर्देश पर पुलिस टीमें हत्यारों की तलाश कर रही हैं। मूलरूप से कानपुर के अशोक नगर निवासी 40 वर्षीय गौरव चंदेल गौर सिटी के पांचवें एवेन्यू में परिवार के साथ रहते थे। परिवार में पत्नी प्रीति चंदेल व 10 वर्षीय बेटा आदित्य है।

पुलिस के अनुसार, हर रोज की तरह सोमवार रात करीब आठ बजे

900 अंतरराष्ट्रीय डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग फर्म ने डिफेंस एक्सपो-2020 के लिए पंजीकरण कराया है। यह पांच से नौ फरवरी के बीच लखनऊ में आयोजित होने वाला है। यह पहली बार है, जब लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है।

'मोदी ने राजनीति को जातिवाद, वंशवाद से किया मुक्त'

- गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री के जीवन पर केंद्रित पुस्तक 'कर्मयोद्धा ग्रंथ' का किया विमोचन
- शाह बोले-पीएम ने तोड़े परंपरागत राजनीति के मिथक, दशकों से लंबित मुद्दे हल करने को उठाए कड़े कदम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति को तीन श्रापों- तुष्टीकरण, जातिवाद और वंशवाद से मुक्त कर दिया है। उन्होंने कुछ ऐसे साहसिक फैसले लिए जो पिछले 70 सालों में कोई और नहीं ले सका।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित पुस्तक 'कर्मयोद्धा ग्रंथ' का विमोचन करते हुए मंगलवार को भाजपा अध्यक्ष व गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि तुष्टीकरण, जातिवाद, परिवारवाद में जकड़ा राजनीतिक नेतृत्व देश की समस्या से निपटने के लिए बड़े फैसले लेने से बचता रहा, जबकि निस्वार्थ सेवा के भाव से शीर्ष पद पर पहुंचे मोदी ने 70 सालों से लंबित मुद्दों को हल करने के लिए देशहित में कई बड़े फैसले किए। मोदी ने अपने राजनीतिक जीवन में भारतीय राजनीति में जड़ जमाए कई राजनीतिक मिथकों और भ्रांतियों को तोड़ने का काम किया है।

प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने लंबे सफर को याद करते हुए अमित शाह ने कहा कि अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा से 'राजा प्रथमो सेवक' के मंत्र पर काम किया। यही कारण है कि मोदी कभी भी अपनी चिंता नहीं करते और उन्होंने हमेशा देश के आम नागरिकों को ध्यान में रखा है। गरीबों के हित में मोदी के ऐतिहासिक कामों को बताते हुए अमित शाह ने कहा कि सरकार करोड़ों परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन, बिजली और पांच लाख रुपये तक सालाना मुफ्त इलाज के बाद 2022 तक सभी को अपना घर देने जा रही है।

नई दिल्ली में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित पुस्तक 'कर्मयोद्धा ग्रंथ' के विमोचन अवसर पर संबोधित करते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। प्रेट्र

अमित शाह ने कहा कि पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के दौरान 14 लाख करोड़ रुपये के घोटाले के आरोपों के बीच प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होकर नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली थी। इसके बाद पिछले छह साल में केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने देश की समस्याओं को लटकाए रखने का काम किया। जबकि मोदी ने अनुच्छेद 370, 35ए, राममंदिर और नागरिकता संशोधन कानून जैसे लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए कठोर निर्णय लेने का काम किया। वैश्विक मंचों पर भारत की छवि मजबूत करने के मुद्दे पर शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पूर्ववर्ती विदेश नीति को बदल दिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा नीति से जोड़ते हुए देश के इन दोनों ही पहलुओं को मजबूत करने का काम किया। उन्होंने विश्व पटल पर यह स्पष्ट कर दिया कि आतंकी हमलों का जवाब भारत अपने दम पर ही देगा। ऐसे कड़े कदम उठाकर भी भारत वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के 2014 के घोषणापत्र में किए गए 90 फीसद वादों को पूरा किया जा चुका है।

राज्यों से ठोस कचरा प्रबंधन व वायु प्रदूषण पर जवाब-तलब

- एनजीटी ने कहा, प्रस्तुत रिपोर्ट में कचरे की निकासी और प्रबंधन के बीच भारी अंतर
- केंद्र शासित प्रदेशों से भी प्रदूषित नदियों के पुनरुद्धार पर मांगी जानकारी

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से ठोस कचरा प्रबंधन, नदियों के प्रदूषित हिस्सों के पुनरुद्धार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन को लेकर जानकारी मांगी है। यह जानकारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) मुख्य सचिवों से एकत्र करेगा।

एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सीपीसीबी ने जो रिपोर्ट सौंपी है वह प्रकार व परिमाण के लिहाज से पूर्ण नहीं है और उपलब्ध जानकारी में मल-मूत्र की निकासी और उसके प्रबंधन के बीच भारी अंतर है। पीठ ने कहा, 'सीपीसीबी ने 'अच्छा', 'औसत', 'खराब' और 'कोई जानकारी नहीं' की श्रेणी में जानकारी उपलब्ध कराई है, जो किसी गुणात्मक विश्लेषण पर नहीं, बल्कि मुहैया कराई गई जानकारी पर आधारित है।'

ठोस कचरा प्रबंधन के मुद्दे पर पीठ ने कहा है कि नगरपालिका क्षेत्र में निकलने वाले कचरे की मात्रा, कचरे की प्रकृति के हिसाब से उसे अलग-अलग करने और उसके प्रबंधन के साथ ही पहले से जमा कचरे के बारे में जानकारी की जरूरत है। नदियों के 351 प्रदूषित हिस्सों के पुनरुद्धार के संदर्भ में एनजीटी ने कहा है कि राज्यों को निर्देशों के अनुपालन के बारे में जानकारी मुहैया करानी है। इसमें स्थाई और अस्थाई उपचार की व्यवस्था और नदियों में गंदे पानी के प्रवाह को रोकने के लिए किए गए उपाय इत्यादि शामिल हैं।

पीठ ने मुख्य सचिवों को यह निर्देश दिया है कि वो जिन शहरों में वायु की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है, वहां कार्य योजना के क्रियान्वयन की स्वयं निगरानी करें और सीपीसीबी को इसकी जानकारी दें। इससे पहले एनजीटी ने कहा था कि सीपीसीबी के डाटा के मुताबिक देश में चार हजार से ज्यादा पुराने कचरे के ढेर पड़े हैं, जिनका तत्काल प्रबंधन अति आवश्यक है, क्योंकि इससे पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है और गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं।

आरपीएफ में सर्वाधिक दस फीसद महिलाएं

नई दिल्ली, प्रेट्र : रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के पास केंद्रीय सुरक्षा बलों में सर्वाधिक महिला कर्मी हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरपीएफ में दस फीसद महिलाएं हैं। बाकी अर्धसैनिक बल केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन हैं, लेकिन आरपीएफ रेल मंत्रालय के तहत आता है।

आरपीएफ के महानिदेशक अरुण कुमार ने मंगलवार को बताया कि वर्ष 2019 में कई गई भर्तियों के चलते आरपीएफ में कुल बल का दस फीसद महिलाएं हो गई हैं। आरपीएफ में कुल 80 हजार जवान हैं जिनमें आठ हजार महिलाएं हैं। आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर के पद के लिए 1121 उम्मीदवारों (823 पुरुष और 298 महिलाओं) ने आवेदन किया था। इनमें से 929 उम्मीदवारों (682 पुरुष और 247 महिलाओं) ने शुरुआती प्रशिक्षण के बाद कामकाज संभाल लिया है। इसी तरह आरपीएफ में कांस्टेबल पद के लिए 5,850 (3350 पुरुष और 2500 महिलाओं) को चयनित कर प्रशिक्षण के बाद पदभार सौंप दिया गया है। जबकि बैंड में 1044 कांस्टेबलों की भर्ती की प्रक्रिया जारी है। मार्च 2019 तक सेंट्रल इंडस्ट्रीयल सिक्योरिटी फोर्स (सीआइएसएफ) में सर्वाधिक महिला जवान (5.55 फीसद) थीं।

न्यूज गैलरी

बंगाल में एनआइए के मामलों की सुनवाई विशेष अदालत में

कोलकाता : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) से संबंधित मामलों पर सुनवाई के लिए विशेष अदालत गठित करने का निर्णय किया है। सूबे के तीन जिलों दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूचबिहार को हालांकि इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) अधिनियम 2019 के अस्तित्व में आने के महीनों बाद यह कदम उठाया गया है। मंत्रालय की ओर से इस बाबत गत सोमवार को अधिसूचना जारी कर कहा गया कि केंद्र सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर कोलकाता स्थित विचार भवन में स्पेशल सीबीआइ कोर्ट नंबर 3 को एनआइए कोर्ट के तौर पर नामजद करने का निर्णय किया है। इसके दायरे में बंगाल के तीन जिले जलपाईगुड़ी, कूचबिहार व दार्जिलिंग को छोड़कर बाकी सारे जिले आएंगे। (जासं)

नदियों को बचाने की चिट्ठी याचिका के रूप में स्वीकार

बिलासपुर : अरपा व प्रदेश की अन्य नदियों की हो रही दुर्दशा को लेकर मिले पत्रों को चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन ने गंभीरता से लिया है। लिखे गए अलग-अलग पत्र को जनहित याचिका के रूप में दायर करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए एक सप्ताह का समय तय किया है। स्टेट बार काउंसिल व अन्य सामाजिक संगठनों ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर अरपा नदी सहित प्रदेश की अन्य नदियों का जिक्र किया है। पत्र में कहा गया था कि नदियों का संरक्षण न होने के कारण लगातार प्रदूषित हो रही हैं। इसके अलावा रेत के अवैध उत्खनन के चलते नदियों का स्वरूप बिगड़ने लगा है। (नईदुनिया)

पूर्व सांसद जयाप्रदा हरियाणा में करेंगी काम

चंडीगढ़ : भाजपा की वरिष्ठ नेत्री पूर्व सांसद एवं अदाकारा जयाप्रदा ने मंगलवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। फरीदाबाद जिले की तिगांव विधानसभा सीट से भाजपा विधायक राजेश नागर ने जयाप्रदा की सीएम से मुलाकात कराई। राजेश नागर और जयाप्रदा के परिवार के बीच पुराने रिश्ते हैं। जयाप्रदा ने करीब आधे घंटे तक सीएम निवास पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ हरियाणा के राजनीतिक व सामाजिक मसलों पर बातचीत की। सूत्रों के अनुसार अगले कुछ दिनों में जयाप्रदा हरियाणा में काम करती हुई दिखाई दे सकती हैं। हालांकि किस मुद्दे पर दोनों की बातचीत हुई, इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। बताया जा रहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा हुई है। जयाप्रदा ने मुख्यमंत्री को शाल भेंट की। (राब्यू)

राजदूतों को कश्मीर ले जाएगा भारत

कूटनीति ▸ प्रदेश की स्थिति से विदेशी राजनयिकों को अवगत कराने का प्रयास

आम जनता से मिलने, सुरक्षा का जायजा लेने का दिया जाएगा मौका

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य के विभाजन के बाद की स्थिति से विदेशी राजनयिकों को अवगत कराने के लिए भारत सरकार उन्हें इसी हफ्ते घाटी ले जाएगा। 9 और 10 जनवरी को यूरोपीय संघ, आसियान, दक्षिण अमेरिकी और कुछ अफ्रीकी देशों के राजदूतों को कश्मीर के दौरे पर ले जाने का फैसला किया गया है। वहां जाने वाले विदेशी राजनयिकों को आम जनता से मिलने, सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने और पत्रकारों तथा नागरिक संगठनों से मिलने का पूरा मौका दिया जाएगा। पांच अगस्त, 2019 को कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद यह पहला मौका होगा, जब सरकार की तरफ से विदेशी राजनयिकों को कश्मीर ले जाया जाएगा। हालांकि, इस बीच यूरोपीय संघ के कुछ सांसदों ने कश्मीर का दौरा किया था।

सूत्रों के मुताबिक, वहां के स्थानीय पत्रकारों से मिलने का मौका दिए जाने के बावजूद अभी तक राजनयिकों की तरफ से वहां प्रेस कान्फ्रेंस करने की कोई योजना नहीं है। यह दौरा सरकार ने तब करवाने का फैसला किया जबकि कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने का प्रावधान समाप्त किए जाने को लेकर विदेश में सवाल उठाए जा रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के कई सांसद लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, जबकि कई विदेशी अखबार भी इस फैसले की आड़ में भारत की छवि एक अलोकतांत्रिक देश के तौर पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विदेशी अखबारों में लगातार भारत विरोधी खबरों के छपने से सरकार भी चिंतित है, क्योंकि इसका दूरगामी असर निवेश पर भी पड़ने की आशंका है। यूरोपीय संघ के कुछ सांसदों के कश्मीर दौरे के बाद सरकार ने स्वयं बताया कि वह उनका निजी दौरा था।

उल्लेखनीय है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान इस मामले को दुनिया के विभिन्न मंचों पर उठा रहा है। प्रधानमंत्री इमरान खान और उसके मंत्रियों का कहना है कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर में लोगों का दमन कर रही है। इस मामले को लेकर पाकिस्तान ने दुनिया भर में भारत विरोधी दुष्प्रचार किया लेकिन किसी भी देश ने उसे तवज्जो नहीं दी। इस मामले को लेकर पाकिस्तान बड़ी उम्मीदों के साथ इस्लामिक देशों के संगठन के पास भी पहुंचा और रोना रोया, लेकिन वहां भी उसकी बात नहीं बनी।

खराब की गई मुद्रा बदलने के मामले पर गौर करे केंद्र : सुप्रीम कोर्ट

- जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी समूह ने खराब की थी भारतीय मुद्रा
- अदालत ने सॉलिसिटर जनरल से दो सप्ताह में सूचित करने को कहा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी समूहों द्वारा भारत विरोधी नारे लिखकर खराब की गई 30 करोड़ की भारतीय मुद्रा बदले जाने के मामले की जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से गौर करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि यह राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा हो सकता है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने सतीश भारद्वाज की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।

जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की जम्मू-कश्मीर शाखा ने खराब की गई 30 करोड़ की भारतीय मुद्रा बदली थी। यह नियमों के मुताबिक सही नहीं है। याचिका में कहा गया है कि कश्मीरी ग्रेफिटी नामक अलगाववादी समूह ने 30 करोड़ की भारतीय मुद्रा पर भारत विरोधी नारे लिखकर और मुहर लगाकर उन्हें खराब किया था। अलगाववादी ग्रुप ने फेसबुक पर पोस्ट करके मई 2013 से अगस्त 2013 के बीच 30 करोड़ की भारतीय मुद्रा को खराब करने की बात कही थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि नियमों के मुताबिक खराब नोटों को बैंक नहीं बदल सकता। आरबीआइ की जम्मू-कश्मीर शाखा ने ऐसे नोटों को बदला था। इस मामले की कोर्ट की निगरानी में सीबीआइ से जांच कराई जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने इस बारे में आरबीआइ से पूछा था और सीबीआइ को भी बताया था। लेकिन, उसे कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उसने यह याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अदालत कक्ष में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह मामले पर गौर करके दो सप्ताह में कोर्ट को बताएं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह याचिका की प्रति सॉलिसिटर जनरल को दे।

राजीव के हत्यारों की रिहाई का प्रस्ताव खारिज किया था : केंद्र

- मद्रास हाई कोर्ट को सरकार ने दी जानकारी
- सजायाफ्ता नलिनी ने रिहाई के लिए दायर की है याचिका

चेन्नई, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने मंगलवार को मद्रास हाई कोर्ट को बताया कि उसने राजीव गांधी हत्या मामले में उम्र कैद की सजा पाए सभी सातों दोषियों को रिहा करने के तमिलनाडु सरकार के मार्च, 2016 के प्रस्ताव को दो साल पहले खारिज कर दिया था, क्योंकि इससे 'खतरनाक परंपरा' की स्थापना होती।

सरकार ने यह भी बताया कि मामले की जांच करने वाले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने भी प्रस्ताव का विरोध किया था। केंद्र सरकार ने 18 अप्रैल, 2018 को तमिलनाडु के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा था कि आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 435 के मुताबिक भी दोषियों की सजा को दोबारा कम करने के प्रस्ताव को मंजूरी देना उचित नहीं है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने पत्र में कहा था कि चार विदेशी नागरिकों ने तीन भारतीय नागरिकों के साथ मिलकर पूर्व प्रधानमंत्री और अन्य 15 लोगों की हत्या कर दी थी। ऐसे लोगों को रिहा करने से खतरनाक परंपरा पड़ेगी और जिसका भविष्य में इस तरह के दूसरे आपराधिक मामलों पर अंतरराष्ट्रीय प्रभाव पड़ने की संभावना बढ़ेगी।

जस्टिस आर सुब्बैया और जस्टिस आर पोंगियप्पन की पीठ के समक्ष अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल जी. राजगोपाल ने उस पत्र की एक कॉपी पेश की। अदालत सात में से एक सजायाफ्ता नलिनी श्रीहरन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने कहा था कि कैबिनेट द्वारा उसे और अन्य लोगों को रिहा करने की सिफारिश करने के बाद उसे वेल्लोर जेल में रखना गैरकानूनी है।

पत्र का संज्ञान लेते हुए पीठ ने केंद्रीय गृह सचिव को इस मामले में पक्षकार बनाते हुए अधिकारियों को 28 जनवरी तक जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया और तब तक के लिए मामले को स्थगित कर दिया। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एक चुनावी रैली में 21 मई, 1991 को आत्मघाती हमले में हत्या कर दी गई थी। विशेष टाडा अदालत ने इस मामले में सात लोगों-वी श्रीहरन, टी सत्येंद्रराजा, जयकुमार, रॉबर्ट पायस (सभी श्रीलंकाई नागरिक) और एजी परीवलन, रविचंद्रन और नलिनी को फांसी की सजा सुनाई थी। बाद में इनकी सजा को उम्रकैद में बदल दी गई थी। तमिलनाडु सरकार ने इस आधार पर सभी को रिहा करने का प्रस्ताव किया था कि, सभी ने 24 साल से ज्यादा समय तक जेल में काट लिए हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।

कर चोरी मामले में कार्ति की डिस्चार्ज अर्जी खारिज

- कोर्ट ने कार्ति और उनकी पत्नी को 21 को हाजिर होने का दिया आदेश, वारंट जारी करने की चेतावनी भी दी

चेन्नई, प्रेट्र : तमिलनाडु की एक विशेष अदालत ने कर चोरी के मामले में कांग्रेस सांसद व पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम तथा उनकी पत्नी श्रीनिधि की आरोपमुक्त करने करने संबंधी (डिस्चार्ज) अर्जी खारिज कर दी। साथ ही अगली तिथि पर उपस्थित नहीं रहने पर वारंट जारी करने की भी चेतावनी दी।

विधायक व सांसदों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित चेन्नई की विशेष अदालत के जज डी. लिंगेश्वरन ने कार्ति व उनकी पत्नी की डिस्चार्ज अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई की। जज ने अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत साक्ष्यों के तथ्यों को मुकदमा चलाने के लिए उपयुक्त पाया और कार्ति तथा उनकी पत्नी की डिस्चार्ज अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अभियोजन को इस मामले में आरोपपत्र दाखिल करने का आदेश देते हुए दोनों आरोपितों को 21 जनवरी को हाजिर होने का आदेश दिया। साथ ही अनुपस्थित रहने पर वारंट जारी करने की चेतावनी भी दी।

मामला मुट्टुकांडु में जमीन की बिक्री से संबंधित है। आरोप है कि कार्ति व उनकी पत्नी ने जमीन की बिक्री से मिली 1.35 करोड़ की नकदी को आयकर विभाग से छिपाया। हालांकि, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि लेनदेन पूरा होने के बाद वर्ष 2015 में आयकर रिटर्न भी दाखिल किया गया था। उस समय कार्ति सांसद नहीं थे। आयकर विभाग के उपनिदेशक (अनुसंधान), चेन्नई ने इस मामले में 12 सितंबर 2018 को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट-2 (आर्थिक अपराध) में शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में इस मामले को विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया।

कार्ति चिदंबरम। फाइल

मां ने आइएस समर्थित बेटी को अफगानिस्तान से लाने की लगाई गुहार

तिरुअनंतपुरम, आइएएनएस : केरल की एक महिला बिंदु ने काबुल (अफगानिस्तान) की जेल में बंद अपनी इस्लामिक स्टेट (आइएस) समर्थक बेटी निमिषा को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार से गुहार लगाई है।

बिंदु ने मीडिया से कहा, उसने सुना है कि उसकी बेटी और पूर्व आइएस कार्यकर्ताओं की नौ अन्य भारतीय विधवाएं इस समय काबुल की जेल में बंद हैं। भारत सरकार से उन्हें वापस लाने का अनुरोध करते हुए उसने कहा, 'मैं भारतीय हूं और उन्होंने जो किया है उसके लिए उनके खिलाफ भारतीय कानून के मुताबिक प्रक्रिया अपनाई जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी पर किसी अंजान देश में मुकदमा चले। मुझे अपने देश के कानून पर पूरा भरोसा है। मेरे पास जो भी जानकारी थी वो मैं पहले ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) के साथ साझा कर चुकी हूं। मैं जानना चाहती हूं कि मेरी बेटी को कैसे और किसने गुमराह किया और उसके साथ क्या हुआ। उसके साथ जो भी हुआ उसके सुबूत केरल में ही हैं इसलिए केंद्र को मेरी बेटी और अन्य को वापस लाना चाहिए।' बता दें कि निमिषा की पिछले साल नवंबर में बिंदु से बात हुई थी।

डीके शिवकुमार मामले में एनजीओ पर उठे सवाल

- सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, किस हैसियत से इस मामले में दायर की है याचिका
- एनजीओ से लोकायुक्त के पास की गई शिकायत की जानकारी मांगी

नई दिल्ली, प्रेट्र : भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के खिलाफ मामला चलाने की मांग करने वाले एक एनजीओ से सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कई सवाल पूछे। शीर्ष अदालत यह जानना चाहती थी कि एनजीओ की तरफ से किस हैसियत से इस मामले में सुनवाई की मांग की जा रही है।

शिवकुमार पर कर्नाटक के राजस्व मंत्री रहते हुए 2010 में जंगल की जमीन के उपयोग को बदलकर आवासीय करने का आरोप था। उनके खिलाफ शिकायत की गई थी, बाद में कर्नाटक हाई कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया था। उसी मामले में समाज परिवर्तन समुदाय नामक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने एनजीओ के वकील प्रशांत भूषण से पूछा कि उसकी तरफ से लोकायुक्त के पास कब शिकायत की गई थी, उस मामले में क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि दो अन्य शिकायतकर्ताओं के हट जाने के बाद एनजीओ ने हस्तक्षेप आवेदन दाखिल किया है।

पीठ ने इस मामले को आगे बढ़ाने की एनजीओ की मंशा पर भी सवाल उठाए। भूषण से स्पष्ट कहा, 'आप दूसरे के कंधे की सवारी नहीं कर सकते।' भूषण ने जब स्पष्ट जानकारी नहीं दी तो पीठ ने फिर कहा कि वह जानना चाहती है कि लोकायुक्त के यहां एनजीओ ने शिकायत की थी या नहीं। पीठ ने जवाब के लिए दो हफ्ते का वक्त दिया है।

कांग्रेस नेता की तरफ से पेश वकील मुकुल रोहतगी और पीएस नरसिम्हा ने भूषण की दलील का विरोध करते हुए कहा कि सुनवाई में एनजीओ कभी पार्टी ही नहीं था और उसकी तरफ से लोकायुक्त के पास कभी कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई थी।

इस मामले में फरवरी, 2012 में एक विशेष अदालत ने येदियुरप्पा, शिवकुमार और अन्य के खिलाफ दायर निजी शिकायत पर संज्ञान लिया था। हालांकि, दिसंबर, 2015 में हाई कोर्ट ने इस मामले में आपराधिक कार्यवाही को रद कर दिया था।

संविधान पीठ करेगी सबरीमाला मामले की सुनवाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश तथा मुस्लिम व पारसी महिलाओं से भेदभाव के मामलों की सुनवाई के लिए गठित संविधान पीठ में जजों को नियुक्त कर दिया है। संविधान पीठ की अध्यक्षता चीफ जस्टिस एसए बोबडे करेंगे और मामलों की सुनवाई 13 जनवरी से शुरू होगी।

संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में जस्टिस आर. भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एल. नागेश्वर राव, जस्टिस एमएम शांतनागौदर, जस्टिस एसए नजीर, जस्टिस सुभाष रेड्डी, जस्टिस बीआर गवई और सूर्य कांत शामिल हैं। इस संविधान पीठ का कोई भी सदस्य पूर्व की पीठ में शामिल नहीं था। शीर्ष अदालत ने संविधान पीठ के गठन संबंधी नोटिस सोमवार को ही जारी किया था, लेकिन जजों के नामों की घोषणा मंगलवार को की गई।

उल्लेखनीय है कि वकीलों के एक संगठन ने याचिका दाखिल कर सभी उम्र की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश दिए जाने संबंधी 28 सितंबर 2018 के ऐतिहासिक फैसले पर विचार करने का आग्रह किया है।

महत्वपूर्ण निर्णय

मंडलायुक्त ने की हरियाणा सीमा विवाद पर बैठक, कहा- लगाए जाएंगे सम-विषम नंबर के पिलर

पिलर सुलझाएंगे हरियाणा और यूपी का सीमा विवाद

जागरण संवाददाता, मेरठ

हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा विवाद के निपटारे के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय किया गया है। दोनों प्रदेश के गांवों में सीमा की पहचान के लिए सम और विषम नंबर के पिलर लगाए जाएंगे। यह निर्णय मंडलायुक्त की अध्यक्षता में शिविर कार्यालय में मंगलवार को उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों की बैठक में लिया गया।

मंडलायुक्त अनीता सी. मेश्राम ने मंगलवार को बैठक के बाद बताया कि पिलर (स्तंभ) की स्थापना का आधा व्यय उत्तर प्रदेश और आधा हरियाणा सरकार वहन करेगी। सीमाओं पर तीन प्रकार के पिलर लगाए जाएंगे। इसमें सीमा पिलर, मुख्य पिलर व उप पिलर हैं। हरियाणा में विषम व उत्तर प्रदेश में सम नंबर के पिलर लगेंगे। उन्होंने सीमा से लगे गांवों की खतौनियां बनवाने का काम जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। हरियाणा सीमा से उप्र के पांच जिलों के 132 गांव व हरियाणा के छह जिलों के उप्र की सीमा से 102 गांव लगते हैं। उन्होंने कहा कि जिन संबंधित जिलों में नदी या भूमि विवाद है, उसे आपस में बैठकर कार्ययोजना बनाकर सुलझाएं। दीक्षित अवार्ड के विवरण का भी उपयोग करें। 10 जनवरी को चंडीगढ़ में उच्चस्तरीय बैठक होगी।

अनीता सी मेश्राम। फाइल

यह है विवाद : मंडलायुक्त ने बताया कि पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री उमा शंकर दीक्षित ने वर्ष 1974-75 में यमुना नदी की गहरी धारा को हरियाणा एवं उप्र की स्थायी सीमा स्वीकार किया था, जिसे दीक्षित अवार्ड कहा जाता है। दीक्षित अवार्ड के अंतर्गत निर्धारित सीमा पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग की निशानदेही के आधार पर सीमा पर पिलर्स लगाए गए थे, लेकिन बाढ़ व नदी के तेज बहाव के कारण पिलर्स नष्ट हो गए। भूमि के स्वामित्व को लेकर विवाद है। दीक्षित अवार्ड के अनुसार ऐसी भूमि पर उसी कृषक का स्वामित्व है जो पूर्व से ही भूमि पर काबिज रहा हो और पूर्व से ही स्वामी हो।

मंडलायुक्त ने उम्मीद जताई है कि सीमा विवाद से निपटने के लिए नए निर्णय कारगर सिद्ध होंगे और दोनों राज्यों में विकास कार्यक्रमों को निर्बाध रूप से चलाया जाएगा।

सीमा पर उप्र के जिले
सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतमबुद्धनगर, अलीगढ़

सीमा पर हरियाणा के जिले
करनाल, पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर, पलवल, फरीदाबाद

सीवीसी ने निपटाए 10 साल से लंबित 500 मामले

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने 5-10 साल से लंबित कथित भ्रष्टाचार के 500 से ज्यादा मामलों को निपटा दिया है। कार्मिक मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्य देख रहे सतर्कता आयुक्त शरद कुमार ने सोमवार को कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और उन्हें आयोग में लंबित और निपटाए गए मामलों की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया, '5-10 साल से लंबित कई मामलों को निपटा दिया गया। लिहाजा, लंबित 1,500 मामलों में दिसंबर 2019 के अंत तक पिछले तीन साल में तेजी से कमी आई और ये करीब 950 रह गए हैं।' मालूम हो कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और एक अन्य सतर्कता आयुक्त का पद पिछले छह महीने से रिक्त है और जून में शरद कुमार को अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नामित किया गया था।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

83 तेंदुओं की मौत हुई है सड़क और रेल दुर्घटनाओं में वर्ष 2019 में। 2010 में यह आंकड़ा 22 था। वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन सोसायटी ऑफ इंडिया (डब्ल्यूपीएसआइ) की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 8 जनवरी 2020

भाटपाड़ा नपा पर तृणमूल का कब्जा, सुप्रीम कोर्ट जाएगी भाजपा

जागरण संवाददाता, बैरकपुर

- अविश्वास प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में तृणमूल के पक्ष में पड़े 19 वोट
- ज्योतिप्रिय ने कहा, तृणमूल के साथ है भाटपाड़ा की जनता

बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले के भाटपाड़ा नगरपालिका के दखल को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देशानुसार कड़ी सुरक्षा के बीच मंगलवार को अविश्वास प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में तृणमूल ने जीत हासिल की। इसमें तृणमूल कांग्रेस के 19 पार्षदों ने भाग लिया। भाजपा पार्षद अनुपस्थित रहे। इस तरह तृणमूल ने 19-0 के अंतर से नपा पर कब्जा जमा लिया। इधर, भाजपा ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। सूत्रों के मुताबिक, अदालत के निर्देशानुसार मंगलवार को पालिका भवन में अविश्वास प्रस्ताव के लिए वोटिंग हुई। इसके मद्देनजर पालिका भवन की गेट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया था। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की गई है। तय समय पर शुरू हुई वोटिंग प्रक्रिया में भाजपा पार्षद नहीं पहुंचे।

मौके पर उपस्थित तृणमूल पार्षद दल के नेता मनोज साहा ने बताया कि कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया पूरी हुई। 19 पार्षदों ने तृणमूल के पक्ष में वोट दिया। गुरुवार को इसकी रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी जाएगी। वोटिंग के दौरान राज्य के खाद्यमंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक, जिला युवा तृणमूल के अध्यक्ष व विधायक पार्थ भौमिक और विधायक पारस दत्त उपस्थित थे। ज्योतिप्रिय ने कहा कि भाटपाड़ा की जनता तृणमूल के साथ है। इससे पहले भी लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में हमारे 19 पार्षद तृणमूल के साथ थे। इस बार भी उन्हीं पार्षदों ने वोट दिया है। भाटपाड़ा नपा पर तृणमूल का कब्जा है और रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि भाजपा के पार्षद यदि प्रक्रिया में भाग लेते तो तृणमूल के पक्ष कुछ और वोट बढ़ने की संभावना थी। मीडिया ने भाजपा सांसद अर्जुन सिंह को बाघ बताया था, लेकिन वह बिल्ली साबित हुए।

मरांडी और भाजपा : फिर मेल-मिलाप के दिख रहे आसार

रांची ब्यूरो, रांची

झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) का विलय भाजपा में हो सकता है। विधानसभा चुनाव के बाद इसके पक्ष में मजबूत समीकरण बनकर सामने आते दिख रहे हैं। इन समीकरणों को हाल के कुछ राजनीतिक घटनाक्रमों का भी साथ मिलता दिख रहा है। एक ओर बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी झाविमो की कार्यसमिति भंग कर दी है और खरमास के बाद नई कमेटी बनाने की बात कही है तो दूसरी ओर भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा नहीं की है।

राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि यह विलय दोनों ही पक्षों यानी मरांडी और भाजपा के लिए अनुकूल साबित हो सकता है। भाजपा को हालिया विधानसभा चुनाव में हार के रूप में झटका लगा है। इस हार का एक बड़ा कारण चुनावी रणनीति की नाकामी माना जा रहा है। पराजय के विश्लेषण में जुटी भाजपा महसूस कर रही है कि राज्य में आदिवासी सीटों पर उसे जैसी करारी हार का सामना करना पड़ा उसे देखते हुए पार्टी को एक आदिवासी चेहरे की तलाश करनी होगी। मरांडी के साथ भाजपा की आदिवासी चेहरे की तलाश पूरी हो सकती है तो मरांडी को भी एक मजबूत पार्टी का सहारा मिल सकता है।

भाजपा की समस्या : झारखंड में 28 आदिवासी सीटों में से भाजपा 26 पर हारी है। इसके बाद पार्टी ने यह महसूस किया है कि आदिवासियों के बीच पकड़ वाकई कमजोर पड़ गई है। अर्जुन मुंडा केंद्र में मंत्री हैं और फिलहाल उन्हें राज्य में पार्टी भेजना नहीं चाह रही है। ऐसे में भाजपा से राज्य के पहले मुख्यमंत्री रह चुके बाबूलाल मरांडी सबसे बेहतर विकल्प हैं। आदिवासियों के बीच उनकी अच्छी पैठ है तो गैर आदिवासियों में भी उन्हें पसंद किया जाता है। प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा और विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव समेत कई बड़े आदिवासी नेता चुनाव हार चुके हैं। मरांडी को यह पद देकर पार्टी आदिवासी आबादी की नाराजगी भी दूर कर सकेगी।

मरांडी की मजबूरी : बाबूलाल मरांडी पिछले लगभग 15 वर्षों से अलग पार्टी चला रहे हैं। इस दौरान उनकी पार्टी से कई नेता विधायक तो बने, लेकिन इनमें से अधिसंख्य पार्टी छोड़कर चले गए। विधायक बनने के बाद सरकार के साथ हो लिए और मरांडी के पास इक्के-दुक्के ही बचे। इस बार मरांडी की पार्टी में दो विधायक हैं और दोनों अपने क्षेत्रों के मजबूत चेहरे हैं। मरांडी के साथ इनके बने रहने की भी कोई गारंटी नहीं है। पिछले दो दिनों से विधानसभा में दोनों विधायक उनसे अलग-थलग ही रह रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर वह अकेले पड़ सकते हैं।

भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से संपर्क में मरांडी: राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि मरांडी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से संपर्क में हैं। बाबूलाल के रुख को लेकर उनके दल के विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की भी पसोपेश में हैं। बाबूलाल ने कमेटी भंग की तो प्रदीप यादव ने सवाल उठाया कि ऐसा करना जरूरी नहीं था। नाराज प्रदीप और बंधु के कांग्रेस में जाने की चर्चा भी जोरों पर है। प्रदीप यादव पहले भी प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह से मिल चुके हैं तो बंधु तिर्की पार्टी के संपर्क में हैं। हालांकि तमाम कयासों को बाबूलाल मरांडी ने खारिज करते हुए कहा है कि कई बार पहले भी मैं इस पर स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं।

राजनीतिक हलचल

- विधानसभा चुनाव में भाजपा को लगे झटके के बाद झारखंड में बदल रहे हैं समीकरण
- पार्टी की मजबूत आदिवासी चेहरे की तलाश पूरी होगी, मरांडी को एक सशक्त मंच मिलेगा
- भाजपा ने खरमास तक रोक रखी है नेता प्रतिपक्ष की घोषणा, झाविमो कार्यकारिणी भी खरमास में फंसी

बाबूलाल मरांडी फाइल

बाबूलाल को हटाकर मुंडा को सीएम बनाया था

बाबूलाल मरांडी जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तो कुछ विधायकों ने उनके खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया। आलाकमान तक मामला पहुंचा, विधायकों ने सीएम को हटाने की शर्त रखी। सरकार बचाने के नाम पर मरांडी को हटाकर भाजपा आलाकमान ने 2003 में अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठाया। कुछ दिन बाबूलाल पार्टी में ही रहे, फिर उन्होंने अपनी अलग पार्टी झारखंड विकास मोर्चा बना ली।

न्यूज गैलरी

ममता ने की घोषणा, बंगाल को मिलेंगे दो नए जिले

कोलकाता : बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को घोषणा की कि बंगाल में दो पुलिस जिलों सुंदरवन और बशीरहाट को नया प्रशासनिक जिला बनाया जाएगा। सुंदरवन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा वर्तमान में दक्षिण 24 परगना जिले में पड़ता है, जबकि बशीरहाट महकमा वर्तमान में उत्तर 24 परगना जिले का हिस्सा है। वर्तमान में बंगाल में कुल 23 जिले हैं और इस तरह दो नए जिले बनने से यह संख्या 25 हो जाएगी। (जासं)

कोलकाता में दिखेगी केंद्र से खारिज बंगाल की झांकी

कोलकाता : गणतंत्र दिवस समारोह के लिए बंगाल की ओर से भेजी गई झांकी के खारिज होने के बाद बंगाल सरकार अब उसे कोलकाता में राज्य के गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदर्शित करेगी। इसे 'जल बचाओ, जीवन बचाओ, हरियाली बचाओ' थीम पर तैयार किया गया है। बंगाल की झांकी खारिज करने पर ममता सरकार की तरफ से कहा गया था कि नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने के कारण दुर्भावनावश यह कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने कहा कि बंगाल के टैब्लो (झांकी) को क्यों खारिज कर दिया गया, रक्षा मंत्रालय की ओर से इस बाबत आधिकारिक तौर पर स्पष्ट कारण भी नहीं बताया गया है। (जासं)

कांग्रेस नेता से अश्लील चैटिंग करने वाला पकड़ा

कासगंज : पंजाब की एक कांग्रेस नेता को फेसबुक पर अश्लील चैटिंग कर परेशान कर रहे युवक को पंजाब पुलिस ने पकड़ लिया है। दो दिन से पंजाब पुलिस उत्तर प्रदेश के कासगंज में डेरा डाले हुए थी। पंजाब के जिला फिरोजपुर की एक कांग्रेस नेता को एक महीने से फेसबुक पर अश्लील चैटिंग कर कासगंज का युवक परेशान कर रहा था। युवक की शरारत से परेशान होकर उसने फिरोजपुर के अपर पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। उपनिरीक्षक चरनजीत सिंह के नेतृत्व में आई पंजाब पुलिस ने कासगंज के अशोक नगर निवासी नोयडिल को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब पुलिस आरोपित को अपने साथ ले गई है। (जासं)

सेंट्रल जेल में खींची तस्वीर के मामले में एडीजीपी करेंगे जांच

पटियाला : बलवंत सिंह राजोआणा की सेंट्रल जेल के अंदर खींची गई तस्वीर के मामले की जांच एडीजीपी जेल पीके सिन्हा करेंगे। राजोआणा पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में केंद्रीय जेल पटियाला में फांसी की सजा काट रहा है। बता दें कुछ दिन पूर्व राजोआणा ने जेल के अंदर भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा की थी। इसके बाद पिछले सोमवार को एसजीपीसी अध्यक्ष गोबिंद सिंह लोंगोवाल ने केंद्रीय जेल पटियाला में राजोआणा के साथ मुलाकात की थी। (जासं)

चपरासियों को न्यायाधीशों से अधिक रियायती बिजली कैसे : हाई कोर्ट

सख्ती ▸ विभाग के कर्मचारियों को रियायती बिजली देने पर कोर्ट ने की टिप्पणी

ऊर्जा निगम के एमडी को दो सप्ताह में जवाब पेश करने के दिए निर्देश

जागरण संवाददाता, नैनीताल

नैनीताल हाई कोर्ट ने ऊर्जा निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को रियायती दरों पर बिजली देने और आम जनता के लिए दरें बढ़ाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर उत्तराखंड ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक को दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है। मंगलवार को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि चपरासियों को न्यायाधीशों से अधिक रियायती बिजली कैसे दी जा रही है। यही नहीं अभी तक निगम द्वारा स्पष्ट जवाब पेश नहीं करने पर भी कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है।

मंगलवार को देहरादून आरटीआइ क्लब की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ऊर्जा निगम की ओर से बताया गया कि बोर्ड की मीटिंग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सालाना आठ हजार यूनिट, तृतीय श्रेणी को दस हजार और प्रथम श्रेणी कार्मिकों को 11 व 12 हजार यूनिट बिजली देने का प्रस्ताव रखा गया है। अगर ये कार्मिक इससे अधिक बिजली खर्च करते हैं तो वह 50 फीसद की दर के हिसाब से भुगतान करेंगे। हालांकि इस प्रस्ताव को अब तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

इस पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि देश के सभी न्यायाधीशों को साल में दस हजार यूनिट बिजली दी जाती है और इससे अधिक खर्च करने पर उनसे प्रचलित दर पर बिल वसूला जाता है। जबकि यहां चपरासी को न्यायाधीशों से अधिक रियायती बिजली दी जा रही है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा प्रदेश नहीं है, मगर वहां एक रुपया प्रति यूनिट बिजली है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है, फिर भी यहां आम जनता से साढ़े चार रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से बिल वसूला जाता है। यही नहीं, हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को सौ से दो सौ यूनिट बिजली सब्सिडी में दी जाती है, जबकि उत्तराखंड में आठ हजार से बारह हजार यूनिट। कोर्ट ने इस पर दो सप्ताह में एमडी से जवाब पेश करने को कहा है। साथ ही अगली सुनवाई की तिथि दस फरवरी के लिए नियत कर दी।

नैनीताल हाई कोर्ट फाइल

कोर्ट ने एमडी से मांगा इनका जवाब

- अभी तक कितने कर्मचारियों के घरों में मीटर लग चुके हैं।
- उन्हें साल में कितनी यूनिट बिजली दी जाती है और किस दर से।
- 2018-19 में कितना राजस्व वसूला गया और निगम को कितना घाटा हुआ।

अधिकारियों के बिल का जनता पर पड़ रहा बोझ

जनहित याचिका में कहा गया है कि सरकार ऊर्जा निगम के अधिकारी-कर्मचारियों से एक महीने का बिल मात्र 400 से 500 रुपये व इनके आश्रितों से 100 रुपये वसूला जा रहा है। जबकि इनका बिल लाखों में आता है। इसका बोझ सीधे जनता पर पड़ रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य के तमाम ऊर्जा निगम अधिकारियों के घर पर मीटर तक नहीं लगे हैं, जो लगे हैं वह खराब हैं। उदाहरण के तौर पर जनरल मैनेजर का 25 महीने का बिजली बिल चार लाख 20 हजार आया था और उनके बिजली के मीटर की रीडिंग 2005 से 2016 तक नहीं ली गई।

भीड़ की हिंसा के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई : द्रौपदी मुर्मू

राज्य ब्यूरो, रांची

झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि राज्य सरकार धर्मनिरपेक्षता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संरक्षित करने के लिए भीड़ की हिंसा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। साथ ही सरकार सीएनटी-एसपीटी एक्ट के प्रावधानों को सख्ती से लागू करवाएगी। वह पांचवीं विधानसभा के प्रथम सत्र के अपने अभिभाषण में नई सरकार की प्राथमिकताएं गिना रही थीं। यह भी कहा कि सरकार सभी समुदायों और सभी धर्मों को सम्मान देने और उनके अधिकार के साथ रहने की पक्षधर है। राज्यपाल ने इस क्रम में कहा कि युवाओं को रोजगार, किसानों को हर संभव सहायता, महिलाओं का सशक्तीकरण, दलितों और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा तथा दुर्भावना आधारित कानूनी उलझनों से दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को मुक्ति देना सरकार की प्राथमिकता होगी। कहा, किसी द्वेष, घृणा और प्रतिशोध की भावना से दूर रहकर वंचितों को विशेष महत्व देते हुए सबको उचित अधिकार, सुरक्षा और हर घर तक समृद्धि पहुंचाना सरकार की प्रतिबद्धता रहेगी।

भाषाओं के विकास के लिए गठित होगी अकादमी : राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार सरकारी कर्मियों, पुलिस कर्मियों, शिक्षकों, अनुबंध कर्मियों तथा आंगनबाड़ी कर्मियों के हितों का पूरा ध्यान रखेगी। उन्होंने हिंदी सहित राज्य में बोली जानेवाली सभी भाषाओं के विकास के लिए अकादमी के गठन तथा जलवायु परिवर्तन व यातायात प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल करने का भरोसा भी दिलाया।

द्रौपदी मुर्मू फाइल

नेहरू के वक्तव्य से अभिभाषण का प्रारंभ

राज्यपाल ने पंडित जवाहर लाल नेहरू के उस वक्तव्य के साथ अपने अभिभाषण की शुरुआत की कि आप दीवार के चित्रों को बदलकर इतिहास के तथ्यों को नहीं बदल सकते। कहा, सरकार भारत की गरिमामयी विरासत का सम्मान करते हुए कल्याणकारी अवधारणा के अनुरूप काम करेगी।

सीबीआइ जल्द पूरी करे जांच रावत करें सहयोग : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नैनीताल

- पूर्व सीएम हरीश रावत के स्टिंग मामले में सुनवाई अब दो मार्च को
- सीबीआइ को चार्जशीट दाखिल करने के लिए लेनी होगी अनुमति

नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के विधायकों की खरीद-फरोख्त के कथित स्टिंग की सीबीआई जांच के मामले में मंगलवार को सुनवाई की। अगली सुनवाई तिथि दो मार्च नियत करते हुए कोर्ट ने सीबीआई को जल्द जांच पूरी करने और चार्जशीट पेश करने से पहले कोर्ट को अवगत कराने के आदेश दिए। साथ ही पूर्व सीएम को जांच में सहयोग करने को कहा है। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। पूर्व सीएम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल व सीबीआइ की तरफ से केंद्र के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल राकेश थपलियाल व संदीप टंडन ने बहस की। सुनवाई के दौरान अदालत परिसर में खासी गहमागहमी रही।

दरअसल, मार्च 2016 में कांग्रेस विधायकों की बगावत के बाद राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो इसी बीच विधायकों की खरीद-फरोख्त का स्टिंग सामने आया था। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद 31 मार्च 2016 को राज्यपाल की संस्तुति पर स्टिंग मामले की सीबीआइ जांच शुरू हुई। जांच एजेंसी द्वारा प्राथमिक जांच पूरी कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश कर पूर्व सीएम के खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुमति मांगी गई। तब बगावत में शामिल व वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भी 15 मई, 2016 के कैबिनेट के उस फैसले को याचिका के माध्यम से चुनौती दी, जिसमें कैबिनेट ने मामले की जांच सीबीआई से हटाकर एसआइटी से करने का निर्णय लिया था। कैबिनेट की इस बैठक में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत की गैर मौजूदगी में कैबिनेट के अन्य सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया था। सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत व न्यूज चैनल के सीईओ उमेश शर्मा के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की थी।

हरीश रावत फाइल

भर्ती घोटाले वाले सिपाहियों को जीआरपी में वापस भेजने पर रोक

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : हरियाणा में चौटाला शासनकाल में हुए जीआरपी भर्ती घोटाले वाले सभी सिपाहियों को जिलों से जीआरपी में रिवर्ट करने के आदेश पर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही हरियाणा सरकार व डीजीपी को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। 2004 में हरियाणा में जीआरपी के 350 पदों पर हुई भर्ती में घोटाले को लेकर हाई कोर्ट में लंबे समय तक सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को बताया गया था कि इन कांस्टेबलों को विभिन्न जिलों में भेज दिया गया है। इसके बाद सरकार ने कहा था कि अपराधिक मामले में किसी भी कांस्टेबल के खिलाफ कोई सुबूत नहीं मिला था, जिस कारण सरकार उन्हें नौकरी से नहीं हटा सकती है। हालांकि, इस मामले में दस्तावेज में बड़ी खामियां पाई गई थीं। वहीं, डीजीपी ने गत तीन जनवरी को एक आदेश जारी कर इन सभी को वापस जीआरपी में भेजने के ओदश जारी कर दिए। इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया कि वह वर्ष 2006 से जिलों में ड्यूटी दे रहे हैं और विभिन्न प्रमोशन के कोर्स भी कर चुके हैं। इतने लंबे समय बाद उन्हें वापस मूल विभाग में भेजना उनके साथ अन्याय होगा और उनके करियर के लिए सही नहीं रहेगा।

हिमाचल में एससी-एसटी विधायकों के आरक्षण पर मुहर

राज्य ब्यूरो, शिमला

एससी-एसटी विधायकों के आरक्षण से जुड़ा संकल्प मंगलवार को हिमाचल विधानसभा के विशेष सत्र में सर्वसम्मति से पास हो गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोक-झोंक के बाद 126वें संवैधानिक संशोधन पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने मुहर लगा दी। इस संशोधन को लोकसभा और राज्यसभा से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसे सदन में पेश किया और चर्चा के बाद उन्होंने इसका जवाब भी दिया। इस बिल पर हुई चर्चा में 12 से अधिक सदस्यों ने हिस्सा लिया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने आरक्षण के बहाने वामपंथियों पर प्रहार किए। वहीं कांग्रेस विधायक आशा कुमारी, जगत सिंह नेगी ने मनुवादी सोच पर सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि या तो दिसंबर में विशेष सत्र बुला लिया जाता या फिर राज्यपाल का अभिभाषण पूरा करवाया जाता। संविधान के मुताबिक राज्यपाल एक बार ही सदन में आ सकते हैं या फिर नई सरकार बनने पर राज्यपाल आ सकते हैं। ये सरकार की नाकामी है कि आज राज्यपाल का अभिभाषण नहीं करवा पाए। आरएसएस आरक्षण की विरोधी रही है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल इस विधेयक का पूरा समर्थन करता है। 70 साल से यह आरक्षण चला आ रहा है। हिमाचल विधानसभा में भी 17 सदस्य एससी से हैं, जबकि तीन सदस्य एसटी वर्ग से चुने हुए हैं। प्रदेश में एससी वर्ग के साथ आज भी भेदभाव हो रहा है। जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जब सब कुछ ही कांग्रेस ने किया है तो मानकर चलें कि भारत के टुकड़े भी कांग्रेस ने किए।

समाज में जागरूकता से दूर होगा भेदभाव : जयराम

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि समाज में दलित वर्ग से भेदभाव को दूर करने के लिए कानून नहीं बल्कि समाज में जागरूकता की भी जरूरत है। सदस्यों ने सदन में जितनी गंभीरता से इस मामले पर चर्चा की है, उतनी ही गंभीरता से से इस मूल समस्या पर ध्यान देते हुए इसका समाधान करने पर भी देना होगा। आज जरूरत बंधन से बाहर निकलने की है और यह स्वीकार करना होगा आज भी परिस्थिति बदली नहीं है।

एंग्लो इंडियन के मुद्दे पर उत्तराखंड कांग्रेस मुखर

राज्य ब्यूरो, देहरादून : एंग्लो-इंडियन समुदाय को संसद और राज्य विधानसभाओं में नामित किए जाने का अधिकार जारी रखने को लेकर कांग्रेस विधानसभा में मुखर रही। संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने कहा कि एक दिवसीय विधानसभा सत्र के एजेंडे में यह विषय शामिल नहीं रहा।

विधानसभा में मंगलवार को संविधान (126 वां संशोधन) विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस ने लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन को प्रतिनिधित्व जारी रखने का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह, उपनेता प्रतिपक्ष करन माहरा, गोविंद सिंह कुंजवाल, हरीश धामी ने कहा कि अनुसूचित जातियों-जनजातियों के लिए आरक्षण जारी रखने के साथ ही एंग्लो-इंडियन का प्रतिनिधित्व जारी रखने के लिए उत्तराखंड विधानसभा से संकल्प पारित होना चाहिए।

विधानसभा में 71वें एंग्लो-इंडियन विधायक जॉर्ज आइवन ग्रेगरीमैन ने एंग्लो-इंडियन समुदाय को लोकसभा और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व आगे 10 वर्ष के लिए जारी रखने का समर्थन करने की राज्य सरकार से गुजारिश की। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश के शैक्षिक, चिकित्सा, सुरक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में इस समुदाय का बड़ा योगदान है। इस समुदाय की आबादी घट रही है। हालांकि देश में महज 296 आबादी और उत्तराखंड में शून्य आबादी दर्शाने पर उन्होंने आपत्ति जताई। देशभर में कम आबादी के बारे में उन्होंने बताया कि जनगणना में एंग्लो-इंडियन का कॉलम नहीं होने से इसकी सदस्य संख्या दर्ज नहीं हो पाई। साथ ही उत्तराखंड में ही यह समुदाय 16 प्रतिष्ठित स्कूलों को संचालित कर रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर जोर दिया है। एंग्लो-इंडियन समुदाय राज्य में सरकार के कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार में योगदान दे रहा है। साथ ही इस समुदाय के कई लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और मंत्रियों से भी समर्थन मांगा।

नई व्यवस्था

देशभर में लगेगा प्रीपेड स्मार्ट मीटर, वसूली में वृद्धि की मांगी रिपोर्ट, स्मार्ट मीटर लगाने वाली बिजली कंपनियों संग बैठक

लागू होगा पहले पैसा फिर बिजली

गौरव दीक्षित, कानपुर

पहले बिल, फिर बिजली, केंद्र सरकार देशभर में यह व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर वाराणसी आदि शहरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने से मिले फायदे के बाद सरकार इस निर्णय की तरफ बढ़ रही है। मंगलवार को केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री आरके सिंह ने दिल्ली में प्रीपेड स्मार्ट मीटर व्यवस्था लागू करने वाली बिजली कंपनियों के साथ बैठक की। इस पद्धति से होने वाले लाभ व लागू करने संबंधी दिक्कतों के बारे में गहन विमर्श किया। बैठक इसलिए हुई ताकि व्यवस्था लागू करने पर खामियों के कारण उपभोक्ता परेशान न हों। बैठक में कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड (केस्को) के एमडी अजय कुमार माथुर की भी भागीदारी रही।

प्रदेश के कई प्रमुख शहरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। 31 दिसंबर 2019 तक कानपुर में 8054 नए कनेक्शन और 68268 पुराने कनेक्शन के मीटर प्रीपेड स्मार्ट मीटर से बदले गए। केस्को एमडी ने ऊर्जा राज्य मंत्री के सामने कानपुर के आंकड़े रखे। इसके अनुसार स्मार्ट प्रीपेड वाले क्षेत्रों में लाइन लॉस पहले की तुलना में 29 फीसद घट गया। बिल वसूली सात फीसद बढ़ी। बिजली खपत घटी। इसकी तारीफ हुई। केस्को एमडी अजय माथुर के अनुसार केंद्र सरकार स्मार्ट मीटर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत पूरे देश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की दिशा में बढ़ रही है।

प्रीपेड मीटर में उपभोक्ताओं को टैरिफ में दो फीसद छूट मिल रही है तो सरकारी बिजली कंपनियों को भी फायदा है। अभी वह पहले पैसा देकर बिजली खरीदती हैं। उपभोक्ता सवा महीने बाद बिल देते हैं। कई बार वह बिल जमा भी नहीं करते। इसीलिए केस्को का एरियर इस समय दो हजार करोड़ रुपये है। इस व्यवस्था में पहले पैसा मिलेगा। कंपनियां नगद देकर बिजली खरीदेंगी और ब्याज का भार घटेगा।

प्रतीकात्मक

सरकारी कार्यालयों में भी स्मार्ट मीटर

एमडी केस्को के अनुसार सरकारी कार्यालयों में भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगेंगे। सरकारी विभाग बिल अदा करने में काफी लेट लतीफ हैं। कानपुर में ही सरकारी विभाग करीब 575 करोड़ रुपये के देनदार हैं।

- 25 करोड़ स्मार्ट मीटर की होगी आवश्यकता
- 100 फीसद कलेक्शन है प्रीपेड स्मार्ट मीटर से
- फीसद की छूट जनता को बिजली टैरिफ मे

ओडिशा सरकार ने एक सप्ताह में 3,166 कर्मचारियों को दी पदोन्नति

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर

ओडिशा सरकार ने एक सप्ताह के अंदर 3,166 कर्मचारियों को उनके अच्छे कार्य के लिए पदोन्नति दी है। कुछ दिन पहले ही 5-टी (ट्रांसपैरेंसी, टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, टाइम व ट्रांसफॉरमेशन) एवं मो सरकार (मेरी सरकार) कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस बात के संकेत दिए थे कि जो कर्मचारी अच्छा काम करेंगे उन्हें राज्य सरकार तात्कालिक रूप से पदोन्नति देगी और जो कर्मचारी गलत काम करेंगे उन्हें दंडित किया जाएगा।

इसी के तहत पिछले महीने सरकार ने 55 कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया था। अब सरकार ने एक ही सप्ताह के अंदर 39 विभाग तथा 30 जिले के ग्रुप 'ए' से लेकर ग्रुप 'डी' तक विभिन्न वर्ग के 3,166 कर्मचारियों को पदोन्नति दी है। एक सप्ताह के अंदर इतनी संख्या में कर्मचारियों की पदोन्नति एक रिकॉर्ड मानी जा रही है।

21 दिसंबर को मुख्यमंत्री ने दिया था निर्देश : कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ग्रुप 'सी' एवं ग्रुप 'डी' के कर्मचारियों की पदोन्नति में हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर की थी। दिसंबर तक सभी योग्य कर्मचारियों को पदोन्नति देने के लिए 21 दिसंबर को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था। इसी के तहत 24 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच ग्रुप 'ए' में 852 कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है। इसी तरह, ग्रुप 'बी' में 527, ग्रुप 'सी' में 1496 एवं ग्रुप 'डी' में 291 कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है। उल्लेखनीय है कि राज्य में वर्ष 2019 में जनवरी से नवंबर महीने के बीच विभिन्न वर्ग में 9,766 कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई थी। ऐसे में बीते एक सप्ताह में 3,166 कर्मचारियों को मिलाकर वर्ष 2019 में विभिन्न वर्ग में कुल 12,932 कर्मचारियों को पदोन्नति मिली है।

2013 सितंबर में सुनवाई अदालत ने निर्भया मामले में दोषियों को दी थी फांसी की सजा, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फैसले पर मार्च 2014 में लगाई थी मुहर।

भारत में फांसी के ये हैं चर्चित मामले

निर्भया मामले में दोषियों को फांसी देने के लिए डेथ वारंट जारी कर दिया गया है। चारों दोषियों को 22 जनवरी को फांसी दी जाएगी। भारत में फांसी के मामले बहुत ज्यादा नहीं हैं। देश में फांसी की सजा बेहद दुर्लभ मामलों में ही दी जाती है। बावजूद इसके कुछ जघन्य अपराध ऐसे थे, जिन्होंने देश को झकझोर कर दिया था। इन्हीं में से एक मामला निर्भया का है। फांसी के ऐसे कई अन्य मामले भी हैं जिनकी बरसों बाद आज तक चर्चा की जाती है। इन्हीं में कुछ मामलों से हम आपको अवगत करा रहे हैं।

याकूब मेमन

पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट याकूब मेमन को 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए बम धमाकों का दोषी पाया गया। मेमन को 30 जुलाई 2015 को फांसी दी गई। उसकी फांसी रोकने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रात के तीन बजे सुनवाई हुई थी। हालांकि इसके बाद भी कोर्ट ने फांसी की सजा को बरकरार रखा। मुंबई धमाकों में 257 लोग मारे गए थे और करीब सात सौ लोग घायल हुए थे। यह धमाके शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में हुए थे।

अफजल गुरु

अफजल गुरु को दिल्ली की तिहाड़ जेल में 9 फरवरी 2013 को फांसी दी गई। भारत की संसद पर हमले में अफजल गुरु की भी भूमिका थी। उसने स्वीकार किया था कि वह तीन महीने की हथियारों की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान गया था। अफजल गुरु सोपोर का रहने वाला था। 13 दिसंबर 2001 को देश की संसद पर पांच आतंकियों ने हमला किया था। इस हमले में आतंकियों सहित 14 लोग मारे गए थे और 16 घायल हुए थे। हमले में लश्कर ए तैयबा और जैश ए मुहम्मद की भूमिका सामने आई थी। अफजल गुरु का शव तिहाड़ में दफन किया गया।

अजमल कसाब

लश्कर ए तैयबा के आतंकी आमिर अजमल कसाब को 21 नवंबर 2012 को मुंबई की यरवडा जेल में फांसी दी गई। 26 नवंबर 2008 को कसाब और उसके 10 साथियों ने मुंबई के पांच प्रमुख स्थानों पर हमला किया था। इस हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी और करीब 300 लोग घायल हुए थे। हमलावरों में से कसाब को जिंदा पकड़ा गया था। वह पाकिस्तानी का रहने वाला था।

मकबूल बट

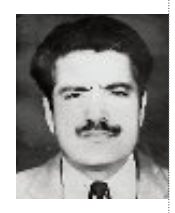

कश्मीरी अलगाववादी नेता मकबूल बट को हत्या के मामले में 11 फरवरी 1984 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। वह आतंकी संगठन नेशनल लिबरेशन फ्रंट का संस्थापक था। फांसी की सजा मिलने के बाद कई आतंकी संगठनों ने उसे छुड़वाने की कोशिशें की। यहां तक की एक विमान अपहरण की भी साजिश रची लेकिन वह उसे छुड़ाने में नाकाम रहे। मकबूल बट का शव तिहाड़ जेल में ही दफन है।

धनंजय चटर्जी

धनंजय चटर्जी को कोलकाता की अलीपोर सेंट्रल जेल में 14 अगस्त 2004 को फांसी दी गई थी। कोर्ट ने धनंजय को दक्षिणी कोलकाता के एक अपार्टमेंट में 5 मार्च 1990 को किशोरी से दुष्कर्म और हत्या का दोषी माना। धनंजय उस अपार्टमेंट में सुरक्षा गार्ड था। हत्या के बाद वह फरार हो गया था। धनंजय ने दया याचिका भी दी लेकिन इसे खारिज कर दिया गया।

फिर शुरू होगा फांसी का ट्रायल

बढ़ी हलचल ▶ 2013 में अफजल को फांसी के बाद से फांसी घर नवंबर 2019 तक बंद था

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

निर्भया के दोषियों के नाम डेथ वारंट जारी होने के साथ ही जेल प्रशासन के लिए तिहाड़ जेल संख्या 3 महत्वपूर्ण बन गया है। यहां के सभी जेलों में जेल संख्या तीन ही है, जिसमें दोषियों को फंदे पर लटकाया जाता है। इस जेल में एक खुले अहाते में ही फांसी घर बना हुआ है। नवंबर में जेल प्रशासन की ओर से निर्भया के दोषियों के नाम जारी नोटिस के बाद से ही फांसी घर में हलचल शुरू हो गई थी। यहां सिविल से जुड़े कार्य को अंतिम रूप पहले ही दिया जा चुका है। दिसंबर में यहां कई बार फांसी का ट्रायल भी किया गया। इस दौरान डमी को लटकाया गया। अब डेथ वारंट जारी होने के बाद फांसी की प्रक्रिया का ट्रायल एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। जेल अधिकारियों का कहना है कि 2013 में आतंकी अफजल को फांसी होने के बाद से यह फांसी घर नवंबर 2019 तक बंद था।

एक साथ लटकाए जाएंगे चारों दोषी : फांसी घर जमीन से 12 फीट ऊपर चारदीवारी से घिरा एक कुएं के आकार का ढांचा होता है, जिसके ऊपर कंक्रीट की छत बनी होती है। छत के बीच के हिस्से में 12-12 फीट लंबा दो तख्त होता है। छत के दोनों ओर लोहे के दो खंभे होते हैं, जो लोहे की एक पाइप से जुड़ी होती है। इसी पाइप पर फंदा बनाया जाता है। इसके किनारे एक लीवर लगा होता है, जिसे दबाने से दोनों तख्त एक-दूसरे से अलग हो जाते हैं और जिस व्यक्ति को फंदा लगाया जाता है, वह छत के नीचे लटक जाता है। जेल सूत्रों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग की ओर से फांसी घर में बने तमाम ढांचों को दुरुस्त कर दिया गया है। यूं तो फांसी घर में एक बार दो दोषियों को फंदे पर लटकाने का इंतजाम है, लेकिन निर्भया के चार दोषियों को देखते हुए फांसी घर की संरचना में फेरबदल किया गया है।

नहीं चला पवन का 'नाबालिग' पैंतरा

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली : 2012 में वारदात के दौरान नाबालिग होने का दावा करते हुए निर्भया केस में दोषी पवन कुमार गुप्ता की तरफ से दायर याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। 19 दिसंबर 2019 को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैट की पीठ ने रिकॉर्ड पर लिया था कि पवन कुमार ने नाबालिग होने का दावा इससे पहले पुनर्विचार याचिका में भी किया था और सुप्रीम कोर्ट ने 9 जुलाई 2018 को इस याचिका को खारिज कर दिया था। इतना ही नहीं पीठ ने अदालत का समय बर्बाद करने के लिए दोषी के वकील पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

पवन कुमार ने याचिका में दावा किया कि उसके स्कूल के प्रमाण पत्र के अनुसार उसका जन्म 8 अक्टूबर 1996 को हुआ था और घटना के दौरान वह नाबालिग था। ऐसे में उसे नाबालिग होने का लाभ मिलना चाहिए। हालांकि, पुलिस की वेरिफिकेशन रिपोर्ट के अनुसार उसके पिता ने कहा था कि पवन का जन्म 17 जुलाई 1992 को हुआ था। इसका मतलब यह है कि 16 दिसंबर 2012 को वह 18 साल का था। याचिका में दोषी पवन कुमार ने आरोप लगाया कि जांच अधिकारियों द्वारा उनकी हड्डी का परीक्षण नहीं किया गया था।

जल्लाद तैयार, सिर्फ बुलावे का इंतजार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : निर्भया कांड के चारों दोषियों को 22 जनवरी को फांसी देने के लिए उत्तर प्रदेश जेल प्रशासन ने मेरठ के पवन जल्लाद को रिजर्व कर दिया है।

निर्भया कांड के दोषी मुकेश सिंह, अक्षय, पवन और विनय शर्मा को न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। ऐसे में लगभग तय है कि मेरठ निवासी पवन जल्लाद इस काम के लिए बुलाए जाएं। नौ दिसंबर को तिहाड़ जेल प्रशासन ने उप्र के जेल महानिदेशक आनंद कुमार को पत्र लिखकर जल्लाद के संबंध में जानकारी मांगी थी।

यहां से जवाब में बताया गया कि उप्र में दो जल्लाद हैं। एक लखनऊ के हैं और दूसरे मेरठ के पवन। डीजी जेल आनंद कुमार ने बताया कि उस पत्र के बाद अभी कोई रिमाइंडर तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से नहीं आया है लेकिन, हमने तैयारी कर ली है।

निर्भया के गुनहगार

मुख्य आरोपित

नाम-राम सिंह निवासी दिल्ली
काम-बल चालक
मौत हो चुकी है (तिहाड़ जेल संख्या 3 में 11 मार्च 2013 को खुदकशी कर ली)

नाम- मुकेश कुमार निवासी दिल्ली
काम- ड्राइवर कम हेल्पर
नोट : राम सिंह का भाई है, दोनों साथ रहते थे। घटना के समय यही बस को चला रहा था।

नाम- अक्षय कुमार सिंह वर्तमान निवासी दिल्ली, मूल निवासी- औरंगाबाद, बिहार
काम- बस पर हेल्पर

नाम- पवन गुप्ता निवासी दिल्ली
काम- फल विक्रेता

नाम- विनय शर्मा निवासी दिल्ली
काम- जिम में हेल्पर

नाबालिग
पता-दिल्ली में स्थायी ठिकाना नहीं, बदायूं (उप्र) का रहने वाला है।
काम- बस का क्लीनर
नोट :-यह वारदात के समय 17 साल छह महीने 11 दिन का था, बालिग होने के बाद उसे 31 अगस्त को बाल न्यायालय से हत्या में अधिकतम 3 साल की सजा सुनाई थी। सजा काटने के बाद दिसंबर 2015 में उसे रिहा कर दिया गया।

...वो 16 दिसंबर 2012 की काली रात

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

16 दिसंबर 2012, रविवार का दिन। शाम को साकेत स्थित सेलेक्ट सिटी मॉल में दोस्त के साथ 'लाइफ ऑफ पाई' मूवी देखने के बाद 23 वर्षीय फीजियोथेरेपिस्ट छात्रा (पीड़िता) और उसका दोस्त ऑटो से रात 9 बजे मुनीरिका आ गए थे। यहां बस स्टैंड के पास खड़े होकर दोनों बस का इंतजार कर रहे थे। तभी 9.15 बजे आइआइटी की तरफ से सफेद रंग की लग्जरी बस इनके पास आकर रुक गई। बस में आगे के शीशे पर ऊपर व नीचे पीले रंग की पट्टी थी और साइड में यादव लिखा हुआ था। बस के परिचालक ने महिपालपुर, धौलाकुआं, द्वारका की आवाज लगानी शुरू कर दी थी। दोनों की नजर जब बस की तरफ पड़ी तब परिचालक ने बहन जी कहते हुए उन्हें बस में आ जाने को कहा था। उनके बस में सवार होते ही परिचालक ने दरवाजा बंद कर दिया। अंदर दोनों ने देखा कि बस में चालक समेत छह लोग सवार थे। किराया वसूलने के बाद एक दोषी ने पीड़िता के दोस्त से कहा था कि वह इतनी रात को लड़की को लेकर कहां जा रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि उसे क्या मतलब है। इसी पर बहस शुरू हुई थी। दोषियों ने पीड़िता से छेड़खानी शुरू कर दी। विरोध पर एक ने रॉड से पीड़िता के दोस्त के सिर पर वार कर घायल कर दिया और उसे पीछे की सीट पर ले जाकर दरिंदों ने जब उसकी अस्मत लूटनी शुरू की तब घायल होकर भी उसने अपने दोस्त को बचाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन उसे युवती तक आने नहीं दिया गया। दो आरोपितों ने उसे पकड़ कर बस के अंदर नीचे गिरा कर पिटाई करते रहे। उधर, दोस्त की पिटाई देख पीड़िता भी दरिंदों को दांत काट उनके चंगुल से खुद को छुड़ाकर दोस्त के पास उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे दोस्त के पास नहीं जाने दिया गया। चलती बस में दोषी पीड़िता की इज्जत तार-तार करते रहे।

इस बीच बस 24 किमी की दूरी तय कर चुकी थी। चालक मुकेश बस को लेकर महिपालपुर रोड एनएच-8 से यू-टर्न लेकर द्वारका रूट पर गया और फिर महिपालपुर आ गया। इसके बाद होटल एरिया के सामने चलती बस से दोनों को गेट से नीचे फेंकने के बाद सभी मौके से फरार हो गए थे। कंपकंपाती ठंड में दोनों को निर्वस्त्र बस से नीचे फेंक देने पर युवती अर्धबेहोशी की हालत में पहुंच गई थी। भीषण ठंड में दोनों करीब 20 मिनट तक ठिठुरते रहे। तभी वहां से गुजर रहे इगिस कंपनी के पेट्रोलिंग ऑफिसर की नजर उन पर पड़ी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इगिस कंपनी नेशनल हाईवे का सिक्योरिटी देखती है।

थाने की पुलिस मौके पर पहुंची तब तक पीसीआर के पुलिसकर्मी दोनों को सफदरजंग अस्पताल पहुंचा चुके थे। पीसीआर कर्मियों ने पास के एक होटल से चादर लाकर दोनों पीड़ितों को दिया था। पीसीआर को लगा कि वह साउथ वेस्ट का इलाका है। इसलिए उन्होंने सफदरजंग अस्पताल पहुंचा दिया। अस्पताल से साढ़े 11 बजे वसंत विहार पुलिस को सूचना मिली कि इलाका उनका लगता है। तब 11.35 बजे तत्कालीन डीसीपी छाया शर्मा पूरी टीम के साथ अस्पताल पहुंच गईं। चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस की नींद उड़ गई।

डेथ वारंट की सूचना पर निर्भया के गांव वालों को मिला सुकून

जागरण संवाददाता, बलिया : निर्भया के गांव में मंगलवार को सुबह से ही लोग टीवी और मोबाइल पर पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले का इंतजार करते रहे। कोर्ट ने जब चारों दोषियों का डेथ वारंट जारी किया तो इस खबर को सुनकर गांव के सभी लोगों को सुकून मिला। गांव की युवतियों ने कहा कि देर से ही सही, फैसला उचित व सही आया। अब सभी दोषियों को फांसी होगी, इस निर्णय से गांव के लोगों की मुराद पूरी हो गई।

गांव में रह रहे निर्भया के बाबा ने कहा कि उसकी मां ने न्याय के लिए लंबा संघर्ष किया। देश में ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इस तरह के केस में त्वरित न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए। वह सरकार से लेकर कोर्ट तक दौड़ कर थक गई थी। अब जब कोर्ट ने फांसी की तारीख निश्चित कर दी है तो घर के सभी लोगों को सुकून मिला है। देर भले हुई लेकिन परिवार को न्याय मिला जिसके लिए न्यायाधीश धन्यवाद के पात्र हैं। इस तरह के फैसले से समाज में अपराधियों के अंदर डर का संदेश जाएगा।

'हम सात साल से खून के आंसू रो रहे हैं'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : पटियाला हाउस अदालत में बहस हो रही थी, तो दोषी मुकेश की मां झोली फैलाए अदालत में आई और क्षमा मांगी। जज ने उसे सुनने से इन्कार करते हुए बहस को जारी रखा। जब फैसला सुनाने का समय तय किया गया तो मुकेश की मां जोर-जोर से रोने लगी। तभी निर्भया की मां ने अदालत में ही कहा कि हम सात साल से खून के आंसू रो रहे हैं। इसके बाद सभी को अदालत से बाहर जाने का आदेश हुआ तो मुकेश की मां बाहर बैठकर भी रोती रही और फैसला आने के बाद तक उनका रोना जारी रहा। फैसले के बाद अदालत परिसर में तनातनी का माहौल हो गया और पुलिसकर्मी पीड़िता की मां को मीडिया की भीड़ से बचाते रहे। अदालत परिसर में भीड़ और तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था।

अकेले रखे गए गुनहगार

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

डेथ वारंट जारी होने के बाद निर्भया के दोषियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जेल अधिकारियों का कहना है कि चारों दोषियों को कड़ी निगरानी वाले सेल में रखा गया है। ये अपने-अपने सेल में अकेले हैं। अब तक इनके साथ रहने वाले अन्य कैदियों को अन्य सेल में भेज दिया गया है। इनकी सुरक्षा में तमिलनाडु पुलिस का एक और एक जेल सुरक्षाकर्मी को तैनात किया गया है। जल्द ही चारों को जेल संख्या-3 में भेज दिया जाएगा। वहां फांसी घर के पास बने सेल में इन्हें रखा जाएगा। इनकी सुरक्षा के लिए जेल कर्मचारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। ये सेल से अब जब कभी बाहर निकलेंगे, इनके साथ सुरक्षाकर्मी मौजूद रहेंगे। अब रोजाना इनकी स्वास्थ्य जांच होगी, जिसकी रिपोर्ट तैयार होगी।

जेएनयू हिंसा मामले में प्रशासन गठित करेगा सुरक्षा समिति

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में रविवार को हुई हिंसक घटना के बाद प्रशासन मंगलवार को अपनी बात रखने के लिए सामने आया। विवि प्रशासन ने बताया कि मामले की विस्तृत रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल को दी गई है। बुधवार को कुलपति की मुलाकात मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों से होगी।

विवि प्रशासन ने बताया कि उनकी तरफ से एक सुरक्षा समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति खुद से सभी पहलुओं पर रविवार की घटना की जांच करेगी। जेएनयू के कुलपति प्रो. एम.जगदीश कुमार ने कहा कि संस्थान के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा के इंतजाम रहते हैं। कैंपस की अपनी सुरक्षा व्यवस्था है और अगर कभी भी लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति बनती है तो हम तुरंत पुलिस को सूचना नहीं देते हैं। पहले देखते हैं कि क्या हमारी सुरक्षा कर्मी उसे देख सकते हैं।

सर्जिकल स्ट्राइक जैसा था हमला : जेएनयू के रेक्टर-1 चिंतामणी महापात्रा ने कहा कि रविवार को जिस तरह से नकाबपोशों ने हमला किया, उससे हम सब सन्न रह गए। जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक एक दम होती है, इसी तरह से इन नकाबपोश लोगों ने जेएनयू में घुसकर हमला किया। उधर, प्रो. एम.जगदीश कुमार ने कहा कि 3 जनवरी की दोपहर को कुछ छात्र नकाब पहनकर संस्थान के डेटा सेंटर पर पहुंचे थे। उन्होने कहा कि अगर वे छात्र ठीक थे तो उन्होंने नकाब क्यों पहना हुआ था।

'फ्री कश्मीर' के पोस्टर पर भाजपा ने शिवसेना को घेरा

राज्य ब्यूरो, मुंबई

जेएनयू में हिंसा के विरोध में मुंबई में प्रदर्शन के दौरान लहराए गए 'फ्री कश्मीर' पोस्टर के मुद्दे पर शिवसेना घिरती नजर आ रही है। भाजपा ने जहां उस पर हमला किया है, वहीं उसके अपने नेता बचाव की मुद्रा में आ रहे हैं। शिवसेना से दो तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। संजय राउत इसे इंटरनेट प्रतिबंध से आजादी बताया है तो आदित्य ठाकरे ने पोस्टर लहराए जाने को गलत बताया है। मुंबई की कोलाबा पुलिस ने पोस्टर लहराने वाली महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

गेट वे ऑफ इंडिया पर प्रदर्शन के दौरान एक महिला ने 'फ्री कश्मीर' लिखा पोस्टर लहराया था। इस पर हंगामा शुरू होने पर उक्त महिला का बचाव करते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि केंद्र सरकार ने कश्मीर में कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं वहां बंद हैं। कश्मीर को इन प्रतिबंधों से मुक्त कराने के भाव से ही उक्त पोस्टर लहराया गया था। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा है कि अगर कोई भारत से कश्मीर की आजादी की बात करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जबकि शिवसेना के युवा नेता एवं राज्य सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने साफ कहा कि ऐसा पोस्टर लहराया जाना गलत है। 'फ्री कश्मीर' पोस्टर मामले का बचाव करने पर भाजपा ने शिवसेना पर और उद्धव सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने शिवसेना के कार्यकर्ताओं को 'सोनिया सैनिक' बताया। नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फड़नवीस एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने सवाल किया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से सिर्फ दो किलोमीटर दूर देशविरोधी आंदोलन किया जा रहा है। क्या यह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को मंजूर है? भाजपा नेता किरीट सोमैया ने फ्री पोस्टर लहराने वाली महिला के साथ ही इस आंदोलन में शामिल होने वाले राज्य सरकार के मंत्री जीतेंद्र आह्वाड के विरुद्ध कोलाबा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

जेएनयू में हुई हिंसा के विरोध में सोमवार को मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर प्रदर्शन के दौरान एक लड़की को पोस्टर लहराते हुए देखा गया जिस पर 'फ्री कश्मीर' का नारा लिखा हुआ था। एएनआइ

मुंबई में प्रदर्शन खत्म : राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि गेटवे ऑफ इंडिया प्रदर्शन की जगह नहीं है। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से वहां से चले जाने को कहा। बाद में कुछ फिल्मी कलाकारों के वहां पहुंचने से भीड़ बढ़ी तो पुलिस ने उन्हें आजाद मैदान पहुंचा दिया। वहां कुछ देर बाद ही प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया।

हिंसा में शामिल छात्रों पर बरसे आठवले

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : जेएनयू हिंसा पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले मंगलवार को नाराज दिखे। उन्होंने पढ़ाई छोड़ कर हिंसा और आंदोलन करने वाले छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही कहा कि विवि परिसर में रोज-रोज होने वाले प्रदर्शन और आंदोलन से निपटने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को एक आचार संहिता बनानी चाहिए। उन्होंने इस बीच एक वीडियो में हिंसा के दौरान नकाब ओढ़े दिख रही विवि छात्रसंघ अध्यक्ष आइशी घोष की भूमिका की भी जांच करने की बात कही।

केंद्रीय मंत्री और आरपीआइ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आठवले ने पत्रकारों से चर्चा में जेएनयू में की गई फीस बढ़ोतरी को लेकर भी अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का मानना है कि ज्यादा फीस बढ़ाना ठीक नहीं है। इसे कम किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय में काफी गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं। इसके साथ ही उन्होंने रविवार रात को जेएनयू में हुई हिंसा को पूरी तरह से गलत बताया। कहा कि इस तरह की गुंडागर्दी ठीक नहीं है। छात्र यहां भविष्य संवारने के लिए आते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और इनमें शामिल छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। वैसे विश्वविद्यालय में हिंसा के पीछे जो वजह सामने आयी है, उसमें छात्रों के एक वर्ग रजिस्ट्रेशन करना चाहता था, लेकिन एक गुट उन्हें ऐसा करने से रोक रहा था।

जेएनयू हिंसा को 26/11 के हमले से जोड़ने के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बयान को अठावले ने पूरी तरह से गलत बताया और कहा कि यह ठीक नहीं है। छात्रों के साथ उनकी हमदर्दी तो ठीक है, लेकिन इसे 26/11 से जोड़ना ठीक नहीं है।

जेएनयू पहुंचीं दीपिका पादुकोण

नई दिल्ली स्थित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंसा के बाद मंगलवार को अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भी विश्वविद्यालय पहुंचीं और छात्रसंघ अध्यक्ष आइशी घोष से मुलाकात की। आइशी हिंसा में घायल हो गई थीं। एएनआइ

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

जेएनयू कैंपस में रविवार को हुई हिंसक घटना के विरोध में छात्रों की तरफ से आयोजित सभा में मंगलवार देर शाम बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण पहुंचीं। सीपीआइ नेता डी. राजा, जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने छात्रों को संबोधित किया। दीपिका ने छात्रों को संबोधित नहीं किया।

हालांकि संस्थान के छात्रों ने कहा कि दीपिका छात्रों का साथ देने के लिए आईं थीं और उन्होंने इस घटना का विरोध किया। सभा में छात्रों ने नारेबाजी भी की।

जेएनयू के रेक्टर-1 चिंतामणी महापात्रा ने कहा कि रविवार को जैसे ही मारपीट शुरू हुई तुरंत पुलिस को सूचित किया गया।

उन्होंने कहा कि छात्रावास की फीस बढ़ोतरी के विरोध में आंदोलन कर रहे छात्रों से निवेदन करते हैं कि वह अपनी हड़ताल को खत्म करें, क्योंकि इससे बाकी छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कैंपस में स्थिरता लाने के लिए काम किया जा रहा है। जिसके तहत प्रशासन की तरफ से सर्दियों के सेमेस्टर के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जा रहा है।

हिंसा की रिपोर्टिंग को लेकर न्यूयार्क टाइम्स पर जावडेकर ने साधा निशाना

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने न्यूयार्क टाइम्स की उस खबर के लिए आलोचना की है, जिसमें इस प्रमुख अमेरिकी अखबार ने कहा था कि जेएनयू के हमलावर जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। ट्विटर पर न्यूयार्क टाइम्स का स्क्रीन शॉट टैग करते हुए उन्होंने कहा, 'ऐसा लगता है कि इस अखबार में भगवान राम के अनन्य भक्त काम करते हैं, जो उन्हें हर जगह दिख जाते हैं।' उन्होंने यह भी कहा कि मैं पिछले सप्ताह पाकिस्तान स्थित सिखों के ऐतिहासिक ननकाना साहिब गुरुद्वारे में हुई हिंसा पर अखबार की ग्राउंड रिपोर्ट पढ़ने का इंतजार कर रहा हूं। वहां पर उन लोगों ने कौन सा नारा सुना?

उल्लेखनीय है कि अमेरिकी अखबार की आलोचना करने से एक दिन पहले जावडेकर ने ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल एक्सप्रेस पर भी निशाना साधा था। इस अखबार ने अपनी रिपोर्ट में जेएनयू में छात्रों और शिक्षकों पर हमला करने वाले नकाबपोश लोगों को राष्ट्रवादी बताया था। जावडेकर ने कहा था, 'मुझे पता है कि भारत को समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आपने कुछ प्रयास किया है। हर संभव मौके पर भारत के विभाजित होने की भविष्यवाणी करना बंद कीजिए। भारत एक विविधता वाला लोकतंत्र है और यह अपने मतभेदों को सुलझाकर हमेशा ज्यादा मजबूत होकर उभरना जानता है।'

जल्द सामने आएंगे जेएनयू हमले में शामिल नकाबपोशों के नाम : केंद्रीय मंत्री जावडेकर ने कहा कि गृह मंत्रालय ने जेएनयू हमले की जांच का आदेश दे दिया है। इसमें शामिल नकाबपोश लोगों के नाम जल्द सामने आएंगे। एक कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जेएनयू और देश के अन्य हिस्सों में जान-बूझकर गलतफहमी फैलाई जा रही है, ताकि हिंसा भड़काई जा सके। इसे भी उजागर किया जाएगा।

'फ्री कश्मीर' का पोस्टर दिखाना गिने-चुने अराजक तत्वों का काम

जेएनयू में हिंसा के खिलाफ गेटवे ऑफ इंडिया पर विरोध प्रदर्शन के दौरान 'फ्री कश्मीर' के पोस्टर दिखाने को जावडेकर ने कुछ गिने-चुने अराजक तत्वों का कृत्य करार दिया। उन्होंने कहा कि समूचे देश ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का समर्थन किया है। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद शांति बहाल हुई है और क्षेत्र विकास कर रहा है।

अहमदाबाद में एबीवीपी और एनएसयूआइ कार्यकर्ता भिड़े

अहमदाबाद, प्रेट्र : जेएनयू हिंसा के विरोध में प्रदर्शन के दौरान यहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआइ) के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। पुलिस के मुताबिक दोनों तरफ के चार लोग घायल हुए हैं।

कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआइ ने शहर के पलाडी इलाके में स्थित एबीवीपी के दफ्तर के सामने इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। इसी दौरान दोनों संगठनों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात नियंत्रण में किया।

पुलिस उपायुक्त केएन दामोर ने बताया कि एबीवीपी और एनएसयूआइ दोनों के ही दो-दो कार्यकर्ता घायल हुए हैं। दोनों तरफ की शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। पुलिस से उलट दोनों ही संगठनों ने 15 से ज्यादा लोगों के घायल होने का दावा किया है।

सिब्बल ने जेएनयू वीसी और दिल्ली के कमिश्नर पर लगाया हिंसा कराने का आरोप

जागरण संवाददाता, नैनीताल

पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने जेएनयू हिंसा पर मंगलवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की वजह से ही विश्वविद्यालयों का माहौल खराब हो रहा है। उन्हें सियासी अड्डा बनाया जा रहा है। पहले भी विश्वविद्यालय में मास्क पहनकर गुंडों ने हिंसा की, अब फिर से यह दोहराया गया। आरोप लगाया कि जेएनयू के वीसी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर की मिलीभगत से हिंसा हुई है। दोनों को बर्खास्त करना चाहिए।

सिब्बल ने कहा कि भाजपा राज में पुलिस छात्रों पर गोली चला रही है, एनकाउंटर किए जा रहें हैं, पीड़ितों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। जेएनयू में हुई घटना के लिए वीसी और पुलिस कमिश्नर दोनों जिम्मेदार हैं। दोनों को बर्खास्त किया जाना चाहिए।

सिब्बल यहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग मामले में बहस करने पहुंचे थे। उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं, टुकड़े-टुकड़े गैंग वो हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जेएनयू में अराजकतत्व गेट पर सुरक्षा के बाद अंदर कैसे गए, उन्हें अंदर से किसने अनुमति दी, हिंसा होने पर वीसी ने क्या किया, एक घंटा हिंसा के बाद भी वीसी ने पुलिस, कमिश्नर और गृह मंत्री को सूचना क्यों नहीं दी। परिसर में एंबुलेंस के टायर की हवा निकाल दी गई, ताकि घायलों को अस्पताल न ले जाया जा सके। हिंसा के दौरान पुलिस तमाशबीन बनी रही। उन्होंने आरोप लगाया कि गृह मंत्री, पुलिस कमिश्नर और वीसी ने ही हिंसा की साजिश रची।

प्रदर्शन के समर्थन पर मांजरेकर से योगेश्वर दत्त ने पूछे सवाल

नई दिल्ली, आइएएनएस : जेएनयू में हुई हिंसा का पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने भी निंदा की है। मांजरेकर ने जेएनयू के छात्रों के समर्थन में मुंबई में हो रहे प्रदर्शन का समर्थन किया है। मांजरेकर ने गेटवे ऑफ इंडिया पर हुए प्रदर्शन के फोटो के साथ एक पोस्ट रीट्वीट किया, जिसमें लिखा था, 'शाबाश मुंबई'। इस पर ओलंपियन पहलवान योगेश्वर दत्त ने उसी प्रदर्शन में लहराए गए 'फ्री कश्मीर' पोस्टर के फोटो के साथ ट्वीट कर मांजरेकर से सवाल किया। उन्होंने लिखा, 'यह भी उसी प्रदर्शन की सच्चाई है। संजय मांजरेकर आपका इस बारे में क्या कहना है।'

1562 लोगों की मौत भारत में 2019 में मौसम की मार (गर्मी, ठंड, वर्षा और चक्रावात आदि) की वजह से हुई। भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, मौसम की इन्हीं अनिश्चितताओं की वजह से 2018 में 1428 लोगों की जान गई थी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 8 जनवरी 2020

भाजपा ने बनाई सीएए पर संवाद की योजना

पहल ▶ मकसद विपक्ष का दुष्प्रचार रोकना

पार्टी ने सभी वर्गों से संपर्क के लिए कार्यक्रमों की एक शृंखला शुरू की

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जिस तरह रविवार को मुंबई में बॉलीवुड हस्तियों से संवाद किया था, उसी तर्ज पर भाजपा ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर समाज के सभी वर्गों से संपर्क करने की योजना बनाई है।

पार्टी सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि सीएए पर समर्थन जुटाने के लिए भाजपा ने कार्यक्रमों की एक शृंखला शुरू की है जिसमें अलग-अलग वर्गों के साथ बैठकें और घर-घर जाने का अभियान शामिल है। अभियान का मकसद कानून के खिलाफ विपक्ष के दुष्प्रचार का जवाब देना और कानून के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करना है।

सूत्रों ने बताया कि गोयल समेत भाजपा नेताओं के साथ रविवार की बैठक में करीब 70 बॉलीवुड हस्तियों ने हिस्सा लिया था और यह संवाद लगभग तीन घंटे तक चला था। इन बॉलीवुड हस्तियों में भूषण कुमार, प्रसून जोशी, अनु मलिक, कैलाश खेर, शान, कुणाल कोहली, रणवीर शौरी, रितेश सिधवानी, राजकुमार संतोषी, सुरेश वाडकर और नीरज श्रीधर शामिल हैं। हालांकि इस कार्यक्रम में सीएए का विरोध कर रहे फरहान अख्तर, अनुराग कश्यप और स्वरा भास्कर को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। हालांकि कुछ हस्तियां ऐसी थीं जो कार्यक्रम में शामिल होना चाहती थीं, लेकिन मुंबई से बाहर होने की वजह से नहीं पहुंच सकीं। इनमें तापसी पन्नू, राजकुमार राव, इम्तियाज अली, जावेद जाफरी, कंगना रनौट और सोनू सूद शामिल हैं।

'झूठमेव जयते' का प्रचार करने वाले परास्त होंगे : नकवी

नई दिल्ली, प्रेट्र : भाजपा के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंगलवार को सीएए के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों को दुष्प्रचार का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि यह कानून नागरिकता देने वाला है, न कि खत्म करने वाला। उन्होंने बताया कि कुछ लोग 'झूठमेव जयते' के दर्शन से देश के सामाजिक तानेबाने और एकता को खंडित करना चाहते हैं, लेकिन यकीनन वे परास्त होंगे।

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नकवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और इसकी सच्चाई के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने छात्रों और युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि उन्हें फर्जी सूचनाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए। छात्रों और युवाओं को देश के सांप्रदायिक सौहार्द और एकता को मजबूत बनाने की दिशा में योगदान देना चाहिए।

नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में अमेरिका में रैली

नागरिकता संशोधन कानून को विदेश में रह रहे भारतवंशियों का अपार समर्थन मिल रहा है। अमेरिका के बोस्टन में भी भारतीयों ने इस कानून के समर्थन में प्रदर्शन किया। प्रेट्र

वाशिंगटन, प्रेट्र : सीएए को लेकर भारत में एक वर्ग के जारी विरोध के बीच अमेरिका में रह रहे भारतवंशियों ने इसके समर्थन में रैली निकाली। बोस्टन की बर्फीली हवाओं के बीच रैली में भारतवंशियों ने भाग लेकर सीएए के प्रति समर्थन जताया।

आयोजकों की तरफ से जारी बयान के अनुसार, बोस्टन और इसके आसपास के शहरों में रहने वाले भारतवंशी शून्य डिग्री तापमान को मात देते हुए ऐतिहासिक हार्वर्ड स्क्वायर पर रविवार को आयोजित रैली में शामिल हुए। रैली में शामिल लोग अपने हाथों में बैनर लिए हुए थे, जिन पर अलग-अलग नारे लिखे थे। इनमें 'हम नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन करते हैं', 'भारतीय-अमेरिकी सीएए का समर्थन करते हैं', 'सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करता है' और 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद' आदि नारे शामिल थे।

आयोजकों ने बताया, 'रैली में अलग-अलग क्षेत्रों और सभी आयुवर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। रैली का उद्देश्य सीएए का समर्थन करना और इसके बारे में लोगों को सही जानकारी देना है।'

बंगाल के फिल्मकारों और कलाकारों ने सीएए के समर्थन में लिखा पत्र

जासं, कोलकाता : बंगाल के शिक्षाविदों, फिल्मकारों, कलाकारों व अन्य पेशों से जुड़े लोगों के एक वर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के प्रति अपना समर्थन जताया है। पत्र में अंजना बसु, प्रो. देवाशीष चौधरी, अरिंदम चक्रवर्ती, एडवोकेट जयदीप सेन, सुप्रिय बंद्योपाध्याय, अनिंद्य पुलक बनर्जी, मिलन भौमिक, संजय सोम और रंतिदेव सेनगुप्ता ने हस्ताक्षर किए हैं। पत्र में कहा गया है-'सीएए लागू करने के लिए हम बंगाल के लोग तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं और इस कदम की प्रशंसा करते हैं। विभाजन के समय से ही बंगाली मानस और आत्मा को पीड़ा दे रहा था। इतिहास गवाह है कि विभाजन से सबसे ज्यादा पीड़ा बंगाल के लोगों को पहुंची हैं। अतीत में बंगाल के कुछ दूरदर्शी नेताओं एवं चिंतकों ने विभाजन के दुष्परिणाम को महसूस था। इनमें जदुनाथ सरकार, इतिहासकार आरसी मजुमदार, प्रो सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय, डॉ. मेघनाथ साहा और डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के नाम उल्लेखनीय हैं।'

पत्र में सीएए को मानवीय एवं ऐतिहासिक करार देते हुए कहा गया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आखिरकार इस मसले को महसूस किया गया। वोट बैंक की राजनीति के कारण पहले इसपर ध्यान नहीं दिया गया।

पीएफआइ के फरार प्रभारी ने जमानत की अर्जी लगाई

जागरण संवाददाता, मेरठ

सीएए के विरोध में हिंसा की पटकथा लिखने वाले पीएफआइ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी आवेद उर्फ परवेज को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस की उदासीनता के चलते परवेज ने कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दायर कर दी है। उधर, पुलिस का दावा है कि परवेज की गिरफ्तारी को दबिश दी जा रही है।

मेरठ में 20 दिसंबर को सीएए के विरोध में हुई हिंसा एक बड़ी साजिश का परिणाम थी। पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) के दो सदस्यों जावेद और अमजद की गिरफ्तारी के बाद इसकी पुष्टि की थी। हिंसा भड़काने में पूरी भूमिका पीएफआइ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी कलछीना, भोजपुर गाजियाबाद निवासी आवेद उर्फ परवेज आलम की थी। उसने अपने साथियों जावेद और अमजद को मेरठ भेजा था। दोनों भीड़ को पत्थरबाजी और फायरिंग के लिए भड़का रहे थे। इन दोनों को पुलिस जेल भेज चुकी है, लेकिन परवेज अभी गिरफ्त से दूर है। इस बीच मंगलवार को परवेज की तरफ से अदालत में अग्रिम जमानत को अर्जी डाली गई है। इसके बाद से पुलिस ने परवेज की धरपकड़ के लिए दबिश तेज कर दी है।

पीएफआइ जुलाई, 2019 से कर रहा था युवाओं को भ्रमित : परवेज के दो साथियों की गिरफ्तारी से यह बात साफ हो गई है कि पीएफआइ, जुलाई 2019 से युवाओं को भ्रमित कर रहा था। इसके लिए शास्त्रीनगर में कार्यालय भी खोला था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक युवाओं को भ्रमित करने के लिए पीएफआइ ने पंफलेट भी बांटे थे। पंफलेट में झारखंड में तबरेज अंसारी की हत्या का भी जिक्र था।

जांच के दौरान दूसरा पंफलेट 15 दिसंबर 2019 को सामने आया। यह पंफलेट एक ई-रिक्शा के पीछे लगा था, जिसमें 6 दिसंबर 1992 को हुए ढांचा विध्वंस की घटना की याद दिलाई गई थी। 20 दिसंबर की हिंसा से दो दिन पहले एक और पंफलेट पुलिस को मिला था।

इस पंफलेट में लोगों से शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए मस्जिद के बाहर सड़क जाम करने को कहा गया था। इसमें मुस्लिमों को गलत जानकारी देकर उन्हें भ्रमित किया गया था।

> पीएफआइ के कार्यालय से काफी सामग्री मिली थी। इनकी फोटो प्रति शासन को भेज दी है। पीएफआइ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी परवेज आलम की धरपकड़ को लगातार दबिश दी जा रही है। परवेज की तरफ से कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई गई है। इस पर पुलिस की नजर है।
> -अजय साहनी, एसएसपी।

न्यूज गैलरी

नेपाल के सीमावर्ती गांवों में भी आतंकियों के पोस्टर चस्पा

गोरखपुर : नेपाल सीमा पर पोस्टर चिपकाने के बाद उससे सटी पगडंडियों से जुड़े गांवों और कस्बों में भी दो आइएस आतंकियों के पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। उनकी धरपकड़ के लिए नेपाल पुलिस का भी सहयोग लिया जा रहा है। इन आतंकियों का नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन और अब्दुल समद है। खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि दोनों उत्तर प्रदेश के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में हैं। पुलिस को खुफिया एजेंसियों की यह रिपोर्ट कुछ दिन पहले मिली है। फोटो के साथ मिली रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों आतंकी सिद्धार्थनगर, महराजगंज या कुशीनगर होते हुए सीमा पार कर सकते हैं। एडीजी दावा शेरपा ने पूरे जोन में अलर्ट करते हुए इन तीन जिलों के पुलिस कप्तानों को विशेष सतर्कता के निर्देश दिए हैं। पहले सीमा पर पोस्टर चिपकाए गए थे। अब अंदरूनी हिस्सों में भी चिपकाने के निर्देश दिए गए हैं। ये आतंकी अंतिम बार 22 दिसंबर 2019 को बंगाल के सिलीगुड़ी में देखे गए थे। उस समय वे खुफिया एजेंसी को चकमा देकर फरार हो गए थे। (जासं)

13 जनवरी से छह चरणों में खुलेगी एएमयू

अलीगढ़ : अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 13 जनवरी से चरणबद्ध खुलेगी। 20 जनवरी तक यूनिवर्सिटी के सभी संकायों में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। यूनिवर्सिटी के मुर्शिदाबाद, मल्लापुरम, किशनगंज केंद्र भी इसमें शामिल हैं। कुलपति प्रो. तारिक मंसूर की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। नौ जनवरी से तीन चरणों में एएमयू से जुड़े स्कूल खोले जाएंगे। नागरिकता कानून को लेकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हुए बवाल के बाद एएमयू में 15 दिसंबर को उपद्रव हुआ था। कुलपति प्रो. तारिक मंसूर की अध्यक्षता में सभी संकाय, विभागों के अध्यक्षों की बैठक में यूनिवर्सिटी को खोलने का फैसला लिया गया। 13 जनवरी को प्रथम चरण में मेडिसिन फैकल्टी, यूनानी मेडिसिन फैकल्टी, मैनेजमेंट स्टडीज व जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फैकल्टी में शिक्षण शुरू होगा। पिछले सेमेस्टर की बची परीक्षाएं 16 जनवरी से होंगी। लॉ फैकल्टी, कॉमर्स, साइंस, लाइफ साइंस व एग्रीकल्चरल साइंसेज फैकल्टी में शिक्षण कार्य 20 से शुरू होगा। (जासं)

युवाओं के बीच पैठ बढ़ाएगा संघ

नईदुनिया, इंदौर

▶ विश्वविद्यालयों में दूसरी विचारधाराओं के बढ़ते प्रभाव को कम करने में भी निभाएगा भूमिका

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकारिणी की इंदौर में तीन दिवसीय बैठक के आखिरी दिन मंगलवार को वरिष्ठ पदाधिकारियों के बीच जनजागरण और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा विचारधारा से जोड़ने सहित प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बुधवार को भी संघ प्रमुख मोहन भागवत और वरिष्ठ पदाधिकारी इंदौर में रहेंगे और कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे।

बैठक में संघ प्रमुख की मौजूदगी में तय हुआ कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक संघ की विचारधारा के साथ पहुंचा जाए। आनुषांगिक संगठनों को भी विश्वविद्यालयों सहित शैक्षणिक संस्थानों में ज्यादा से ज्यादा सक्रिय रहने के लिए कहा जाएगा। पदाधिकारियों ने कहा कि विश्वविद्यालयों में अन्य विचारधाराएं ज्यादा सक्रियता दिखा रही हैं। युवाओं तक वस्तुस्थिति पहुंचाना आवश्यक है। इसके लिए समग्र और त्वरित प्रयास बेहद जरूरी है। पदाधिकारियों ने कहा कि सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय उच्च शिक्षित महिलाओं को भी जोड़ा जाए। इससे महिलाओं के बड़े वर्ग में भी जनजागरण की विचारधारा आसानी से घर-घर तक पहुंचाई जा सकेगी। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण, ग्राम विकास, सामाजिक समरसता और धार्मिक आयोजन के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा गतिविधियां संचालित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। बैठक में संघ प्रमुख भागवत के अतिरिक्त सरकार्यवाह भय्याजी जोशी, सह सरकार्यवाह सुरेश सोनी और दत्तात्रेय होसबोले सहित केंद्रीय स्तर के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

जनजागरण के लिए आयोजनों पर जोर : बैठक में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में जनजागरण के आयोजनों की संख्या वृद्धि पर भी जोर दिया गया। संघ के वार्षिक कैलेंडर पर भी पदाधिकारियों के बीच चर्चा हुई। कौन-कौन से आयोजन कहां होंगे, कितने बड़े आयोजन होंगे, इनका स्वरूप कैसा रहेगा, जैसे बिंदुओं पर पदाधिकारियों ने सुझाव दिए। सोशल इंजीनियरिंग पर भी चर्चा हुई।

परिसर में स्वयंसेवकों का रहता है मजबूत घेरा : इंदौर के रिंग रोड स्थित गार्डन में संघ की मंथन बैठक में शामिल संघ प्रमुख को भले ही जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त है, लेकिन परिसर के भीतर स्वयंसेवकों का मजूबत सुरक्षा घेरा पूरे समय सक्रिय रहता है। बैठक में शामिल अन्य पदाधिकारियों के रुकने की व्यवस्था अन्यत्र की गई है, लेकिन संघ प्रमुख भागवत आयोजन स्थल पर ही ठहरे हैं।

आचार्य विद्यासागर का लिया आशीर्वाद

संघ प्रमुख मंगलवार को आचार्य विद्यासागर का आशीर्वाद लेने पहुंचे। आचार्यश्री और संघ प्रमुख के बीच कई विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। आचार्यश्री ने कहा कि देश के विकास के लिए हथकरघा का बड़ा महत्व है। जेल में बंद कैदियों के पुनर्वास के लिए हथकरघा का प्रयोग उनके जीवन को बदल सकता है। इस पर भागवत ने कहा कि आपका यह प्रयास अनुमोदनीय है। संघ इस काम में पूरा सहयोग करेगा। आचार्यश्री ने संघ प्रमुख से हिंदी को प्राथमिकता देने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मातृभाषा हिंदी को सभी जगह प्राथमिकता देना जरूरी है।

दुष्कर्म व हत्या के दोषी की फांसी की सजा पर हाई कोर्ट की मुहर

जागरण संवाददाता, नैनीताल

▶ दो साल पहले देहरादून में दुष्कर्म के बाद कर दी थी बच्ची की हत्या

▶ हाई कोर्ट ने निचली कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार

हाई कोर्ट ने देहरादून के सहसपुर थाना अंतर्गत दस साल की बच्ची से दुष्कर्म व उसकी हत्या करने के मामले में अभियुक्त की फांसी की सजा पर मुहर लगा दी है। मंगलवार को उसकी अपील खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने निचली अदालत के सजा के आदेश को बरकरार रखा।

न्यायमूर्ति आलोक सिंह व न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ में मंगलवार को मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 28 जुलाई 2018 को बच्ची के पिता ने देहरादून के सहसपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कहा था कि वह और अभियुक्त जय प्रकाश निर्माणाधीन शिवालिक इंजीनियरिंग कॉलेज में मजदूरी करते थे। 28 जुलाई को वह काम पर चले गए और उनकी तीनों बेटियां घर में थीं। उस दिन अभियुक्त जयप्रकाश काम पर नहीं गया। अभियुक्त ने उनकी बेटियों को खाने का लालच देकर बुलाया और दो छोटी बेटियों को दस-दस रुपये देकर बाहर भेज दिया। इस बीच अभियुक्त ने बड़ी बेटी से दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद बच्ची की लाश कमरे में ही गड्ढा खोदकर दफना दिया। देहरादून जिले की पॉक्सो कोर्ट ने आरोपित जयप्रकाश को 28 अगस्त 2019 को फांसी की सजा सुनाई थी। इस आदेश को रेफरेंस के लिए 29 अगस्त को हाई कोर्ट भेज दिया गया था। अभियुक्त जयप्रकाश ने भी फांसी से बचने के लिए अपील दायर की। कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को सही पाते हुए सजा बरकरार रखी है।

नैनीताल हाई कोर्ट। फाइल

34 जिलों में अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं 1022 लोग

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि हिंसा के मामले में प्रदेश के 34 जिलों के 1022 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन जिलों में सीएए के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई है। हिंसा से अलीगढ, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बुलंदशहर, कानपुर, रामपुर, गोरखपुर व वाराणसी में 17 लोगों की मौत हो गयी। मुख्यमंत्री ने लखनऊ, मेरठ, हापुड़, सहारनपुर, रामपुर, फीरोजाबाद, कानपुर नगर, मुजफ्फरनगर, मऊ, अलीगढ़, गोरखपुर व बुलंदशहर के जिला अधिकारियों को नुकसान का आकलन कर दोषियों से वसूली करने का आदेश दिया है। वीडियो क्लिपिंग से पहचान कर नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

एनएचआरसी से एक माह में मांगी एएमयू की जांच रिपोर्ट : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) में प्रदर्शन के दौरान पुलिसिया कार्रवाई की जांच कर रहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को एक माह में अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आयोग द्वारा की जा रही जांच के चलते एसआइटी से जांच का आदेश देने से इन्कार कर दिया है।

राजस्थान में बच्चों की मौत पर हाई कोर्ट सख्त मांगी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, जोधपुर: राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में हो रही नवजात बच्चों की मौत पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और राज्य सरकार से मौत के कारणों पर रिपोर्ट मांगी है। हाई कोर्ट ने न्याय मित्र राजवेंद्र सारस्वत व अतिरिक्त महाधिवक्ता पंकज शर्मा को निर्देश दिया है कि वे राज्य के किन्हीं दो जिला अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर वहां के हालात के बारे में विस्तृत रिपोर्ट पेश करें। अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी।

मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति व न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी की बेंच ने मंगलवार को मामले की सुनवाई की। न्यायमित्र राजवेंद्र सारस्वत ने जनता का पक्ष रखा। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में बड़ी संख्या में डॉक्टरों व अन्य कर्मचारियों के पद रिक्त होने पर चिंता जताते हुए बेंच ने कहा कि पर्याप्त कर्मचारियों के बगैर मरीजों का इलाज कैसे संभव हो पाएगा? इसके बाद उन्होंने राज्य सरकार से सभी सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों के कुल स्वीकृत व रिक्त पदों की सूची मांगी। इसके अलावा बेंच ने सभी सरकारी अस्पतालों के रिकॉर्ड को कंप्यूटरीकृत करने का आदेश दिया।

बारिश व बर्फबारी से फिर ठिठुरने लगा उत्तर भारत

जेएनएन, नई दिल्ली

▶ वैष्णो देवी यात्रा में हेलीकॉप्टर व केबल कार सेवा रही बाधित

▶ ऊंचाई वाले इलाकों में बुधवार को भी हिमपात का अलर्ट

उत्तर भारत में ठंडी हवाओं का दौर लौट आया है। पहाड़ों पर लगातार जारी बर्फबारी और बारिश के चलते दिल्ली-एनसीआर समेत मैदानी इलाकों में भी ठंड महसूस की गई। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज लगातार तल्ख बना हुआ है। दिल्ली में मंगलवार को पूरे दिन रुक-रुक का बारिश होती रही।

उत्तराखंड में बर्फबारी के चलते गंगोत्री, यमुनोत्री और बदरीनाथ हाईवे बंद हैं। इसके अलावा चमोली में औली और कुमाऊं में थल-मुनस्यारी मार्ग पर भी यातायात बाधित है। हिमपात से प्रदेश में 150 से ज्यादा गांव अलग-थलग पड़ गए हैं। बुधवार को भी ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात के आसार हैं। हिमाचल में भी मंगलवार को ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी रहा तो निचले क्षेत्र में बारिश लगी रही। इससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ हुआ है।

मसूरी-धनोल्टी मार्ग पर यातायात रोका : बर्फबारी के चलते टिहरी प्रशासन ने मसूरी-धनोल्टी मार्ग पर फिलहाल यातायात रोक दिया है। प्रशासन के अनुसार मौसम की चेतावनी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। पिछले दिनों इस मार्ग पर 500 से ज्यादा पर्यटक फंस गए थे, जिन्हें आइटीबीपी की मदद से निकाला गया था। वहीं, विजीबिलिटी कम होने से पिथोरागढ़ से सभी छह उड़ानें रद कर दी गईं। इसी तरह हिमाचल के कांगड़ा, शिमला और कुल्लू में भी हवाई उड़ानें नहीं हो पाई।

कश्मीर का देश से सड़क संपर्क पूरी तरह टूटा : जम्मू-कश्मीर में मौसम के मिजाज पूरी तरह बिगड़े हुए हैं। लगातार बर्फबारी, बारिश और भूस्खलन से जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार दूसरे दिन भी बंद रहा। इससे हाईवे पर जगह-जगह हजारों वाहन विशेषकर ट्रक फंसे हुए हैं। कश्मीर का देश से सड़क संपर्क पूरी तरह कट गया है। इधर, माता वैष्णो देवी भवन, पत्नीटॉप, नत्थटॉप भद्रवाह, किश्तवाड़, बिलावर, राजौरी, पुंछ में बर्फबारी जारी रही। वैष्णो देवी में खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर सेवा और भवन-भैरो घाटी के बीच चलने वाली केबल कार सेवा भी बंद रही।

हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है। दो दिन से शिमला में हो रही बर्फबारी से कई जगहों के संपर्क मार्ग बंद हो गए है। मंगलवार को कप के आकार के फूलदान और वाहन बर्फ से ढके हुए। महेंद्र ठाकुर

पंजाब में भी दिनभर बारिश से ठंडा हुआ मौसम

पंजाब में मंगलवार को दूसरे दिन भी दिनभर बूंदाबांदी होती रही। बारिश से तापमान में गिरावट के कारण ठंड बढ़ गई। बठिंडा में व सरहिंद में ठंड से एक-एक व्यक्ति की मौत हो गई। मंगलवार को कई जिलों में तेज बारिश भी हुई। मौसम विभाग चंडीगढ़ की मानें तो बुधवार को भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव बरकरार रहेगा और सूबे के अधिकतर जिलों में बारिश के आसार हैं।

बिहार में बीबीए की छात्रा को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म

जासं, पटना : पटना में बीबीए की एक 19 वर्षीया छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। चार लड़कों ने पिस्टल के बल पर छात्रा को जबरन कार में बिठाया। फिर पाटलिपुत्र इंडिस्ट्रयल एरिया में पीएंडएम मॉल के पास एक मकान में ले जाकर दो युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद छात्रा को कार से उतारकर दोनों फरार हो गए। पीड़ित छात्रा ऑटो लेकर नागेश्वर कॉलोनी स्थित हॉस्टल पहुंची। घटना सोमवार रात की है। छात्रा ने अपनी बहन को आपबीती सुनाई। देर रात पीड़िता एसकेपुरी थाने पहुंची। वहां से उसे महिला थाना ले जाया गया। उसने मामले में चार युवकों विनायक सिंह, संदीप मुखिया, विकास और कुश पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। छात्रा गोपालगंज की रहने वाली है तथा नोएडा के एक कॉलेज से दूरस्थ शिक्षा के तहत बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बीबीए-द्वितीय वर्ष) की पढ़ाई कर रही है। दो आरोपित कुश व विकास को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने घटना की निंदा करते हुए कठोरतम कार्रवाई की मांग की।

अंतिम विदाई

सोमवार को ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हुआ था निधन, बारिश के बावजूद अंतिम विदाई देने पहुंचे सैकड़ों लोग

सियाचिन के हीरो पीएन हून आपको याद रखेगा हिंदुस्तान

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़

ऑपरेशन मेघदूत की अगुआई करने वाले रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हून को मंगलवार को अंतिम विदाई दी गई। मंगलवार को सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही थी। इसके बावजूद सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने वाले रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हून के अंतिम संस्कार में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। दोपहर सवा तीन बजे सैन्य सम्मान के साथ पीएन हून को श्रद्धांजलि दी गई। उनकी पार्थिव देह श्मशान घाट लाने से पहले ही बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंच गए थे।

इस दौरान पश्चिमी कमान के सैन्य अधिकारी व पूर्व सैन्य अधिकारी भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। सात डोगरा रेजीमेंट के जवानों ने अपने जांबाज अधिकारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटे रौनी हून ने उन्हें मुखाग्नि दी।

रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हून। फाइल

चीन और पाक के साथ जंग में दिखाया था अदम्य साहस

हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी उनके सेक्टर-6 स्थित निवास स्थान पर श्रद्धासुमन अर्पित करने पहुंचे। गुप्ता ने कहा कि हून के निधन से बेहद दुख हुआ। उन्होंने भारत की सेवा की और राष्ट्र को मजबूत और अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चार अक्टूबर, 1929 को पाकिस्तान के एबटाबाद में जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल हून ने ऑपरेशन मेघदूत का नेतृत्व किया था। बंटवारे को बाद उनका परिवार भारत आ गया। लेफ्टिनेंट जनरल हून ने 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान भी अदम्य साहस दिखाया। उन्होंने डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के रूप में भी काम किया और 1987 में पश्चिमी कमान के प्रमुख के तौर पर रिटायर हुए थे। अक्टूबर 2015 में उन्होंने अपनी पुस्तक द अनटोल्ड ट्रूथ लॉन्च की थी।

ब्रेन स्ट्रोक और कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई मौत

परिवार के सदस्यों ने बताया कि रविवार सुबह उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद उन्हें तुरंत चंडीमंदिर स्थित कमांड हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया जहां डॉक्टरों ने ब्रेन स्ट्रोक बताया। सोमवार को उनका देहांत हो गया था।

हून के योगदान के लिए देश सदा रहेगा उनका ऋणी : लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हून के साथ सेना में अपनी सेवाएं दे चुके रिटायर्ड ब्रिगेडियर बलबीर सिंह अपने दोस्त को अंतिम विदाई देने के लिए खासतौर पर बेंगलुरु से चंडीगढ़ पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि हून भारत मां के सच्चे सपूत थे। उन्होंने चार दशक तक सेना में रहकर कई मोर्चों पर तिरंगा लहराया। हून के योगदान के लिए देश सदा उनका ऋणी रहेगा।

'एयरलाइनों से यात्रियों को शहद के सैशे देने को कहेंगे'

पुणे, प्रेट्र : केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में काम करेगा। अगले पांच साल में इसका टर्नओवर पांच लाख करोड़ रुपये कर दिया जाएगा। फिर चाहे दूध, शहद, बांस, जैविक ईंधन, ब्लू इकोनामी या एथेनॉल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इन्हीं क्षेत्रों में बढ़ाया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि वह एयरलाइनों से चाय या कॉफी में डालने के लिए शहद के सैशे का इस्तेमाल करने की अपील करेंगे। इससे शहद के उद्योग को बढ़ावा मिलने के साथ ही बेहतर स्वास्थ्य को भी बल मिलेगा। गडकरी ने सेंट्रल बी रीसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (सीबीआरटीआइ) के एक कार्यक्रम में कहा कि आमतौर पर एक चम्मच शहद तीन चम्मच चीनी के बराबर होता है। मौजूदा समय में रिफाइंड चीनी के सैशे फ्लाइट में यात्रियों को दिए जाते हैं। लेकिन अब प्रयास होगा कि यात्रियों को फ्लाइट में और होटल में शहद के सैशे और क्यूब दिए जाएं। उन्होंने बताया कि शहद और चीनी का विकल्प दिया जाएगा। वह एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट और गोएयर एयरलाइनों और खादी ग्रामोद्योग के आयोग के अध्यक्ष से अपील करेंगे कि विमानों में उड़ान के दौरान दोनों ही विकल्पों को उपलब्ध कराएं। उन्होंने बताया कि सरकार शहद के क्लस्टर बनाने पर विचार कर रही है। वह शहद का उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सरकार शहद के विभिन्न उत्पाद बनाने पर भी विचार कर रही है। शहद के विभिन्न समूहों की स्थापना से देश की ग्रामीण और आदिवासी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। किसानों की आय में इजाफा होगा। उनका मंत्रालय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए काम करेगा।

1.2 लाख करोड़ रुपये के आसपास होगा जम्मू-कश्मीर का वित्त वर्ष 2020-21 का बजट। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 88.911 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया था। बजट को अंतिम मंजूरी 31 जनवरी को शुरू होने वाले संसद के बजट सत्र में ही मिलेगी।

कश्मीर में हिजबुल का आतंकी ढेर

मुठभेड़ ▸ सोमवार की रात को चुरसु गांव में अपने संपर्क सूत्र से मिलने पहुंचा था

सुरक्षाबलों ने शुरू की आतंकी के दो अन्य साथियों की तलाश

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

दक्षिण कश्मीर में अवंतीपोरा के एक गांव में अपने किसी संपर्क सूत्र से मिलने आए हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी को सुरक्षाबलों ने मंगलवार को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। उसकी पहचान बिजबिहाड़ा के ईदगाह मोहल्ला निवासी शाहिद अहमद गदांजी के रूप में हुई है। उसके दो अन्य साथियों की धरपकड़ के लिए सुरक्षाबलों ने अभियान जारी रखा हुआ है। वर्ष 2020 में कश्मीर में सुरक्षबलों और आतंकियों के बीच यह पहली मुठभेड़ है, जिसमें एक आतंकी मारा गया।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि स्वचालित हथियारों से लैस आतंकियों का एक दल सोमवार को आधी रात के बाद अवंतीपोरा के साथ सटे चुरसु गांव में अपने किसी संपर्क सूत्र के पास आया था। इसका पता चलते ही पुलिस और सेना के संयुक्त कार्यदल ने आतंकियों को पकड़ने के लिए गांव की घेराबंदी की और तलाशी अभियान चलाया। मंगलवार तड़के सुरक्षाबलों ने आतंकियों को लाउडस्पीकर के जरिए कई बार सरेंडर करने के लिए कहा। इसके बावजूद वह गोलियां चलाते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने हमला तेज करते हुए घेराबंदी तोड़कर भागने की कोशिश, लेकिन वह इसमें कामयाब नहीं हो सके। इस दौरान दोनों तरफ से करीब 20 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। इसके बाद आतंकियों की तरफ से गोली चलना बंद हो गई। जवानों ने जब मुठभेड़ स्थल की तलाशी ली तो उन्हें वहां गोलियों से छलनी आतंकी शाहिद अहमद गदांजी का शव मिला।

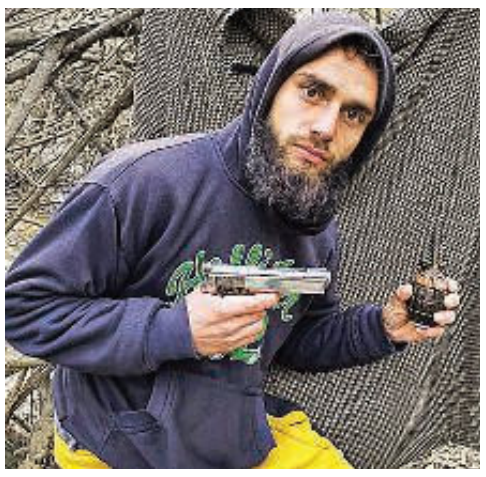

आतंकी शाहिद अहमद गदांजी। फाइल

दो आतंकी बच निकले : स्थानीय सूत्रों की मानें तो गांव में तीन आतंकी थे। एक मारा गया और दो बच निकले। हालांकि, पुलिस ने इससे इन्कार करते हुए कहा कि वहां एक ही आतंकी था जो मारा गया। इसके बावजूद पुलिस ने आतंकियों के छिपे होने की संभावना से इन्कार नहीं किया है। इसलिए चुरसु व उसके साथ सटे इलाके में एहतियात के तौर पर तलाशी अभियान जारी रखा गया है।

परिवार और इमाम की अपील पर भी नहीं पिघला : सुरक्षाबलों ने आतंकी शाहिद अहमद गदांजी को सरेंडर कराने के लिए उसके परिवार और इलाके के इमाम से अपील कराई। परिवार के लोगों और इमाम ने लाउड स्पीकर से शाहिद को सरेंडर करने के लिए कई बार कहा। इसके बावजूद वह गोलियां चलाता रहा। जब वह नहीं माना तो सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में मारा गया। जरूरी औपचारिकताओं के बाद आतंकी के शव को उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया।

हनीट्रैप में फंसे युवक ने गिरफ्तारी से पहले नष्ट किया सिमकार्ड

जागरण संवाददाता, जम्मू : पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ के हनीट्रैप में फंसे युवक के मोबाइल फोन को पुलिस ने जांच के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) में भेज दिया है। वहीं, युवक ने पुलिस के हत्थे चढ़ने से पूर्व ही अपने सिमकार्ड को नष्ट कर दिया था। उसे जब पता चला कि वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का शिकार हो चुका है तो उसने अपने मोबाइल फोन से सभी तस्वीरों को भी हटा दिया था। जब्त किए गए मोबाइल फोन से पुलिस इस बात की जानकारी हासिल करने में जुटी है कि युवक ने सीमांत इलाके के किन-किन संवेदनशील स्थलों की तस्वीरें अपने फोन से खींचकर अनजाने में पाकिस्तानी एजेंट को भेजी हैं। चूंकि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है इसलिए पुलिस अधिकारी खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहे।

पाक रेंजरों ने रेंज बढ़ाकर दागे गोले, कोई हताहत नहीं

जागरण संवाददाता, हीरानगर

- हीरानगर सेक्टर में लगातार हो रहा है संघर्ष विराम का उल्लंघन
- रात को बारिश के चलते लोगों को बंकरों में भी जाने का नहीं मिला मौका

कठुआ जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान पिछले करीब डेढ़ महीने से रात के समय लगातार गोलाबारी कर रहा है। सोमवार की रात को भी पाकिस्तानी रेंजरों ने सीमावर्ती गांवों में गोलाबारी के साथ मोर्टार भी दागे। गोलाबारी में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है। कई घरों की छतें टूट गई हैं। वहीं, बारिश होने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

हीरानगर सेक्टर में सुरक्षाबल के जवान डिच यानी सुरक्षा बांध बना रहे हैं। जब से यह काम शुरू किया है तब से भी पाकिस्तानी रेंजर बौखलाहट में सीजफायर का उल्लंघन कर रहे हैं।

पाकिस्तानी रेंजरों ने सोमवार आधी रात को अपनी ओर के पप्पू चक व करोल पंगा इलाकों से गोलीबारी शुरू कर दी। इस दौरान 82 एमएम मोर्टार के गोले दागे गए। एक गोला भारतीय क्षेत्र में करोल माथरियां गांव के उत्तम चंद के घर के पास सड़क पर गिरा, जिससे उसके मकान को क्षति पहुंची। करोल बीजो गांव के पास भी गोले गिरे हैं। मंगलवार की सुबह बीडीसी चेयरमैन करण कुमार ने दोनों गांवों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। पंच रतन चंद, उत्तम चंद ने बताया कि रात को बारिश हो रही थी। रात साढ़े 12 बजे अचानक गोलाबारी के चलते लोगों को बंकरों के अंदर जाने का मौका भी नहीं मिला। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी रेंजर पहले 51 एमएम मोर्टार के गोले चलाते थे जो गांव के अंदर नहीं पहुंचते थे। ऐसे में अब उन्होंने रेंज बढ़ा दी है। इससे गोले करोल माथरियां से एक किलोमीटर पीछे करोल विद्दो में भी गिरे।

> करोल माथरियां के जिस बंकर की छत टपक रही है, उसे ठीक करवाने के लिए कहा गया है। वहीं, जिनके घरों में बंकर निर्माण के लिए जगह कम है, उसकी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है। आगे जो आदेश मिलेगा उसके तहत बंकर बनाएंगे।
> **केके अत्री, एईई, पीडब्ल्यूडी**

बंकर की छत से टपक रहा पानी : करोल माथरियां के कमल किशोर की पत्नी वंदना देवी ने बताया कि पीडब्ल्यूडी ने जो बंकर बनाया है उसका स्लैब एक फीट मोटा है, इसके बावजूद छत से पानी टपक रहा है। इस कारण वह रात को गोलीबारी के दौरान भी बंकर में नहीं जा सके। अधिकारियों से शिकायत की थी, मगर छत ठीक नहीं हुई। बीडीसी ने इस मामले को उप राज्यपाल के सलाहकार तक पहुंचाने का भरोसा दिया है।

जम्मू में 3141 बंकरों में 1838 बनकर तैयार

जागरण संवाददाता, राजौरी : जम्मू संभाग के राजौरी जिले में ग्रामीण विकास विभाग और लोक निर्माण विभाग द्वारा सीमांत क्षेत्रों में बनाए जा रहे बंकरों की प्रगति को लेकर जिला आयुक्त (डीसी) मुहम्मद नजीर शेख ने अपने कक्ष में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्हें जानकारी दी गई कि जिले में कुल 3141 बंकर बनने हैं, जिनमें से 1838 बनकर तैयार हो गए हैं।

ग्रामीण विकास विभाग के तहत बंकर निर्माण के बारे में बताया गया कि 1892 बंकरों में 1745 व्यक्तिगत और 147 सामुदायिक बंकर बनाए जा रहे हैं। इनमें 306 बंकर नींव स्तर पर हैं। 84 बंकरों का निर्माण कार्य वन विभाग की मंजूरी न मिलने के कारण शुरू नहीं हो पाया है। डीसी ने खंड विकास अधिकारियों से सीमा पर बंकर निर्माण की स्थिति के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी। राजौरी डिवीजन में लोक निर्माण विभाग द्वारा बंकर निर्माण के बारे में संबंधित अधिकारी ने कहा कि 133 बंकरों में से 61 व्यक्तिगत और 72 सामुदायिक बंकर शामिल हैं। इनमें से 86 बंकर का कार्य पूरा हो चुका है।

नौशहरा डिवीजन में बंकर निर्माण की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 1,116 बंकरों में से 638 व्यक्तिगत व 48 सामुदायिक बंकरों का कार्य पूरा हो चुका है। जबकि अन्य का काम चल रहा है। डीसी ने संबंधित अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर कामों को पूरा करने के लिए कहा। उन्होंने इन बंकरों पर काम करते समय गुणवत्ता बनाए रखने का भी आग्रह किया।

न्यूज गैलरी

केरल में मुथूट फाइनेंस के एमडी पर हमला

कोच्चि : केरल में कर्मचारियों की छंटनी के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच मंगलवार को कुछ लोगों ने मुथूट फाइनेंस कंपनी के दफ्तर के पास ही प्रबंध निदेशक जॉर्ज एलेक्जेंडर के वाहन पर पथराव कर दिया। इस दौरान एक बड़ा पत्थर कार की खिड़की का शीशा तोड़ते हुए एलेक्जेंडर के सिर में लगा और वे घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। हालांकि, राज्य के श्रम मंत्री टीपी रामकृष्णन व सीटू नेता ए. आनंदन ने हमले में किसी कर्मचारी के शामिल होने की संभावना से इन्कार किया है। (एजेंसियां)

नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे दो वाहन फूंके

राजनांदगांव : महाराष्ट्र की सीमा से सटे औंधी थाना से दस किमी दूर ग्राम सरखेड़ा और घोड़ाझरी के बीच 20 से 22 हथियारबंद नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। यहां सड़क निर्माण में लगे दो डंपर को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। इसके पहले उन्होंने काम में लगे मजदूरों को मारकर भगा दिया। गांवों में दहशत फैलाने के लिए नक्सलियों ने पोस्टर व पर्चे भी फेंके। लंबे समय बाद मानपुर-औंधी क्षेत्र में नक्सल गतिविधि सामने आने को लेकर पुलिस भी हरकत में आ गई। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक बीएस ध्रुव और नक्सल सेल के एएसपी जीएन बघेल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। (नईदुनिया)

गोरखपुर में बच्चों की मौत पर तीन सप्ताह में मांगा जवाब

लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कालेज में 2017 में हुई मासूमों की मौतों की न्यायिक जांच कराने को लेकर दायर याचिका पर जवाब न दाखिल करने पर एतराज जताया है। हालांकि कोर्ट ने राज्य सरकार को फिर से तीन हफ्ते का समय दिया है। यह आदेश जस्टिस पंकज जायसवाल व जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने सेंटर फार सिविल लिबर्टीज नामक संस्था की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया। 2017 में दाखिल याचिका पर कोर्ट ने प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह की बहस सुनने के बाद राज्य सरकार को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। तब से जवाब नहीं दाखिल किया गया। अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी। (विसं)

पीएम ने सुरक्षा और जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों की समीक्षा की

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मंत्री परिषद की बैठक में जम्मू-कश्मीर में पिछले छह महीने में कराए गए विकास कार्यों और सुरक्षा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की। सरकार से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि बैठक में जम्मू-कश्मीर में चल रहे विकास कार्यों को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया। इसमें यह गौर किया गया कि राज्य में अब विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं।

इसके अलावा, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र से जुड़े मामलों और रणनीतिक मुद्दों पर भी बैठक में चर्चा की गई। मंत्री परिषद की यह चौथी बैठक थी, जिसमें किसी विशेष मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। इस तरह की हर बैठक में शीर्ष सरकारी अधिकारी प्रेजेंटेशन देते हैं। सूत्रों ने बताया कि यह कवायद प्रमुख मंत्रालयों के लिए अगले पांच साल की कार्य योजना तैयार करने का हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक समीक्षा कार्यों को पूरा करने के लिए अगले हफ्ते फिर इस तरह की बैठक हो सकती है। इसमें विकास कार्यों में तेजी लाने पर जोर रहेगा।

बारिश और धुंध के कारण आतंकियों पर अंतिम प्रहार एक दिन और टला

जागरण संवाददाता, राजौरी

घना जंगल, कंपा देने वाली ठंड और उस पर लगातार बारिश के बावजूद नौशहरा के पास जंगल में सुरक्षा बल मुस्तैदी से पाकिस्तानी आतंकियों पर अपना घेरा पल-पल कसते जा रहे हैं। मौसम के कारण इन खूंखार आतंकियों पर अंतिम प्रहार भले ही एकदिन टालना पड़ गया पर अब उनका बच निकलना संभव नहीं है। अगर सब ठीक रहा तो संभव है आठ दिन से जारी यह सर्च ऑपरेशन बुधवार को अंजाम तक पहुंच जाएगा। इस अभियान में अन्य बलों के अलावा सेना की स्पेशल फोर्स के जवान भी डटे हैं। फिलहाल उन आतंकियों की संख्या तीन बताई जा रही है।

यहां बता दें कि 31 दिसंबर की रात बच कर निकलने का प्रयास रहे आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के दो जवान शहीद हो गए थे। उसके बावजूद सुरक्षा बलों ने उन्हें घेराबंदी तोड़कर भागने का मौका नहीं दिया। उनकी तलाश में ड्रोन से आसमान से भी नजर रखी जा रही है। नौशहरा के जंगलों में तीन हजार के करीब सेना, स्पेशल फोर्स, पुलिस व सीआरपीएफ के जवान जुटे हुए हैं। आतंकवादियों को दबोचने के लिए सुरक्षा बलों का घेरा कसता जा रहा है और इसका दायरा दस किलोमीटर से घटाकर तीन किलोमीटर कर दिया है।

वीआइपी को निशाना बनाने घुसे हैं आतंकी: नियंत्रण रेखा के पास से घुसपैठ कर आए तीन पाकिस्तानी आतंकी जम्मू-कश्मीर में फिर से दहशत फैलाना चाहते हैं। पाकिस्तान में बैठे आकाओं ने करीब 10 दिन पहले वीआइपी को निशाना बनाने के लिए घुसाया था। सुरक्षा बलों से जुड़े सूत्रों के अनुसार इन तीनों आतंकवादियों को लेने कालाकोट के एक गांव से गाइड भी आने वाला था, लेकिन जैसे ही उसे इनके मंसूबों की जानकारी मिली तो वह घबरा गया और उन्हें लेने ही नहीं पहुंचा। नियंत्रण रेखा से चलकर यह करीब 20 किलोमीटर अंदर भी पहुंच गए और फिर अपना रास्ता भटक गए। उसके बाद सुरक्षा बलों की घेरेबंदी से निकल नहीं पाए।

पठान है इनका कमांडर : सूत्रों की माने तो तीनों आतंकी पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इनका कमांडर करीब 35 वर्ष का एक पठान है और वही इन हमलों की पूरी साजिश के साथ आया है।

नईदुनिया व मिडडे को 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

जागरण समूह के दो समाचारपत्रों नईदुनिया और मिडडे गुजराती को प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान से नवाजा गया। मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर और आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीपद येसो नाइक ने यह सम्मान प्रदान किए। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जावडेकर ने कहा कि यह पुरस्कार ऐसे मीडिया संस्थानों के सराहनीय प्रयासों को मान्यता देने का अभिनव उपक्रम है, जो समाचारों, विचारों और विज्ञापनों की दुनिया से परे भी समाज के व्यापक हितों की पूर्ति में मिशन मोड में रत हैं। पुरस्कारों के लिए गठित निर्णायक मंडल के अध्यक्ष भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सीके प्रसाद थे। नईदुनिया और मिडडे ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में योग के प्रति जनजागरूकता को विस्तार देने के लिए जो प्रयास किए, उन्हें इस सम्मान का हकदार माना गया।

नई दिल्ली में मंगलवार को नईदुनिया के ऑपरेशंस हेड नरेश पांडे को सम्मान प्रदान करते केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर। पीआइबी

इल्तिजा मुफ्ती को नाना की मजार पर जाने की नहीं मिली इजाजत

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती को मंगलवार प्रशासन ने उनके नाना स्व. मुफ्ती मोहम्मद सईद की चौथी बरसी पर श्रद्धांजलि अर्पित करने की इजाजत नहीं दी। इससे गुस्साई इल्तिजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य प्रशासन को आड़े हाथ लिया। उन्होंने प्रशासन से अपनी स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप (एसएसजी) सुरक्षा हटाने के लिए जोर दिया।

इल्तिजा ने कहा कि यह सुरक्षा कवच मेरी और मेरे परिवार के अन्य सदस्यों की गतिविधियों पर निगरानी रखने और उन पर पाबंदी लगाने का एक जरिया बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। मंगलवार को भी पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट का प्रयास किया है। इल्तिजा ने आरोप लगाया कि आतंकियों द्वारा 1989 में अगवा डॉ. रुबिया सईद की सुरक्षा भी प्रशासन ने वापस ले उनकी जान को खतरे में डाल दिया है।

मजार पर पहुंचे सिर्फ दो लोग : पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री और जम्मू कश्मीर के दो बार मुख्यमंत्री रह चुके स्व. मुफ्ती मोहम्मद सईद के मजार पर उनके दो ही रिश्तेदार पहुंच सके। इनमें एक उनके चाचा बताए जाते हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद का सात जनवरी 2016 को देहांत हो गया था। हालांकि इल्तिजा ने सोमवार शाम दावा किया था कि उन्हें और परिवार के कुछ करीबी सदस्यों को बिजबिहाड़ा के दाराशिकोह बाग में मुफ्ती मोहम्मद सईद की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित करने की अनुमति मिल गई है, लेकिन जिला उपायुक्त अनंतनाग खालिद जहांगीर ने साफ कर दिया था कि इस संदर्भ में अंतिम फैसला तात्कालिक परिस्थितियों के आधार पर ही लिया जाएगा।

इल्तिजा मुफ्ती। फाइल

जम्मू-कश्मीर में मिलने लगा नए सियासी मोर्चे का संकेत

राज्य ब्यूरो, जम्मू

- पीडीपी में जारी अंतर्कलह के बीच आठ वरिष्ठ नेताओं ने उपराज्यपाल जीसी मुर्मू से की मुलाकात

केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में नए सियासी मोर्चे के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। मंगलवार को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) में जारी अंतर्कलह के बीच पूर्व वित्तमंत्री सईद अल्ताफ बुखारी के नेतृत्व में आठ वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल जीसी मुर्मू से मुलाकात की। इस आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में पीडीपी के पांच पूर्व विधायक, एक पूर्व एमएलसी, एक पीडीपी से निष्कासित पूर्व मंत्री और डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनलिस्ट के अध्यक्ष (कभी पीडीपी का ही हिस्सा) शामिल थे। इन नेताओं ने सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई, जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा, स्थानीय लोगों के सामाजिक-आर्थिक और जमीन के मालिकाना अधिकार संबंधी विभिन्न अधिकारों के संरक्षण को यकीनी बनाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन भी उपराज्यपाल को सौंपा।

स्थानीय सियासी हलकों में आठ नेताओं की उपराज्यपाल से मुलाकात को केंद्र व जम्मू कश्मीर प्रशासन के बीच पहला खुला संवाद माना जा रहा है। बीते पांच माह के दौरान पहली बार किसी गैर भाजपा और मुख्यधारा के दल के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल से मुलाकात की है। जम्मू कश्मीर में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव कराए जाने के केंद्र सरकार के इरादों को देखते हुए यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है।

कौन कौन था मुलाकात में शामिल : उपराज्यपाल के साथ इस मुलाकात को ज्यादा तूल न दिया जाता। अगर इसमें पीडीपी के निष्कासित अल्ताफ बुखारी और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वाले बारामुला के पूर्व विधायक जावेद हसन बेग और पूर्व कृषि मंत्री गुलाम हसन मीर शामिल नहीं होते। जावेद हसन बेग पूर्व उपमुख्यमंत्री और पीडीपी के संरक्षक मुजफ्फर हुसैन बेग के भतीजे हैं। वहीं, प्रतिनिधिमंडल में शामिल डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनलिस्ट के अध्यक्ष और पूर्व कृषि मंत्री गुलाम हसन मीर भी पीडीपी के संस्थापक सदस्यों में एक रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल में शामिल अन्य सदस्यों में पीडीपी के चार पूर्व विधायक मोहम्मद दिलावर मीर, चौधरी कमर हुसैन, नूर मोहम्मद शेख और राजा मंजूर अहमद के अलावा एक पूर्व एमएलसी जफर इकबाल मन्हास शामिल थे।

हम किसी दल विशेष के एजेंडे को लेकर नहीं मिले : पीडीपी से निष्कासित अल्ताफ बुखारी बीते तीन माह से ही केंद्र शासित जम्मू कश्मीर राज्य में एक नए सियासी मोर्चे के गठन में सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी कवायद के तहत वह गत दिनों दिल्ली, मुंबई और जम्मू में भी अपने पुराने संपर्क सूत्रों के साथ बैठकों में व्यस्त रहे हैं। अल्ताफ बुखारी ने उपराज्यपाल के साथ अपनी मुलाकात पर कहा कि जब सियासी लोग किसी से मिलने जाएंगे तो सियासी मुद्दों पर ही बातचीत करेंगे। खैर, हमने उपराज्यपाल को अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर के लोगों में जो भ्रम, असुरक्षा और चिंता का भाव है, उन्हें दूर करने पर जोर दिया है। हम किसी दल विशेष के एजेंडे को लेकर नहीं मिले हैं।

सियासत में कुछ भी असंभव नहीं : पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के असंतुष्ट और निष्कासित नेताओं के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू से मिलने पर पूर्व कृषि मंत्री गुलाम हसन मीर ने कहा कि हम सभी का एजेंडा एक ही था। एकसाथ मिलकर ही अपनी बात को जोरदार तरीके से रखा जा सकता है। नए सियासी मोर्चे की संभावना पर उन्होंने कहा कि सियासत में कुछ भी असंभव नहीं है। जल्द ही स्थिति साफ हो जाएगी।

ज्ञापन में की मांगें

- सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई।
- जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा।
- विधान परिषद के गठन की मांग।
- पत्थरबाजी में लिप्त युवाओं के खिलाफ एफआइआर वापस ली जाए।
- सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों, कला-संस्कृति, भाषा, साहित्य व खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए आरक्षण।
- स्थानीय लोगों के सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश की तरह विशेष प्रावधान व डोमिसाइल की सुविधा।
- जम्मू-कश्मीर बैंक की प्रक्रियात्मक स्वायत्तता, कृषि एवं बागवानी क्षेत्र की पुनर्बहाली, उद्योग एवं निर्माण क्षेत्र व संबंधित गतिविधियों को मजबूती।
- इंटरनेट सेवाओं की बहाली, बंद से प्रभावित दुकानदारों, बस चालकों, टैक्सी ऑपरेटरों के लिए राहत पैकेज।

सख्ती

मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में आयु के दस्तावेज लिए बिना शादियां कराई तो होगी कार्रवाई

बाल विवाह कराने पर पंडित को भी होगी जेल

राजेश शर्मा, राजगढ़

मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में बाल विवाह रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा एक बार फिर से प्रयास किए जा रहे हैं। अब जन्म प्रमाण पत्र या आयु को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज देखे बगैर यदि शादियां कराई गईं, तो ऐसे पंडितों व विवाह कराने वालों पर भादंवि की धारा 188 (शासकीय आदेश के उल्लंघन) के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस धारा में आरोपित को दोषी पाए जाने पर एक माह की जेल या जुर्माने का प्रावधान है।

प्रशासन पहले देगा समझाइश : राजगढ़ जिला प्रशासन सभी पंडितों को बाल विवाह नहीं कराने की समझाइश देते हुए बुधवार को पत्र लिखेगा। एक दिन पूर्व नातरा कुप्रथा को लेकर हुई कार्यशाला में कलेक्टर निधि निवेदिता ने कहा था कि बाल विवाह न हो, इसके लिए सभी समाज प्रमुख, शादियां कराने वालों सहित सभी जिम्मेदार लोग सजग हो जाएं। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिए थे कि लोगों को सचेत कर दें।

नातरा व झगड़े की मूल वजह है बाल विवाह : प्रशासन का मानना है कि बाल विवाह ही नातरा और झगड़े का मूल कारण है। कलेक्टर के निर्देश पर सभी एसडीएम अपने क्षेत्र के विवाह कराने वाले पंडितों, मंदिरों पर विवाह की पाती लिखने वालों को बुधवार से पत्र लिखेंगे। उन्हें हिदायत दी जाएगी कि कोई भी विवाह वर-वधु के जन्म-प्रमाण पत्र या आयु को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज देखकर ही कराएं।

जालपा माता मंदिर की पाती पर भी शिकंजा

क्षेत्र के जिन लोगों के विवाह के मुहूर्त नहीं निकलते हैं, वे राजगढ़ जिले के जालपा माता मंदिर की पाती के आधार पर विवाह कर लेते हैं। अब इस मंदिर पर भी विवाह की पाती लिखने वालों को भी वर-वधु की आयु की जांच करना होगी। उल्लेखनीय है कि राजगढ़ जिले में हर साल बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं। इस कारण कुछ समाजों में नातरा (दूसरा विवाह) एवं झगड़े की स्थिति बनती है।

प्रतीकात्मक

> बाल विवाह रोकने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। पंडितों और विवाह कराने वालों को कोई भी शादी कराने से पहले वर-वधु के जन्म प्रमाण पत्र या आयु प्रमाणित करने वाले दस्तावेज जांचने का निर्देश दिया गया है। यदि कहीं नाबालिग का विवाह हुआ, तो संबंधित पंडित, व्यवस्थापक आदि पर धारा 188 की कार्रवाई की जाएगी।
> **-संदीप अस्थाना, एसडीएम, राजगढ़**

बंगाल में पुलिया की पाइप में डालकर 17 साल की लड़की को जला दिया

जेएनएन, कोलकाता : बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले में पुलिया की पाइप में डालकर 17 वर्षीय किशोरी को जला देने का मामला सामने आया है। पुलिस मौके पर पहुंची तो उस लड़की की पहचान की गई। मृतका के स्वजनों को आशंका है कि उसे सामूहिक दुष्कर्म के बाद जलाया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक देवर्षी दत्ता का कहना है कि मृतका के जले हुए शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। पुलिस ने संदेह के आधार पर तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही कहा जा सकता है कि लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है या नहीं।

मृतका के भाई का कहना है कि वह रविवार दोपहर को पास की दुकान से सामान लेने गई थी, उसके बाद से लापता थी। लड़की की जली हुई लाश मिलने के बाद लोग आक्रोषित है। स्थानीय भाजपा सांसद सुकांत मजूमदार ने दोषियों को न पकड़े जाने पर आंदोलन की धमकी दी है।

कोलकाता में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, एक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- मकान में लोहे के पुर्जे तैयार करने की आड़ में चल रहा था अवैध कारोबार
- पिस्तौल व मैगजीन समेत अधबने हथियार उपकरण समेत अन्य सामान बरामद

कोलकाता में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवैध हथियार बनाने के कारखाने का भंडाफोड़ करते हुए कारीगर को गिरफ्तार किया गया है। मौके से एक तैयार पिस्तौल, मैगजीन तथा अर्धनिर्मित हथियार समेत उपकरण बरामद किए गए हैं।

मकान मालिक और अन्य कर्मचारी फरार होने में सफल रहे। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने संयुक्त रूप से सोमवार रात करीब 1.30 बजे नदियाल की एक इमारत में छापेमारी की, जहां पर लोहे के पुर्जे तैयार करने की आड़ में अवैध रूप से मुंगेर ब्रांड के हथियार बनाए जा रहे थे। पुलिस ने रंगे हाथों एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मौके से तैयार एक 7एमएम की पिस्तौल, मैगजीन, दो सेमी मैगजीन, एक बैरल, अर्धनिर्मित हथियार के साथ ही हथियार बनाने के उपकरण समेत अन्य सामान जब्त किए गए। पूछताछ में आरोपित ने अपना नाम अब्दुल कयूम (28) (निवासी मुंगेर, बिहार) बताया है। आरोपित उक्त थाना क्षेत्र के अयुबनगर में चाइना मैरिज हॉल के पास किराये के मकान में रहता था। छापेमारी की भनक लगते ही मकान मालिक मोहम्मद कलीम पुत्र मोहम्मद नईम और उसके अन्य कर्मचारी फरार होने में कामयाब रहे। आरोपित के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। आरोपित ने बताया कि मकान मालिक मोहम्मद कलीम की देखरेख में अवैध हथियार तैयार किया जाता था। इसके बाद उसे उत्तर व दक्षिण 24 परगना जिले के इलाकों में सप्लाई किया जाता था।

दैनिक जागरण
मानवीय गुणों में विनम्रता सर्वोत्तम मानी जाती है

न्याय की गति

आखिरकार सात साल बाद देश को विचलित करने वाले निर्भया कांड के चार गुनहगारों के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने डेथ वारंट जारी कर दिया। इसके तहत इन चारों को फांसी की सजा 22 जनवरी को दी जाएगी, लेकिन इसे लेकर सुनिश्चित नहीं हुआ जा सकता और इसका कारण यह है कि दोषियों के वकील यह दावा कर रहे हैं कि उनके पास अभी कुछ और कानूनी विकल्प हैं। निःसंदेह जघन्य अपराध के दोषियों को भी उपलब्ध कानूनी विकल्प इस्तेमाल करने का अधिकार है, लेकिन सबको पता है कि इन विकल्पों की आड़ में किस तरह तारीख पर तारीख का खेल खेला जाता है। यह केवल हास्यास्पद ही नहीं, बल्कि शर्मनाक है कि 2012 के जिस मामले ने देश को थर्रा दिया था उसके दोषियों की सजा पर अमल अब तक नहीं हो सका है और वह भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला 2017 में ही सुना दिया था। इसके बाद जो कुछ हुआ वह न्याय प्रक्रिया की कच्छप गति को ही बयान करता रहा। न्याय प्रक्रिया की सुस्त रफ्तार से न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पदों पर बैठे लोग अनजान नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से उन परिस्थितियों का निराकरण होता नहीं दिखता जिनके चलते समय पर न्याय पाना कठिन है।

लगता है किसी को इस पर लज्जा नहीं आई कि निर्भया के मां-बाप को न्याय के लिए किस तरह दर-दर भटकना पड़ रहा? दुर्भाग्य से यह एकलौता ऐसा मामला नहीं जिसमें न्याय पाना पहाड़ जैसी समस्या बना हो। यह तो गनीमत है कि इस मामले में सात साल बाद न्याय होता दिख रहा है। अधिकांश मामलों में तो दशकों बाद भी अंतिम स्तर पर न्याय नहीं हो पाता। इनमें तमाम मामले संगीन किस्म के होते हैं। जब संगीन मामलों में भी जटिल कानूनी प्रक्रिया के कारण देरी होती है तब केवल न्याय व्यवस्था का उपहास ही नहीं उड़ता, बल्कि अपराधी तत्वों को बल भी मिलता है। यह विडंबना ही है कि सब इससे भली तरह अवगत हैं कि न्याय में देरी न्याय से इन्कार है, फिर भी वैसे प्रयास नहीं हो रहे हैं जिससे न्याय में देरी न होने पाए। बेहतर हो कि हमारे नीति-नियंता कानून के शासन को लेकर घिसे-पिटे उपदेश देने के बजाय यह देखें कि न्याय की शिथिल गति भारतीय लोकतंत्र को दुर्गति की ओर ले जा रही है। इसी के साथ समाज को भी यह समझना होगा कि दुष्कर्मी तत्वों को केवल कठोर सजा से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। दुष्कर्म सरीखे अपराध कहीं न कहीं यह भी बताते हैं कि समाज बेहतर नागरिकों का निर्माण करने के अपने दायित्व का निर्वाह सही ढंग से नहीं कर पा रहा है।

पर्यटन स्थलों पर चुनौतियां

इन दिनों उत्तराखंड पर कुदरत मेहरबान है। बर्फ से लकदक पहाड़ों में मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटकों का रैला उमड़ रहा है। मसूरी, औली, धनोल्टी, सुरकंडा, चोपता, हर्षिल, चकराता, नैनीताल और पिथौरागढ़ के मुनस्यारी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। जाहिर है मसरी और नैनीताल जैसे स्थल सैलानियों की पहली पसंद हैं। उत्तराखंड में पर्यटन की दृष्टि से पर्यटकों का यह रुझान उत्साहित करने वाला है, लेकिन इसी के साथ चुनौतियां भी कम नहीं हैं। मसलन भारी बर्फबारी में सड़कों का बंद होना आम है। पाला पड़ने के बाद सड़कों पर पसरी बर्फ फिसलन भरी हो जाती है और इससे वाहनों के लिए खतरा बढ़ जाता है। पिछले दिनों सप्ताहांत में ऐसा ही हुआ। मसूरी के पास धनोल्टी में बर्फबारी का लुत्फ ले रहे पर्यटकों के वाहन लौटते हुए बीच रास्ते में फंस गए। पर्यटकों को पूरी रात वाहनों में ही बितानी पड़ी। ऐसे में पुलिस और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (आइटीबीपी) के जवान रात भर रास्ता खोलने में तो जुटे ही रहे, सैलानियों को भोजन और पानी भी मुहैया कराया। अगले दिन दोपहर बाद सैलानियों को वहां से निकाला जा सका। निश्चित तौर पर पर्यटकों की मदद कर पुलिस और आइटीबीपी के जवानों ने उत्तराखंड जैसे पर्यटन प्रदेश की छवि को निखारा है। खैर पुलिस ने हालात से सबक लेते हुए मसूरी में एक टीम तैनात कर दी है। यह टीम बर्फबारी के बीच फंसे पर्यटकों की मदद करेगी। इसके लिए एक क्रेन भी तैयार रखी जाएगी, जिससे सड़क पर फंसे वाहनों को निकालने में सहायता मिल सके। यह स्थिति सिर्फ मसूरी की नहीं, बल्कि औली, चकराता और अन्य पर्यटन स्थलों का भी है। दरअसल इन हालात में सवाल यह है कि भीड़ के प्रबंधन को लेकर वक्त रहते कदम क्यों नहीं उठाए जाते। वजह यह है कि ऐसे हालात करीब-करीब हर साल सामने आते हैं। पिछले साल चकराता के पास लोखंडी में फंसे दिल्ली के पर्यटकों को निकालने में प्रशासन को लंबा वक्त लग गया था। इसी साल थल-मुनस्यारी मार्ग पर उत्तर प्रदेश के सैलानियों को पूरी रात सड़क पर गुजारनी पड़ी। इससे पर्यटन प्रदेश की छवि को भी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन, होटल व्यवसायी और पर्यटन विभाग तालमेल से कार्य करे। पर्यटन विभाग और प्रशासन को पता होना चाहिए कि पर्यटन स्थलों पर होटल की बुकिंग की स्थिति क्या है।

उत्तराखंड में बर्फ के दीदार के लिए उमड़ रहा सैलानियों का सैलाब आर्थिकी की दृष्टि से तो शुभ है, लेकिन जरूरी है कि क्राउड मैनेजमेंट को लेकर भी कसरत की जाए

बिना कानून वाली व्यवस्था

यशपाल सिंह

जब तक न्यायिक सुधार, प्रशासनिक सुधार और चुनावी सुधार नहीं होते तब तक कानून एवं व्यवस्था में सुधार नहीं होने वाला

लोकतंत्र में जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। चूंकि स्वतंत्र प्रेस और संचार माध्यमों के साथ सोशल मीडिया का व्यापक विकास हुआ है इसलिए कोई बड़ी घटना होते ही सड़क जाम, घेराव, धरना-प्रदर्शन आदि आम बात हो गई है। इसके चलते दबाव इतना बढ़ जाता है कि आजकल की सरकारें परेशान हो जाती हैं। विपक्ष किसी भी छोटी-बड़ी घटना को बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर धरना-प्रदर्शन करने लगता है। कभी-कभी तो यह धरना-प्रदर्शन आंदोलन का रूप ले लेता है। इस आंदोलन को विपक्षी दलों के साथ सरकार विरोधी अन्य गुट भी हवा देने लगते हैं। वे सरकार को 'निकम्मी' बताने के साथ पुलिस पर भी आक्षेप लगाने लगते हैं। ऐसे में सामान्य जनभावना सरकार के खिलाफ होने लगती है। लोकतंत्र में जनता का वोट ही सब कुछ है। ऐसे में सरकारें क्या करें? पुलिस प्रमुख यानी डीजी बुलाए जाते हैं और उनसे कहा जाता जाता है 'ऐसे काम नहीं चलेगा डीजी साहब। हमें फिर जनता से वोट मांगने जाना पड़ेगा। कैसे करेगें? क्या करेंगे? आप जानिए और आपका काम।' यही बात डीजी साहब अपने मातहत आइजी और डीआइजी से कहते हैं। आइजी और डीआइजी यही बात एसएसपी या फिर एसपी को अपनी पुलिसिया भाषा और अंदाज में समझाते हैं। एसएसपी और एसपी यही बात थानाध्यक्षों से कहते हैं। अब जो करना है वह थानाध्यक्ष को करना है। वह क्या करे? या तो वह लाइन हाजिर होकर मुंह लटकाए पुलिस लाइन चला जाए या फिर कुछ ऐसा करे कि अपराधी दहशत में आ जाएं और उसके क्षेत्र में अपराध करने की हिम्मत ही न कर सकें।

कानून एवं व्यवस्था की स्थिति आज इस हालत में पहुंच गई है कि धीरे-धीरे कानून गायब होता जा रहा है। बस व्यवस्था बची है। कोई भी सरकार व्यवस्था किसी कीमत पर ठीक रखना चाहेगी और उसे ऐसा करना भी चाहिए। चूंकि पुलिस उसके सीधे नियंत्रण में होती है अतः सारा का सारा दबाव थानेदार पर आ जाता है। न्यायिक व्यवस्था से उसे कोई विशेष मदद नही मिल पाती। अभियुक्तों को अग्रिम जमानत या फिर जमानत देर-सबेर मिल ही जाती है और ट्रायल तो फिर उनकी मर्जी से ही चलता है। प्रक्रिया के जाल में कानून इतना उलझ जाता है कि उससे निकलकर न्याय हासिल करने में दशकों लग जाते हैं। जब मामला लंबा खिंचता है तो अक्सर न्याय वादी के पक्ष में जाने की जगह अभियुक्त के पक्ष में जाने का अंदेशा बढ़ जाता है। एक जनपद में एक अपराधी ने एक दबंग की दिन दहाड़े, सरेबाजार गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या ने जातीय रूप पकड़ लिया। वह अपराधी विधायक, सांसद, मंत्री बना। उससे संबंधित हत्या का मुकदमा सत्र न्यायालय में किसी न किसी कानूनी प्रक्रिया के दांवपेच के चलते 18-20 साल लंबित रहा। सारी परिस्थितियां जब हर तरह से अनुकूल हो गईं तो केस चला और वह बाइज्जत बरी हो गया। मालूम हुआ कि सभी गवाहों को बोलेरो गाड़ी मिल गई थी। न्यायालय को साक्ष्य चाहिए।

अवधेश राजपूत

गवाहों पर न तो नैतिक दबाव रहा और न ही सामाजिक भय। प्रशासनिक इकबाल भी नहीं रहा। शायद उनके लिए इतने दिनों बाद गवाही देने का कोई अर्थ नहीं रह गया था।

फूलन देवी ने अपने गैंग के साथ 14 फरवरी 1982 को एक गांव में दिन-दहाड़े करीब 20 लोगों की हत्या कर दी थी। चश्मदीद गवाहों की कोई कमी न थी। फूलन ने मध्य प्रदेश में सरेंडर किया। फिर राजनीति में सक्रिय होकर दो बार सांसद बनीं। अंततः उनकी भी हत्या हुई। गैंग के अन्य साथियों पर मुकदमा चलता रहा। इनमें से 12 मर चुके हैं। चार बचे हुए हैं। इस मामले में सत्र न्यायालय का जो फैसला करीब 38 साल बाद इसी छह जनवरी को आने वाला था वह कुछ दिनों के लिए टल गया है। जब सत्र न्यायालय से फैसला आएगा तो उसके खिलाफ ऊपरी अदालतों में अपील होगी। कोई नहीं जानता कि अंतिम फैसला कब आएगा? आखिर न्याय किसे मिलेगा, क्योंकि फूलन गैंग के हाथों मारे गए कई लोगों के भाई-बंधु तो न्याय का इंतजार करते-करते मर गए।

हैदराबाद की मुठभेड़ के बाद मुख्य न्यायधीश महोदय ने बिल्कुल सही कहा था कि न्याय 'बदला' नहीं है और यह तात्कालिक भी नहीं हो सकता, लेकिन यह समझना होगा कि आखिर पुलिस तब भी एनकाउंटर क्यों करती है जब उस पर जांच, कार्रवाई की तलवार लटकती रहती है? अक्सर पुलिस सुधारों की बात होती है और यह कहा जाता है कि पुलिस सुधार होने से हालात बदल जाएंगे। हालांकि यह काम भी नहीं हुआ, जबकि उच्चतम न्यायालय ने पुलिस सुधार संबंधी निर्देश 2006 में ही दे दिए थे। मेरा मानना है कि केवल पुलिस सुधारों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जब तक आमूलचूल न्यायिक सुधार, प्रशासनिक सुधार और चुनावी सुधार नहीं होते तब तक कानून एवं व्यवस्था में सुधार नहीं होने वाला। न्यायशास्त्र की सदियों पुरानी परिभाषा को बदलना होगा। अभी पूरी कानूनी प्रक्रिया अभियुक्त के हितों की रक्षा की ओर झुकी रहती है। ध्यान दें कि चर्चित निर्भया कांड के दोषियों की सजा पर अब तक अमल नहीं हो सका है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए कई वर्ष हो चुके हैं।

वास्तव में न्यायपालिका को प्रोएक्टिव होने की आवश्यकता है। अगर फूलन देवी जैसे लोग नरसंहार करने के बाद भी सांसद बनेंगे तो समाज में क्या संदेश जाएगा? 'जब तक सजा न मिले, व्यक्ति निर्दोष है' यह सिद्धांत भी विचारणीय है और खासकर जनप्रतिनिधियों के मामले में। जब सजा मिलते-मिलते कई दशक लग जाते हैं तो फिर इस सिद्धांत का क्या अर्थ रह जाता है? न्याय मिलने की भी एक समय सीमा होनी चाहिए। न्याय समयबद्ध हो। पूरी अपराधिक न्यायिक प्रक्रिया ने पुलिस को अविश्वसनीय मान लिया है, जबकि विवेचक ही केस की सच्चाई जानता है। कोई पुलिस वाला गलत गवाही दे या साक्ष्य पेश करे तो सख्त सजा दी जाए, लेकिन पूरी पुलिस को अविश्वसनीय मान लेना कहां तक उचित है? कानून एवं व्यवस्था के मामले में समग्रता से अत्यंत गहन विचार की आवश्यकता है। मुश्किल यह है कि जो विचार कर सकते हैं उनकी कोई सुनता नहीं और जिनकी सुनता है उनके पास समय नहीं। न्याय मिला या नहीं, इस पर वोट नहीं मिलता। व्यवस्था नियंत्रित हो, इस पर जरूर सरकार की छवि बनती अथवा बिगड़ती है। पुलिस को जनता और जनप्रतिनिधियों का दबाव झेलना ही पड़ेगा। उसे न्यायपालिका की तरह वैधानिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है। सारी समस्या का समाधान मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति में ही निहित है। जिन देशों ने कानून का राज कानून के दम पर स्थापित किया वे ही आज विकसित देश हैं। हमें भी वही राह पकड़नी होगी।

(लेखक उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे हैं)

response@jagran.com

बेरुखी का शिकार पर्यटन क्षेत्र

जीएन वाजपेयी

पर्यटन क्षेत्र में जीडीपी के पांच फीसद के बराबर योगदान की क्षमताएं हैं, पर उन्हें भुनाने के लिए जरूरी प्रयास नहीं हो रहे

कुछ दिन पहले कंबोडिया जाना हुआ। वहां सिएम रीप अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शानदार वेशभूषा वाले एक गाइड ने मेरा स्वागत किया। वह अंग्रेजी में भी पारंगत निकला। कंबोडिया के इतिहास, भूगोल, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं पर उसकी जानकारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। उससे भी अधिक उसके सभ्य व्यवहार ने मेरे मन को मोह लिया। अगले तीन दिनों तक मैंने इस मनमोहक पर्यटन स्थल के विभिन्न स्थानों का आनंद लिया। मुझे महसूस हुआ कि कंबोडिया ने टूरिस्ट गाइड के रूप में स्वरोजगार का एक सम्मानजनक पेशा विकसित किया है। सिएम रीप स्थित अंकोरवाट एक विशालकाय बौद्ध मंदिर परिसर है। उत्तरी कंबोडिया के इस हिस्से में मौजूद इस मंदिर का निर्माण बारहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में एक हिंदू मंदिर के रूप में हुआ था। वास्तुशिल्प के इस अप्रतिम केंद्र में हिंदू मान्यताओं से जुड़ी तस्वीरों की भरमार है। वास्तुशिल्प के ये डिजाइन निश्चित रूप से भारत से प्रेरित हैं। करीब चार सौ एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैले इस परिसर को दुनिया में सबसे बड़ा धार्मिक स्थल माना जाता है। हॉलीवुड की लोकप्रिय फिल्म 'टूंब राइडर' के कुछ दृश्यों की शूटिंग यहां हुई थी। इसके बाद दुनिया का ध्यान इसकी ओर आकृष्ट हुआ। अंकोरवाट को विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिला हुआ है। इस परिसर के संरक्षण को लेकर सबका ध्यान गया। मंदिर के कुछ हिस्सों का व्यापक जीर्णोद्धार होना है। इसके लिए वित्तीय संसाधन एवं तकनीक की दरकार है। भारत, चीन, जापान और जर्मनी जैसे देश इस मुहिम में मदद कर रहे हैं ताकि मंदिर के मूल स्वरूप और उसके वैभव को पुनर्स्थापित किया जा सके।

इसके उलट अगर भारत की तस्वीर देखें तो जब भारत सरकार ने कुछ पर्यटन केंद्रों के संरक्षण के लिए निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया तो इस पर खूब हंगामा किया गया। सरकार ने कुछ वर्षों के लिए लीज के आधार पर यह व्यवस्था की। इसका मकसद उन विरासत स्थलों की मदद के लिए निजी क्षेत्र को जोड़ना था, जो स्थल वक्त के थपेड़ों से अपनी आभा खो रहे थे और जिन्हें वास्तव में अच्छे रखरखाव की दरकार थी। तब कुछ एनजीओ और निहित स्वार्थी समूहों ने इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया मानों सरकार ने इन स्थलों को उन्हें उपहार में दे दिया या बेच दिया हो। अगर आज हंपी पर्यटन मानचित्र पर वापस उभरा है तो एक बड़ी हद तक इसका श्रेय जेएसडब्ल्यू स्टील के प्रवर्तक सज्जन जिंदल और संगीता जिंदल को जाता है। उन्होंने इसके लिए न केवल अपना समय और धन खर्च किया, बल्कि अपने संयंत्र की निजी हवाई पट्टी को वाणिज्यिक विमानों के लिए इस्तेमाल की अनुमति भी दी। इससे विजयनगर की प्राचीन राजधानी जीवंत हो उठी।

पर्यटन से होने वाले फायदों पर गौर किया जाना चाहिए। कंबोडियन न्यूज ने सिएम रीप के प्रांतीय पर्यटन विभाग के हवाले से जानकारी दी कि वर्ष 2018 के पहले नौ महीनों के दौरान सिएम रीप में 44,50,732 पर्यटक आए। इससे 4.375 अरब डॉलर की कमाई हुई। सिएम रीप एक छोटा शहर है जहां की आबादी बमुश्किल दो लाख है, लेकिन यहां बीस से अधिक पांच सितारा होटल हैं। यहां पर्यटन के जरिये सबसे अधिक रोजगार मिले हुए हैं। करीब 90 प्रतिशत आर्थिक गतिविधियां पर्यटन पर केंद्रित हैं। अंकोरवाट विदेशी पूंजी अर्जित करने वाला सबसे बड़ा माध्यम बन गया है। यह सिएम रीप और कंबोडिया की जीडीपी में अहम योगदान दे रहा है।

कंबोडिया में टूरिस्ट गाइड बनने के लिए लाइसेंस की दरकार होती है। यह लाइसेंस परीक्षा पास करने के बाद ही मिलता है। परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान आवेदक के ज्ञान के अलावा इतिहास, भूगोल, संस्कृति एवं पर्यटन स्थलों की सटीक जानकारियों को कसौटी पर कसा जाता है। किसी एक विदेशी भाषा में महारत भी अनिवार्य है। लाइसेंस हासिल होने के साथ ही यह सिलसिला पूरा नहीं होता। उसका नवीनीकरण भी कराना होता है। पर्यटकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने गाइड को रेटिंग दें। यह उनके मेहनताने को बढ़ाने में काम आती है। केवल सिएम रीप में ही सक्रिय दस हजार से अधिक टूरिस्ट गाइड आधा दर्जन से अधिक विदेशी भाषाओं में सिद्धहस्त हैं। ये स्वतंत्र पेशेवर हैं जो अपनी मर्जी से काम करते हैं। वे विभिन्न ट्रैवल एजेंसियों और टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन से जुड़े होते हैं जो उनसे संबंधित जानकारियां सहेजकर रखती हैं। इनमें उनकी रेटिंग का भी उल्लेख रहता है। एक सम्मानजनक जीवन के लिए ये गाइड पर्याप्त कमा लेते हैं। अधिकांश गाइड स्नातक हैं। उनके लिए एक यूनिफॉर्म भी है।

वहां पर्यटन स्थलों पर इंतजाम भी बहुत अच्छे हैं। टिकटों की कमाई में कोई सेंध न लगे, इसे रोकने के लिए टिकट पर्यटक की फोटो के साथ जारी किए जाते हैं। इसमें श्रेणी के हिसाब से ही शुल्क लिया जाता है जिसमें प्रवास की अवधि एक पैमाना होती है कि सैलानी को यह कितने दिन के लिए चाहिए। अमूमन एक से तीन दिनों के टिकट का चलन है। पर्यटक के हवाई अड्डे पर आगमन, परिवहन, आवास, खानपान, खरीदारी, मनोरंजन और सुरक्षा की पूरी प्रक्रिया बेहद पेशेवर है।

इसकी तुलना में यदि भारत को देखें तो उसका भौगोलिक आकार कंबोडिया के दस गुने से भी अधिक है। आबादी भी 75 गुना ज्यादा है और संभवतः कंबोडिया की तुलना में हजारों आकर्षक पर्यटन स्थल हैं। उनमें से कई तो अति प्राचीन हैं। इनके जरिये निश्चित रूप से लाखों पेशेवर गाइडों के रूप में स्वरोजगार के व्यापक अवसर सृजित किए जा सकते हैं।

भारत के पर्यटन क्षेत्र में जीडीपी के लगभग पांच प्रतिशत के बराबर योगदान की संभावनाएं हैं। इससे अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है तो लाखों-करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल सकता है। अफसोस की बात यही है कि इन अवसरों को भुनाने की दिशा में हमारी कोशिशें उतनी दमदार नहीं हैं। इनमें पर्यटन को एक उद्योग के रूप में विकसित करने का प्रयास नहीं होता। हमारे देश में पर्यटन को एक उद्योग बनाने की दिशा में कंबोडिया जरूर बड़ी सीख दे सकता है।

(लेखक सेबी और एलआइसी के पूर्व चेयरमैन हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

प्रभु-तरंग

संसार के लुभावने एवं आकर्षक दिखने वाले जीवनरूपी विविधरंगी तार तभी तक सुंदर और उपयोगी लग सकते हैं, जब तक उनमें ईश्वर रूपी करेंट मौजूद है। देह में प्रभुरूपी शिवत्व के अभाव में देह से व्युत्पन्न सभी आसक्तियां शव रूप में परिणत होकर जीव में विरक्ति के संसार का विस्तारण करती हैं। देवत्व से अनुराग के लिए भौतिकता से वैराग जरूरी है। भौतिकता की जड़ और चेतन में प्राण-प्रतिष्ठा का प्रवाह सुचारू रूप से तभी संभव है, जब ईश्वर रूपी पावर-हाउस से उनकी दयारूपी करुणादृष्टि का स्विच ऑन हो। इसके अभाव में उनमें प्राण रूपी संचार कदापि संभव नहीं है।

प्रभुकृपा के करेंट के बिना मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं के महान भवननुमा जीवन में खुशियों की दीपमालाएं नहीं जल सकतीं। जिस प्रकार केवल आकर्षक भवन एवं हवेली को तब तक घर नहीं कहा जा सकता, जब तक उसमें निवास करने वाला मानव प्रसन्न न हो। इसके विपरीत महज त्रिपालनुमा घर में भी प्रभुकृपा से खुशनुमा परिवार देखा जा सकता है। मनुष्य आभाषित आनंद के लिए कामनाओं के जितने पासे फेंकता रहता है, उतनी ही बार असली खुशियों की पूंजी से हाथ मलता महसूस करता जाता है। यदि वास्तविक आनंद केवल भौतिकता में होता तो एक अभीष्ट के बाद मनुष्य वांछित सुख के सरोवर में डूब स्वयं को विश्व का सबसे आनंदित एवं सौभाग्यशाली व्यक्ति घोषित कर चुका होता।

वस्तुतः भौतिकता के एक अभीष्ट की प्राप्ति, पुनः अनंत आकांक्षाओं के द्वार खोल देती है। ये असंख्य द्वार हर पिछले लक्ष्य को दोयम करार कर अगले कल्पित, श्रेष्ठ मुकाम की ओर अग्रसर होने के लिए उकसाते हैं। जीव का चंचल मन, किसी भी पायदान पर पहुंच, कहीं भी उस सुख को बटोर पाने में सक्षम नहीं हो पाता। यदि सुख भौतिक एवं मृत्युमय संसार में होते तो कोई भी व्यक्ति अभागा न महसूस करता। प्रभु-भक्ति के करेंट से तरंगायित संसार अथवा माध्यमों से ही शाश्वत सुख की प्राप्ति संभव है जो पश्चताप, दिग्भ्रम, अनित्य एवं नश्वरता जैसी अस्थिरताओं के भय से सर्वथा मुक्त हैं।

प्रो. दिनेश चमोला 'शैलेश'

बाजार, किताब और लेखक

अंशुमाली रस्तोगी

दिल्ली में हर साल लगने वाला पुस्तक मेला हमारे पढ़ने की भूख को जिंदा रखे रहने का एक खूबसूरत आयोजन है

किताबों और लेखकों, दोनों की दुनिया बदल चुकी है। आज हर किताब और हर लेखक का अपना बाजार है। इसी के सहारे वे अपने पाठकों तक पहुंच रहे हैं। इस बाजार को बनाने में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया की भी महत्ती भूमिका है। लेखक अब अपनी किताब खुद ही बेच रहा है। अपने फेसबुक पेज और ट्विटर खाते से अपनी किताबों का प्रचार-प्रसार कर रहा है। इसका फायदा लेखक को मिला है। ज्यादा से ज्यादा लोग उसे जानने एवं पढ़ने लगे हैं।

ऐसा भी नहीं है कि किताबें सिर्फ ऑनलाइन ही बिक रही हैं। ऑफलाइन भी किताबें बेची जा रही हैं। जब बिक रही हैं तो इसका मतलब लोग पढ़ रहे हैं। अक्सर यह ताना मार दिया जाता है कि लोग अब पढ़ते ही कहां हैं। मोबाइल ने पढ़ने की भूख छीन ली है, पर ऐसा नहीं है। जिन्हें पढ़ने का शौक है, वे आज भी पढ़ रहे हैं। चाहे इंटरनेट पर पढ़ें या किंडल पर, लेकिन पढ़ रहे हैं। खोज-खोजकर पढ़ रहे हैं। पढ़ने के लिए समय निकाल रहे हैं। दिल्ली में हर साल लगने वाला पुस्तक मेला दरअसल हमारे पढ़ने की भूख को जिंदा रखे रहने का एक खूबसूरत आयोजन है। किताबों के दीवाने मेले तक पहुंचते हैं, अपनी पसंद की किताबें खरीदते हैं। इस बहाने उनका उन लेखकों से भी मिलना हो जाता है, जिन्हें वे अब तक पढ़ते आए हैं। पुस्तक मेला भी बाजार में किताबों को स्थापित कर रहा है। यह बात अब हर कोई जान-समझ गया है कि बिना बाजार का सहारा लिए अपनी किताब को बेच पाना असंभव है। लिखा वह जा रहा है, जो बिके। लेखन अगर दिलचस्प होगा तो शर्तिया बिकेगा। श्रीलाल शुक्ल का क्लासिक 'राग दरबारी' इतने वर्ष गुजर जाने के बाद भी आज तक बिंदास बिक रहा है और खूब पढ़ा भी जा रहा है। प्रेमचंद और परसाई को भी पढ़ा जा रहा है।

अब तक इस बात का सेहरा अंगरेजी के लेखकों के सिर पर ही बांधा जाता था कि वे बड़ी खूबसूरती से बाजार में अपनी किताबें बेच लेते हैं। बाजार भी उन्हें हाथों-हाथ लेता है। विज्ञापन के सहारे भी वे अपनी किताब को बाजार और पाठकों के बीच लेकर आते हैं, पर अब हिंदी के लेखक भी खुद को बाजार से जोड़ रहे हैं। वे भी अपनी किताब का प्रमोशन कर रहे हैं। यह आवश्यक भी है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने लेखकों और पाठकों को और नजदीक लाया है। अब पाठक लेखकों की पढ़ी हुई किताबों पर अपनी राय रख सकता है। जबकि कुछ समय पहले तक यह इतना आसान न था। तब संवाद की प्रक्रिया काफी समय लेती थी। खत लिखे जाते थे। तब कहीं जाकर जवाब आता था, मगर अब लेखक और पाठक दोनों एक-दूसरे के करीब हैं।

पुस्तक मेला दिल्ली ही नहीं, बल्कि देश के दूसरे शहरों में भी निरंतर लगता रहना चाहिए। इससे लोगों के भीतर किताब को खरीदकर पढ़ने की आदत तो बनेगी ही, साथ-साथ किताबों की बाजार में मांग भी बढ़ेगी। यह समय बाजार का है। जिस लेखक ने खुद को बाजार के अनुरूप ढाल लिया फिर उसे 'हिट' होने से कोई नहीं रोक सकता।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

जेएनयू की हिंसा में किसका हाथ

दुश्मनी में बदलते वैचारिक मतभेद शीर्षक से लिखे अपने लेख में अवधेश कुमार ने जेएनयू के हिंसक टकराव की निंदा करते हुए इसके समाधान का जो रास्ता बताया है वह अपनी जगह ठीक है, लेकिन इससे दो विपरीत वैचारिक ध्रुवों के बीच पनपने वाली कड़वाहट कम हो पाएगी इसकी संभावना नहीं दिखती। जिन नकाबपोशों ने जेएनयू में हिंसक वारदात की वे कौन थे और किसके निर्देश पर कैंपस में दाखिल हुए थे। इनकी तस्वीरें कैंपस में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद जरूर हुई होंगी। अब ये निष्पक्ष जांच से ही पता लगेगा कि जेएनयू परिसर में हुए हिंसक उत्पात और अराजकता के पीछे किसका हाथ है, लेकिन किसी भी शिक्षण संस्थान में वैचारिक मतभेद को लेकर इस तरह की अराजकता और हिंसा को सही नहीं ठहराया जा सकता। इस दृष्टि से वैचारिक मतभेद से पनपी जेएनयू की हिंसक आग देश के अन्य विश्वविद्यालयों को अपने आगोश में ले, इससे पूर्व त्वरित जांच करके जेएनयू हिंसा के लिए जिम्मेदार नकाबपोश चेहरों को बेनकाब करना जरूरी है। ताकि देश-दुनिया के सामने यह सच्चाई आ सके कि आखिर जेएनयू की हिंसा में कौन से तत्व संलिप्त थे और इस निंदनीय कृत्य के पीछे उनका उद्देश्य क्या था।

pandeyvp1960@gmail.com

जनसंख्या नियंत्रण कानून की दरकार

मोदी सरकार पूरे एक्शन में है। दोबारा सत्ता में आने के बाद सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। जैसे अनुच्छेद 370 समाप्त करना, तीन तलाक, नागरिकता संशोधन विधेयक आदि। इस समय देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की बहुत जरूरत है। मोदी सरकार से उम्मीद है कि संसद के अगले अधिवेशन में यह कानून संसद में रखा जाए। मौजूदा समय में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बनी हुई है, जिसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अभी भारत जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर है। अगर जल्द ही इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो पहले नंबर पर पहुंच जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनने से देश समाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत होगा। इसलिए भारत सरकार से प्रार्थना है कि वह जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाए ताकि देश के विकास का रास्ता खुल सके।

विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

नई राजनीति की शुरुआत

यह पत्र 'काम के आधार पर हमें चुनेगी जनता : केजरीवाल' के संदर्भ में है। दिल्ली में चुनाव की घोषणा के बाद जो दो-तीन बातें उभर कर सामने आती हैं। वह हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सकारात्मक बयान। उनका यह कहना कि अगर मैंने आपके लिए पिछले 5 सालों में काम किया है तो ही मुझे वोट दें अन्यथा नहीं। मैं नकारात्मक चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर कांग्रेस या भाजपा के घोषणा पत्र में भी कुछ अच्छा लगा तो पार्टी उसे अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई राजनेता चुनाव से पहले इस तरह की बात करे। आमतौर पर चुनाव प्रचार के दौरान राजनेता अपने स्तर से गिरकर शर्मनाक बयान तक दे देते हैं। ऐसे में केजरीवाल के बयान ने राजनीति में एक नई परिपाटी को जन्म दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पांच साल पहले दिल्ली की जनता से बहुत सारे वादे किए थे, उनमे से कुछ तो पूरे हुए, लेकिन बहुत कुछ अभी भी बाकी है। अब जनता पर निर्भर है कि वह उनको एक और मौका देना चाहती है या नहीं। भाजपा के सामने सबसे बड़ी दिक्कत दिल्ली में केजरीवाल के बराबर का कोई नेता न होना है। जहां तक कांग्रेस की बात है तो वह शीला दीक्षित के जाने के बाद बिल्कुल अनाथ प्रतीत हो रही है।

बाल गोविंद, नोएडा

ओछी मानसिकता का परिचायक

जेएनयू में जो हिंसा हुई है वह चिंताजनक है। चाहे जेएनयू हो जामिया या अलीगढ़ विश्वविद्यालय। यहां से पढ़ाई कर बच्चे पुलिस अधिकारी, राजनेता, विचारक, कवि व लेखक बनते हैं, लेकिन हिंसक कभी नहीं। यहां सभी धर्म, जाति वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसा लगता है यहां के बच्चों की साफगोई कुछ लोगों को रास नहीं आ रही। तभी तो सुनियोजित षड्यंत्र कर इन विश्वविद्यालयों को बदनाम करने की परिपाटी चल रही है, जो बहुत ही ओछी मानसिकता का परिचायक है।

hemahariupadhyay@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संप

2030 तक भारत को बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 4.5 ट्रिलियन डॉलर के निवेश की जरूरत होगी।

आजकल

चेहरे की पहचान से बेनकाब होंगी साजिशें

अभिषेक कुमार सिंह
संस्था एफआइएस ग्लोबल से संबद्ध

दो दिसंबर, 2019 को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल होने आए लोगों के चेहरों को फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक के इस्तेमाल से स्कैन किया गया। दरअसल इस तकनीक के बल पर जहां कानून-व्यवस्था बनाना आसान हो जाता है, वहीं किसी बड़े आयोजन में संलग्न पुलिस की मुश्किलें भी कम हो जाती हैं। यह भरोसा भी जगता है कि यदि कोई तत्व आयोजन में गड़बड़ी की कोशिश करता है तो उसे आसानी से पकड़ा जा सकता है

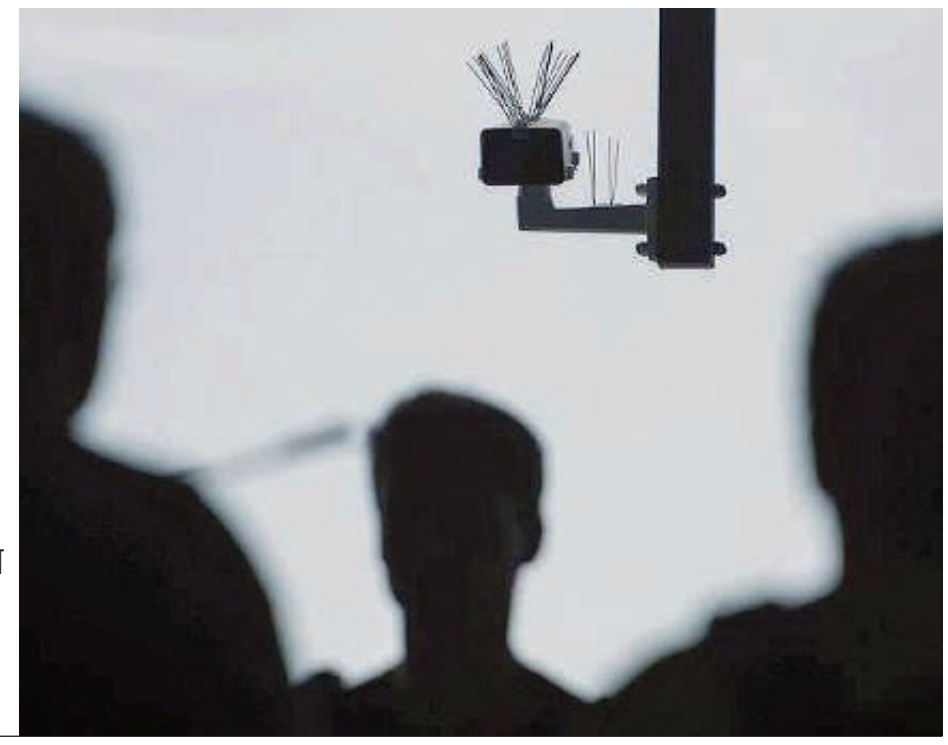

देश में शायद यह पहला मौका था, जब गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस परेड से अलग किसी प्रधानमंत्री की रैली में सुरक्षा कायम रखने के नजरिये से आधुनिक तकनीक फेशियल रिकॉग्निशन का इस्तेमाल किया गया। दावा किया गया है कि दो दिसंबर, 2019 को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल होने आए लोगों के चेहरों को फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक के इस्तेमाल से स्कैन किया गया। स्कैनिंग से मिले चेहरों का मिलान दिल्ली पुलिस ने अलग-अलग विरोध प्रदर्शनों के दौरान बनाए गए वीडियो में दर्ज हुए चेहरों से किया। इस तकनीक के इस्तेमाल का उद्देश्य रैली में मौजूद लोगों में से ऐसे तत्वों की पहचान करना था जो पहले किसी मामले में संदिग्ध रह चुके हों। 'कानून तोड़ सकने वाला कोई संदिग्ध' रैली में नहीं आए, यह सुनिश्चित करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन के इस पहले बड़े प्रयोग ने साफ कर दिया है कि तकनीक के बल पर जहां कानून-व्यवस्था बनाना आसान हो जाता है, वहीं किसी बड़े आयोजन में संलग्न पुलिस-प्रशासन की मुश्किलें भी कम हो जाती हैं। साथ ही यह भरोसा भी जगता है कि यदि कोई तत्व आयोजन में गड़बड़ी की कोशिश करता है तो पहचान कर उसे आसानी से पकड़ा जा सकता है और उसे सजा दी जा सकती है।

उल्लेखनीय है कि फेशियल रिकॉग्निशन का सॉफ्टवेयर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रिकॉर्ड में मौजूद तस्वीरों का मिलान करके गुमशुदा बच्चों की खोजबीन के उद्देश्य से खरीदा था, लेकिन यह तकनीक कानून तोड़ने वाले शरारती तत्वों पर नजर रखने और उनकी धरपकड़ में भी कारगर साबित हो सकती है। इसका अंदाजा दिल्ली में दो बार स्वतंत्रता दिवस परेड और एक बार गणतंत्र दिवस परेड में प्रायोगिक इस्तेमाल के रूप में हो गया था। देश भर के संवेदनशील इलाकों में विरोध प्रदर्शनों के दौरान भी इस तकनीक को आजमाया जा सकता है। इस पर बढ़ते विश्वास के कारण ही राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने 'ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम' (एएफआरएस) के लिए कुछ समय पहले एक टेंडर जारी किया था। एएफआरएस तकनीक से चेहरों को सटीक तरीके से पहचाना जा सकेगा और इसके प्रयोग से अपराध की रोकथाम और गुमशुदा लोगों की खोजबीन के काम में सहूलियत हो जाएगी। यह भी कहा गया है कि इस तकनीक में सीसीटीवी फीड से प्राप्त डाटा का इस्तेमाल होगा और उसका मिलान पासपोर्ट के आंकड़ों और विभिन्न मंत्रालयों में मौजूद डाटाबेस में दर्ज सूचनाओं से किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक का इस्तेमाल भारत में ही किया जा रहा है। पड़ोसी चीन में तो हाल में यह नियम बनाया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को मोबाइल के लिए किसी नेटवर्क का सिम लेना है तो इसके लिए उसे अपना चेहरा इसी तकनीक से स्कैन कराना होगा। इसका मकसद यह बताया जा रहा है कि इससे वहां की सरकार देश के करोड़ों इंटरनेट यूजर्स की पहचान से जुड़ा डाटा संभालकर रख पाएगी।

मकसद अधिकारों की सुरक्षा करना : असल में चीन की सरकार कह रही है कि फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक से चेहरे की स्कैनिंग का एक बड़ा उद्देश्य लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करना है, लेकिन साइबर दुनिया में ऐसी सरकारी ताकझांक ने चीन में विवाद पैदा कर दिया है। सिम कार्ड के बहाने चेहरे की स्कैनिंग कर हासिल किए जाने वाली जानकारी का इस्तेमाल दुकानों, सुपरमार्केट में खरीदारी के वक्त से लेकर टिकट बुकिंग आदि के लिए भी किया जा रहा है, जिससे लोगों में यह भ्रम पैदा हुआ है कि कहीं इससे जुटाए गए डाटा का इस्तेमाल चीन की सरकार आम लोगों पर निरंतर नजर रखने में तो नहीं करेगी। इस आशंका का एक संकेत नवंबर, 2019 में तब मिला, जब वहां के एक प्रोफेसर ने चीन के हांगझाऊ स्थित उद्यान पर इसके लिए मुकदमा दायर किया था कि उसने पार्क में भ्रमण के लिए जाने वाले लोगों के चेहरे की पहचान अनिवार्य कर दी थी। सितंबर में जब चीन ने एलान किया था कि देश में चेहरे की पहचान की तकनीक (फेशियल रिकॉग्निशन) को नियमित किया जाएगा तो इससे पहले वहां की एक यूनिवर्सिटी के बारे में खबरें आई थीं कि वहां छात्रों के व्यवहार और उपस्थिति की निगरानी के लिए चेहरा पहचानने की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। बाद में कहा गया कि चूंकि चीनी सरकार जुटाए गए डाटा की चोरी संभाल नहीं पा रही है, इसलिए हैकिंग और लोगों के उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं।

विवाद भी उठे चेहरों की जांच पर : गत वर्ष न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीन के पश्चिमी इलाके शिनजियांग में लाखों उइगर मुस्लिमों को हिरासत में लिए जाने के पीछे उनके चेहरे की पड़ताल वाली तकनीक का हाथ था। वैसे चीन को तो अपने नागरिकों की हर किस्म की पहचान सतत दर्ज करते रहने वाले मुल्क के रूप में अरसे से जाना जाता रहा है। वहां काफी समय से फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक का इस्तेमाल जनगणना के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा वहां सड़कों, रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट, सार्वजनिक जगहों, मॉल आदि में करोड़ों सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। एक आंकड़े के मुताबिक चीन में 2017 तक 17 करोड़ अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके थे और वर्ष 2020 के अंत तक चीन के चप्पे-चप्पे पर करीब 40 करोड़ सीसीटीवी कैमरे नजर रख रहे थे। सिर्फ चेहरा और अन्य बायोमीट्रिक पहचानों के अलावा हरेक चीनी नागरिक के आचरण और सार्वजनिक बातचीत को एक डाटाबेस में दर्ज किया जा रहा है। चीनी सरकार के मुताबिक जिसका उद्देश्य सरकारी 'सोशल क्रेडिट' सिस्टम को अपडेट करना है।

क्या अपराध रुकेंगे इस पहचान से : इस तकनीक को भी सवालों से बरी नहीं किया जा सकता है। भारत में तो अभी इसकी शुरुआत है, पर अमेरिका से लेकर चीन तक में इसका व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। वहां नागरिकों कआपत्तियों के बावजूद सरकारें इसे इस तर्क के साथ लागू कर रही हैं कि इससे अपराधों की रोकथाम में मदद मिलती है। जैसे एक दावा चीन का है कि वर्ष 2018 में फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक से 60 हजार की भीड़ वाले एक कंसर्ट के बीच में एक भगोड़े को पुलिस ने खोजकर पकड़ लिया था। यूं तो इंटरनेट जालसाजी और साइबर बुलिंग से तंग लोगों को तकनीकी सुरक्षा के ये उपाय कारगर प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन इन्हें लेकर लोगों का पहला एतराज यही है कि यह तकनीक और इनके कड़े कायदे जनता की सहमति के बगैर लागू किए गए हैं। जहां तक इंटरनेट की निगरानी और उसके कंट्रोल का सवाल है तो चीन लंबे समय से ऐसी सारी सामग्री सेंसर करता रहा है जिससे सरकार को कोई समस्या हो या उसमें चीन की नीतियों की आलोचना की गई हो। हालांकि चेहरे और निजी जानकारियों तक सरकारी पहुंच के मामले में लोगों के मन में एक डर भी है। चूंकि चीन में भी डाटा लीकेज की समस्या कायम है। इस वजह से लोगों के पास अनजान लोगों के काफी फोन आते हैं जिन्हें उनके बारे में सब कुछ पहले से मालूम रहता है। यानी समस्या फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक नहीं, दूसरे साइबर फर्जीवाड़े हैं। साफ है कि फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक आम नागरिकों से लेकर खास हस्तियों की सुरक्षा चाकचौबंद करती है और अपराध के मंसूबों पर पानी फेरती है।

कहां से आई फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक

यूं तो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम एक अत्याधुनिक तकनीक है, लेकिन इसकी नींव कई दशक पहले अमेरिका में रखी गई थी। फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक के आविष्कार में अमेरिकी वैज्ञानिकों वूडी ब्लेडसोए, हेलेन चान वूल्फ और चार्ल्स बाइसन की अहम भूमिका है, जिन्होंने एक इंटेलिजेंस एजेंसी से मिले फंड के आधार पर इस तकनीक पर काम शुरू किया था। आरंभ में ब्लेडसोए ने कंप्यूटरों के जाल की मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने वाले लोगों के चेहरे (खासतौर से आंखों और मुंह) पर नजर रखना शुरू किया। अलग-अलग स्थानों पर स्थापित कंप्यूटरीकृत सिस्टम स्वचालित ढंग से ये पहचानें दर्ज करता था। दशकों के अनुसंधान और लगातार प्रयोगों के बाद वर्ष 2006 में यह स्थिति आई, जब हाई रेजोल्यूशन फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक विकसित रूप में सामने आई। इसमें चेहरे की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरों, चेहरे के थ्री-डी स्कैन और आंखों की पुतलियों (आइरिस) को मिलाकर किसी व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित की जा सकती थी। यह सिस्टम इतना दक्ष है कि इससे एक जैसे दिखने वाले जुड़वां लोगों की अलग-अलग पहचान की जा सकती है। बहरहाल आज चेहरा पहचानने वाली यह तकनीक डिजिटल तस्वीरों और वीडियो इमेज से बायोमीट्रिक तथ्यों का मिलान करते हुए हजारों लोगों के बीच में एक व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित कर सकती है। इस तकनीक को बायोमीट्रिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है।

तकनीक से हिंसा पर लगाम की कोशिश

बायोमीट्रिक इंटेलिजेंस और फेशियल रिकॉग्निशन जैसे तकनीकी इंतजाम नए अवश्य हैं, पर सुरक्षा के स्तर पर पैदा हुई चुनौतियों के मद्देनजर देश ने सीखा है कि कैसे नए जमाने की तकनीक की मदद से संबंधित दिक्कतों का हल ढूंढा जा सकता है। सीसीटीवी कैमरों के संजाल और संवेदनशील इलाकों में ड्रोन की तैनाती ऐसे ही कुछ उपायों में हैं। जहां तक ड्रोन यानी मानवरहित विमानों की मदद से उत्पात मचाने वाले शरारती तत्वों और भीड़ पर काबू पाने की बात है तो देश में कई स्थानों पर ये उपाय आजमाए जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली में ही शरारती तत्वों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा चुका है। हाल में दिल्ली के सीलमपुर इलाके में भी ड्रोन तैनात किए गए थे। दिल्ली में ड्रोन का पहली बार प्रयोग वर्ष 2014 में छठ पूजा के दौरान भीड़ की निगरानी के लिए किया गया था। फिर जब अक्टूबर-नवंबर 2014 में यहां के त्रिलोकपुरी में माहौल कुछ बिगड़ा तो पुलिस ने पूरे इलाके की निगरानी के लिए चार-पांच ड्रोन आकाश में तैनात कर दिए थे। इसी तरह साल 2016 की शुरुआत में हुए जाट आंदोलन के दौरान बेकाबू हुए हालात के लिए किरकिरी झेल चुकी हरियाणा सरकार ने उसी वर्ष आंदोलनों की निगरानी करने के मकसद से पुलिस-प्रशासन को ड्रोन से लैस कर दिया, ताकि भीड़ जमा होने पर आंदोलनकारियों की आसमान से तस्वीरें ली जा सकें और जरूरत पड़ने पर उन्हें सुबूत के रूप में पेश किया जा सके। ऐसे ज्यादातर ड्रोन पुलिस ने कंपनियों से किराए पर लिए थे। दो मीटर लंबे, एक मीटर चौड़े और करीब दो किलोग्राम वजन के इन मानवरहित विमानों ने अपने कैमरों से पूरे इलाके की नजदीक से छानबीन की और वे तस्वीरें-वीडियो पुलिस कंट्रोल रूम में हाथों-हाथ पहुंचाईं। इससे पुलिस को शरारती तत्वों पर काबू पाने में काफी मदद मिली।

खरी-खरी

नन्हे-मुन्ने बच्चे की करुण पुकार

अरुण अर्णव खरे

दूर कहीं एक गाना बज रहा था-नन्हे-मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या...? जाहिर है, इसमें बच्चे से एक सवाल पूछा जा रहा है। इस पर बच्चा क्या जवाब देगा? दूसरे बच्चों का तो पता नहीं, लेकिन इस गाने को सुनकर सरकारी अस्पताल में भर्ती एक बच्चे के मुंह से बेसुधी की स्थिति में बस यही निकला-चंद सांसें! ये शब्द सुनकर पैर थम गए, मन भारी हो गया, हृदय के भीतर कुछ रिसता-सा महसूस हुआ। सोचने लगा-आखिर क्यों पड़ते हैं गरीब के बच्चे बीमार असमय मरने के लिए? क्या उन्हें पता नहीं है कि इस संवेदनहीन व्यवस्था में उनकी उखड़ती सांसों को पूरी तरह उखाड़ फेंकने की पूरी-पूरी व्यवस्था की गई है? उनकी मौत किसी को झकझोरेगी नहीं, अपितु एक आंकड़े के रूप में कागजों में दर्ज हो जाएगी। जब जरूरत होगी तो व्यवस्था उन कागजों को हाथ में लहराते हुए बताएगी कि गत वर्ष इन्हीं महीनों में 101 बच्चों की मौत हुई थी, जबकि इस साल यह आंकड़ा मात्र 99 है। पिछले एक साल में स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार किए गए सुधार से इस वर्ष शिशु मृत्युदर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज हुई है। अगले साल यह आंकड़ा और भी नीचे लाने के प्रयास किए जाएंगे।

यदि ज्यादा बवाल मचा तो मजिस्ट्रीयल जांच के आदेश हो जाएंगे। अव्वल तो इस जांच की रिपोर्ट आएगी नहीं और यदि आ भी गई तो उसी निर्धारित फॉर्मेट में आएगी, जिसमें पहले भी अनेक प्रांतों से सैकड़ों रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। वह यह नहीं बताएगी कि अस्पताल में उपलब्ध उपकरणों और स्टाफ की स्थिति क्या है? उस बच्चे के शब्दों से व्यथित हुए हृदय के साथ उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा-ऐसा नहीं कहते बेटा! तुम देश का भविष्य हो। वह अर्द्धमूर्छा में फिर बुदबुदाया-भविष्य? यहां से बच भी गया तो कोई दरिंदा शोषण करके गला घोंट देगा या कोई हमें बेचने के लिए अपहरण कर ले जाएगा या फिर छिपकली गिरने से जहरीला हुआ मिड-डे मील खाकर फिर यहीं आ जाऊंगा। हमें भविष्य मानता कौन है? हम तो एक आंकड़ा भर हैं, जिंदा रहने के साथ भी और जिंदा रहने के बाद भी। निरुत्तर कर दिया था उसने। लगातार सोच में पड़ा हूं। पर अभी तक कोई उत्तर नहीं मिल सका है, जो उसे दे सकूं।

ट्वीट-ट्वीट

निर्भया की मां के जीवट की भी दाद देनी होगी। उन्होंने कहां से इतनी हिम्मत जुटाई? अब दोषियों को फांसी की तारीख सुनाने वाली न्यायपालिका को उन्होंने धन्यवाद दिया है। कल्पना कर सकते हैं कि कोई भी शख्स कानूनी प्रक्रिया को लेकर चिड़चिड़ा हो जाता। उन्हें अदालत में बार-बार वह व्यथा याद करनी पड़ी होगी।
स्मिता प्रकाश@smitaprakash

हम सभी एक ही तरह से पैदा होते हैं और वैसे ही मरते हैं। भौतिक, मानसिक एवं भावनात्मक रूप से हम एक जैसे ही हैं। सभी समस्याओं से मुक्त एक खुशमिजाज जिंदगी चाहते हैं, लेकिन भौतिकतावाद में हम प्रेम और अनुराग के महत्व की अक्सर अनदेखी कर देते हैं। दलाई लामा@DalaiLama

क्या कहा था और क्या हो गया! वर्ष 2014 : अच्छे दिन आने वाले हैं। वर्ष 2020 : आर्थिक वृद्धि 11 साल में सबसे कम। भारत सरकार ने आज आंकड़े जारी किए हैं कि 2019-20 में जीडीपी ग्रोथ पांच प्रतिशत रहेगी जो 2018-19 में 6.8 प्रतिशत थी।
मिलिंद खांडेकर@milindkhandekar

छत्तीसगढ़ डायरी

कांग्रेस की चाल से गच्चा खा गई भाजपा

आलोक मिश्रा
राज्य संपादक
नईदुनिया, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में भाजपा के बुरे दिन जारी हैं। बीच में मोदी चुनाव (लोकसभा चुनाव) बाद जो गाड़ी पटरी पर आती दिख रही थी, वह निकाय चुनाव में पूरी तरह उतर गई। यह बाजी कांग्रेस ने अपनी सरकारी हनक की बदौलत कायदे से जीत ली। भाजपा अब पंचायत चुनावों के भरोसे है कि शायद वहां धान कोई गुल खिलाए और किसान उसका नसीब बदलवाएं, लेकिन किसानों के बूते सत्ता में आई भूपेश सरकार उसमें भी धोबीपाट की तैयारी किए बैठी है।

पद्रंह साल छत्तीसगढ़ की राजनीति में पूरी तरह छाई रही भाजपा के लिए पिछला एक साल बहुत बुरा बीता। सूबे की सत्ता गंवाई, बीच में हुए दो विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में पिटी और उसके बाद निकाय चुनाव भारी पड़ा। बीच में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे जरूर उसके पक्ष में आए, लेकिन इसका श्रेय मोदी करिश्मे को ही मिला। स्थानीय नेतृत्व की चर्चा तक नहीं हुई। भाजपा आस लगाए थी कि 10 नगर निगमों एवं 151 नगरीय निकायों के चुनाव में शायद वह कांग्रेस के एक साल के कार्यकाल को मुद्दा बना अपने दिन ठीक कर लेगी, लेकिन भूपेश सरकार ने ऐसे पत्ते फेटे कि बाजी उसी के हाथ रही। उसने ईवीएम के बजाय बैलेट से चुनाव करवाया और मेयर एवं अध्यक्ष को जनता से न चुनवा कर पार्षदों से चुनवाया। लिहाजा अब तक दस निगमों में से आठ में हुए चुनाव में भाजपा का एक भी मेयर नहीं बन पाया। इन आठ निगमों में पहले कांग्रेस के पास केवल रायपुर एवं जगदलपुर में ही अपना मेयर था, जबकि चार में भाजपा एवं दो में निर्दलियों का कब्जा था। इसमें इजाफा करना तो दूर वह अपने सभी गढ़ गंवा बैठी। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के क्षेत्र राजनांदगांव में तो भाजपा अपने पार्षदों तक को नहीं संभाल पाई। उसके 21 जीते, लेकिन वोट 20 ही मिले। अब बचे दो निगमों में उसे केवल कोरबा से ही आस है, जहां वह अपनी इज्जत बचा सकती है। जबकि अंबिकापुर किसी भी हालत में उसके हाथ नहीं आने वाला।

निकाय चुनाव में जीत का जश्न मनाते कांग्रेसी।

अब विधानसभा, लोकसभा के बाद के इस आखिरी राउंड के दूसरे चरण यानी पंचायत चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। भाजपा फिर एक बार जोर-आजमाइश में है। वह इस फिराक में है कि जो किसान उसे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के धान समर्थन मूल्य बढ़ाने के दांव के कारण गच्चा दे चुके थे, उन्हें अपने पाले में ले आए। क्योंकि 2500 रुपये समर्थन मूल्य देने में भूपेश सरकार के सामने केंद्र रोड़ा बना हुआ है। खरीदी 1835 में ही हो रही है। बाकी रकम के लिए आश्वासन जारी है कि कमेटी तय करेगी कि किस तरह इसे दिया जाए। बढ़े समर्थन मूल्य के कारण बढ़ा धान का कोटा भी सरकार के लिए संकट बना हुआ है। हालांकि केंद्र ने अपने कोटे में 24 लाख मीट्रिक चावल लेने की सहमति देकर उसका कुछ बोझ हल्का कर दिया है, लेकिन फिर भी 8 लाख टन और लेने की मांग पर वह अड़ी है। इधर खराब मौसम एवं खरीदी के तरह-तरह के नियम किसानों को परेशान किए हैं। वह किसानों के बीच यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उन्हें मूर्ख बनाया जा रहा है। वह मोदी सरकार की किसान सम्मान निधि का हवाला दे खुद को उनका सबसे बड़ा शुभचिंतक ठहराने का प्रयास कर रही है। अब देखना यह होगा कि वह इसमें कितना सफल हो पाती है या भूपेश सरकार फिर बाजी मार ले जाती है, क्योंकि केंद्र पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस किसानों से ही 17 लाख पाती केंद्र को लिखवा कर खुद को किसानों का सच्चा हिमायती बताने का दांव चल चुकी है।

आदिवासी नृत्य महोत्सव की धूम : आदिवासी और किसान, यही दोनों हैं सूबे में कांग्रेस की जान। किसानों के लिए तो वह तरह-तरह के प्रयोग कर ही रही है, वहीं इस बार उसने राष्ट्रीय स्तर का आदिवासी नृत्य महोत्सव करवा कर उनसे भावनात्मक रिश्ता जोड़ने की कोशिश की। इसके लिए उसने ब्रांडिंग भी खूब की। हर प्रदेश में उसके नेता जाकर वहां के मुख्यमंत्रियों एवं राज्यपालों को न्योता देकर आए। इसमें छह देशों और 25 राज्यों के करीब 18 सौ कलाकार जुटे। इतनी बड़ी जुटान की कल्पना खुद भूपेश को भी नहीं थी, लिहाजा परिणाम देख इसे आगे भी जारी रखने का वादा भी कर दिया गया। बहरहाल सरकार के एक साल पूरे हो चुके हैं। इनमें इसी तरह के महोत्सव एवं त्योहारों का ही जोर रहा। बीच-बीच में चुनावी शोर उठते रहे। इन्हीं गतिविधियों के बीच सरकार ने अपने एक साल काट दिए हैं। अब आगे की डगर उसके लिए भी आसान नहीं रहने वाली, जब उसके सामने विकास को लेकर सवाल खड़े किए जाएंगे।

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या टेस्ट मैचों की अवधि को घटाकर चार दिन किया जाना चाहिए?

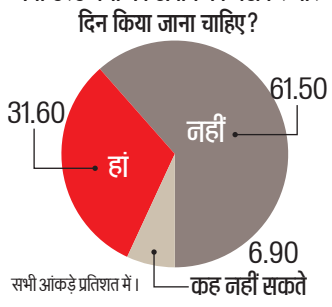

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या निर्भया के दोषियों को फांसी देने से अपराधियों के मन में डर बैठेगा?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

शैतानों को अंतत : मिली सजा-ए-मौत,
अब दोजख की राह से नहीं सकेंगे लौट।
नहीं सकेंगे लौट भुगतनी होगी करनी,
हल्की होगी बंधु पापियों से कुछ धरणी।
कुदरत का कानून सही है अब तो मानो,
देख सजा-ए-मौत जरा सुधरो शैतानों।
- ओमप्रकाश तिवारी

यथार्थ

योजना दमदार मगर चुनौतियां अपार

प्रणव सिरोही
pranav.sirohi@nda.jagran.com

बुनियादी ढांचे पर 102 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की सरकारी योजना बहुत शानदार है, लेकिन उसकी राह में चुनौतियां भी कम नहीं। यदि इनसे पार लिया गया तो अर्थव्यवस्था की कायापलट होना तय है

एक ऐसे दौर में जब अर्थव्यवस्था सुस्ती की शिकार है तब सरकार द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे पर अगले पांच वर्षों के दौरान 102 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की योजना किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं। नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन यानी एनआइपी पर गठित कार्यबल की रिपोर्ट पर सरकार ने यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। इसमें संदेह नहीं कि यह कदम अर्थव्यवस्था को तेजी देने का काम करेगा, परंतु इसे मूर्त रूप देने की राह में तमाम चुनौतियां भी हैं।

इसके तहत अगले पांच वर्षों के दौरान निवेश के लिए जो लक्ष्य तय किया है वह बीते छह वर्षों के दौरान बुनियादी ढांचे पर निवेश हुए 51 लाख करोड़ रुपये के दोगुने से भी अधिक है। प्रस्तावित योजना में केंद्र और राज्य सरकारों को 39-39 प्रतिशत तो शेष 22 प्रतिशत निवेश निजी क्षेत्र को करना होगा। इसके लिए ऊर्जा, सड़क निर्माण, रेलवे, शहरी विकास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों को चिन्हित किया है। हालांकि इन योजनाओं में से 42 प्रतिशत पर अमल शुरू भी हो चुका है, वहीं 19 प्रतिशत का खाका तैयार है जबकि 31 प्रतिशत योजनाओं की अभी तक संकल्पना ही सामने आई है। जहां तक इससे होने वाले फायदों की बात है तो यह किसी से छिपा नहीं है कि देश का बुनियादी ढांचा अभी उस स्थिति में नहीं जो आर्थिक संभावनाओं को पूरी तरह भुनाने में मददगार हो सके। एक अनुमान के तहत वर्ष 2030 तक भारत को बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 4.5 ट्रिलियन डॉलर के निवेश की जरूरत होगी। इस कड़ी में सरकार की यह कोशिश न केवल कई क्षेत्रों को व्यापक लाभ पहुंचाएगी, बल्कि इससे मांग को भी सहारा मिलेगा। जैसे स्टील एवं सीमेंट जैसे बुनियादी उद्योगों में मांग जोर पकड़ेगी तो कुशल एवं अकुशल श्रमिकों के लिए भी रोजगार के तमाम अवसर सृजित होंगे। यानी तय है कि सरकार की यह पहल कई तरह से फलदायी होने जा रही है।

फिर भी मौजूदा माहौल में इसे सिरे चढ़ाना टेढ़ी खीर मालूम पड़ता है। इसकी तमाम वजह हैं। सबसे पहली तो वित्तीय संसाधन जुटाने की है। इसमें केंद्र और राज्यों को मिलकर 78 प्रतिशत अंशदान करना है। फिलहाल कायम सुस्ती के कारण सरकारी कर संग्रह दबाव में है। वहीं निजी क्षेत्र पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबा है। सुस्त मांग को देखते हुए वह भविष्य में निवेश को लेकर सशंकित भी है। यदि निजी क्षेत्र निवेश के लिए तत्परता दिखाए भी तब क्या फंसे कर्जों से त्रस्त बैंक इन परियोजनाओं के लिए कर्ज उपलब्ध कराने के लिए तैयार होंगे। यह सवाल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के स्वरूप को देखते हुए और मौजूं है, क्योंकि ये अमूमन लंबी अवधि में पूरी होती हैं तो प्रतिफल भी देर से मिलना शुरू होता है। यदि किसी तरह टल जाएं तो उनकी लागत भी लगातार बढ़ती जाती है। ऐसे में चाहे निजी निवेशक हो या ऋणदाता बैंक, कोई भी अपनी मुश्किलें बढ़ाना नहीं चाहेगा। यहां यह भी याद दिलाना होगा कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी एनबीएफसी के हालात बिगाड़ने में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को एक बड़ी हद तक जिम्मेदार माना गया।

मुश्किलें आर्थिक ही नहीं, सियासी मोर्चे पर भी हैं। बदलते राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए परियोजनाओं पर सहमति बनाना आसान नहीं होगा। इसके संकेत जीएसटी परिषद की पिछली बैठक में दिखे भी जहां पहली बार मतदान की नौबत आई। कई राज्यों में सरकारें बदलने से नीतिगत अनियमितता भी ऐसी परियोजनाओं की राह अटकाएगी। जैसे मोदी सरकार की बुलेट ट्रेन परियोजना पर महाराष्ट्र में सरकार बदलते ही संकट के बादल मंडराने लगे। आंध्र की नई राजधानी अमरावती को लेकर भी जगन सरकार फैसले पलट रही है। यह निवेशकों के लिए अच्छे संकेत नहीं जो इन परियोजनाओं पर दांव लगाना चाहेंगे।

चूंकि यह केंद्र की पहल है तो इसकी राह में आने वाली बाधाएं दूर करने का बीड़ा भी उसे ही उठाना होगा। इसके लिए जरूरी है कि केंद्र अपना खर्च बढ़ाए। अभी कुल सरकारी व्यय में बुनियादी ढांचे पर 0.83 फीसद खर्च हो रहा है। वहीं कर राजस्व में अपेक्षित वृद्धि न होने पर सरकार चाहे तो अपनी परिसंपत्तियों का मॉनिटाइजेशन यानी उन्हें भुनाकर या वास्तविक रूप से विनिवेश की गाड़ी आगे बढ़ाकर इस खर्च के लिए बंदोबस्त कर सकती है।

इसके अलावा राज्यों को भरोसे में लेकर उनके साथ व्यावहारिक परियोजनाओं पर आगे बढ़ने की राह केंद्र को तलाशनी होगी। निजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए भी अनुकूल परिवेश बनाना होगा। इसके लिए विशेष उद्देश्य इकाई यानी एसपीवी के गठन का विकल्प भी उचित होगा। परियोजनाओं की नियमित रूप से निगरानी, समीक्षा और आवश्यक हस्तक्षेप भी उतना ही जरूरी होगा। सरकार को सिंगल विंडो क्लीयरेंस की व्यवस्था भी करनी होगी, क्योंकि कई परियोजनाओं को लेकर कुछ मंत्रालयों या विभागों में ही गतिरोध पैदा हो सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के पीएमओ को कमान खुद अपने हाथ में लेनी होगी ताकि सही तालमेल सुनिश्चित हो। इस मामले में मोदी सरकार चाहे तो पूर्ववर्ती मनमोहन सरकार से दो सबक ले सकती है। पहला तो यही कि मनमोहन सरकार जब नीतिगत जड़ता के आरोपों से परेशान हो गई तो उसने बुनियादी ढांचे की कुछ अटकी हुई परियोजनाओं की बाधाएं दूर करने का जिम्मा प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव पुलक चटर्जी की अगुआई वाली एक समिति को सौंप दिया। दूसरा सबक यही हो सकता है कि संप्रग सरकार ने यह कदम उठाने में इतनी देर कर दी कि उसका मनवांछित लाभ नहीं मिल सका। इससे सीख लेते हुए मोदी सरकार यह अवश्य विचार करे कि उसकी यह योजना भले ही कितनी अच्छी और भली मंशा वाली हो, लेकिन उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि कोई योजना तभी सफल हो सकती है जब उस पर क्रियान्वयन भी उतना ही बेहतर हो।

प्रतीकात्मक।

24 डिग्री से कम तापमान पर एसी नहीं चलेंगे। सभी कंपनियों को हर तरह के एसी में डिफॉल्ट तापमान 24 डिग्री रखना होगा। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और सरकार ने एक जनवरी से यह एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड तय किया है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 8 जनवरी 2020

बंगाल

सुप्रीम फैसले के बाद ममता की चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल मदरसा सेवा आयोग कानून को संवैधानिक ठहरा दिया है। इस फैसले ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए एक तरफ शिक्षित अल्पसंख्यकों को लुभाने का मौका दिया है तो दूसरी तरफ मौलवी और मदरसा प्रबंधकों के विरोध का भी खतरा उत्पन्न कर दिया है। यह सुप्रीम फैसला ममता सरकार के लिए दो धारी तलवार पर चलने जैसा है। वर्ष 2008 में यह कानून तबकी वाम सरकार ने बनाया था, लेकिन मदरसा संचालक लामबंद होकर सरकार के खिलाफ कोर्ट चले गए थे। तब कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को पलट दिया था। फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और ताजा फैसले के बाद अब गेंद ममता बनर्जी की सरकार के पाले में है।

चुनावी तैयारियों में रात-दिन एक कर रहीं तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी को सरकारी तौर पर इस फैसले को साधने की चुनौती खड़ी हो गई है। अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने में सक्रिय ममता के लिए शिक्षित अल्पसंख्यकों को लुभाने के साथ ही मदरसा संचालकों को भी विरोध में जाने से रोकना है। जाहिर है यह एक भावनात्मक मुद्दा है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। प्रदेश में किसी सरकार को बनाने या हटाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। लिहाजा कोई भी पार्टी इनके वोट हासिल करने का लोभ नहीं छोड़ती है। ऐसे संकेत मिले हैं कि ममता बनर्जी के मुस्लिम सिपहसालार फैसला आने के बाद मदरसा संचालकों को साधने में सक्रिय हो गए हैं ताकि कहीं से भी विरोध का स्वर न उठे। अब यह संदेश देने की कोशिश होगी कि मदरसों में आयोग के जरिये काबिल युवाओं की नियुक्ति होगी और दूसरे संचालकों को भी कुछ बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। बहुत जल्द निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। उसके पहले ममता सरकार दोनों पक्षों को खुश करने की पहल करेगी।

अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने में सक्रिय ममता के लिए शिक्षित अल्पसंख्यकों को लुभाने के साथ ही मदरसा संचालकों को भी विरोध में जाने से रोकना है।

बहरहाल ममता को अल्पसंख्यकों को साधने के लिए नया हथियार मिल गया है। वह इसे चुनावी बिसात पर साधने का कोई मौका चूकेगीं नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में मदरसा संचालकों द्वारा की गई नियुक्तियों को भी बहाल रखने के आदेश दिए हैं। करीब तीन हजार शिक्षकों की नौकरी पर अब खतरा नहीं रहेगा। इन तीन हजार परिवारों तक भी दीदी का संदेश भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश भी ममता के लिए फायदेमंद हो गया है। अगर शिक्षकों को मदरसों से बाहर करना पड़ता तो माहौल बिगड़ता। इस फैसले से सबसे खास संदेश यह गया है कि मदरसा संचालक अपने भाई-भतीजे और नफा-नुकसान के आधार पर नियुक्ति नहीं कर पाएंगे। अब मदरसा आयोग द्वारा जो भी नियुक्ति होगी उसमें पारदर्शिता रहेगी। इससे प्रतिभा संपन्न युवाओं को आगे आने का अवसर मिलेगा। साथ ही ममता सरकार को अब मदरसा सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का भी मौका मिलेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस फैसले से प्रदेश में मदरसों का माहौल बदलेगा। और मुस्लिम समाज को इससे फायदा मिलेगा।

झारखंड

नवजात की बचे जान

पिछले दिनों जो स्थिति सामने आई, वह अच्छी नहीं हैं। देश के कुछ राज्यों में नवजात की मौत के खौफनाक आंकड़े सामने आए हैं। इसके पीछे अस्पतालों में लापरवाही उजागर हुई। हालांकि झारखंड की बात करें तो यहां स्थिति उतनी खराब नहीं है। अभी यहां नवजात की मौत का आंकड़ा प्रति लाख 165 है, जो पहले करीब 200 था। सरकारी संस्थाओं की कोशिश का नतीजा है कि प्रति लाख नवजात की मौत का आंकड़ा कम हुआ है। धनबाद के पाटलीपुत्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (पीएमसीएच) की बात करें तो यहां पिछले साल 813 नवजात की जान गई। ये आंकड़े सुखद नहीं हैं।

इन मौतों के पीछे यह तथ्य उजागर हुआ है कि अधिसंख्य नवजातों ने संक्रमण और कम वजन होने के कारण दम तोड़ा। यह बात ध्यान देने लायक है कि पीएमसीएच क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहां धनबाद के आसपास के जिलों से भी नवजात इलाज के लिए लाए जाते हैं। इनमें कई की स्थिति नाजुक होती है, जिस कारण उनका इलाज संभव नहीं हो पाता है। पिछले साल पीएमसीएच में जितने नवजातों ने दम तोड़ा, उनमें अधिसंख्य बाहर के जिलों के ही थे। नवजात में संक्रमण का बड़ा कारण अस्पतालों में साफ-सफाई की बदहाली है। दूध पिलाने के समय भी अगर कपड़े आदि की सफाई पर ध्यान नहीं दिया गया तो वह भी संक्रमण का कारण बनता है। नवजात के कम वजन के पीछे माताओं का एनीमिया से ग्रस्त होना बड़ा कारण है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके सामने कई तरह की शुरुआती मुश्किलें आती हैं, जिनसे निपटने के लिए अस्पतालों में व्यवस्था होनी चाहिए।

प्रतीकात्मक

अस्पतालों में सुविधा या व्यवस्था के अभाव में किसी नवजात की जान नहीं जानी चाहिए। यह इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि हर किसी के पास बड़े-बड़े निजी क्लिनिकों में जाने का सामर्थ्य नहीं होता। पैसे के बल पर आधुनिकतम इलाज भी हर किसी के बस की बात नहीं। जब सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के विशाल ढांचे पर अच्छी-खासी रकम खर्च करती है तो इसे ऐसा होना चाहिए कि जिंदगी की जंग में यह मददगार साबित हो सके। लांसेट में सितंबर, 2019 में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पांच साल आयु तक के बच्चों की मौत के 68 फीसदी मामलों का कारण कुपोषण है। शिशु मृत्यु दर का राष्ट्रीय औसत भी ज्यादा है। यूनिसेफ द्वारा जारी 'एवरी चाइल्ड अलाइव रिपोर्ट' के मुताबिक देश में प्रत्येक वर्ष जन्म लेने वाले 26 लाख बच्चे एक महीने की जिंदगी भी नहीं जी पाते हैं। इन 26 लाख बच्चों में दस लाख बच्चे तो ऐसे हैं जो जन्म लेने के दिन ही अपनी जान गंवा देते हैं। वहीं एक संसदीय समिति की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में दस हजार की आबादी पर केवल पांच डॉक्टर ही उपलब्ध हैं जबकि नॉर्वे में प्रति दस हजार लोगों पर 218 डॉक्टर हैं, वहीं ब्राजील में 93 हैं।

भारत के अस्पतालों में मरीजों के लिए उपलब्ध बेडों की संख्या भी संतोषजनक नहीं है। प्रति हजार लोगों पर ब्राजील में जहां बेडों की संख्या 2.3 है, वहीं पड़ोसी देश श्रीलंका में 3.6 है, जबकि भारत में बेडों की उपलब्धता केवल 0.7 है। लिहाजा डॉक्टर, नर्स और बेड की बात करें तो आबादी के लिहाज से इनकी संख्या बेहद कम है। एक अध्ययन के अनुसार भारत के अस्पतालों में चार लाख डॉक्टर, 40 लाख नर्स और 7 लाख बिस्तरों की कमी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में बच्चों के डॉक्टर की संख्या मात्र 25 हजार है जबकि जरूरत दो लाख से ज्यादा की है। जाहिर है राज्य ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वास्थ्य सेक्टर की तस्वीर सही नहीं है।

हिमाचल प्रदेश

हरियाली के मोर्चे पर उत्साहवर्धक परिणाम

जीवन के लिए जल व जंगल अहम हैं। पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक तापमान में भी काफी बदलाव आया है। इसी का असर है कि मौसम चक्र में भी बदलाव आ गया है। बरसात में बारिश की कमी हो रही है जबकि सर्दियों व गर्मियों के मौसम भी तय समय से आगे सरक गए हैं। हालात ऐसे हो रहे हैं कि पहाड़ों से अधिक ठंडे मैदान हो गए हैं। मैदानों को धुंध ने इस तरह घेरा है कि वहां पर दिन में भी सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। पर्यावरण को लेकर दुनिया भर में व्यापक चिंता व्यक्त की जा रही है। इसी बीच यह तथ्य उत्साह बढ़ाता है कि हिमाचल प्रदेश में 334 वर्ग किलोमीटर हरित आवरण में वृद्धि हुई है।

यह खुलासा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया (एफएसआइ) की रिपोर्ट में हुआ है। एफएसआइ प्रत्येक दो साल में सर्वेक्षण करता है। हरित पट्टी बढ़ाने के लिए सरकार के साथ-साथ कई स्वयंसेवी संस्थाओं की भी अहम भूमिका रही है। दैनिक जागरण भी पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण अभियान चलाता रहा है। सामूहिक प्रयासों का ही नतीजा है कि प्रदेश में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है।

हिमाचल प्रदेश में वन क्षेत्र में वृद्धि की सूचना उत्साह बढ़ाने वाली है। राज्य में वन क्षेत्र बढ़कर 15,434 वर्ग किलोमीटर हो गया है। जरूरत है कि हरियाली के संरक्षण के लिए हर हाथ उठे।

एफएसआइ की 2017 की रिपोर्ट में राज्य में 15,100 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र था जो वर्ष 2019 में बढ़कर 15,434 वर्ग किलोमीटर हो गया है। यह सही है कि राज्य में हर साल लाखों पेड़ परियाजनाओं के निर्माण व अन्य विकास कार्यों के लिए बलि चढ़ते हैं। सरकार ने इस क्षतिपूर्ति के लिए नियम भी निर्धारित किए हैं कि यदि कहीं पर पेड़ काटे जाते हैं तो उसके बदले पौधारोपण किया जाना जरूरी है। प्रदेश में हर साल करीब एक करोड़ पौधे रोपे जाते हैं। यह शोध का विषय अवश्य है कि इनमें से कितने पौधे पेड़ बन पाते हैं।

सरकार ने हरित पट्टी बढ़ाने के लिए कई योजनाएं भी शुरू कर रखी हैं। 'एक बूटा बेटी के नाम' महत्वाकांक्षी योजना भी है। लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विशेष अवसरों पर पौधारोपण के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। हिमाचल के लिए यह भी इतराने का विषय है कि कई बेटियां पौधों को राखी बांधकर उनका संरक्षण भी कर रही हैं। कई अभिभावकों ने बच्चों के नाम पर भी पौधे रोपे हैं। अब यह उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रदेश का प्रत्येक नागरिक पौधों की अहमियत समझेगा और प्रदेश के वनक्षेत्र में वृद्धि होगी।

यदि प्रदेश इस मोर्चे पर उत्तरोत्तर प्रगति करता रहा तो वह अन्य प्रदेशों के लिए एक अनुकरणीय मिसाल के रूप में स्थापित हो सकता है। इसके साथ ही यह प्रदेश के लिए कई और संभावनाओं के द्वार खोलने की क्षमता रखता है। आने वाले समय में जब वन क्षेत्रों पर दबाव और बढ़ेगा तब यह वन भूमि प्रदेश के लिए 'ग्रीन बोनस' का आधार बन सकती है। दुनिया में जिस तरह हरित असंतुलन बढ़ रहा है, उसे संतुलित करने की बहुत आवश्यकता है। इस दिशा में निरंतर प्रयासों में ही सफलता की कुंजी निहित होगी।

जम्मू-कश्मीर

पाक की चाल

पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ जम्मू-कश्मीर के युवाओं को हसीनाओं के जाल में फंसा कर उनसे यहां की अहम जानकारियां हासिल करने की फिराक में हैं। यह देश के सुरक्षा के लिहाज से काफी गंभीर मसला है। विगत सोमवार को अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे अरनिया के गांव पोवल के एक युवक को पुलिस ने पाक की खुफिया एजेंसी आइएसआइ से संपर्क होने की आशंका में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि युवक आइएसआइ की महिला एजेंट के साथ सोशल साइट के माध्यम से संपर्क में आया और उसने कई अहम जानकारियां उसके साथ साझा कर डाली। मामला संगीन है और सुरक्षा परिदृश्य गंभीर भी है। यह पहला मामला नहीं है जब देश का युवा पाक की 'हसीन चाल' में फंसा हो। इससे पूर्व भी कई मामले सामने आए हैं और पाक की साजिश का राज भी फाश हुआ है।

सभी जानते हैं कि पाकिस्तान हर क्षेत्र में भारत से मात खा रहा है। भारतीय सेना के हौसलों के आगे कहीं नहीं टिकता है। बीते वर्षों से आतंकवाद के खिलाफ चले अभियानों ने पाक समर्थकों एवं पाक पोषित आतंकी संगठनों की कमर तोड़ डाली है। ऐसे में बौखलाहट का मारा पाकिस्तान किसी ने किसी रूप से भारत को कमजोर करने की फिराक में है। और उसी कोशिश में उसने हसीन जाल भी बिछा रखा है। सोशल मीडिया अथवा साइट्स पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एजेंट महिलाओं के नाम फर्जी अकाउंट बना रहे हैं, जिसमें एजेंट के भारतीय होने की फर्जी जानकारी डाली जा रही है, ताकि किसी को उनपर शक न हो।

प्रतीकात्मक

यहां सुखद पक्ष यह है कि जब बात फोन नंबर पर बातचीत की आ जाती है तो सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो जाती हैं, लेकिन कई बार पर्दाफाश तब होता है, तब बहुत देर हो चुकी हो। सोशल मीडिया पर सक्रिय युवाओं को समझदारी और सतर्कता दिखानी होगी। युवाओं को उन्हीं लोगों के मित्रता अनुरोध को स्वीकार करना होगा, जो उनकी जान पहचान के हों। जो लोग जान पहचान के नहीं हैं और लेकिन सोशल साइट्स पर मित्र सूची में हैं, उन्हें किसी भी तरह की जानकारी न दें।

भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कुटिल सोच जगजाहिर है। बंटवारे के बाद से ही वह भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहा है। वह बंदूक के बल पर भारत के क्षेत्र पर काबिज होने के असंभव सपने देखता रहा है। इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। लिहाजा भारत को हर समय चौकन्ना रहना होगा।

अन्य राज्यों में मदरसा समितियां करती हैं शिक्षकों की नियुक्ति

जेएनएन, नई दिल्ली

बंगाल की तरह अन्य राज्यों में मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कोई आयोग नहीं है, बल्कि मदरसों की अपनी समितियां ही शिक्षकों की नियुक्ति करती हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू-कश्मीर, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान आदि अन्य राज्यों में मदरसों पर नियंत्रण तो जिला शिक्षा अधिकारी, वक्फ बोर्ड और मदरसा बोर्ड का होता है, लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार सरकार के पास न होकर मदरसों की समितियों के पास ही है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बंगाल मदरसा सेवा आयोग कानून को संवैधानिक ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि यह कानून अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के अधिकारों का हनन नहीं करता। हालांकि, जिन शिक्षकों की भर्ती मदरसों ने मामला लंबित रहने के दौरान स्वयं कर ली थी, वह भी बनी रहेगी। इसके बाद कानून के मुताबिक आयोग द्वारा किया गया शिक्षकों का चयन वैध होगा। आइए जानते हैं अन्य राज्यों में क्या है मदरसा शिक्षकों की नियुक्त की व्यवस्था...

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश के मदरसा शिक्षा परिषद के अधीन चलते हैं। मदरसों में शिक्षकों की भर्ती मदरसा प्रबंधन विज्ञापन निकालकर करते हैं। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं रहती है। मदरसा प्रबंधकों को दो अखबारों में विज्ञापन निकालना होता है। इसके बाद इंटरव्यू के जरिए भर्तियां होती हैं। शिक्षकों की नियुक्ति के बाद मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार अनुमोदन देते हैं। बता दें सूबे में करीब 18 हजार मदरसे हैं। इनमें से मानक पूरे करने वाले 13,316 मदरसे उप्र सरकार के मदरसा पोर्टल में पंजीकृत हैं।

बंगाल मदरसा सेवा आयोग कानून को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया है संवैधानिक

प्रतीकात्मक

बिहार : यहां 1942 अनुदानित मदरसे हैं, जिनके शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन के लिए सरकार अनुदान देती है। जबकि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड की निगरानी में प्रबंध समितियों द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। यहां भी नियुक्ति के लिए दो दैनिक अखबार में विज्ञापन देने का प्राविधान है। इसके आधार पर योग्य अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन जमा किया जाता है। आवेदनों और प्रमाण पत्रों की जांच के बाद प्रबंध समितियों की ओर से लिखित और मौखिक परीक्षा ली जाती है। परीक्षाफल के बाद चयनित अभ्यर्थियों का पैनल बनता है, जिसे अनुमोदन के लिए बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड में भेजा जाता है। पूरी प्रक्रिया की छानबीन के बाद ही नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जम्मू-कश्मीर : राज्य में लगभग 700 मदरसे हैं। जम्मू में 150 और कश्मीर में 250 पंजीकृत हैं। अन्य गैर पंजीकृत हैं। जम्मू कश्मीर में मदरसों को नियंत्रित करने वाली कोई विशेष संस्था नहीं हैं। इनमें कुछ मदरसे जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड तो कुछ मुस्लिम अकाफ ट्रस्ट के अधीन हैं। अधिकांश मदरसे विभिन्न मजहबी संगठनों द्वारा ही चलाए जाते हैं। कुछ मदारसे को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और उर्दू काउंसिल द्वारा भी मान्यता दी गई है। मदरसों में अध्यापकों की नियुक्ति में सरकार का कोई सीधा दखल नहीं है।

छत्तीसगढ़ : राज्य में करीब 330 मदरसों में 20 हजार छात्रों के लिए करीब एक हजार शिक्षक हैं। इन्हें केंद्र सरकार से अनुदान मिलता है। शिक्षकों की नियुक्तियां मदरसा समितियां करती हैं। लेकिन नियंत्रण जिला शिक्षा अधिकारी का रहता है। राज्य में मदरसा बोर्ड भी है, जो मदरसों को मिलने वाले अनुदान का हिसाब किताब रखता है।

उत्तराखंड : यहां मदरसा बोर्ड के अंतर्गत 297 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति अशासकीय विद्यालयों की भांति मदरसा प्रबंधन कमेटी करती है। नियुक्तियां मदरसा बोर्ड की देखरेख में होती हैं। मदरसों की निगरानी और उन नियंत्रण का जिम्मा उत्तराखंड मदरसा बोर्ड व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पास है।

मध्यप्रदेश : राज्य में करीब पांच हजार मदरसे रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 1800 मदरसा अनुदानित हैं। मदरसों को केंद्र सरकार से अनुदान मिलता है। मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति पर राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। नियुक्ति मदरसा सोसायटी और मदरसा संचालक के माध्यम से होती है।

झारखंड : राज्य में 186 गैर सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति मदरसा प्रबंध समिति द्वारा की जाती है। राज्य सरकार सिर्फ मदरसों के शिक्षकों के पद सृजन को स्वीकृति प्रदान करती है।

राजस्थान : यहां मदरसा शिक्षा बोर्ड के अधीन मदरसे चलते हैं। बोर्ड के साथ पंजीकृत 3226 मदरसों में करीब 2.35 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। मदरसा शिक्षा बोर्ड आवेदन आमंत्रित कर जरूरत के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति करता है।

नई शर्तों पर लॉग-इन होगी आइडी, फर्जी कार्ड बनाने पर अब सीधी एफआइआर

धरमिंदर सिंह, फतेहगढ़ साहिब

आयुष्मान में फर्जीवाड़ा

एक लाख कार्डों के रिव्यू के लिए स्टेट हेल्थ एजेंसी ने गठित की टीम

पंजाब में आयुष्मान भारत (सरबत स्वास्थ्य बीमा योजना) में फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद पंजाब सरकार के हरकत में आते ही स्टेट हेल्थ एजेंसी भी रोजाना सिस्टम में नए सुधार कर रही है। फर्जी कार्डों को रद करने की प्रक्रिया के साथ ही मंगलवार को जिले के सभी 130 कॉमन सर्विस सेंटर की आइडी बंद कर दी गई। स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू के निर्देशों पर नई शर्तों के साथ आइडी लॉग-इन होंगी। यही नहीं, अब यदि किसी कॉमन सर्विस सेंटर से फर्जी कार्ड बना तो उसके संचालक के खिलाफ स्टेट हेल्थ एजेंसी सीधे एफआइआर भी दर्ज करवाएगी। इससे पहले सिस्टम में यह तय नहीं था कि फर्जी कार्ड बनने पर क्या कार्रवाई होगी। दैनिक जागरण की तरफ से मामले को प्रमुखता से उजागर करने पर सरकार के निर्देशों पर यह बदलाव किया गया है।

स्टेट हेल्थ एजेंसी ने अब तक जिले में बने एक लाख से अधिक कार्डों का रिव्यू भी तेज कर दिया है। इसके लिए मोहाली मुख्यालय में एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जो रिव्यू पूरा करेगी। रिव्यू पूरा करने के बाद जिले के कॉमन सर्विस सेंटर चालू किए जाएंगे। एजेंसी के मैनेजर डॉ. संजीव जैन ने कहा कि आम लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न आए, इस लिए उनकी कोशिश है कि जल्द ही रिव्यू पूरा कराकर फर्जी कार्डों को रद किया जाए और नए सिरे से कार्ड बनाने का काम शुरू कराया जाए। भविष्य में बीमा योजना का फर्जी कार्ड बनना संभव ही नहीं होगा।

प्रतीकात्मक

डीसी ने रोकी रिपोर्ट, उठे सवाल : फतेहगढ़ साहिब में बीमा योजना के तहत फर्जी कार्डों के मामले में डिप्टी कमिश्नर अमृत कौर गिल के पास भी शिकायत पहुंची थी। उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। हालांकि, जिला मेडिकल अधिकारी डॉ. जगदीश अपनी जांच में भी 13 कार्ड फर्जी पा चुके हैं और इस जांच रिपोर्ट डीसी कार्यालय को दे चुके हैं, लेकिन डीसी ने इस पर अगली कार्रवाई रोकी हुई है। डीसी गिल ने कहा कि उनके कार्यालय में रिपोर्ट आ चुकी है। आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। उधर, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राकेश गुप्ता व सरहिंद मंडल अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि सियासी दबाव में कार्रवाई रोकी गई है। सीबीआइ से जांच करवाई जाए।

'75 फीसद आबादी को सेहत बीमा के दायरे में लाया गया'

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि सेहत बीमा योजना में राज्य की 75 फीसद आबादी (45 लाख परिवार) कवर होती है। इनको पांच लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा दी गई है। किसान, छोटे व्यापारी, कामगार, पत्रकार और राशन स्कीम के लाभार्थियों को सेहत बीमा का लाभ दिया गया है।

गिलोय के सेवन से गुर्दा रहेगा सलामत

संतोष शुक्ल, मेरठ : कहते हैं कि दवा कड़वी हो तो ज्यादा कारगर होती है। आयुर्वेद के खजाने में गिलोय ऐसी ही दवा है। मेरठ स्थित महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के फार्माकोलॉजी विभाग ने शोध में पाया कि गिलोय गुर्दे की बीमारी को पूरी तरह ठीक कर सकता है। यह शोध अंतरराष्ट्रीय मेडिकल जर्नल में भी छपा है।

चूहों का गुर्दा खराब किया, फिर गिलोय से ठीक : मेडिकल कॉलेज के फार्माकोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. केके सक्सेना ने बताया कि डॉ. मोनिका शर्मा व डॉ. पिंकी ने 24 चूहों को चार भागों में बांटकर शोध किया। एंटीबायोटिक जेंटामाइसिन का प्रयोग चूहों की किडनी को डैमेज करने के लिए किया गया। ग्रुप-एक में चूहों को 21 दिनों तक दो मिलीलीटर नमक, ग्रुप दो में चूहों को 21 दिनों तक नमक के साथ पांच दिनों तक जेंटामाइसिन दी गई। ग्रुप-3 में 250 मिलीग्राम गिलोय 21 दिनों तक देने के बाद फिर पांच दिनों तक जेंटामाइसीन दी गई। अंतिम ग्रुप के चूहों को 500 मिलीग्राम गिलोय दिया गया।

परिणाम यह रहा कि डैमेज किडनी में 60 प्रतिशत तक सुधार मिला। इस शोध को जुलाई 2019 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बेसिक एंड क्लीनिकल फार्माकोलॉजी में प्रकाशित किया गया। बाद में यह फार्मूला मरीजों पर अपनाया गया, जहां क्षतिग्रस्त किडनी में तेजी से सुधार मिला।

लघु उद्योग के लिए प्लॉट की आकार सीमा खत्म

कैलाश नाथ, चंडीगढ़

आर्थिक मंदी के दौर में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने छोटे उद्योगों व कमर्शियल सेक्टर में निवेश के लिए बूस्टर डोज दी है। इसके साथ ही पंजाब सरकार ने भवन निर्माण नियमों में भी बड़े स्तर पर सुधार किए हैं। इन सुधारों के अनुसार अब लघु उद्योग स्थापित करने के लिए प्लॉट के आकार की सीमा व अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है।

छोटे होटल, मोटल व गेस्ट हाउस को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्व निर्धारित अनिवार्य प्लॉट के आकार को घटा कर 200 वर्ग फीट कर दिया गया है। सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। पंजाब सरकार ने सिनेमाघर को मिनीप्लेक्स में बदलने का रास्ता साफ कर दिया है। प्रदेश में पेट्रोल पंप अब 60 फीट की सड़कों पर भी खुल सकेंगे। पहले यह शर्त 100 फीट की थी। जिन शहरों में मास्टर प्लान नहीं है, वहां कमर्शियल प्रोजेक्टों के लिए सड़कों की चौड़ाई के नियम तय कर दिए गए हैं।

पंजाब सरकार ने होटल, मोटल और गेस्ट हाउस खोलने के लिए प्लॉट के अनिवार्य आकार 1000 स्क्वायर फीट में कटौती करते हुए इसे 200 स्क्वायर फीट कर दिया है। इस फैसले से न सिर्फ छोटे होटल व मोटल को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में निवेश के अवसर खुलेंगे।

कैप्टन अमरिंदर सिंह फाइल

लघु उद्योगों को बड़ी राहत

- पंजाब सरकार ने लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए प्लॉट में 360 स्क्वायर फीट की अनिवार्यता को ही खत्म कर दिया है।
- अब किसी भी आकार वाले प्लॉट पर लघु उद्योग स्थापित किया जा सकता है। इससे होजरी, कॉटेज इंडस्ट्री और अन्य लघु उद्योगों को लाभ होगा।
- टेक्सटाइल, निट वियर और आइटी इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए इनकी बिल्डिंग की ऊंचाई को 15 मीटर से बढ़ा कर 21 मीटर कर दिया गया है।
- कोई भी इंडस्ट्री अपने औद्योगिक प्लॉट में ही गोदाम का निर्माण करवा सकेगी।
- सुरक्षा की दृष्टि से गोदामों में थोक विक्रेता की ओर से भंडारण की सीमा को भी तय कर दिया गया है।

सिनेमाघरों के नियमों में किए गए ये बदलाव

- एक मिनीप्लेक्स में दो स्क्रीन की अनिवार्यता को हटा कर चार स्क्रीन तक कर दिया गया है।
- कम से कम 250 सीटें होने की शर्त को खत्म कर दिया गया है। अब अधिकतम 999 सीटें हो सकती हैं।
- 50 फीट चौड़ाई वाली सड़कों पर बने सिनेमा घरों को भी मिनीप्लेक्स में बदला जा सकेगा। इसे कमर्शियल प्रयोग में भी लाया जा सकेगा।

मल्टीप्लेक्स में निवेश के प्रावधानों में सुधार

- विभिन्न चौड़ाई वाली सड़कों पर बने मल्टीप्लेक्स के फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) को भी बढ़ा दिया गया है।
- पंजाब पर्चेस ऑफ एफएआर का नया प्रावधान किया गया है। इसके तहत मल्टीप्लेक्स में एफएआर की खरीद-फरोख्त की जा सकेगी। इसके लिए नियम व शर्तें तय कर दी गई हैं। इसमें ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स भी शामिल हैं।

ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के नियमों में नए प्रावधान

- ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के नियमों में सुधार करते हुए अब सोसायटियों में प्राइमरी स्कूल व क्रेच खोले जाने का भी प्रावधान किया गया है।
- फ्लैटों की बालकनी को एफएआर से बाहर कर दिया गया है। बालकनी की लंबाई की सीमा को भी 1.2 से बढ़ा कर 1.8 मीटर कर दिया गया है।

मेडिकल कॉलेज व नर्सिंग होम्स का एफएआर बढ़ाया

- 10 एकड़ से बड़ी जमीन पर बने अस्पताल जिनमें नर्सिंग कॉलेज और हॉस्टल हैं, उन्हें अब इंस्टीट्यूशनल भवन माना जाएगा। सरकार ने इनका एफएआर बढ़ा दिया है।
- छोटे नर्सिंग होम्स और अस्पताल को मल्टी लेवल पार्किंग के लिए पांच फीसद अतिरिक्त ग्राउंड कवरेज के प्रावधान के साथ मल्टी लेवल पोडियम पार्किंग को एफएआर व ग्राउंड कवरेज से बाहर कर दिया गया है।
- इनमें वेटिंग हॉल रिसेप्शन और आपातकालीन सीढ़ियां भी एफएआर से मुक्त होंगे।

बिहार में 539 दवाओं के खिलाफ मिली शिकायत

नीरज कुमार, पटना : मानव शरीर पर 539 दवाओं के दुष्प्रभाव के खिलाफ पिछले एक वर्ष में पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आइजीआइएमएस) में शिकायत की गई है। यह शिकायत संस्थान के एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग सेंटर पर मरीज व डॉक्टरों ने की है।

आइजीआइएमएस के फार्माकोलॉजी विभाग के अध्यक्ष व मॉनिटरिंग सेंटर के हेड डॉ. हरिहर दीक्षित का कहना है कि जिस तरह विभिन्न बीमारियों में दवाओं का प्रयोग हो रहा है, उसका मानव शरीर पर दुष्प्रभाव भी बढ़ रहा है। उसी का नतीजा है कि राज्यभर से 539 दवाओं के मानव शरीर पर दुष्प्रभाव के खिलाफ शिकायत मिली है। इन दवाओं पर विस्तृत अध्ययन करने के लिए जल्द ही रिपोर्ट इंडियन फार्माकोपिया कमीशन को भेज दी जाएगी जो अपने स्तर से दवाओं के दुष्प्रभाव का अध्ययन कर उसे प्रतिबंधित करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट भेजेगा। बाद में उसकी रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य केंद्र को भी भेजी जाएगी।

दवाओं के दुष्प्रभाव के खिलाफ कोई भी मरीज शिकायत कर सकता है। मरीज के परिजन या उसे इलाज करने वाले डॉक्टर भी संबंधित दवाओं के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। इस संबंध में आइजीआइएमएस में एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग सेंटर में लिखित में शिकायत की जा सकती है। इसके अलावा मॉनिटरिंग सेंटर की ओर से टोल फ्री नंबर 18001803024 भी जारी कर दिया गया है।

मानव शरीर पर एंटी बायोटिक का सर्वाधिक दुष्प्रभाव : आइजीआइएमएस में सबसे ज्यादा एंटी बायोटिक दवाओं के दुष्प्रभाव के खिलाफ शिकायत की गई है। दूसरे स्थान पर दर्द की दवाएं हैं। गैस व सर्दी-खांसी की दवाओं के खिलाफ भी शिकायत मिली है।

दवाओं के दुष्प्रभाव से पेट संबंधी हो रही परेशानी : आइजीआइएमएस के मॉनिटरिंग सेंटर में मिली शिकायतों के अनुसार दवाओं का सबसे ज्यादा दुष्प्र

4 दिन काम करने का प्रस्ताव रखा है फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरिन ने सप्ताह में। एक दिन में छह घंटे काम करना होगा। सना के मुताबिक, इससे लोग परिवार को समय दे पाएंगे और उत्पादन भी बढ़ेगा।

करंट भरी बौछार से होगा स्मॉग का खात्मा

जागरण विशेष ▸ विद्युत तरंगों वाली महीन बौछार दिलाएगी स्मॉग से निजात, पहले पानी छिड़काव ही था विकल्प

केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन (सीएसआइओ) ने विकसित की स्वदेशी मशीन

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़

केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन (सीएसआइओ) ने स्मॉग से निपटने के लिए स्वदेशी मशीन तैयार की है। एक निजी कंपनी को इसकी तकनीकी हस्तांतरित की जा रही है, जो जल्द ही व्यावसायिक उत्पादन शुरू करेगी। इलेक्ट्रोस्टेटिक डस्ट मिटीगेशन डिवाइस नामक यह मशीन विद्युत तरंगों पर आधारित है, जिसमें पानी का न्यूनतम इस्तेमाल होगा।

स्मॉग से निपटने के लिए अभी तक सिर्फ पानी के छिड़काव को ही कारगर विकल्प माना जाता है, लेकिन सीएसआइओ द्वारा तैयार की गई इलेक्ट्रोस्टेटिक डस्ट मिटिगेशन डिवाइस में पानी को विद्युत तरंगों के वाहक के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें जहां पानी का बेहद कम इस्तेमाल होगा, वहीं अन्य विकल्पों की अपेक्षा स्मॉग का सफाया कहीं अधिक आसान होगा।

पानी की महीन बौछार को विद्युत तरंगों के वाहक के रूप में किया जाएगा इस्तेमाल। सौ. सीएसआइओ

इस मशीन से 50 मीटर तक के दायरे में स्मॉग का सफाया किया जा सकेगा, जबकि जरूरत के मुताबिक इससे अधिक क्षमता वाली मशीन भी विकसित की जा सकेगी। मशीन को ट्रैक्टर ट्रॉली या छोटे ट्रक में रखकर धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए स्मॉग को नियंत्रित किया जा सकता है।

चंडीगढ़ स्थित देश के प्रतिष्ठित रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सीएसआइओ ने करीब एक साल की कड़ी मेहनत के बाद इस तकनीक को विकसित किया है। प्रोजेक्ट से जुड़े सीनियर साइंटिस्ट डॉ. मनोज कुमार पटेल के अनुसार, इस खास डिवाइस से वातावरण में मौजूद प्रदूषक कणों को विद्युत तरंगों से ढेर किया जा सकेगा। विद्युत तरंगों से टकराकर यह कण नीचे आ गिरेंगे। इस युक्ति में पानी की बेहद महीन बौछार होगी, जो विद्युत तरंगों की संवाहक होगी। लिहाजा, पानी की खपत बेहद कम होगी। प्रति मशीन तैयार करने पर 50 से 60 हजार रुपये लागत आएगी। मशीन तैयार करने वाली टीम में संस्थान के वैज्ञानिक अनिल जांगड़ा, अनूप कुमार, अनिल कुमार, अंकित कांची, योगिता सिंह, सुकृति आचार्य, प्रदीप कुमार और अनु सैनी का भी विशेष योगदान रहा है।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

यह तकनीक पहले से काफी बेहतर

सीएसआइओ द्वारा इस तकनीकी को हरियाणा के यमुनानगर स्थित कंपनी क्लाउड टेक प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित किया जा सकता है। कंपनी के निदेशक निशांत सैनी ने बताया कि सीएसआइओ से मिलने वाली तकनीक से स्मॉग को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकेगा। पानी भी बहुत कम लगेगा। बता दें कि यह वही कंपनी है जिसने विगत में स्मॉग का सफाया करने वाली अपनी कुछ मशीनों का दिल्ली सरकार के सामने प्रस्तुतीकरण किया था, लेकिन पानी की अधिक खपत के तर्क पर बात नहीं बनी थी।

प्रदूषण की समस्या काफी बढ़ गई है। सीएसआइओ वैज्ञानिकों द्वारा तैयार यह डिवाइस इससे निपटने में काफी फायदेमंद साबित होगी। इस टेक्नोलॉजी को हरियाणा की एक निजी फर्म को ट्रांसफर करने के लिए एमओयू किया जाएगा, जो इसका व्यावसायिक उत्पादन करेगी।

–डॉ. सुरेंद्र सिंह सैनी, प्रमुख, बिजनेस इनोवेटिव एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग, सीएसआइओ, चंडीगढ़

फिर होंगे मप्र के सफेद बाघों को जंगल में बसाने के प्रयास

वन विभाग ने 2012 में सफेद बाघों को खुले जंगल में बसाने का प्रस्ताव भेजा था। फाइल

राज्य ब्यूरो, भोपाल

▸ राज्य में नौ सफेद बाघ, 2012 में वन्य जीव संस्थान ने नहीं दी थी इजाजत

▸ अब एक शोध के बाद बदली संस्थान की राय

मध्य प्रदेश के रीवा के जंगल में पहली बार मिले सफेद बाघ को प्रदेश के खुले जंगलों में बसाने के प्रयास फिर से किए जा सकते हैं। वन विभाग ने 2012 में सफेद बाघों को खुले जंगल में बसाने का प्रस्ताव नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (एनटीसीए) को भेजा था। तब भारतीय वन्य जीव संस्थान ने इसकी इजाजत नहीं दी थी, लेकिन हाल ही में एक शोध के बाद संस्थान ने एनटीसीए को पत्र लिखकर कहा है कि यहां सफेद बाघों को जंगल में बसाया जा सकता है। इसके बाद चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने राज्य शासन को इस दिशा में फिर से संभावना तलाशने को कहा है।

अभी चिड़ियाघरों में हैं कैद : मप्र में नौ सफेद बाघ हैं। ये सभी रीवा स्थित ह्वाइट टाइगर सफारी और इंदौर के चिड़ियाघरों में कैद हैं, जिन्हें खुले जंगल में नहीं छोड़ा जा सकता है। इसलिए केंद्र सरकार सफेद बाघ प्रोजेक्ट लाकर ही इस प्रजाति को संरक्षित कर सकती है। ज्ञात हो कि देश में वर्तमान में 2967 बाघ हैं, जबकि वर्ष 2006 में 1411 बाघ थे।

अलग प्रजाति मान लिया गया : सरकारें बाघों की सफेदी का कारण अब तक आनुवांशिक मानती आई हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान के विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे बाघों का जीन बदल जाता है। लंबे समय के शोध के बाद संस्थान के विशेषज्ञों ने इसे अलग प्रजाति मान लिया है। पिछले माह संस्थान ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को इसकी जानकारी दी है और यह भी बताया है कि सफेद बाघों को खुले जंगलों में छोड़ा जा सकता है। वे शिकार करने और जंगल की समस्याओं से जूझने में सक्षम हैं।

विशेषज्ञों की राय जुदा : बाघ विशेषज्ञों का कहना है कि चिड़ियाघरों में लंबा समय गुजार चुके ये बाघ जंगल में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दरअसल, इन्हें मनुष्यों के नजदीक रहने और देखरेख की आदत पड़ चुकी है। ये जंगल में जाएंगे तो सामान्य बाघ के सामने नहीं टिक पाएंगे। इनकी आबादी बढ़ाने व उनकी संतानों को जंगल के माहौल में तैयार करने के बाद ही इस प्रजाति के बाघों को जंगल में छोड़ा जा सकता है।

वर्ष 1952 में राजा मार्तंड सिंह को मिला था पहला सफेद बाघ

वर्ष 1952 में रीवा राजघराने के राजा मार्तंड सिंह को शिकार के वक्त सफेद बाघ मिला था। संभवत: वह अपनी मां से बिछुड़ गया था। पहले तो राजा ने उसे मारना चाहा, लेकिन बाद में उसे साथ ले आए। उसका नाम मोहन रखा गया। मोहन ने 34 संतानों को जन्म दिया। उसके कुनबे में 114 बाघ होने का रिकॉर्ड है। मोहन की संतान ही देश और विदेश में पहुंचीं।

चिड़ियाघरों के बाघों को खुले जंगल में नहीं छोड़ा जा सकता है। नई जनरेशन से ही यह संभव है। इसमें भी कई जनरेशन के बाद सफेद बाघ पैदा किए जा सकते हैं। इस संबंध में राज्य सरकार जल्द निर्णय लेगी।

– डॉ. यू. प्रकाशम्, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, वन विभाग मप्र

लखनऊ से भी रहा वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का संबंध

ज्ञान बिहारी मिश्र, लखनऊ

महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का लखनऊ से भी कनेक्शन रहा है। जी हां, स्टीफन जब ऑक्सफोर्ड में स्कूल जाते थे, तब उनके पिता फ्रैंक हॉकिंग लखनऊ में शोध कर रहे थे। उस समय नौ-दस साल के रहे स्टीफन छुट्टियों में लखनऊ आकर पिता के पास रहते थे। फ्रैंक हॉकिंग केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (सीडीआरआइ) में एक साल तक रहे। स्टीफन हॉकिंग की जयंती की पूर्व संध्या पर मंगलवार को सीडीआरआइ के वैज्ञानिकों ने फ्रैंक हॉकिंग से जुड़ी यादें ताजा कीं।

हॉकिंग को 1951 में सीडीआरआइ के पहले निदेशक सर एडवर मेलेंबी संस्थान लेकर आए थे। सीडीआरआइ के प्रवक्ता डॉ. संजीव ने बताया कि सर मेलेंबी ब्रिटेन से थे और उनके फ्रैंक से करीबी ताल्लुक थे। राजधानी में जब फ्रैंक काम कर रहे थे तब हॉकिंग उनके पास रहने आए थे। बताया जाता है कि स्टीफन की बहन ने राजधानी के एक स्कूल में शिक्षा ग्रहण की थी।

नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल रिसर्च के प्रमुख थे फ्रैंक : स्टीफन के पिता इंग्लैंड में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल रिसर्च के प्रमुख थे। माता-पिता के मार्गदर्शन में ही स्टीफन का रुझान भौतिकी विज्ञान की तरफ बढ़ा। 21 साल की उम्र में डॉक्टरों ने बता दिया था कि उन्हें मोटर न्यूरोन (एक ऐसी बीमारी, जो शरीर की नसों पर लगातार हमला करती है) नामक लाइलाज बीमारी है। डॉक्टरों ने स्टीफन को तब जीने के लिए महज दो या तीन साल का समय बताया था। इसके बाद स्टीफन शोध कार्य में रम गए थे।

1952 में पिता के मार्गदर्शन में राजधानी में गुजारा था समय

स्टीफन हॉकिंग फाइल

76 साल की आयु में दुनिया को कहा अलविदा

स्टीफन हॉकिंग का जन्म आठ जनवरी, 1942 को ऑक्सफोर्ड में हुआ था। इन्होंने ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी को समझने में अहम योगदान दिया था। 14 मार्च, 2018 को 76 साल की आयु में उनकी मौत हो गई थी। स्टीफन पर लिखी एक पुस्तक में भी उनके लखनऊ कनेक्शन का जिक्र है।

नवाबों की अरबों की संपत्ति चट कर रहे दीमक

मुस्लेमीन, रामपुर

▸ संपत्ति के बंटवारे में लग गए 45 साल, कोर्ट से हो सका निर्णय

▸ कोठी खासबाग में 450 एकड़ जमीन, दीवार में टंगी हैं 26 रायफल

नवाब खानदान की अरबों रुपये की संपत्ति के बंटवारे का मुकदमा तय होने में 45 साल लग गए। इस दौरान करोड़ों की संपत्ति को दीमक चट कर गए, जबकि हथियारों को जंग लग गया है। इस कोठी में 500 से ज्यादा हथियार हैं।

नवाब खानदान की रामपुर में अरबों की संपत्ति है। इसमें कोठी खास बाग, लक्खी बाग, बेनजीर बाग, नवाब रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। 1974 में इसके बंटवारे को लेकर शुरू हुआ विवाद पहले मुंसिफ कोर्ट पहुंचा। इसके बाद जिला जज और फिर हाई कोर्ट। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी यह मुकदमा लंबे समय तक चला। पिछले साल सितंबर माह में सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामी शरीयत के हिसाब से बंटवारा करने के आदेश दिए।

बंटवारे की जिम्मेदारी जिला जज को सौंपी गई है। उन्हें दिसंबर 2020 तक बंटवारा करना है। संपत्ति के सर्वे के लिए उन्होंने एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए हैं। कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर अरुण प्रकाश सक्सेना इसका सर्वे कर रहे हैं। उन्होंने पूर्व सांसद बेगम नूरबानो और उनके बेटे पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां के साथ खास बाग का सर्वे किया। खास बाग की 450 एकड़ जमीन का सर्वे करने के साथ ही कोठी का भी जायजा लिया।

कोठी में हैं 250 कमरे : अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया कि कोठी में 250 कमरे हैं। कमरों के अंदर बेशकीमती सामान था। बर्मा टीक से बेड, डाइनिंग टेबल के साथ ही कमरों की दीवारों पर काम हुआ, लेकिन लकड़ी के तमाम सामान को दीमक चाट गए। कमरों के झूमर, पेंटिंग्स, पियानो और पर्दे भी खराब हो चुके हैं। कोठी में थियेटर भी था, जिसका सारा फर्नीचर खराब हो गया है। एक कमरे में दीवार पर 16 राइफल भी लगी मिलीं, लेकिन इन्हें भी जंग लगा है। नवाबों के 400 हथियार आरमरी में रखे हैं, जबकि सवा सौ हथियार कमरों लगे हैं।

रामपुर में कोठी खास बाग। जागरण

कोठी खास बाग में जर्जर पियानो। जागरण

देखरेख के अभाव में हुई खराब

कोठी खास बाग देश की पहली एयर कंडीशनर कोठी थी, लेकिन देखरेख के अभाव में एयर कंडीशनर सिस्टम भी खराब हो चुका है। कोठी के अंदर बेशकीमती पेंटिंग्स भी लगी थी, जिनमें अधिकतर खराब हो गई हैं या फिर गायब हैं। इस संपत्ति में 16 हिस्सेदार हैं। पाकिस्तान के पूर्व एयर चीफ मार्शल अब्दुल रहीम खान की पत्नी मेहरुन्निशा भी हिस्सेदार हैं, लेकिन लंबे समय से रामपुर से उनका कोई वास्ता नहीं है। इस कारण उनकी संपत्ति को सरकार कस्टोडियन घोषित करेगी।

नंधौर अभयारण्य रहा सूना, अभी तक एक पर्यटक नहीं पहुंचा

विनोद चतुर्वेदी, चंपावत : जिम कार्बेट में जगह नहीं। नैनीताल में पर्यटकों का जमावड़ा। इस फेहरिस्त में नंधौर अभयारण्य बहुत पीछे छूट गया है। नव वर्ष और जाड़े की छुट्टियों के बाद भी इस साल अभी तक एक भी पर्यटक यहां नहीं पहुंचा। ऐसे में वन विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहा है।

वन विभाग ने नवंबर अंत में अभयारण्य को पर्यटकों के लिए खोल तो दिया, लेकिन क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक नहीं किया। इस कारण नेचर गाइड पर्यटकों को यहां घुमाने से परहेज कर रहे हैं। नंधौर अभयारण्य की शुरुआत 11 जनवरी, 2018 को हुई थी। तब से प्रतिवर्ष 15 नवंबर से 15 जून तक अभयारण्य को पर्यटकों की आवाजाही के लिए खोला जाता है। पिछले वर्ष अभयारण्य में 32 विदेशी समेत 1,005 पर्यटक पहुंचे। इस वर्ष भी वन विभाग ने इसके दरवाजे 15 नवंबर को पर्यटकों के लिए खोले, लेकिन एक भी पर्यटक यहां नहीं पहुंचा। इसका मुख्य कारण नंधौर तक ककरालीगेट से जाने वाले 40 किलोमीटर मार्ग का खस्ताहाल होना है। उत्तराखंड वन विभाग के शारदा रेंज के रेंजर महेश सिंह बिष्ट ने बताया कि नंधौर अभयारण्य के लिए मार्ग दुरुस्त करने का काम शीघ्र शुरू किया जाएगा।

मानसिक रोगियों के 97 फीसद तीमारदार भी तनाव के शिकार

पुनीत शर्मा, रोहतक

मानसिक रोगियों का इलाज कराने के दौरान उनके परिजन भी मानसिक तनाव के शिकार हो जाते हैं। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के चिकित्सकों की रिसर्च में यह चौंकाने वाली बात सामने आई है। रिसर्च में 30 मानसिक रोगियों के परिजनों को शामिल किया गया था। मरीज को अस्पताल लाने व ले जाने, समय पर दवाई देने, मरीज की हरकतों से परेशान होकर मरीजों के 97 फीसद परिजन मानसिक रूप से बीमार हो चुके थे। संस्थान के चिकित्सकों द्वारा काउंसिलिंग कर इन मरीजों के परिजनों का उपचार किया गया।

पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (पीजीआइएमएस) के मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में मानसिक रोगी पहुंचते हैं। इनमें से बड़ी संख्या में ऐसे मरीज होते हैं, जिन्हें खतरनाक स्तर की मानसिक बीमारी है। ऐसे मरीजों को न केवल संस्थान में भर्ती कर उपचार किया जाता है, बल्कि उनकी काउंसिलिंग भी की जाती है। इन मरीजों के परिजनों को न केवल आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ता है, बल्कि मरीज की तीमारदारी के दौरान वह भी मानसिक रोगी बन जाते हैं। ऐसे ही 30 रोगियों के परिजनों पर रिसर्च की गई। पीजीआइएमएस के मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के चिकित्सक डॉ. भूपेंद्र के मुताबिक रिसर्च के अनुसार, 20.3 फीसद परिजनों को शुरुआती, 56.4 फीसद परिजनों को मध्यम स्तर, 13.4 फीसद परिजनों को खतरनाक स्तर और 6.7 फीसद परिजनों को अधिक खतरनाक स्तर की मानसिक बीमारी के लक्षण पाए गए। केवल 3.3 फीसद परिजन ही सामान्य मिले हैं। इसके अलावा इन परिजनों के जीवन जीने की गुणवत्ता भी निम्न स्तर की पाई गई।

पीजीआइएमएस फाइल

इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के चिकित्सकों की रिसर्च में बात सामने आई है कि मानसिक रोगियों के परिजन भी मरीज के उपचार के लिए चक्कर काटकर परेशान हो जाते हैं। इससे वह भी तनाव ग्रस्त हो जाते हैं।

–डॉ. ओपी कालरा, कुलपति, पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

76 फीसद परिजनों में मिली घबराहट और उदासी की समस्या

रिसर्च में शामिल किए गए 76 फीसद परिजनों में सिमिलरली एंजाइटी (घबराहट और उदासी) की समस्या पाई गई। चिकित्सकों ने बताया कि 50 फीसद परिजनों को माइल्ड (शुरुआती), 16 फीसद परिजनों को मॉडरेट (मध्यम) और 10 फीसद परिजनों को सीवियर (खतरनाक) स्तर का सिमिलरली एंजाइटी डिसऑर्डर पाया गया। वहीं 24 फीसद परिजनों की स्थिति सामान्य पाई गई।

अब सौर ऊर्जा से रोशन होंगे हरियाणा के सभी आइटीआइ

जागरण संवाददाता, सिरसा

हरियाणा के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आइटीआइ) में अब बिजली आपूर्ति बाधित होने पर कार्य प्रभावित नहीं होगा। सभी आइटीआइ में विभाग ने निर्बाध रूप से बिजली उपलब्ध करवाने के लिए सौर ऊर्जा को अपनाने का फैसला ले लिया है। इसके तहत दो तरह के मॉडल को स्वीकृति दे दी गई है। शहरी क्षेत्र में ग्रिड आधारित प्रणाली से सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में सौर उपकरणों के साथ बैट्रियां भी दी जाएंगी ताकि पावर बैंक बनाया जा सके।

प्रदेश में 248 आइटीआइ को सौर ऊर्जा से जोड़ने के प्रस्ताव को उच्च स्तर पर स्वीकृति मिल चुकी है।

विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के अनुसार शहरी क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता अधिक है इसलिए यहां ग्रिड सिस्टम से सौर उपकरणों को जोड़ा जाएगा। अतिरिक्त बिजली निगम को मिलेगी और आवश्यकता पड़ने पर बिजली निगम इसे वापस करेगा। ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटे बिजली की उपलब्धता नहीं है, इसलिए वहां ग्रिड सिस्टम को नहीं अपनाया जाएगा। यहां जितनी भी बिजली बनेगी उसका उपयोग आइटीआइ में ही किया जाएगा।

कंपनी लगाएगी उपकरण, आइटीआइ देगी केवल बिल : निदेशालय स्तर पर एक अलग से प्रस्ताव भी तैयार किया गया, जिसमें हरेडा से स्वीकृत कंपनी को आइटीआइ में सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए जगह दी जाएगी।

आइटीआइ का जो बिल है उसका भुगतान सोलर कंपनी को किया जाएगा और सोलर कंपनी बदले में आइटीआइ को सस्ती बिजली देगी। कंपनी को यह लाभ रहेगा कि उन्हें पावर प्लांट लगाने के लिए जगह फ्री में मिलेगी और आइटीआइ को यह लाभ होगा कि उसे सस्ती बिजली मिलेगी।

सभी राजकीय आइटीआइ को सौर ऊर्जा से जोड़ रहे हैं। सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। अब कंपनियों से बातचीत की जा रही है। शहरी क्षेत्र में ग्रिड आधारित सोलर पावर प्लांट को स्वीकृति देंगे और ग्रामीण क्षेत्र में दूसरे प्रोजेक्ट को अपनाएंगे ताकि वहां बिजली पर्याप्त रूप से मिले।

– प्रभजोत सिंह, महानिदेशक, स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रीज ट्रेनिंग डिपार्टमेंट

'भाभा कवच' को और मजबूत व ताकतवर बनाया

श्रीनारायण मिश्र, कानपुर : देश की सबसे हल्की और मजबूत बुलेट प्रूफ जैकेट 'भाभा कवच' अब और ताकतवर बन गई है। पहले यह 630 मीटर प्रति सेकेंड की गति से आने वाली 7.62 कैलीबर की हार्डकोर स्टील बुलेट के लिए बनी थी। अब यह 700 मीटर प्रति सेकेंड की गति वाली गोली को भी मात दे देगी। भाभा कवच में यह बदलाव गृह मंत्रालय की जरूरत के अनुसार किया गया है। जैकेट परीक्षण के लिए अहमदाबाद के लिए रवाना कर दी गई है।

भाभा अनुसंधान केंद्र की तकनीक पर मिश्र धातु निगम (मिधानि) हैदराबाद और आर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री कानपुर ने भाभा कवच का निर्माण किया था। यह देश की सबसे हल्की और सुरक्षित बुलेट प्रूफ जैकेट है। इसे सुरक्षा बलों से लेकर विभिन्न राज्य पुलिस में भी बेहद पसंद किया गया। अब आतंकियों के पास हाई स्पीड गन और स्टील की हार्ड कोर बुलेट को देखते इसकी ताकत और बढ़ाई गई है। गृह मंत्रालय ने इसकी जरूरत जताई थी। इसके बाद मिधानि ने इसकी धातु में बहुलकों को और सघन करके इसे आर्डनेंस फैक्ट्री को उपलब्ध कराया। आर्डनेंस फैक्ट्री ने अब इसे पूरी तरह तैयार कर लिया है।

नजदीक से फायरिंग पर भी बचेगी जान : भाभा कवच का अपग्रेड वर्जन उस स्थिति में भी सशस्त्र बलों के जवान की जान सुरक्षित रखेगा, जब हमलावर बेहद नजदीक से फायरिंग कर रहे हों, वह भी 7.62 कैलीबर की हार्ड कोर स्टील बुलेट से। इस बुलेट का प्रयोग अधिकतर आतंकी करते हैं।

वजन में मामूली फर्क : सामान्य तौर पर बुलेटप्रूफ जैकेट का वजन 17 किलोग्राम होता है, लेकिन भाभा कवच का कुल वजन 9.2 किलोग्राम ही है। हालांकि इसे अपग्रेड करने के कारण इसके वजन में कुछ ग्राम की हल्की बढ़ोतरी हो गई है।

भाभा कवच के अपग्रेड वर्जन को परीक्षण के लिए गुजरात रवाना कर दिया गया है। अहमदाबाद के परीक्षण सेंटर में इसकी क्षमता आंकी जाएगी।

– दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, महाप्रबंधक, आर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री, कानपुर

हुनर

खादी और सूती कपड़े की टोपी के कारोबार से बिलारी के 100 परिवारों में आई खुशहाली, गांधी–नेहरू टोपी, नमाजी और राजनीतिक दलों के लिए टोपी बनाने वाली शायरा बनीं नजीर

नारी सशक्तीकरण

मुरादाबाद से इंडोनेशिया तक जा पहुंची शायरा की बनाई टोपी

आशुतोष मिश्र, मुरादाबाद

▸ नौ साल पहले 25 हजार से शुरू हुआ टोपी बनाने का काम, 60 महिलाओं को मिला रोजगार

बात नौ साल पहले की है। उप्र के मुरादाबाद के बिलारी स्थित रुस्तमपुर सहसपुर के मोबीन के पास कोई काम नहीं था। पत्नी शायरा के हाथ में सिलाई का हुनर था, लेकिन वह रूढ़ीवादी बेड़ियों में बंधी थी। मोबीन ने शायरा के हुनर को पंख दिए और 25 हजार रुपये का इंतजाम करके टोपी सिलाई के काम की शुरुआत की। गांव की अन्य महिलाओं को इस काम से जोड़ा गया। आज 60 महिलाएं इस काम से जुड़कर अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत कर रही हैं।

इतना ही नहीं, शायरा का हुनर अब करीब सौ परिवारों की खुशहाली का वाहक बन गया है। इनकी बनाई टोपी देश ही नहीं अब विदेश में भी आमद दर्ज करा चुकी है। गांधी-नेहरू की टोपी, नमाजी और राजनीतिक दलों के लिए टोपी बनाने वाली शायरा दूसरों के लिए नजीर बन गई हैं। शायरा की टीम में शामिल महिलाएं घर बैठे हर दिन दौ सौ रुपये तक कमा रही हैं।

समूह की मुखिया शायरा।

उप्र के मुरादाबाद के रुस्तमनगर सहसपुर में टोपी की सिलाई करतीं समूह की सदस्य।

शायरा की टीम द्वारा तैयार की गई गांधी टोपियां। सभी फोटो जागरण

शायरा ने अपने काम को देखते हुए दस-दस महिलाओं की टीम बना रखी है। एक टीम दिन भर में एक हजार टोपी बना रही है। टीम में पुरुष भी हैं, जो टोपी के कपड़े काटते हैं, उसके बाद महिलाएं उनकी सिलाई करती हैं। कपड़े की कटिंग, सिलाई और पैकिंग के काम अलग-अलग टीम करती है। नए साल की दस्तक के बीच समूह ने 60 हजार रुपये की टोपी बेची हैं। खादी के कपड़े की टोपी 26 जनवरी के लिए मांगी जा रही है।

शायरा महिला टीम की कर्ताधर्ता हैं। घरों में टोपी सिलने वाली महिलाओं के काम की निगरानी शायरा ही करती हैं। उनका कहना है कि बच्चों को स्कूल भेजने और घर का अन्य काम करने के बाद महिलाएं टोपी बनाने का काम करती हैं।

इंटरनेशनल डिमांड... : रुस्तमनगर सहसपुर से शुरू हुआ टोपी का सफर दिल्ली होते हुए इंडोनेशिया तक पहुंच चुका है। इसके अलावा बंगलादेश से भी शायरा को टोपी के ऑर्डर मिल रहे हैं। साथ ही देश में लखनऊ, उत्तराखंड के हल्द्वानी, बागेश्वर अल्मोड़ा और मुर्शियारी में बिलारी की टोपी बिक रही है। अब दिल्ली के सदर बाजार और झंडे वाली गली के थोक कारोबारी यहां आर्डर दे रहे हैं।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

पंजाब नेशनल बैंक ने सस्ता किया कर्ज

नई दिल्ली, (वि.) : पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने कर्ज सस्ता करने का एलान किया है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए पीएनबी ने एमसीएलआर में पांच से 30 आधार अंकों तक की कटौती की है। अब एक साल के लिए एमसीएलआर को 8.15 फीसद से घटाकर 8.05 फीसद किया गया है। वहीं एक महीने के लिए एमसीएलआर 7.80 फीसद से घटकर 7.50 फीसद हो गई है। नई दरें पहली जनवरी, 2020 से प्रभावी हो गई हैं।

प्याज बंदरगाह पर उतरने लगे हैं, तब राज्य पीछे हट रहे हैं। फिलहाल केंद्र सरकार प्याज को मंडी तक पहुंचाने का खर्च भी वहन करने को तैयार है।

— रामविलास पासवान, केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्री

सेंसेक्स	40,869.47	▲ 192.84
निफ्टी	12,052.95	▲ 59.90
सोना (प्रति दस ग्राम)	₹ 41,210	▼ ₹ 420
चांदी (प्रति किलोग्राम)	₹ 48,600	▼ ₹ 830
$ डॉलर	₹ 71.82	▼ ₹ 0.11
क्रूड (ब्रेंट) (प्रति बैरल)	$ 68.29	

घरेलू आपूर्ति सुधरी तो आयातित प्याज खरीदने से बचने लगे राज्य

मुश्किल में केंद्रीय एजेंसियां ▶ अब सरकार 'नो प्रॉफिट, नो लॉस' पर बेचने को तैयार

मुंबई बंदरगाह पर अब तक पहुंच चुका है 12 हजार टन आयातित प्याज

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

जब कीमतें ऊंचे स्तर पर थीं, तब राज्यों ने की थी 33 हजार टन की मांग। प्रतीकात्मक फोटो

किल्लत के कारण बढ़ी प्याज की कीमतों को थामने के प्रयासों को राज्यों ने अब ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया है। केंद्र ने राज्यों के समक्ष 49 से 58 रुपये प्रति किलो की दर से आयातित प्याज बेचने की पेशकश की है। लेकिन कई राज्यों ने प्याज की अपनी पुरानी मांग को वापस ले लिया है। इससे आयातित प्याज अब केंद्रीय एजेंसियों के लिए मुश्किलों का सबब बन सकता है। दरअसल, घरेलू आपूर्ति बढ़ने से प्याज की महंगाई थमने लगी है, जिससे संबंधित राज्यों ने महंगा आयातित प्याज लेने से इन्कार करना शुरू कर दिया है।

कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की उच्च स्तरीय समिति की बैठक में इस मुद्दे पर लंबी चर्चा हुई। विदेश से आया महंगा प्याज लेने से मना करने वाले राज्यों में महाराष्ट्र, असम, हरियाणा, कर्नाटक और ओडिशा हैं। इनमें सबसे ज्यादा 10 हजार टन प्याज असम ने मांगा थी, जबकि 3480 टन प्याज की मांग महाराष्ट्र, 2500 टन हरियाणा और 100 टन की मांग ओडिशा से थी।

सचिवों की समिति की बैठक से लौटे केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय के सचिव अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अब तक मुंबई बंदरगाह पर 12000 टन प्याज पहुंच चुका है। श्रीवास्तव ने बताया कि मुंबई बंदरगाह पर पहुंचा प्याज 49 से 58 रुपये प्रति किलो की दर से राज्यों को बेचा जाएगा। सूत्रों का कहना है कि जिन राज्यों में घरेलू प्याज की आमद होने लगी है, वहां कीमतें घटने लगी हैं। इसके मद्देनजर उन राज्यों को आयातित प्याज महंगा लगने लगा है।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले व खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने बताया, 'जब नवंबर में प्याज के मूल्य 120 से 150 रुपये प्रति किलो हो गए थे, उस समय राज्यों की ओर से 33,139 टन प्याज की मांग आई थी। अब आयातित प्याज बंदरगाहों तक पहुंचने लगा है और संबंधित राज्यों में कीमतों का बढ़ना रुका अथवा कीमतें काबू में आईं तो राज्य पीछे हटने लगे हैं। केंद्र सरकार ने 'नो प्रॉफिट, नो लॉस' के आधार पर प्याज बेचने का फैसला किया है।' उन्होंने कहा कि बंदरगाह से प्याज को उपभोक्ता मंडी तक लाने का खर्च केंद्र सरकार वहन करने को तैयार है। एक अन्य सवाल पर पासवान ने कहा कि आयातित प्याज के स्वाद को लेकर सरकार कुछ नहीं कर सकती। जहां जैसा प्याज मिला, वहां से लाने की कोशिश की गई है। सरकारी एजेंसी एमएमटीसी ने अब तक 41 हजार टन से अधिक का आयात अनुबंध कर लिया है।

फरवरी बाद ही आपूर्ति में पर्याप्त सुधार : सचिव श्रीवास्तव ने बताया कि घरेलू प्याज की आपूर्ति में फरवरी के बाद ही पर्याप्त सुधार की संभावना है। मासिक अनुमानित उत्पादन का आंकड़ा देते हुए उन्होंने बताया कि जनवरी में पिछले साल के 13.80 लाख टन के मुकाबले 9.25 लाख टन उत्पादन का अनुमान है। फरवरी में उत्पादन 16.76 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल फरवरी में 25.62 लाख टन रहा था। मार्च में प्याज का उत्पादन 29.26 लाख टन पहुंचने की उम्मीद है, जो पिछले साल इसी महीने में 25.8 लाख टन था। श्रीवास्तव ने बताया कि भारत में प्याज की दैनिक खपत करीब 67 हजार टन है।

नीति आयोग ने रेलवे में निजी निवेश पर मसौदा पेश किया

नई दिल्ली, प्रेट्र : नीति आयोग ने रेलवे में निजी निवेश पर मसौदा पेश किया है। 100 नए मार्गों पर निजी ट्रेन चलाने की योजना को लेकर पेश किए गए इस मसौदे पर साझेदारों की सलाह मांगी गई है। रेल मंत्रालय और नीति आयोग मिलकर 100 नए रूट पर प्राइवेट ट्रेन चलाने की संभावनाओं विचार कर रहे हैं। यह मसौदा उसी का हिस्सा है।

इस संबंध में आरएफक्यू डॉक्यूमेंट, कंसेशन एग्रीमेंट गाइडिंग प्रिंसिपल, प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम और प्रोजेक्ट की कुछ मुख्य विशेषताएं नीति आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की गई हैं। प्रोजेक्ट के साझेदार 17 तारीख से इस मसौदे की समीक्षा कर सकेंगे और अपने लिखित सुझाव भी दे सकेंगे। रेल मंत्रालय और नीति आयोग मिलकर इस प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं। इसमें 100 ऐसे रूट की पहचान की गई है, जहां 150 निजी ट्रेन चलाए जाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह नीति आयोग और इंडियन रेलवे ने 'प्राइवेट पार्टिसिपेशन' नाम से डिस्कशन पेपर पेश किया था। इसमें 150 नए रूट की बात की गई थी। जिसमें मुंबई सेंट्रल-नई दिल्ली, नई दिल्ली-पटना, इलाहाबाद-पुणे और दादर-वडोदरा सहित कई रेलमार्ग शामिल हैं। इन रूट को 10-12 क्लस्टर में बांटा जाएगा। योजना के मुताबिक निजी संचालकों को बाजार के आधार पर किराया तय करने का अधिकार होगा। इसके अलावा निजी संचालक ट्रेन के ठहराव और क्लास में भी अपने हिसाब से परिवर्तन कर सकेंगे।

जीएसटी चोरी रोकने के उपाय तलाशने को बनेगी समिति

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रतीकात्मक फोटो

- केंद्र और राज्यों के अधिकारियों को समिति में किया जाएगा शामिल
- आइजीएसटी रिफंड और विदेशी मुद्रा के लिए एक ही बैंक खाते पर विचार

जीएसटी चोरी और फर्जी रिफंड के दावों पर लगाम लगाने के उपायों की तलाश के लिए केंद्र और राज्यों के अधिकारियों की एक समिति गठित होगी। साथ ही सरकार रिस्की और नए निर्यातकों के आइजीएसटी रिफंड को उनके विदेशी मुद्रा की आमदनी से जोड़ने की संभावनाओं पर भी विचार कर रही है ताकि आइजीएसटी के फर्जी रिफंड के दावों पर लगाम लग सके।

मंगलवार को राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे की अध्यक्षता में हुई दूसरी राष्ट्रीय जीएसटी कांफ्रेंस में इन बातों पर सहमति बनी। कांफ्रेंस में सेंट्रल टैक्स जोन, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआइसी), सीबीडीटी के देशभर के सभी चीफ कमिश्नर, राज्यों के टैक्स कमिश्नरों और डायरेक्टर एफआइयू समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक टैक्स चोरी और रिफंड के फर्जी दावों को रोकने और जीएसटी रेवेन्यू की रफ्तार बढ़ाने के उपायों पर विचार के लिए बुलाई गई थी।

बैठक में सहमति बनी कि रिफंड के फर्जी दावों पर लगाम के उपाय और उन्हें तुरंत प्रभाव से लागू करने की संभावनाएं तलाशने के लिए केंद्र व राज्यों के अधिकारियों की एक समिति बने। समिति इनवर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में रिफंड के दावों और जीएसटी चोरी के मामलों पर भी विचार करेगी। समिति एक सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके आधार पर प्रावधानों को जनवरी के अंत से पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त बैठक में इनपुट टैक्स क्रेडिट के झूठे दावों के प्रमुख मामलों, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में होने वाले फ्रॉड व और फर्जी दावों की अनिवार्य तौर पर इनकम टैक्स विभाग से जांच कराए जाने पर भी सहमति बनी। सीबीआइसी, सीबीडीटी और जीएसटीएन में एक करार किया जाएगा जिसके तहत तीनों विभाग एक दूसरे से तिमाही आधार पर डाटा साझा करेंगे। अभी तक यह काम सालाना आधार पर होता है।

आरबीआइ और एनपीसीएल से विमर्श के बाद जीएसटी सिस्टम में दी गई बैंकिंग जानकारी के आधार पर बैंकिंग ट्रांजैक्शन तक पहुंच बनाने की संभावना के तहत निर्यातकों के लिए विदेशी मुद्रा आमदनी प्राप्त करने और रिफंड वितरण के लिए एक ही बैंक खाता रखना अनिवार्य करने के विकल्प पर विचार हुआ।

न्यूज गैलरी

टाटा संस की याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को टाटा संस की याचिका पर सुनवाई करेगा। इस याचिका में टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन सायरस मिस्त्री के पद बहाली वाले एनक्लैट के फैसले को चुनौती दी गई है। यह मामला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबड़े, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है। इससे पहले टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड ने 18 दिसंबर को एनक्लैट द्वारा सुनाए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसी मामले में टाटा समूह के मानद चेयरमैन रतन टाटा और ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी टीसीएस भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। (प्रेट्र)

सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम के पक्ष में सुनाया फैसला

नई दिल्ली : इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया से गुजर रही रिलायंस कम्युनिकेशंस को सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहत मिली है। कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वह आरकॉम को गारंटी के 104 करोड़ रुपये वापस लौटाए। इस मामले में टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल (टीडीएसएटी) ने दूरसंचार विभाग को गारंटी की राशि लौटाने का आदेश दिया था। टीडीएसएटी ने डीओटी से कहा था कि वह गारंटी में से स्पेक्ट्रम चार्ज काटकर बाकी राशि आरकॉम को वापस लौटा दे। डीओटी ने फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी। (प्रेट्र)

हाई स्पीड ट्रेन के लिए बीएसपी पटरियों को देगा मजबूती

भिलाई : भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) हाई स्पीड ट्रेन के लिए पटरियों की मजबूती पर जोर दे रहा है। रेल पटरी की शक्ति को और बढ़ाने के लिए स्टील प्रॉपर्टी को विकसित किया जाएगा। इसके लिए आइआइटी भिलाई और एनआइटी रायपुर से मदद ली जा रही है। इससे भविष्य में देश के भीतर ही हाई स्पीड ट्रेनों के लिए पटरियों का निर्माण हो सकेगा, जिससे विदेशों पर निर्भरता खत्म होगी। बीएसपी दुनिया में सबसे लंबी रेल पटरी बनाती है। यह छह दशक से रेलवे के लिए अपना योगदान दे रही है। (नईदुनिया)

एयर इंडिया की बिक्री के लिए ईओआइ के मसौदे को मंजूरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने एयर इंडिया की बिक्री के लिए अभिरुचि पत्र के मसौदे (ईओआइ) को मंजूरी दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाले मंत्रिसमूह ने इस अभिरुचि पत्र के मसौदे और एयर इंडिया के निजीकरण के लिए शेयर खरीद समझौते को मंजूरी प्रदान कर दी है।

ईओआइ और शेयर खरीद समझौता इसी महीने बोली लगाने वालों के लिए उपलब्ध हो जाने की उम्मीद है। मंत्रिसमूह की पिछली बैठक सितंबर 2019 में हुई थी। पिछले वर्ष ही एयर इंडिया स्पेशिफिक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म (एआइएसएएम) ने संकट में चल रही इस सरकारी विमानन कंपनी में 100 परसेंट हिस्सेदारी बेचने की योजना को मंजूरी दी थी। गौरतलब है कि 2018-19 में एयर इंडिया का कुल घाटा 8,556 करोड़ रुपये रहा था। वहीं कंपनी का कुल कर्ज बढ़कर 80,000 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुका है। सूत्रों के मुताबिक एआइएसएएम ने वीआरएस और डेट रिकंस्ट्रक्शन योजना को भी मंजूरी दे दी है। हालांकि इस बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है। इससे पहले एयर इंडिया प्रमुख अश्विनी लोहानी ने कंपनी बंद करने के कयासों को आधारहीन और गलत बताया है।

हड़ताल पर फैसला मतदान से

नई दिल्ली, आइएएनएस : एयर इंडिया के पायलट संगठन (आइसीपीए) ने गुप्त मतदान करने का फैसला किया है। इसके जरिये आइसीपीए यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी को एनसीएलटी के समक्ष ले जाया जाए अथवा बकाया वेतन मिलने तक हड़ताल की जाए। आइसीपीए का यह फैसला कंपनी की बिक्री के लिए अभिरुचि पत्र के मसौदे को मंजूरी मिलने से कुछ समय पहले ही सामने आया।

आर्थिक विकास की धुरी हैं व्यापारी : सीतारमण

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- वित्त मंत्री ने व्यापारियों के लिए कर व्यवस्था आसान बनाने का दिया भरोसा
- दुबई की तर्ज पर भारत में होगा वार्षिक मेगा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन

नई दिल्ली में मंगलवार को कैट की ओर से आयोजित राष्ट्रीय व्यापारी महाधिवेशन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (दाएं) को जयपुरी रजाई भेंट की गई। प्रेट्र

कर प्रक्रिया को आसान बनाने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए सरकार लगातार व्यापारियों से सुझाव ले रही है। रामलीला मैदान में व्यापारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय व्यापारी महाधिवेशन के दूसरे दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि व्यापारी समुदाय राजस्व संग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सरकार की भी कोशिश है कि उन्हें किसी प्रकार की अनुचित कठिनाई का सामना न करना पड़े।

व्यापारियों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी से इंस्पेक्टर राज समाप्त हुआ है। यह इस व्यवस्था की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जीएसटी की प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए सरकार लगातार उसमें बदलाव कर रही है। व्यापारियों के बिना भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना मुमकिन नहीं। वित्त मंत्री ने कहा कि व्यापारियों के हित को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने 2014 से 2019 के बीच कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। देश में आंतरिक व्यापार के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हमने सरकार में आते ही इसकी व्यवस्था की और इसके लिए अलग से उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआइआइटी) का गठन किया। यही नहीं हमने छोटे दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों के लिए पेंशन योजना भी शुरू की।

देश के विभिन्न राज्यों से आए व्यापारियों को संबोधित करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा, 'घरेलू व्यापार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार दुबई की तर्ज पर जल्द ही भारत में वार्षिक मेगा शॉपिंग फेस्टिवेल का आयोजन करने जा रही है। इससे आर्टिफिशियल ज्वैलरी, टेक्सटाइल, लेदर और हस्तशिल्प क्षेत्र के व्यापारियों को सीधे तौर पर फायदा होगा।'

व्यापारियों ने वित्त मंत्री से ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा सरकार की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) नीति का उल्लंघन करने समेत खुदरा व्यापारियों को प्रभावित कर रहे विभिन्न मुद्दों के समाधान की मांग की। वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि व्यापारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों की समीक्षा कर आवश्यक कदम उठाया जाएगा। तीन दिवसीय महाधिवेशन का समापन बुधवार को होगा। इसमें केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल शामिल होंगे।

स्पीड ब्रेकर से मुक्त किए जाएंगे राष्ट्रीय राजमार्ग

- एनएचएआइ की ओर से विशेष अभियान चलाकर हटाए जा रहे हैं स्पीड ब्रेकर
- फास्टैग की व्यवस्था लागू होने के बाद से टोल प्लाजा पर सुगम हुआ है यातायात

नई दिल्ली, प्रेट्र : आने वाले दिनों में आपको स्पीड ब्रेकर मुक्त राष्ट्रीय राजमार्ग देखने को मिल सकते हैं। सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों से स्पीड ब्रेकर हटाने के लिए विशेष अभियान चला रही है। हाइवे पर बाधा रहित यातायात के लिए यह फैसला किया गया है। इस अभियान में टोल प्लाजा को विशेष रूप से ध्यान में रखा जा रहा है।

फास्टैग की सुविधा लागू हो जाने के बाद यातायात की बड़ी बाधा से बहुत हद तक छुटकारा पाया जा चुका है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से टोल एकत्र करने के लिए पिछले महीने की 15 तारीख को फास्टैग की सुविधा लागू की गई थी।

केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि गति और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सड़कों का वर्गीकरण किया गया है, जिससे बिना किसी व्यवधान के सुरक्षित ड्राइविंग की जा सकती है। हालांकि कुछ स्थानों पर खतरे के चलते गति नियंत्रण आवश्यक होता है। स्पीड ब्रेकर हटाते समय इसे ध्यान में रखा जाएगा। स्पीड ब्रेकर हटाने का काम नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआइ) द्वारा किया जा रहा है।

राजमार्गों पर बाधा रहित यातायात में मददगार होगा यह कदम। प्रतीकात्मक फोटो

मंत्रालय ने बताया कि हाइवे पर स्पीड ब्रेकर होने से यात्रियों को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इससे समय तो नष्ट होता ही है, वाहन को नुकसान भी पहुंचता है। इसके अलावा बार-बार स्पीड कम-ज्यादा करने से ईंधन की खपत भी बढ़ जाती है। स्पीड ब्रेकर हटने से वाहन को एक समान गति में चलाया जा सकेगा, जिससे यात्रा में लगने वाले समय और लागत दोनों की बचत होगी। सरकार की यह कवायद एंबुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं के लिए बहुत लाभकारी होगी।

राजमार्गों से स्पीड ब्रेकर हटाने के फैसले से लंबी अवधि में और भी बेहतर नतीजे मिलने की उम्मीद है। ईंधन का आयात देश के ऊपर सबसे बड़ा बोझ है। भारत अपनी खपत का अधिकतर ईंधन आयात करता है। इससे विदेशी मुद्रा का खर्च बढ़ जाता है, जिसका असर चालू खाता घाटे पर पड़ता है। ईंधन की खपत में कटौती से विदेशी मुद्रा तो बचेगी ही, प्रदूषण भी कम होगा। सरकार के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से टोल कलेक्शन के फायदे दिखने शुरू हो गए हैं। स्पीड ब्रेकर हटने से हाइवे के यातायात में और सुधार होगा।

आधा किलो से ज्यादा गहने हैं तो देना होगा हिसाब

नईदुनिया, रायपुर

- रिटर्न फाइल करते समय जानकारी देना जरूरी
- पकड़े जाने पर स्रोत नहीं बता पाए तो लगेगा भारी टैक्स

आपके पास भी अगर ज्यादा आभूषण हैं, तो संभल जाएं। कैश ही नहीं आभूषणों का हिसाब देने में चूक से भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आयकर विभाग ने पिछले दिनों इस संबंध में नियमों पर स्पष्टीकरण दिया था। कर विशेषज्ञों के अनुसार अब आपको अपने गहनों की भी जानकारी देनी होगी कि कहां से और कैसे मिले। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो भारी-भरकम टैक्स के साथ ही दूसरी कार्रवाई भी झेलनी पड़ सकती है।

नोटबंदी के बाद से ही आयकर नियम सख्त किए जा रहे हैं। खासकर बेनामी संपत्ति वालों पर शिकंजा कसने के लिए। अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने पास बड़ी मात्रा में कैश के साथ सोने-चांदी के जेवर और अन्य आभूषण रखते हैं। पूछे जाने पर सभी का एक ही जवाब होता है कि यह उन्हें गिफ्ट में मिला है या शादी में। अब आपको बताना ही होगा कि सोना गिफ्ट में मिला है तो किससे मिला है। अगर आपने खरीदा है तो उसका बिल आपके पास होना चाहिए। कर विशेषज्ञ चेतन तारवानी का कहना है कि नियमानुसार अब आपको अपने गहनों का पूरा हिसाब रखना होगा। इन सभी चीजों की जांच विभाग करेगा और अगर आप जवाब से संतुष्ट नहीं कर पाए तो कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। अगर आपने लापरवाही बरती तो 77.25 फीसद टैक्स भरना पड़ सकता है।

जब्ती नहीं कर सकता विभाग : अगर आप अपने आभूषणों की जानकारी बैलेंस शीट में देते हैं और पूरा हिसाब भी आपके पास है तो विभाग आपके आभूषण जब्त नहीं कर सकता। इसलिए आपको यह ध्यान रखना ही होगा कि गहनों का पूरा हिसाब रखें।

यह बताना होगा

आपने गहने कमाई से खरीदे तो इसकी पूरी जानकारी दें कि कहां से और कितनी मात्रा में खरीदे

अगर आपको गहना फ्री में मिला है तो बैलेंस शीट में इसका भी पूरा ब्योरा रखें

इतना रख सकते हैं आभूषण	
महिलाएं	500 ग्राम
अविवाहित युवतियां	250 ग्राम
पुरुष	100 ग्राम

अघोषित आय छिपाने के लिए कई लोग करते हैं आभूषणों का संचय। प्रतीकात्मक फोटो

शेयर बाजार

पश्चिम एशिया में तनाव कम होने से मजबूत हुआ निवेशकों का मनोबल, पिछले सत्र की जोरदार गिरावट से उबरे घरेलू शेयर बाजार

सेंसेक्स पटरी पर लौटा, निफ्टी फिर हुआ 12 हजारी

मुंबई, प्रेट्र : ग्लोबल चिंताओं के चलते सोमवार को जोरदार गिरावट झेलने वाले भारतीय बाजारों में मंगलवार को रौनक लौटी। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 192.84 अंकों की बढ़त के साथ 40,869.47 पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में 550 से ज्यादा अंकों की बढ़त लेते हुए इसने 41,230.14 अंक का ऊंचा स्तर छू लिया था। हालांकि बाद में मुनाफावसूली ने बढ़त को थाम दिया। वहीं एनएसई का निफ्टी भी 59.90 अंक सुधरकर 12 हजार का मनोवैज्ञानिक आंकड़ा पार कर गया। यह 12,052.95 के स्तर पर बंद हुआ।

सेंसेक्स पैक में अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों में सबसे ज्यादा 2.10 परसेंट का उछाल दर्ज किया गया। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सन फार्मा, एनटीपीसी और एशियन पेंट्स के शेयर भी हरे निशान पर बंद हुए। वहीं इन्फोसिस, आइसीआइसीआइ बैंक, भारती एयरटेल, नेस्ले इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प और पावरग्रिड के शेयरों में गिरावट देखी गई। बीएसई में रियल्टी, बेसिक मटेरियल्स, एनर्जी, फाइनेंस और मेटल सेक्टर के शेयरों में 1.83 परसेंट तक की तेजी दर्ज की गई। वहीं टेलीकॉम, टेक, आइटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियों के शेयरों में 0.99 परसेंट तक की गिरावट दर्ज की गई।

ईरान-अमेरिका तनाव के कारण सोमवार को दर्ज की गई थी बड़ी गिरावट। प्रतीकात्मक फोटो

जानकारों के मुताबिक पश्चिम एशिया में फिलहाल तनाव नहीं बढ़ने की खबरों से शेयर बाजारों ने राहत की सांस ली है। ईरान की ओर से अमेरिका पर कोई बड़ी बदले की कार्रवाई नहीं होने से कच्चे तेल के भाव में स्थिरता देखी गई है। इससे दुनियाभर में निवेशकों का मनोबल मजबूत हुआ है। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपये में मजबूती से भी घारेलू बाजार को गति मिली। 11 पैसे की मजबूती के साथ रुपया प्रति डॉलर 71.82 के स्तर पर बंद हुआ। मंगलवार को एशिया के अन्य बाजारों में भी सुधार देखा गया। इस दौरान शंघाई, हांगकांग, टोक्यो और सियोल के शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुए। यूरोपीय शेयर बाजारों ने भी अपने शुरुआती सत्र में बेहतर प्रदर्शन किया।

सोना-चांदी के भाव में गिरावट

नई दिल्ली : मंगलवार को दिल्ली के प्रमुख सराफा बाजारों में सुस्ती का रुख रहा। सोना 420 रुपये की गिरावट के साथ 41,210 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिका। वहीं चांदी भी 830 रुपये फिसलकर 48,600 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई। इससे पहले सोमवार को सोना-चांदी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला था। जानकारों के मुताबिक डॉलर के मुकाबले रुपये में मजबूती और प्रॉफिट बुकिंग के चलते सोने के भाव में गिरावट देखी गई। ग्लोबल मार्केट में सोना 1,568 डॉलर और चांदी 18.19 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) पर बिके।

4 हजार मीटर से ज्यादा की ऊंचाई वाले सीमावर्ती क्षेत्र में नई हथियार प्रणालियां तैनात की है चीन ने। इनमें हल्के युद्धक टैंक टाइप-15 और 155-एमएम व्हीकल-माउंटेड होवित्जर तोप जैसे हथियार भी शामिल हैं। दरअसल, चीन ने भारत की सीमा से सटे तिब्बत में बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है।

ईरान की संसद ने अमेरिकी सेना को घोषित किया आतंकी

खाड़ी में तनाव ▸ कमांडर सुलेमानी की मौत पर उठाया कदम

पारित बिल में हमले का आदेश देने वालों को भी आतंकी करार दिया

तेहरान में मंगलवार को ईरानी संसद में अमेरिका के सभी सैन्य बलों को आतंकी करार देने वाले विधेयक के प्रति समर्थन व्यक्त करते सदस्य। एपी

तेहरान, एएफपी : ईरान की संसद ने मंगलवार को अमेरिका के सभी सैन्य बलों को आतंकी करार दिया। संसद में पारित एक बिल में कहा गया कि सभी अमेरिकी बलों, पेंटागन के कर्मचारियों, संबद्ध संगठनों, कमांडरों और कासिम सुलेमानी की शहादत का आदेश देने वालों को आतंकी घोषित किया जाता है। बीते शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने बगदाद एयरपोर्ट के करीब ड्रोन हमले में सुलेमानी को मौत की नींद सुला दिया था।

बिल में कहा गया, 'इन बलों के साथ सैन्य खुफिया, वित्तीय, तकनीकी, सेवा या माल ढुलाई समेत किसी भी तरह की सहायता को आतंकी कृत्य में सहयोग माना जाएगा।' ईरानी सांसदों ने अपने मुल्क के विशिष्ट बल रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कुद्स फोर्स को 20 करोड़ यूरो (करीब 1600 करोड़ रुपये) देने के समर्थन में भी मतदान किया।

सुलेमानी ईरान की सीमा से बाहर सैन्य अभियान को अंजाम देने वाले इसी बल के प्रमुख थे। वह ईरान में सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के बाद दूसरी सबसे ताकतवर हस्ती माने जाते थे।

अमेरिका को करार दिया था आतंकवाद प्रायोजक : ईरान की संसद में गत अप्रैल में जिस प्रस्ताव को अपनाया गया था, उसमें संशोधन के लिए ही मंगलवार को यह बिल पेश किया गया। संसद ने इससे पहले अमेरिका को आतंकवाद प्रायोजक और क्षेत्र में तैनात अमेरिकी बलों को आतंकी संगठन करार दिया था। अमेरिका की ओर से रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकी संगठन घोषित किए जाने के जवाब में ईरान की संसद में यह प्रस्ताव पारित हुआ था।

ईरान के विदेश मंत्री को नहीं मिला अमेरिकी वीजा

समाचार एजेंसी रायटर के अनुसार, अमेरिका ने ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ को वीजा देने से इन्कार कर दिया है। जरीफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की गुरुवार को होने वाली बैठक में हिस्सा लेना चाहते थे। इस बीच चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा, 'हम अमेरिका से जरीफ को वीजा देने का आग्रह करते हैं।' 1947 के संयुक्त राष्ट्र समझौते के तहत अमेरिका को ऐसा करना चाहिए।

सुलेमानी के जनाजे में भगदड़ से 32 लोगों की मौत

तेहरान, एएफपी : ईरान के शीर्ष कमांडर कासिम सुलेमानी के जनाजे में मंगलवार को भगदड़ मच गई। इसमें 32 लोगों की मौत हो गई। करीब दो सौ लोग घायल हुए हैं। इस घटना के चलते सुलेमानी के शव को सुपुर्द-ए-खाक नहीं किया गया।

ईरानी मीडिया के अनुसार, जनरल सुलेमानी को दफनाने के लिए उनके गृहनगर करमान में निकाले गए जनाजे के दौरान भगदड़ मच गई। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। ऑनलाइन पोस्ट किए गए वीडियो में एक सड़क पर कई लोग अचेत दिखे और कुछ लोग उनकी मदद के लिए चिल्लाते सुनाई दिए। ईरान के सरकारी टीवी ने इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के प्रमुख पिरहोसैन कोलिवंद के हवाले से हताहतों की संख्या के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, 'जनाजे के दौरान भगदड़ से कुछ हमवतन लोगों की मौत हो गई और कुछ घायल हो गए।' जबकि अर्ध सरकारी न्यूज एजेंसी इसना ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि भारी भीड़ के कारण सुलेमानी को सुपुर्द-ए-खाक करने में कुछ देरी होगी। उन्होंने हालांकि यह नहीं बताया कि उन्हें कब दफनाया जाएगा।

ईरान के करमान में मंगलवार को शीर्ष कमांडर कासिम सुलेमानी के जनाजे में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। एपी

तेहरान में जुटे थे दस लाख लोग : ईरान की राजधानी तेहरान में सोमवार को निकाले गए सुलेमानी के जनाजे में करीब दस लाख लोग शामिल हुए थे। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने जनाजे की नमाज पढ़ी। सुलेमानी को श्रद्धांजलि देते वक्त उनकी आंखें नम हो गई थीं।

न्यूज गैलरी

न्यूयॉर्क में जज नियुक्त की गईं दो भारतवंशी महिलाएं

न्यूयॉर्क : भारतीय मूल की दो महिलाओं को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के क्रिमिनल और सिविल कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है। जज अर्चना राव की क्रिमिनल कोर्ट और जज दीपा अंबेकर की सिविल कोर्ट में पुनर्नियुक्ति हुई है। इनकी नियुक्ति न्यूयॉर्क के मेयर बिल डी ब्लासियो ने की है। अर्चना राव को जनवरी, 2019 में सिविल कोर्ट में कार्यवाहक जज नियुक्त किया गया था। वह अभी क्रिमिकल कोर्ट में अपनी सेवाएं दे रही हैं। इससे पहले उन्होंने करीब 17 साल तक न्यूयॉर्क काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटार्नी के दफ्तर में काम किया था। अर्चना ने वासर कॉलेज से स्नातक और फोरधम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ से कानून की पढ़ाई की है। दीपा अंबेकर (43) अभी क्रिमिनल कोर्ट में कार्यरत हैं। उनकी पहली नियुक्ति मई, 2018 में सिविल कोर्ट में कार्यवाहक जज के तौर पर हुई थी। इससे पहले दीपा ने बतौर वरिष्ठ वकील न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल में काम किया था। वह लीगल एड सोसायटी में स्टाफ अटार्नी के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। उन्होंने मिशिगन यूनिवर्सिटी से स्नातक और रटगर्स लॉ स्कूल से कानून की डिग्री ली है। (प्रेट्र)

ननकाना साहिब पर पाक की 'चोरी और सीनाजोरी'

इस्लामाबाद : ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर भीड़ के हमले और एक सिख युवक की हत्या के मामले में पाकिस्तान उल्टे भारत पर ही आरोप लगा रहा है। मंगलवार को उसने भारत के उप उच्चायुक्त गौरव अहलूवालिया को बुलाकर भारत पर इस मसले पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि अहलूवालिया को दक्षिण एशिया और सार्क मामलों के महानिदेशक जाहिद हफीज चौधरी ने समन किया और ननकाना साहिब पर हमले और पेशावर में सिख युवक की हत्या को गलत बताते हुए विरोध जताया। यही नहीं चौधरी यह बताने से भी नहीं चूके कि पाकिस्तान का संविधान सभी नागरिकों का समानता का अधिकार देता है। पाकिस्तान सरकार सभी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि भारत ने सोमवार को पाकिस्तान के कार्यवाहक उच्चायुक्त सैयद हैदर शाह को समन किया और ननकाना साहिब पर हमले और सिख युवक की हत्या पर कड़ा विरोध जताया था। इस हत्याकांड ने एक बार पाक की कलई खोल दी है। (एजेंसियां)

ईरान की धमकी के बाद खतरे से निपटने की तैयारी में जुटा अमेरिका

न्यूयॉर्क टाइम्स से

वाशिंगटन : अमेरिकी हवाई हमले में ईरान के शीर्ष कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत के बाद पश्चिम एशिया में संकट गहरा गया है। ईरान ने धमकी दी है कि वह अमेरिका से सुलेमानी की मौत का बदला लेगा। ऐसे में ईरान के किसी भी खतरे या छद्म हमले से निपटने के लिए इराक और सीरिया में तैनात अमेरिकी सेना पूरी तैयारी में जुट गई है। इसके लिए पश्चिम एशिया में रक्षा साजो-सामान के साथ ही अमेरिकी सैनिकों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है।

सुलेमानी की मौत के बाद ईरान की ओर से मिल रही धमकियों से निपटने के लिए अमेरिका का रक्षा विभाग पेंटागन क्षेत्र में अपने सैन्य अड्डों के लिए अतिरिक्त बल भेज रहा है। करीब 4500 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती का आदेश दिया गया है। ये अतिरिक्त सैनिक मुख्य रूप से क्षेत्र में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों और परिसरों की सुरक्षा पुख्ता करेंगे और किसी भी संभावित हमले का जवाब देंगे। अमेरिकी सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नॉर्थ कैरोलिना स्थित 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के करीब चार हजार सैनिकों को कुवैत रवाना किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य कई कोर के सैकड़ों पैराट्रूपर्स भी भेजे जा रहे हैं।

▸ **अमेरिकी सैन्य अड्डों और परिसरों की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए भेजे जा रहे अतिरिक्त सैनिक**

पश्चिम एशिया में रहती है इनकी मौजूदगी

- समुद्री गश्ती विमान, अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट और बमवर्षक बी-52
- पैट्रियॉट एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम और रीपर ड्रोन
- विमानवाहक पोत यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन के नेतृत्व में युद्धपोतों का बेड़ा
- 2200 नौसैनिकों वाली 26वीं मरीन यूनिट भी भेजी जा रही है

सेलफोन नहीं रख सकेंगे सैनिक

रक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पश्चिम एशिया में भेजे जा रहे सैनिक अपने साथ सेलफोन नहीं ले जा सकेंगे। मोबाइल फोन से सोशल मीडिया पर होने वाले पोस्ट से सैनिकों की लोकेशन की जानकारी मिल सकती है।

खाड़ी में तैनात है 65 हजार अमेरिकी सैनिक

इराक में 5,500 और सीरिया में 600 सैनिकों समेत सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों में अभी 45 से 65 हजार तक अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। पेंटागन ने गत मई में ईरान के साथ तनाव बढ़ने पर फारस की खाड़ी के क्षेत्र में 14 हजार अतिरिक्त सैनिक तैनात किए थे।

भूराजनीतिक तनाव इस सदी के उच्चतम स्तर पर : गुतेरस

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : ईरान के शीर्ष कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या पर अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने कहा है कि भूराजनीतिक तनाव इस सदी में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। देश अप्रत्याशित फैसले ले रहे हैं, जिससे गलतफहमी का गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। गुतेरस ने यहां संवाददाताओं से कहा, 'नया साल हमारी दुनिया में उथल-पुथल के साथ शुरू हुआ है। हम खतरनाक समय में जी रहे हैं।'

उन्होंने आगाह किया कि परमाणु अप्रसार भी अब ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। गुतेरस ने कहा कि इन तनावों के बीच व्यापार और तकनीकी संघर्ष के चलते वैश्विक बाजार अस्थिर हो रहे हैं, विकास की गति कम हो रही है और असमानताएं बढ़ रही हैं।

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा कि हमारा ग्रह जल रहा है। जलवायु संकट बढ़ता जा रहा है। विश्व के कई हिस्सों में हम बहुत से लोगों को निराश और गुस्से में देख रहे हैं। हम खासकर अफ्रीका में बढ़ती सामाजिक अशांति, बढ़ते चरमपंथ, राष्ट्रवाद, कट्टरता और आतंकवाद को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति बहुत दिनों तक नहीं रहने वाली है। मैं हाल में बढ़े वैश्विक तनाव को लेकर बहुत चिंतित हूं। मैं दुनियाभर के प्रमुख अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में हूं।

एंटोनियो गुतेरस। फाइल

▸ **संरा महासचिव बोले, उथल-पुथल के साथ शुरू हुआ नया साल**

▸ **विश्व के कई हिस्सों में बहुत से लोग निराश और गुस्से में हैं**

कार्लोस गोन की पत्नी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

टोक्यो, एएफपी : कार निर्माता कंपनी निसान के पूर्व सीईओ कार्लोस गोन की पत्नी कैरल गोन के खिलाफ मंगलवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। गोन पर जापान में वित्तीय अनियमितता का मुकदमा चल रहा है। वह जमानत पर थे और वहां से तिकड़म कर फरार हो गए। वह 29 दिसंबर को लेबनान पहुंच गए थे।

अभियोजकों ने एक बयान में कहा कि उन्हें इस संदेह के आधार पर वारंट प्राप्त हुआ है कि कैरल ने अप्रैल में टोक्यो जिला अदालत में गवाही के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति के साथ मुलाकात के बारे में गलत बयान दिए थे। कार्लोस को कड़ी शर्तों पर जमानत पर रिहा किया गया था, जिसमें पत्नी से संपर्क पर रोक शामिल था। कार्लोस की दूसरी पत्नी कैरल ने अपने पति को रिहा करने के लिए अभियान का नेतृत्व किया था। उन्होंने जापानी अभियोजकों की आलोचना करते हुए पति को निर्दोष बताया था। उधर, गोन परिवार के प्रवक्ता ने वारंट को निराशाजनक कदम बताते हुए कहा कि इस मुद्दे पर कार्लोस बुधवार को बेरूत में एक प्रेस कांफ्रेंस करेंगे।

ट्रंप पर महाभियोग सुनवाई में गवाही देना चाहते हैं बोल्टन

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) जॉन बोल्टन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ संसद के ऊपरी सदन सीनेट में होने वाली महाभियोग की सुनवाई में गवाही देने की इच्छा जताई है। उनके बयान से ट्रंप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ट्रंप ने बोल्टन को गत सितंबर में एनएसए पद से बर्खास्त कर दिया था।

बोल्टन के इस एलान से ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया में एक नई कड़ी जुड़ गई है। अमेरिका के इतिहास में ट्रंप तीसरे राष्ट्रपति हैं, जिन पर महाभियोग चलाया जा रहा है। यह हालांकि अभी तय नहीं है कि सीनेट में महाभियोग की सुनवाई कब शुरू होगी। 71 वर्षीय बोल्टन ने सोमवार रात को कहा, 'मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर सीनेट मेरी गवाही के लिए समन भेजती है तो मैं इसका सामना करने के लिए तैयार हूं। मैं बतौर नागरिक के साथ ही पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर भी पर अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहता हूं।'

गत 18 दिसंबर को विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुमत वाले संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग पर मुहर लगाई थी। ट्रंप के खिलाफ सत्ता के दुरुपयोग और संसद की कार्यवाही में रोड़ा अटकाने के आरोप तय किए गए हैं। सीनेट में हालांकि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी बहुमत में है। इसलिए यह माना जा रहा है कि सीनेट में महाभियोग गिर सकता है। डेमोक्रेट्स भी यह आरोप लगा चुके हैं कि उन्हें सीनेट में निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद नहीं है।

▸ **पूर्व एनएसए को राष्ट्रपति ट्रंप ने गत सितंबर में पद से कर दिया था बर्खास्त**

▸ **सीनेट में पेश होने की इच्छा जताई, इसी सदन में होनी है सुनवाई**

इस कारण से गवाही अहम : सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी के नेता मिच मैककोनेल ने सुनवाई में पूर्व एनएसए बोल्टन की गवाही की मांग की है। उन्होंने दलील दी कि बोल्टन ऐसे अहम गवाह हैं, जिन्हें यूक्रेन मामले में ट्रंप की भूमिका की जानकारी हो सकती है। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने गत 25 जुलाई को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से फोन पर बात के दौरान राष्ट्रपति चुनाव में अपने संभावित डेमोक्रेट प्रतिद्वंद्वी जो बिडेन के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए दबाव बनाया था।

पाक में एफएटीएफ की शर्तें पूरा करने वाला बिल पारित

दूसरे देशों से सूचनाओं और अपराधियों की अदला-बदली को लेकर किए गए हैं खास प्रावधान

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने एफएटीएफ की एक महत्वपूर्ण शर्त को पूरा करने संबंधी अहम विधेयक पारित किया है। इसमें सूचनाओं और अपराधियों की अदला-बदली को लेकर कुछ खास प्रावधान किए गए हैं। बता दें कि वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) ने पाक को फरवरी 2020 तक 'ग्रे' सूची में रखा है। इसने अक्टूबर में चेतावनी दी थी कि यदि इस्लामाबाद ने 27 सवालों की सूची में शेष 22 बिंदुओं का अनुपालन नहीं किया तो उसे काली सूची में डाल दिया जाएगा। पाक ने छह दिसंबर को एफएटीएफ को 22 सवालों का जवाब देते हुए एक रिपोर्ट सौंपी थी।

परस्पर कानूनी सहायता (आपराधिक विषय) विधेयक, 2019 पाकिस्तान की संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली में सोमवार शाम पारित किया गया। इस कानून के तहत सरकार गवाहों, संदिग्धों और अपराधियों के ठिकानों तथा उनकी पहचान के बारे में जानकारी के लिए किसी देश को परस्पर कानूनी सहायता का अनुरोध भेजने के लिए सक्षम हो सकेगी। इसके बाद उचित प्रक्रिया के तहत उस व्यक्ति को पाकिस्तान की हिरासत में स्थानांतरित किया जा सकता है। पाकिस्तान उस देश की कानूनी प्रक्रिया के जरिये जांच या कार्यवाही से जुड़ी संपत्तियों को जब्त या कुर्क भी कर सकता है। सदन में इस विधेयक को संसदीय कार्य राज्य मंत्री अली मुहम्मद खान ने पेश किया। बिल का विरोध करते हुए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के संसदीय नेता सैय्यद नावेद कमर ने विधेयक को पाकिस्तान के नागरिकों के मूल अधिकारों के खिलाफ बताया। उन्होंने दावा किया कि इस बिल की मंजूरी मिलने के बाद सरकार विदेशों से सूचनाएं प्राप्त करने में जहां सक्षम हो जाएगी, वहीं बगैर किसी संधि पर हस्ताक्षर किए अपने नागरिकों को अन्य देशों की मांग पर प्रत्यर्पित भी कर सकेगी।

संघीय गृह सचिव को मिलेंगी असीम शक्तियां : यह विधेयक संघीय गृह सचिव को विदेशी बैंक खातों और किसी नागरिक द्वारा किए गए लेनदेन के बारे में सूचना मांगने की असीम शक्तियां देगा। पीएमएल (एन) ने भी विधेयक का विरोध किया और आरोप लगाया कि पाकिस्तान जैसे देशों को उपनिवेश बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि यह देश (पाकिस्तान) उन पर वित्तीय रूप से निर्भर है।

चीन-पाक मुक्त व्यापार समझौते का दूसरा चरण शुरू : चीन-पाकिस्तान मुक्त व्यापार समझौते का दूसरा चरण एक जनवरी से लागू हो गया। इस समझौते के तहत एक हजार से अधिक पाकिस्तान उत्पादों को शून्य शुल्क की सुविधा प्रदान की गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार चीन के साथ पाकिस्तान का व्यापार घाटा 2018 में लगभग 9.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग सत्तर हजार करोड़ रुपये) के स्तर पर पहुंच गया है। पहले चरण पर दोनों देशों ने वर्ष 2006 में दस्तखत किए थे।

जनरल बाजवा का कार्यकाल बढ़ाने का विधेयक भी पास

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान की संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली ने मंगलवार को सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल तीन साल बढ़ाने संबंधी बिल समेत तीन महत्वपूर्ण विधेयक पारित कर दिए। इन विधेयकों को अब संसद के उच्च सदन सीनेट में पेश किया जाएगा। रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने सोमवार को इन विधेयकों को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी और विश्वासपात्र माने जाने वाले बाजवा का तीन साल का कार्यकाल पिछले साल 29 नवंबर को खत्म होना था। लेकिन प्रधानमंत्री ने 19 अगस्त को एक अधिसूचना जारी कर क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति का हवाला देते हुए 59 वर्षीय सेना प्रमुख के कार्यकाल की अवधि तीन साल बढ़ा दी थी। गत 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस आदेश पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि सेना प्रमुख के कार्यकाल को विस्तार देने का कोई कानून नहीं है। शीर्ष अदालत ने सरकार के आश्वासन के बाद जनरल बाजवा को छह महीने का सेवा विस्तार दिया था। सरकार ने अदालत को संसद में छह महीने के भीतर सेना प्रमुख के विस्तार और पुनर्नियुक्ति को लेकर एक कानून पारित कराने का आश्वासन दिया था।

ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग

न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, विक्टोरिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया प्रांतों से पकड़े गए लोगों में कई नाबालिग भी शामिल

आगजनी करने के आरोप में सैकड़ों गिरफ्तार

कैनबरा, आइएएनएस : ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जानबूझकर आग लगाने के आरोप में अब तक सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आग से बुरी तरह प्रभावित न्यू साउथ वेल्स (एनएसडब्ल्यू), क्वींसलैंड, विक्टोरिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया प्रांतों से पकड़े गए इन लोगों में कई नाबालिग भी हैं।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, अकेले न्यू साउथ वेल्स में ही नवंबर से अब तक 183 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 24 पर जानबूझकर जंगलों में आग लगाने का आरोप है। विक्टोरिया में 43 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्वींसलैंड में पकड़े गए 101 लोगों में 70 फीसद नाबालिग हैं। स्विनबर्न यूनिवर्सिटी के फोरेंसिक बिहेवियरल साइंस के निदेशक जेम्स ओग्लॉफ के मुताबिक पचास फीसदी जगहों पर आग जानबूझकर लगाई गई थी। जिन लोगों ने ऐसा किया था वह आग देखने में रुचि रखते हैं। मेलबर्न यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर जेनेट स्टेनली ने कहा, आग लगाने वाले किसी वर्ग विशेष से नहीं आते। लेकिन देखने से ऐसा लगता है उनकी परवरिश अच्छे माहौल में नहीं हुई और बचपन में उन्हें उपेक्षा का सामना करना पड़ा है।

आग लगने से कंगारू द्वीप पर फ्लाइंडर्स चेज नेशनल पार्क पूरी तरह जल कर खाक हो गया है।

चिली तक पहुंचा आग का धुआं : ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग का धुआं दक्षिणी अमेरिकी देश चिली तक पहुंच गया है। मौसम विज्ञानी एडिटा अमाडोर ने सोमवार को कहा, धुएं को सेंट्रल चिली में आसानी से देखा जा सकता है। आसमान पर धुंध ही धुंध दिख रही है जबकि सामान्य दिनों में यहां आसमान साफ रहता है। आने वाले दिनों में इसके अर्जेंटीना की तरफ बढ़ने की संभावना है।

ब्लेक से उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भारी बारिश : चक्रवात ब्लेक के चलते मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के उत्तर-पश्चिमी तट पर भारी बारिश हुई। तटीय शहर ब्रूम में 102 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं से नुकसान पहुंचा। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, चक्रवात के चलते 24 घंटे में 14 हजार की आबादी वाले इस शहर में छह इंच बारिश हुई।

जिला-उल-हक पर किताब की प्रतियां आइएसआइ ने कीं जब्त

कराची, एपी : पाकिस्तानी उपन्यासकार और न्यूयार्क टाइम्स के स्तंभकार का कहना है कि उसके देश के पूर्व तानाशाह जिया-उल-हक पर लिखी उसकी किताब की सभी प्रतियां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ ने जब्त कर ली हैं। इसके लिए आइएसआइ ने उसके प्रकाशक के यहां छापेमारी भी की है। पाकिस्तानी उपन्यासकार मुहम्मद हनीफ ने मंगलवार को बताया कि विगत सोमवार को आइएसआइ ने कराची में छापे डाले।

हनीफ की चर्चित किताब 'ए केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज' वर्ष 2008 में अंग्रेजी में प्रकाशित हुई थी। तब भी यह किताब खूब चर्चा में आई थी। इसमें लेखक ने दावा किया था कि वर्ष 1988 में विमान में रखी आम की पेटी में छिपे बम में विस्फोट करके तत्कालीन तानाशाह जिया उल हक की हत्या की गई थी। हालांकि इस हादसे में हक के अलावा अमेरिकी राजदूत अर्नाल्ड राफेल और तत्कालीन आइएसआइ प्रमुख जनरल अख्तर अब्दुर रहमान भी मारे गए थे।

बच्चे की मौत के मामले में कंपनी देगी 350 करोड़ का मुआवजा

फिलाडेल्फिया, एपी : स्वीडन की दिग्गज होम फर्निशिंग कंपनी आइकिया दो साल के बच्चे के माता-पिता को 4.6 करोड़ डॉलर (करीब 350 करोड़ रुपये) का हर्जाना देने को सहमत हो गई है। कंपनी द्वारा बनाई गई 32 किलो की आलमारी गिरने से वर्ष 2017 में अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के ब्यूना पार्क निवासी दो वर्षीय बच्चे जोजेफ डुडेक की मौत हो गई थी। उसके माता-पिता ने 2018 में फिलाडेल्फिया में कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

बच्चे के पिता ने आरोप लगाया था कि कंपनी द्वारा बनाई गई आलमारियां गिरने से कई बच्चे घायल हो चुके हैं और कुछ की मौत भी हो गई। इसके बावजूद कंपनी उपभोक्ताओं को यह बताने में विफल रही कि बिना दीवारों पर फिट किए इस आलमारी को प्रयोग नहीं करें। लगातार आ रही शिकायतों के बाद कंपनी ने इन अलमारियों को 2016 में वापस ले लिया था। समझौते के तहत आइकिया को ना केवल करीब 350 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा बल्कि आम लोगों को कंपनी द्वारा आलमारी वापस लेने के बारे में भी बताना होगा।

▸ **आलमारी गिरने से कैलिफोर्निया में दो वर्षीय बच्चे की हुई थी मौत**

▸ **2018 में आइकिया के खिलाफ माता-पिता ने दर्ज कराया था केस**

डुडेक परिवार मिलने वाले मुआवजे में से दस लाख डॉलर (करीब सात करोड़ रुपये) उन संगठनों को दान करेगा, जिन्होंने इसके लिए आवाज उठाई। परिवार ने कहा शायद यह पहला मामला है जिसमें इतनी बड़ी रकम बतौर मुआवजा दी जा रही है। पूरे मामले पर कंपनी ने कहा है, कोई भी मुआवजा होने वाली दुखद घटनाओं को बदल नहीं सकता। हमें इस बात से संतोष है कि इस मुद्दे पर चली अदालती कार्यवाही एक मुकाम तक पहुंची।

ये भी जानिए

भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टी-20 मुकाबला शुरू होने से पहले एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। कप्तान विराट कोहली मजाकिया लहजे में हरभजन सिंह के एक्शन में गेंदबाजी करते दिखे।

टीम इंडिया का सीरीज में शानदार आगाज

दूसरे टी-20 में श्रीलंका को सात विकेट से हराया शार्दुल ने झटके तीन विकेट, भारत 1-0 से आगे

नईदुनिया, इंदौर: भारत के शार्दुल ठाकुर की अगुआई में युवा गेंदबाजों ने बल्लेबाजों के अनुकूल मानी जाने वाली होलकर स्टेडियम की पिच पर श्रीलंका को दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में सात विकेट से शिकस्त दी। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में नौ विकेट पर 142 रन बनाए। भारत की ओर से तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने 23 रन देकर तीन विकेट झटके, जबकि नवदीप सैनी और कुलदीप यादव को दो-दो विकेट मिले। जवाब में भारतीय टीम ने 17.3 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 144 का स्कोर कर मैच अपने नाम किया। मेजबान टीम की तरफ से सर्वाधिक रन लोकेश राहुल (45) ने बनाए। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया और लगातार गेंदबाजी में बदलाव की उनकी रणनीति बल्लेबाजों की मददगार इस पिच पर कारगर साबित हुई। श्रीलंकाई पारी के दौरान उन्होंने शुरुआत से ही गेंदबाजों में बदलाव किया, जिससे श्रीलंकाई बल्लेबाज लय हासिल करने से वंचित रहे और भारत को लगातार अंतराल में विकेट भी मिलते चले गए, जिससे विपक्षी टीम बड़ा स्कोर नहीं बना सकी।

पहले पांच ओवरों में चार बदलाव: श्रीलंकाई पारी के दौरान पहला ओवर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने फेंका। चोट के बाद भारतीय टीम में वापसी करने वाले बुमराह की पहली ही गेंद वाइड रही। इस ओवर में एक चौका भी लगा। दूसरे छोर से शार्दुल ठाकुर ने मोर्चा संभाला। अविष्का फर्नांडो और दनुष्का गुणतिलका ने शुरुआत संभालकर की। श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने दोनों छोर से करीब छह की औसत से रन बटोरे। बल्लेबाजों की लय बिगाड़ने के लिए कप्तान ने लगातार गेंदबाजों में बदलाव किया। कोहली ने तीसरे ओवर में नवदीप सैनी को और पांचवें ओवर में वाशिंगटन सुंदर को गेंद थमाई। गुणतिलका ने सुंदर की पहली ही गेंद पर रिवर्स स्वीप से चौका जड़ा। लेकिन, इसी ओवर की पांचवीं गेंद पर उन्होंने मजबूती से बढ़ती इस साझेदारी को तोड़कर टीम को पहली सफलता दिलाई। सुंदर ने पांचवीं गेंद पर फर्नांडो को मिडऑफ पर नवदीप सैनी के हाथों कैच कराया। फर्नांडो और गुणतिलका ने पहले विकेट के लिए 38 रन जोड़े। श्रीलंका ने सातवें ओवर में 50 रन पूरे किए। नवदीप ने अगले ओवर में गुणतिलका के डंडे बिखरते हुए उनकी पारी का अंत किया। करीब 148 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी यॉर्कर गुणतिलका के डंडे ले उड़ी। गुणतिलका ने 21 गेंदों पर तीन चौकों की मदद से 20 रन बनाए। भारत ने इसी ओवर में एक रन आउट का मौका गंवा दिया। पांचवीं गेंद पर ओशाडा फर्नांडो और कुशल परेरा एक तेज रन के लिए दौड़े, लेकिन क्षेत्ररक्षक श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी छोर पर गेंद फेंकी, जबकि कुशल बल्लेबाजी छोर पर पहुंचने से काफी दूर थे।

नौवें ओवर में लगा पहला छक्का: श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने शुरुआत से चौके लगाए, लेकिन मैच का पहला छक्का लगभग आधे ओवर बीत जाने के बाद ही लगा सके। श्रीलंकाई पारी का पहला छक्का सुंदर द्वारा फेंके गए मैच के नौवें ओवर में लगा। पांचवीं गेंद पर कुशल परेरा ने डिप मिडविकेट पर यह छक्का जड़ा। ओशाडा फर्नांडो और कुशल परेरा ने धीरे-धीरे पारी को आगे बढ़ाया।

कुलदीप ने दिए दोहरे झटके: 11वें ओवर में कोहली ने कुलदीप यादव को गेंद थमाई। तीसरी ही गेंद पर ओशाडा (10) ने आगे बढ़कर मारने का प्रयास किया, लेकिन वह गेंद चूक गए और रिषभ पंत ने स्टंप कर उन्हें चलता किया। अपने अगले ओवर में कुलदीप ने कुशल परेरा का महत्वपूर्ण विकेट लिया। कुलदीप की ऑफ स्टंप से बाहर फेंकी गेंद पर कुशल ने मारने का प्रयास किया, जिसे लांगऑन पर शिखर धवन ने लपक लिया। परेरा ने 28 गेंदों पर तीन छक्कों की मदद से 34 रन बनाए। भानुशा राजपक्षे ने कुलदीप के इसी ओवर में एक रन लेकर टीम के 100 रन पूरे किए। हालांकि वह ज्यादा देर नहीं टिक सके और अगले ही ओवर में नवदीप का शिकार बनें।

शार्दुल ने पांच गेंदों में तीन विकेट झटके: एक बार फिर बदलाव के तहत लौटे बुमराह ने 17वें ओवर में विकेट लेते हुए कोहली की बदलाव की रणनीति को सही साबित किया। बुमराह की सीधी स्टंप्स पर फेंकी गई गेंद को दासुन शनाका जल्दी खेल बैठे और गेंद सीधे उनके स्टंप्स में जा लगी। दूसरे छोर पर धनंजय डिसिल्वा ने कुछ शॉट जरूर खेले। शार्दुल ने एक ही ओवर में तीन विकेट चटकाते हुए श्रीलंका की रही-सही उम्मीदों को भी खत्म कर दिया।

स्कोर बोर्ड

टॉस : भारत (गेंदबाजी) — मैन ऑफ द मैच : नवदीप सैनी

श्रीलंका — 142/9 (20 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
दनुष्का गुणातिलका बो. सैनी	20	21	03	00
अविष्का फर्नांडो का. सैनी बो. सुंदर	22	16	05	00
कुशल परेरा का. धवन बो. कुलदीप	34	28	00	03
ओशादा फर्नांडो स्टं. पंत बो. कुलदीप	10	09	01	00
भानुका राजपक्षे का. पंत बो. सैनी	09	12	01	00
दासुन शनाका बो. बुमराह	07	08	00	00
धनंजय डिसिल्वा का. दुबे बो. ठाकुर	17	13	02	00
वनिंदु हसरंगा नाबाद	16	10	03	00
इसुरु उदाना का. सैनी बो. ठाकुर	01	02	00	00
लसित मलिंगा का. कुलदीप बो. ठाकुर	00	01	00	00
लाहिरु कुमारा नाबाद	00	00	00	00

अतिरिक्त : (बा-1, लेबा-1, वा-4) 6
कुल : 20 ओवर में नौ विकेट पर 142 रन

विकेट पतन : 1-38 (अविष्का, 4.5), 2-54 (दनुष्का, 7.4), 3-82 (ओशादा, 11.3), 4-97 (कुशल, 13.2), 5-104 (राजपक्षे, 14.5), 6-117 (दासुन, 16.6), 7-128 (धनंजय, 18.2), 8-130 (इसुरु, 18.5), 9-130 (मलिंगा, 18.6)

गेंदबाजी :
जसप्रीत बुमराह 4-0-32-1
शार्दुल ठाकुर 4-0-23-3
नवदीप सैनी 4-0-18-2
वाशिंगटन सुंदर 4-0-29-1
कुलदीप यादव 4-0-38-2

भारत — 144/3 (17.3 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
लोकेश राहुल बो. हसरंगा	45	32	06	00
शिखर धवन एलबीडब्ल्यू बो. हसरंगा	32	29	02	00
श्रेयस अय्यर का. शनाका बो. लाहिरु	34	26	03	01
विराट कोहली नाबाद	30	17	01	02
रिषभ पंत नाबाद	01	01	00	00

अतिरिक्त : (बा-1, लेबा-1) 2
कुल : 17.3 ओवर में तीन विकेट पर 144 रन

विकेट पतन : 1-71 (राहुल, 9.1), 2-86 (धवन, 11.2), 3-137 (अय्यर, 17.1)

गेंदबाजी :
लसित मलिंगा 4-0-41-0
लाहिरु कुमारा 3.3-0-30-1
धनंजय डिसिल्वा 2-0-15-0
दासुन शनाका 4-0-26-0
वनिंदु हसरंगा 4-0-30-2

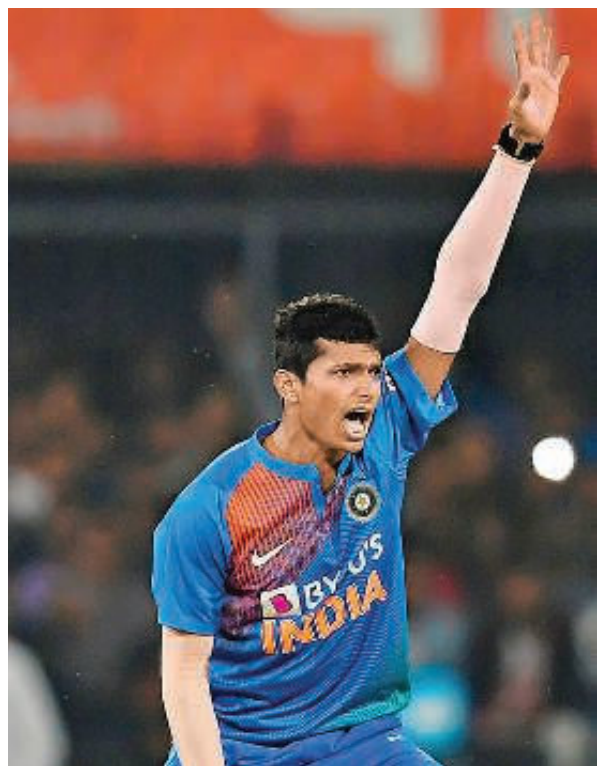

दूसरे टी-20 में श्रीलंका के अविष्का फर्नांडो के खिलाफ आउट की अपील करते भारतीय तेज गेंदबाज नवदीप सैनी। ● प्रेट्र

मोबाइल टॉर्च से जगमग हुआ होलकर स्टेडियम

इंदौर: श्रीलंकाई पारी के 10वें ओवर में पूरा स्टेडियम मोबाइल टॉर्च की जगमग से चमक उठा। श्रीलंकाई पारी के दौरान मैच कुछ नीरस हो चला था। ऐसे में दर्शकों ने भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए मोबाइल टॉर्च जला लिए। ईस्ट गैलेरी से इसकी शुरुआत हुई और देखते ही देखते पूरा स्टेडियम मोबाइल टॉर्च से जगमगा उठा। इंदौर में ही सबसे पहले मोबाइल टॉर्च से स्टेडियम की जगमगाहट की शुरुआत हुई थी। इससे पहले भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए वन-डे मैच के दौरान भी इसी तरह पहली बार पूरा स्टेडियम मोबाइल टॉर्च से जगमग हुआ था। आज के समय में अक्सर मैदान में दर्शक मोबाइल टॉर्च से स्टेडियम की जगमगाहट की जाती है। इसे देखकर स्टेडियम काफी सुंदर नजर आता है। कई बार दर्शक हाथ उठाकर भी लहर नुमा दृश्य बनाते हैं, ये भी काफी पसंद किया गया।

न्यूजीलैंड की चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार रोहित

नई दिल्ली, प्रेट्र: हाल ही में टेस्ट ओपनर की जिम्मेदारी संभालने वाले रोहित शर्मा मानते हैं कि न्यूजीलैंड का घातक तेज गेंदबाजी आक्रमण अपने घर में और भी ज्यादा कारगर साबित होता है क्योंकि वह अपनी योजनाओं को बखूबी अंजाम देते हैं। इसके बावजूद रोहित मानते हैं कि वह आने वाली चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। टेस्ट में ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालने के बाद अब तक एक दोहरे शतक समेत तीन शतक ठोक चुके रोहित इस बार न्यूजीलैंड जाकर नई लाल गेंद से नील वैगनर, मैट हेनरी, ट्रेंट बोल्ट और टिम साउथी के मिश्रण वाले तेज गेंदबाजी आक्रमण का सामना करेंगे। यहां भारतीय टीम को दो टेस्ट मैच खेलने हैं, जो फरवरी में वेलिंगटन और क्राइस्टचर्च में खेले जाएंगे। रोहित ने बताया कि क्रिकेट खेलने के लिए न्यूजीलैंड कोई आसान जगह नहीं है। पिछली बार जब हम यहां खेले थे, तो हमने यहां (0-1 से) टेस्ट सीरीज गंवाई थी, लेकिन इसके बावजूद हमने उनके सामने अच्छी चुनौती पेश की थी। हमारा मौजूदा गेंदबाजी आक्रमण पहले के मुकाबले अब बिलकुल अलग है।

रोहित टेस्ट क्रिकेट में पहली बार विदेश में नई गेंद से बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि निजी रूप से मेरे लिए बिना किसी शक के यह चुनौतीपूर्ण होगा। यहां मुझे नए गेंद का सामना करना होगा। रोहित बखूबी जानते हैं कि भारत से बाहर की इन पिचों पर गेंद कहीं ज्यादा स्विंग और सीम करती है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बीते साल खेली गई घरेलू सीरीज भी भारत में स्वागत योग्य वाले बदलाव के साथ खेली गई थी। अब भारत की पिचें अपने पुराने स्वभाव से अलग हो रही हैं, अब ये ऐसी नहीं रहीं जैसा कि उपमहाद्वीप की पिचों को माना जाता है। रोहित ने भारतीय पिचों की तारीफ करते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में नए गेंद का सामना करना आसान नहीं होता।

नजरिया

- विदेशी धरती पर पहली बार टेस्ट में ओपनिंग करेंगे शर्मा
- कहा, अब भारत की पिचें अपने पुराने स्वभाव से अलग

रोहित ने मुंबई रणजी टीम को प्रोत्साहित किया

मुंबई, प्रेट्र: भारतीय टीम के सीनियर बल्लेबाज रोहित शर्मा ने मंगलवार को लगातार दो हार झेलने वाली मुंबई रणजी टीम को इस परिस्थिति से बाहर निकलने की सीख दी। मुंबई पहले रेलवे से 10 विकेट से और फिर कर्नाटक से पांच विकेट से हार गई थी। मुंबई टीम के सूत्र ने कहा कि भारत की सीमित ओवरों की टीम के उप कप्तान ने बांद्रा कुर्ला परिसर (बीकेसी) में मुंबई रणजी टीम के खिलाड़ियों से बात की उन्हें बताया कि वर्तमान स्थिति से कैसे उबरना है। उन्होंने शनिवार को थोड़ी देर के लिए मुंबई और कर्नाटक के बीच दूसरे दिन का खेल देखा था। मुंबई को अपना अगला रणजी मैच 11 जनवरी से तमिलनाडु के खिलाफ चेन्नई में खेलना है।

एक नजर में

कराटे संघ की मान्यता रद

नई दिल्ली: भारतीय ओलंपिक संघ (आइओए) ने संविधान और दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए भारतीय कराटे संघ (केएआइ) की मान्यता रद कर दी। आइओए ने 30 दिसंबर को वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान यह फैसला किया, लेकिन विश्व कराटे महासंघ (डब्ल्यूकेएफ) को सोमवार को इस संबंध में औपचारिक पत्र भेजा गया। आइओए ने पत्र में लिखा, 'आइओए की एजीएम में भारत में कराटे के संचालन संबंधी मसले पर चर्चा की गई। केएआइ की मान्यता को मंजूरी अब भी लंबित थी क्योंकि पिछले दो वर्षों से उनके खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं।' डब्ल्यूकेएफ सीईओ सारा वोल्फ को भेजे गए पत्र में कहा गया है, 'एजीएम के दौरान इस पर सहमति जताई गई कि संविधान के सिद्धांतों और उसके दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी राष्ट्रीय महासंघ को भारत में ओलंपिक अभियान का हिस्सा नहीं होना चाहिए। आइओए ने सर्वसम्मति से केएआइ की मान्यता खत्म करने और उससे नाता तोड़ने का फैसला किया।' (प्रेट्र)

खेलो इंडिया खेल राष्ट्रीय महत्व की प्रतियोगिता : रिजिजू

नई दिल्ली: खेल मंत्री किरन रिजिजू ने मंगलवार को बताया कि भारत सरकार ने खेलो इंडिया खेलों को राष्ट्रीय महत्व की प्रतियोगिता घोषित किया। खेलो इंडिया खेलों का तीसरा सत्र 10 जनवरी से गुवाहाटी में शुरू होना है। रिजिजू ने कहा, 'हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खेलो इंडिया खेल सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं है, यह एक अभियान है। युवाओं के बीच खेल और फिटनेस को बढ़ावा देना तथा माता-पिता को संवेदनशील बनाना कि वे युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करें, वे खेल में करियर बनाने का सपना देखें, यह भारत को खेलों की महाशक्ति बनाने की दिशा में पहला कदम है। मुझे यकीन है कि यह कदम अधिक युवाओं को खेलों से गंभीरता से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा।' इन खेलों के तीसरे सत्र में लगभग 6800 खिलाड़ियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। (प्रेट्र)

वेर्सटापेन 2023 तक रेड बुल के साथ बने रहेंगे

लंदन : फॉर्मला-1 टीम रेड बुल ने नीदरलैंड्स के ड्राइवर मैक्स वेर्सटापेन के करार में तीन साल का विस्तार किया है। वेर्सटापेन का इस साल के आखिर तक रेड बुल के साथ करार था, लेकिन अब इस नए करार के तहत वेर्सटापेन 2023 सीजन तक रेड बुल टीम के साथ बने रहेंगे। इसके साथ ही रेड बुल ने मंगलवार को उन अफवाहों पर भी विराम लगा दिया, जिसमें कहा जा रहा था कि वर्सटापेन फरारी या फिर मर्सडीज के साथ जुड़ सकते हैं। वर्साटापेन 2016 में रेड बुल टीम के साथ जुड़े थे। (आइएएनएस)

इस बार आइपीएल में एक दिन में खेला जाएगा एक ही मैच

नई दिल्ली, आइएएनएस: इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) 2020 की शुरुआत मुंबई में 29 मार्च को वानखेड़े स्टेडियम में होनी तय है। वहीं इसका फाइनल अब 24 मई को खेला जाएगा। यह टूर्नामेंट 57 दिन चलेगा। इसका अर्थ यह है कि शायद अब प्रसारणकर्ता की चल जाए और किसी भी दो दिन मुकाबले नहीं होंगे। इस बार हर मैच शाम साढ़े सात बजे ही शुरू होंगे। पहले शनिवार व रविवार को दिन में दो मैच होते थे, जिनमें पहला मैच शाम चार बजे से और दूसरा मैच रात आठ बजे से होता था। बाकी अन्य दिन एक ही मैच होता था जो रात आठ बजे शुरू होता था।

करीबी सूत्रों ने बताया कि 2020 का संस्करण 57 दिन चलेगा। लंबे समय का अर्थ यह है कि एक दिन में दो मुकाबले अब इतिहास की बात हो सकते हैं। सूत्र ने कहा कि हालांकि अभी पूरा कार्यक्रम तैयार नहीं है, लेकिन यह तय है कि टूर्नामेंट का फाइनल 24 मई को होगा और इसकी शुरुआत 29 मार्च को मुंबई में होगी। इसका अर्थ है कि आपको 45 दिन से ज्यादा वक्त मिलेगा। ऐसे में एक दिन में एक मैच करवाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यह देखते हुए कि प्रसारणकर्ता मैच को जल्दी शुरू करना चाहते थे। सूत्र ने कहा कि यह भी लगभग तय है कि मैच शाम साढ़े सात बजे शुरू हो जाएंगे। यह सिर्फ प्रसारणकर्ताओं की बात नहीं है, बल्कि अगर हम पिछले सत्र को देखें तो अधिकतर मैच काफी देर से समाप्त हुए थे। उन्होंने कहा कि देखिए, टीआरपी एक सवाल जरूर है, लेकिन आप सिर्फ उसे ही मत देखिए। आप देखिए कि पिछले साल मैच कितनी देर से समाप्त हुए थे। यह उन लोगों के लिए भी समस्या थी जो मैच देखने स्टेडियम में आए थे। उन लोगों को भी मैच के बाद घर जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इस बारे में काफी बात की गई और अब लगता है कि इस सत्र में मैच शाम को साढ़े सात बजे शुरू हो सकते हैं।

हालांकि, फ्रेंचाइजी मानते हैं कि जिस समय मैच शुरू करने की बात कही जा रही है उस समय तक लोगों के लिए काम खत्म करके मैदान पर पहुंच पाना लगभग असंभव है।

एक फ्रेंचाइजी के अधिकारी ने कहा कि मान लीजिए आप दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे किसी महानगर में रहते हैं तो आपको ट्रैफिक की भारी समस्या से जूझना पड़ता है। तो क्या आपको वाकई लगता है कि लोग दफ्तर से छह बजे निकलकर अपने परिवार के साथ मैच शुरू होने से पहले स्टेडियम में पहुंच सकते हैं? मैच शुरू करने का वक्त बदलने से पहले इस बारे में विचार किया जाना चाहिए।

एक दिन में दो मैचों के बारे में भी फ्रेंचाइजी का कहना है कि प्रसारणकर्ता चार बजे के मैच को लेकर अधिक उत्साहित नहीं थे, लेकिन सूत्र का कहना है कि यहां कमाई का भी एक बड़ा प्रश्न था। सूत्र ने बताया कि क्या आपको लगता है कि सिर्फ प्रसारणकर्ता को ही परेशानी थी? हमें व्यावहारिक होकर बात करनी चाहिए। फ्रेंचाइजी को भी दोपहर के मैचों में स्टैंड भरने में परेशानी हो रही थी। तो अच्छा यही है कि दोपहर के मैचों को विदा कहा जाए और एक दिन में एक ही मैच पर फोकस किया जाए।

बदलाव

- पहले शनिवार व रविवार को होते थे दो मैच
- अब सभी मैच शाम साढ़े सात बजे होंगे शुरू

भारत नहीं आएंगे लैंगर, मैकडोनाल्ड होंगे कोच

सिडनी, एएफपी: ऑस्ट्रेलिया के कोच जस्टिन लैंगर ब्रेक ले रहे हैं। लैंगर भारत दौरे पर नहीं आएंगे, जहां उनके वरिष्ठ सहायक एंड्रयू मैकडोनाल्ड 14 जनवरी से शुरू हो रही तीन वनडे मैचों की सीरीज में टीम की कोचिंग संभालेंगे। मैकडोनाल्ड पहली बार राष्ट्रीय पुरुष टीम के प्रभारी की भूमिका में होंगे और लैंगर को भरोसा है कि 38 साल का यह पूर्व तेज गेंदबाज अपनी नई भूमिका में सफल रहेगा।

जस्टिन लैंगर ने कहा कि उन्हें बहुत अच्छा मौका मिला है। क्रिकेट से जुड़ी चीजों को लेकर मुझे अपने कोचिंग स्टाफ पर अब काफी भरोसा है। अब काफी बार मैं क्रिकेट के बारे में 30 प्रतिशत समय ही सोचता हूं, बाकी समय मैं अन्य चीजों के बारे में सोचता हूं। बड़ी तस्वीर क्या होगी, टीम की संस्कृति आदि। लैंगर ने कहा कि वह शानदार कोच हैं, उनका साथ देने के लिए और बेहतरीन कोच भी हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं फोन पर उससे बात नहीं करूंगा, मैं उन्हें पूरी स्वत्रंता दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं आपको फोन कर सकता हूं, यही अंतर है। वह काफी अच्छा काम करेंगे। घरेलू सत्र में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा देखने को मिला, जहां उसने न्यूजीलैंड से पहले पाकिस्तान का भी टेस्ट सीरीज में 2-0 से सूपड़ा साफ किया।

लाबुशाने बोले, भारत में उसके खिलाफ खेलना सबसे मुश्किल: तेजी से उभर रहे ऑस्ट्रेलिया के युवा बल्लेबाज मार्नस लाबुशाने भारत के खिलाफ अपने कौशल को आजमाने के लिए उत्सुक हैं। उनका मानना है कि क्रिकेट की दुनिया में भारत का दौरा करना सबसे मुश्किल है। 25 साल के लाबुशाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई घरेलू सत्र शानदार रहा, जिसमें उन्होंने पांच मैचों में चार शतक जमाए। इसमें हाल में संपन्न तीसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया दोहरा शतक भी शामिल है।

लाबुशाने को भारत के खिलाफ मुंबई में 14 जनवरी से शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में जगह दी गई है। लाबुशाने ने कहा कि जब आप भारत से खेलते हो तो यह कड़ी सीरीज होती है क्योंकि वे काफी मजबूत विरोधी हैं। उनके पास बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज हैं, इसलिए यह चुनौती होगी। उन्होंने कहा कि लेकिन एक खिलाड़ी के रूप में आप हमेशा खुद को सबसे मुश्किल हालात में सर्वश्रेष्ठ विरोधी के खिलाफ परखना चाहेंगे और भारत के खिलाफ भारत में खेलने से कड़ा कुछ नहीं है। सिर्फ 14 टेस्ट खेलने वाले लाबुशाने के आइसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत के विराट कोहली और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ के बाद तीसरे स्थान पर काबिज होने की उम्मीद है। लाबुशाने की तुलना आधुनिक पीढ़ी के महान खिलाड़ियों से हो रही है, लेकिन उन्होंने इसे अधिक तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि लोगों का इस तरह की बातें करना शानदार है, लेकिन इस से पहले काफी काम किए जाने की जरूरत है। लाबुशाने ने कहा कि केन विलियमसन, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, ये खिलाड़ी पांच, छह, सात साल से ऐसा कर रहे हैं। एक अच्छा सत्र होने का मतलब यह नहीं है कि आप महान खिलाड़ी हैं। इसलिए मेरा ध्यान अपने प्रदर्शन में निरंतरता लाने और ऑस्ट्रेलिया को मैच जिताने में मदद करने का प्रयास करने पर है। लाबुशाने ने कहा कि भारत के दौरे पर जाने से पहले स्पिनरों के अनुकूल सिडनी के हालात में खेलना तैयारी के लिहाज से अच्छा रहा।

भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज

भारत से टेस्ट सीरीज में बदला लेने की नहीं सोच रहे : पेन

सिडनी, एएफपी : लगातार पांच टेस्ट जीतने के बाद आत्मविश्वास से भरे ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन ने कहा कि वह इस साल शानदार सीरीज में भारत की मेजबानी करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित तौर पर बदला लेने की बात उनके दिमाग में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने 2018-19 सत्र में घरेलू सरजमीं पर पहली बार भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज गंवाई थी, लेकिन तब गेंद से छेड़छाड़ प्रकरण के कारण टीम के दिग्गज बल्लेबाजों स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर पर प्रतिबंध लगा था। तब से ऑस्ट्रेलिया ने लंबा सफर तय किया है। टीम के युवा बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, जबकि तेज गेंदबाज भी बेहतर कर रहे हैं और स्मिथ-वार्नर की जोड़ी की भी टीम में वापसी हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने हाल में संपन्न घरेलू सत्र में पाकिस्तान को दोनों टेस्ट में चार दिन के भीतर हराया, जबकि न्यूजीलैंड का भी 3-0 से क्लीनस्वीप किया। पेन ने कहा कि बांग्लादेश दौरे पर अगर हम अच्छा खेल पाए और कुछ जीत दर्ज कर पाए तो इसके बाद हमें ऑस्ट्रेलिया में भारत के खिलाफ खेलना है और यह खिलाड़ियों तथा प्रशंसकों के लिए शानदार सीरीज होगी। उन्होंने कहा कि उस सीरीज के बारे में न सोच पाएं यह मुश्किल है और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में कुछ लोग हैं, जो पहले ही उस सीरीज को लेकर बेताब हैं, लेकिन खिलाड़ियों के लिए अगला लक्ष्य बांग्लादेश है और हम उन्हें हल्के में नहीं ले सकते। पिछले सत्र में भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के जूझने का अंदाजा इस बात से लग सकता है कि तब उसकी ओर से 79 रन की सर्वश्रेष्ठ पारी मार्कस हैरिस ने सिडनी में हुए अंतिम टेस्ट में खेली थी।

त्रिकोणीय सीरीज के लिए रविवार को टीम चयन

इंदौर, प्रेट्र: ऑस्ट्रेलिया में होने वाली महत्वपूर्ण त्रिकोणीय सीरीज के लिए भारतीय महिला टीम और ऑस्ट्रेलिया में ही होने वाले आगामी टी-20 विश्व के लिए संभावितों का चयन रविवार को मुंबई में किया जाएगा।

त्रिकोणीय सीरीज का आगाज 31 जनवरी को कैनबरा में होगा, जिसमें भारत के अलावा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें भाग लेंगी। फाइनल से पहले तीनों टीमें एक-दूसरे के खिलाफ दो बार आमने-सामने होंगी। इस टूर्नामेंट से स्पष्ट संकेत मिलेंगे कि 21 फरवरी से शुरू हो रहे टी-20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम की तैयारी कैसी है। हरमनप्रीत कौर की अगुआई में भारत टी-20 विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत पहले दिन मेजबान और चार बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में करेगा। महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दो सबसे सफल टीमों में से हैं। बीसीसीआइ के एक अधिकारी ने कहा, 'त्रिकोणीय सीरीज महत्वपूर्ण होगी। इससे हमें पता चलेगा कि क्या लड़कियां सर्वश्रेष्ठ टीमों (ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड) को चुनौती दे सकती हैं। अधिकतर खिलाड़ियों का चयन तय है, इसलिए हैरानी भरे नाम की उम्मीद मत कीजिए। जो टीम सीरीज में खेलेगी वही टी-20 विश्व कप में भी खेलेगी।'

फुटबॉल सीरी-ए में इंटर ने नापोली को 3-1 से हराया, रोमेलू ने दो, जबकि मार्टिनेज ने दागा एक गोल

लुकाकू ने इंटर मिलान को शीर्ष पर पहुंचाया

मिलान, एएफपी: बेल्जियम के स्टार स्ट्राइकर रोमेलू लुकाकू के दो गोल की मदद से इटालियन फुटबॉल लीग सीरी-ए में इंटर मिलान ने नापोली को 3-1 से हराकर फिर से शीर्ष स्थान पर कब्जा जमा लिया।

मैनेजर एंटोनी कोंटे की इंटर टीम ने इस जीत के साथ पिछले 23 साल से नेपल्स में चले आ रहे अपने जीत के इंतजार को खत्म किया। 1997 के बाद यह पहला मौका है जब इंटर ने घरेलू मैदान से बाहर नापोली को हराया है। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर युनाइटेड के पूर्व स्ट्राइकर लुकाकू ने खेल के 14वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को शुरुआती बढ़त दिलाई। इसके बाद उन्होंने नापोली के गोलकीपर एलेक्स मेरेट की गलती का फायदा उठाकर 33वें मिनट में इंटर को दोहरी बढ़त दिलाई और मौजूदा सत्र में अपने गोल की संख्या 14 पहुंचा दी। इसके बाद हाफ टाइम से चार मिनट पहले आर्कादिज मिलिक ने गोल करके नापोली को वापसी दिलाने की कोशिश की, लेकिन लॉरेंटो मार्टिनेज (62वें मिनट) ने गोल करके इंटर मिलान को फिर से दोहरी बढ़त पर ला खड़ा किया, जो अंत तक कायम रही। सोमवार को सीरी-ए में अपनी पहली हैट्रिक की बदौलत क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जुवेंटस को काग्लियरी पर 4-0 से जीत दिलाते हुए शीर्ष स्थान पर पहुंचाया था, लेकिन बाद में इंटर ने जीत के साथ फिर से शीर्ष स्थान पर कब्जा जमा लिया। तालिका में इंटर और जुवेंटस के 45-45 अंक हैं, लेकिन इंटर बेहतर गोल अंतर की वजह से शीर्ष पर काबिज हो गया।

आर्सेनल ने लीड्स को हराया: इंग्लिश एफए कप में सोमवार को आर्सेनल ने लीड्स को 1-0 से हराकर चौथे दौर में जगह बनाई। पहले हाफ में लीड्स को गोल करने के कई मौके मिले लेकिन वह उसका फायदा नहीं उठा सका। आर्सेनल की ओर से रीड नेल्सन ने खेल के 55वें मिनट में इकलौता गोल दागा। हालांकि आर्सेनल के मैनेजर मिकेल आर्टेटा अपनी टीम के प्रदर्शन से खुश दिखाई नहीं दिए। उनकी टीम ने पहले हाफ में काफी सुस्त खेल दिखाया। हाल ही में आर्टेटा आर्सेनल के मैनजर बनाए गए हैं।

डि रोसी ने लिया संन्यास

ब्यूनस आयर्स, एएफपी: इटली के दिग्गज खिलाड़ी डेनियल डि रोसी ने सोमवार को फुटबॉल से संन्यास की घोषणा। डि रोसी छह महीने पहले ही अर्जेंटीनी क्लब बोका जूनियर्स से जुड़े थे जिसके लिए वह केवल सात मैचों में केवल एक गोल कर पाए। उन्हें पारिवारिक कारणों से घर लौटना पड़ा। इटली की 2006 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे 36 वर्षीय डि रोसी ने कहा कि मुझे घर जाना पड़ेगा। मैं बोका जूनियर्स और फुटबॉल को छोड़ रहा हूं। पिछले सत्र में बोका जूनियर्स से जुड़ने से पहले उन्होंने इटालियन क्लब एसी रोमा के साथ 18 साल गुजारे। डि रोसी ने 2004 से 2017 तक इटली की राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व किया और इस दौरान उन्होंने 117 मुकाबले खेले।

इटालियन फुटबॉल लीग सीरी-ए में नापोली के खिलाफ गोल करने के बाद जश्न मनाते इंटर मिलान के स्ट्राइकर रोमेलू लुकाकू ● एएफपी

पहले दिन भारतीय शटलरों ने किया निराशाजनक प्रदर्शन

कुआलालंपुर, प्रेट्र: मलेशिया मास्टर्स में मंगलवार को भारतीय शटलरों की शुरुआत बेहद खराब रही। लक्ष्य सेन मुख्य ड्रॉ के लिए क्वालीफाई करने में नाकाम रहे, जबकि सात्विकसाईराज रेंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को पहले दौरे में ही बाहर होना पड़ा।

उभरते हुए सितारे लक्ष्य को 49 मिनट तक चले पुरुष सिंगल्स क्वालीफायर के कड़े मुकाबले में डेनमार्क के हेंस क्रिस्टियन सोल्बर्ग विटिंग्स के खिलाफ 21-11, 18-21, 14-21

मेरे करियर को सही दिशा देने में न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज मार्टिन क्रो का अहम योगदान रहा है।
– रॉस टेलर, न्यूजीलैंड क्रिकेटर

करीम के बेटे की कार ने पैदलयात्री को टक्कर मारी

मुंबई, आइएएनएस : भारत के पूर्व विकेटकीपर सबा करीम के बेटे को उस वक्त हिरासत में ले लिया गया जब उनकी कार से 24 साल की महिला जख्मी हो गई। यह हादसा मंगलवार सुबह दक्षिण मुंबई के कैंप कॉर्नर के समीप हुआ। कार सबा करीम का बेटा फिदेल चला रहा था। यह हादसा सुबह 6:30 बजे हुए तब करीम अपने बेटे फिदेल के साथ कैंप कॉर्नर की तरफ जा रहे थे।

सेरेना ने 2020 में सिंगल्स में पहली जीत दर्ज की

टेनिस डायरी ▸ ऑकलैंड डब्ल्यूटीए क्लासिक टेनिस टूर्नामेंट में इटली की कैमिला जॉर्जी को हराया

कैमिला जॉर्जी के खिलाफ अंक हासिल करने के बाद जोश में अमेरिका की दिग्गज महिला टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स। एएफपी

सेरेना को शुरुआत में रूस की स्वेतलाना कुच्नेत्सोवा के खिलाफ खेलना था

ऑकलैंड, एएफपी : अमेरिका की दिग्गज महिला टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने मंगलवार को ऑकलैंड डब्ल्यूटीए क्लासिक टेनिस टूर्नामेंट में इटली की क्वालीफायर कैमिला जॉर्जी को सीधे सेटों में हराकर 2020 सत्र की सकारात्मक शुरुआत की। इस महीने होने वाले ऑस्ट्रेलियन ओपन पर नजरें टिकाए बैठीं 38 साल की अमेरिकी खिलाड़ी सेरेना ने दुनिया की 99वें नंबर की खिलाड़ी कैमिला को 6-3, 6-2 से हराया। सेरेना को शुरुआत में दो बार की ग्रैंडस्लैम विजेता रूस की स्वेतलाना कुच्नेत्सोवा के खिलाफ खेलना था, लेकिन बीमार होने के कारण विरोधी खिलाड़ी टूर्नामेंट से हट गईं।

मुश्किल से जीतीं ओसाका

ब्रिसबेन, एएफपी : जापानी स्टार टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने ब्रिसबेन अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के पहले दौर में ग्रीस की मारिया साकारी के खिलाफ कड़ी मशक्कत के बाद जीत हासिल की। दो घंटे तक चले मुकाबले में साकारी ने दूसरा सेट टाई ब्रेकर में जीता, जबकि तीसरे सेट के पहले गेम में ओसाका की सर्विस भी तोड़ी। लेकिन, पूर्व विश्व नंबर एक खिलाड़ी यह मैच 6-2, 6-7, 6-3 से जीतने में सफल हुईं।

प्रजनेश बेंडिगो चैलेंजर से बाहर

बेंडिगो (ऑस्ट्रेलिया), प्रेट्र : प्रजनेश गुणेश्वरन मंगलवार को यहां जापान के टेरो डेनियल के खिलाफ कड़ी चुनौती पेश करने के बावजूद दूसरे दौर में हार के साथ बेंडिगो चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। दुनिया के 122वें नंबर के खिलाड़ी प्रजनेश को एटीपी चैलेंजर प्रतियोगिता में जापान के खिलाड़ी के खिलाफ 4-6, 6-7 से हार झेलनी पड़ी, जिनकी रैंकिंग उनसे 16 स्थान बेहतर है। भारतीय खिलाड़ी एक घंटा और 30 मिनट चले मुकाबले के दौरान छह में से एक ही ब्रेक प्वाइंट का फायदा उठा पाया, जबकि उन्होंने अपने खिलाफ आठ में से छह ब्रेक प्वाइंट बचाए। प्रजनेश ने कहा, 'यह करीबी मैच था और मुझे काफी मौके मिले, लेकिन मैं इनका फायदा नहीं उठा पाया। मैंने काफी गलतियां कीं। मैं आक्रामक था और मैंने आक्रमण करने का प्रयास किया और यह मैच का सकारात्मक पक्ष रहा।'

ऑस्ट्रेलियन ओपन में देरी की संभावना नहीं

सिडनी, एएफपी : ऑस्ट्रेलियन ओपन के आयोजकों ने मंगलवार को बताया कि जंगलों में लगी आग के धुएं के कारण इस ग्रैंडस्लैम टेनिस टूर्नामेंट में विलंब होने की संभावना नहीं है। आयोजकों ने कहा कि उन्होंने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखते हुए सभी जरूरी कदम उठाए हैं। मेलबर्न में 20 जनवरी से शुरू हो रहे 2020 के पहले ग्रैंडस्लैम से पूर्व शहर में पिछले कुछ दिनों से जंगलों में लगी आग के कारण धुएं की चादर बिछी नजर आती है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग के कारण 25 लोगों की मौत हो चुकी है। एटीपी खिलाड़ी परिषद के अध्यक्ष नोवाक जोकोविक ने कहा कि अगर हालात में सुधार नहीं होता है तो आयोजकों को अंतिम कदम के तहत टूर्नामेंट में विलंब करने पर विचार करना चाहिए। टेनिस ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख क्रेग टिली ने हालांकि कहा कि उनको इसकी संभावना नजर नहीं आती। उन्होंने कहा कि इस तरह की काफी अटकलबाजी चल रही हैं कि क्या जंगलों में लगी आग से निकल रहे धुएं का ऑस्ट्रेलिया ओपन पर असर होगा। अगले सप्ताह क्वालीफाइंग मुकाबले शुरू होने हैं और मौसम की भविष्यवाणी अच्छी है।

चोटिल पृथ्वी इंडिया-ए के अभ्यास मैच से बाहर

क्रिकेट डायरी

मुंबई, प्रेट्र: सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ न्यूजीलैंड दौरे पर होने वाले दो अभ्यास मैचों में इंडिया-ए की ओर से नहीं खेलेंगे। शॉट को चोट के कारण इस सीरीज से हटना पड़ा है। बीसीसीआइ की ओर से कहा गया कि न्यूजीलैंड दौरे पर होने वाले वनडे और चार दिवसीय मैचों में उनकी भागीदारी को लेकर बाद में फैसला लिया जाएगा।

बीसीसीआइ ने कहा कि पृथ्वी को मुंबई और कर्नाटक के बीच खेले गए रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान तीन जनवरी को फील्डिंग करते समय कंधे में चोट लग गई थी। पृथ्वी इस समय बेंगलुरू में नेशनल क्रिकेट अकादमी में रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं।

पृथ्वी को न्यूजीलैंड दौरे के लिए इंडिया-ए टीम में शामिल किया गया था। बता दें कि इससे पहले भी पृथ्वी भारतीय टीम में रहते चोटिल हो गए थे।

बर्न्स चार महीने के लिए हुए बाहर

लंदन, एएफपी : इंग्लैंड क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज रॉरी बर्न्स बायें टखने की सर्जरी के कारण चार महीनों के लिए बाहर हो गए हैं। वह मार्च में श्रीलंका के खिलाफ होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। बर्न्स को केपटाउन टेस्ट मैच से पहले वॉर्मअप के दौरान फुटबॉल खेलते हुए चोट लग गई थी। इसी कारण वह दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेल पाए थे।

इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने मंगलवार को कहा कि इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज रॉरी बर्न्स की सर्जरी सफल रही। सर्जरी सोमवार को लंदन में हुई। इसी कारण सरे के कप्तान चार महीने तक मैदान से दूर रहेंगे। बर्न्स के चोटिल होने के बाद इंग्लैंड ने वॉर्मअप में फुटबॉल खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

ब्रावो 10 पीएल-टेनिस गेंद विश्व कप से जुड़े

दुबई, प्रेट्र : वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो को शारजाह में आठ से 13 मार्च तक होने वाले '10पीएल-टेनिस गेंद क्रिकेट विश्व कप' के तीसरे सत्र का 'चेहरा' बनाया गया है। शारजाह क्रिकेट परिषद के तत्वावधान में होने वाले इस टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा लेंगी। ब्रावो ने कहा कि 10पीएल-टेनिस गेंद क्रिकेट विश्व कप का चेहरा बनाए जाने की मुझे काफी खुशी है। मैंने अपना काफी कौशल टेनिस गेंद से सीखा है और मुझे यकीन है कि टूर्नामेंट में खिलाड़ी अपना कौशल दिखाएंगे विशेषकर धीमी गेंद और यार्कर।

मैं आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं : शमी

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय तेज गेंदबाज मुहम्मद शमी को श्रीलंका के खिलाफ टी-20 सीरीज से आराम दिया गया है। वह इस खाली वक्त को खुद को फिट रखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। शमी ने सोमवार को सोशल मीडिया पर अपने वर्कआउट की तस्वीरें पोस्ट की हैं। उन्होंने इन तस्वीरों के साथ कैप्शन दिया है कि वह नए साल की चुनौतियों के लिए तैयार हैं।

शमी ने इन ट्वीट के साथ कैप्शन दिया है कि ट्रेनिंग जारी है... आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करते हुए। साल 2019 बंगाल के इस दायें हाथ के तेज गेंदबाज के लिए बहुत अच्छा रहा। वह साल में सबसे ज्यादा वनडे विकेट लेने वाले बोलर रहे। उन्होंने 20 मैचों में 42 विकेट लिए। उन्होंने इंग्लैंड में खेले गए 50 ओवर विश्व कप में अफगानिस्तान के खिलाफ हैटट्रिक भी ली थी।

भारतीय तेज गेंदबाज शमी। फाइल फोटो, प्रेट्र

शमी अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 14 जनवरी से शुरू हो रही तीन वनडे मैचों की सीरीज से वापसी करेंगे। सीरीज का पहला मैच मुंबई में खेला जाएगा।

हाल ही में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने मुहम्मद शमी की तारीफ करते हुए उनकी तुलना वेस्टइंडीज के दिग्गज गेंदबाज मैलकम मार्शल के साथ की थी। गावस्कर ने कहा था कि शमी को देखकर उन्हें मार्शल की याद आती है।

ताइ जू को शटलर पीवी सिंधू के साथ भिड़ंत का इंतजार

चेन्नई, प्रेट्र : दुनिया के दूसरे नंबर की महिला शटलर चीनी ताइपे की ताइ जू यिंग को प्रीमियर बैडमिंटन लीग का प्रारूप बेहद रोचक लगता है और वह इस टूर्नामेंट के आगामी संस्करण में विश्व चैंपियन पीवी सिंधू से मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं।

एशियन गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता ताइ जू 20 जनवरी से शुरू हो रहे पांचवें संस्करण में बेंगलुरु रैप्टर्स की ओर से खेलती नजर आएंगी। हालांकि सत्र का आगाज सिंधू की टीम हैदराबाद हंटर्स और चेन्नई सुपरस्टार्स के बीच मुकाबले के साथ होगा। ताइ जू ने कहा कि पिछली बार मुझे पीबीए में खेलने में बड़ा मजा आया था। लीग का प्रारूप बहुत रोचक है और यही वजह है कि मुझे इसमें खेलना पसंद है। मैं बेंगलुरु रैप्टर्स से जुड़ने के लिए बेकरार हूं। मैं सभी टीमों के खिलाफ खेलने का इंतजार कर रही हूं। मुझे पीवी सिंधू के खिलाफ खेलने का इंतजार है। सिंधू और ताइ जू की टीमें 31 जनवरी को भिड़ेंगी। ताइ जू का सिंधू के खिलाफ रिकॉर्ड बेहतर रहा है। उन्होंने सिंधू के खिलाफ 16 मुकाबलों में से 11 अपने नाम किए हैं।

भारतीय शटलर पीवी सिंधू। फाइल फोटो, प्रेट्र

हैकिंग के बाद ट्विटर से हटे लेहमन

सिडनी, एएफपी : ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट कोच डेरेन लेहमन सोशल मीडिया से हट गए हैं। लेहमन ने अपना ट्विटर अकाउंट हैक होने और उसका इस्तेमाल ईरान विरोधी संदेश सहित कुछ 'घृणित' सामग्री पोस्ट करने के लिए होने के बाद यह कदम उठाया। घरेलू टी-20 टूर्नामेंट बिग बैश लीग में ब्रिसबेन हीट के कोच की भूमिका निभा रहे 49 साल के लेहमन सोमवार को जब सिडनी थंडर के खिलाफ अपनी टीम के मैच पर ध्यान लगा रहे थे तब यह घटना हुई। हीट की टीम ने उलटफेर करते हुए थंडर को हराया। इस घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति ने लेहमन के तीन लाख 41 हजार प्रशंसकों के बीच ईरान विरोधी संदेश और विचारधारा का प्रचार किया। इराक में अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद वैश्विक स्तर पर तनाव का माहौल है और तेहरान ने इसका जवाब देने की धमकी दी है। लेहमन ने कहा कि जो हुआ उससे वह हताश और हैरान हैं। ट्विटर ने हालांकि इसके बाद समस्या को सुलझा दिया और सामग्री को हटा दिया। उन्होंने कहा कि संभवत: आपने ध्यान दिया होगा कि कल रात जब हम अपना बीबीएल मैच खेल रहे थे तब किसी ने मेरा अकाउंट हैक किया और इसका इस्तेमाल दुर्भावनापूर्ण और पीड़ादायक बयान फैलाने के लिए किया। मैंने निकट भविष्य में सोशल मीडिया से ब्रेक लेने का फैसला किया है।

विविध

तरनतारन के आठ और पुलिस मुलाजिम निकले नशेड़ी

धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन

- डोप टेस्ट रिपोर्ट आई पॉजिटिव, सभी मुलाजिमों को किया लाइन हाजिर
- डोप टेस्ट करवाने से इन्कार करने पर चार पुलिस कर्मियों को किया सस्पेंड

पुलिसकर्मियों की डोप टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर फजीहत झेल रही जिला पुलिस के आठ और कर्मी नशेड़ी पाए गए हैं। रिपोर्ट मिलते ही सभी कर्मियों को तुरंत लाइन हाजिर कर दिया गया है। इसके साथ ही डोप टेस्ट करवाने से इन्कार करने पर चार पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है।

डेढ़ माह पहले ही जिले के डेढ़ दर्जन पुलिसकर्मी डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे। एसएसपी को सूचना मिली थी कि विभाग में तैनात कर्मी अब भी नशा कर रहे हैं। इसके चलते डीएसपी सुखनिंदर सिंह की अगुवाइ में चार दिन पहले नौ कर्मियों के डोप टेस्ट करवाए गए। आठ कर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें से तीन कर्मी मौरफिन व चार कर्मी हेरोइन के आदी पाए गए।

इसके अलावा डोप टेस्ट न करवाने वाले सब इंस्पेक्टर परमजीत सिंह, एएसआइ अश्विनी कुमार, हेड कांस्टेबल तेजिंदरपाल सिंह व हरजीत सिंह को एसएसपी ध्रुव दहिया के आदेश पर सस्पेंड कर दिया गया है। इन चारों को भी डोप टेस्ट करवाने लिए लिखित आदेश दिए गए थे। उन्होंने पहले बहानेबाजी की और फिर डोप टेस्ट करवाने से इन्कार ही कर दिया। उधर, एसएसपी ध्रुव दहिया ने बताया कि पुलिस विभाग से नशा मिटाने लिए संदिग्ध पुलिस कर्मियों के डोप टेस्ट करवाए जाते हैं। आने वाले समय में भी यह अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि डोप टेस्ट पॉजिटिव पाए गए पुलिसकर्मियों के मामले की अभी जांच की जाएगी।

सिविल अस्पताल से डेढ़ महीने पहले डेढ़ दर्जन पुलिसकर्मियों की डोप टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आई थी। संदेह होने पर एसएसपी ने अमृतसर के अस्पताल से दोबारा टेस्ट करवाए। वहां से रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद सिविल अस्पताल तरनतारन में कथित तौर पर फर्जीवाड़े की डीसी प्रदीप सभ्रवाल ने जांच के आदेश दिए थे। एडीसी ने जांच रिपोर्ट भी तैयार कर ली, परंतु रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई।

एपीकॉन में बोले डॉक्टर- ठीक हो सकती है डायबिटीज, लेनी होगी कम कैलोरी

जागरण संवाददाता, आगरा

- अमेरिका में 300 मरीजों पर हुआ कम कैलोरी का शोध
- एपीकॉन में मरीजों के बीच बेहतर संबंध पर भी हुई चर्चा

डायबिटीज के मरीजों को जीवनभर दवा खाने की जरूरत नहीं है। खाने में कम कैलोरी का इस्तेमाल किया जाए तो इसे ठीक किया जा सकता है। अमेरिका में 300 मरीजों पर हुए शोध के बाद यह बात सामने आई है। एसोसिएशन आफ फिजिशियन आफ इंडिया कांफ्रेंस (एपीकॉन) में दूसरे दिन इस पर चर्चा की गई। साथ ही मधुमेह की रोकथाम और मरीजों से बेहतर संबंध पर भी बात की गई।

केएनसीसी फतेहाबाद में एपीकॉन के दूसरे दिन मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय डायबिटीज फेडरेशन के अध्यक्ष डॉ. एंड्रयू जेएम बुल्टन ने बताया कि मधुमेह रिवर्सेबल है। यानी, एक बार दवा शुरू होने के बाद बंद भी हो सकती है। अमेरिका में पांच साल से मधुमेह की दवा ले रहे 300 मरीजों पर ट्रायल किया गया। इन मरीजों को तीन महीने तक 800 कैलोरी दी गईं। कम कैलोरी लेने से तीन महीने के बाद बिना दवा के मधुमेह रोगियों में शुगर का स्तर नियंत्रित हो गया। मधुमेह रोगियों में डायबिटिक फुट अल्सर होने पर कैंसर मरीजों से तीन गुना ज्यादा खर्चा आता है।

मरीजों को दें समय, पिता की तरह करें व्यवहार : यूके की मायो क्लीनिक के डॉ. अमित घोष ने शेयर डिसीजन मेकिंग विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि डॉक्टर पर्चे पर दवाएं लिखने के बजाय मरीजों से बात भी करें। मरीजों से बात करने की चार तकनीक पेटेरनिस्टिक, डॉक्टर इज ए परफेक्ट एजेंट, शेयर डिसीजन मेकिंग, इंफॉर्म कंसर्ट डिसीजन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि किस बीमारी और स्थिति में किस तकनीक से बात करनी है। डॉक्टर अपने फायदे की जगह मरीजों की भलाई देखें। मरीज को समय दें और उनकी बात सुनें। उन्होंने बताया कि डॉक्टर और मरीज के बीच वार्ता और संबंध के लिए फाउंडेशन कोर्स भी शुरू हो गया है।

शराब और सिगरेट की लत बना रही बुरी गति : जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई के डॉ. संतोष सलाग्रे ने बताया कि ब्लड प्रेशर अधिक होने के कारण ब्रेन, हार्ट, रेटिना और गुर्दा पर असर पड़ता है। धूमपान और शराब पीने की लत के चलते 40 साल से कम उम्र के लोग भी हाई बीपी का शिकार हो रहे हैं।

आला का प्रयोग और नब्ज देखने की आदत भी डालें चिकित्सक : भारत में क्लीनिकल मेडिसिन डेड हो रही है। जांचों पर इलाज की निर्भरता का फीसद बढ़ रहा है। डॉक्टर सिर्फ परीक्षणों के नतीजों पर निर्भर न हों। आला का प्रयोग और नब्ज देखने की आदत भी डालें। मशीनों द्वारा किए गए परीक्षण गलत हो सकते हैं, लेकिन एक डॉक्टर का कॉमन सेंस नहीं। यह कहना था एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया का। वह एपीकॉन में आयोजित दीक्षा समारोह कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस मौके पर देशभर के 110 फिजीशियन को इंडियन कॉलेज ऑफ फिजीशियन द्वारा फेलोशिप प्रदान की गई। डॉ. आर राजशेखर को मास्टर टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंडियन एकेडमी ऑफ डायबिटीज के अध्यक्ष भी मौजूद रहे।

सीबीआइ की कार्रवाई की अनुशंसा से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप

राज्य ब्यूरो, पटना

आश्रय गृह मामला

बिहार के 17 शेल्टर होम (आश्रय गृह) में बच्चों से यौन शोषण और प्रताड़ना के मामले में सीबीआइ द्वारा अधिकारियों पर कार्रवाई करने की अनुशंसा के बाद बिहार के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप है। सचिवालय के गलियारों तक में अधिकारियों पर संभावित कार्रवाई को लेकर दबी जुबान चर्चा शुरू हो गई है।

उल्लेखनीय है कि सीबीआइ ने इस मामले में बिहार के 25 तत्कालीन जिलाधिकारियों और तीन दर्जन से अधिक अन्य सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई की अनुशंसा की है। इतना ही नहीं सीबीआइ ने प्रदेश के 52 अन्य लोगों और कई एनजीओ को भी तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट करते हुए उनके रजिस्ट्रेशन रद करने की भी अनुशंसा की है।

सीबीआइ ने हालांकि अपनी अनुशंसा एक बंद लिफाफे में सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी है जिसकी एक कॉपी बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार को भी दी गई है। मुख्य सचिव फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जल-जीवन-हरियाली यात्रा पर हैं। हालांकि उनके कार्यालय ने इस प्रकार की किसी अनुशंसा रिपोर्ट प्राप्त होने से इन्कार किया है।

मंगलवार को सीबीआइ की अनुशंसा रिपोर्ट में से जुड़ी खबर समाचार पत्रों में छपने के साथ ही सचिवालय के गलियारों में कर्मचारियों-पदाधिकारियों के बीच इस बात का आकलन होता रहा कि इस मामले में किस-किस जिले के डीएम और दूसरे अधिकारी हो सकते हैं। किस जिले में कौन-कौन डीएम 2012-से 2017-18 की अवधि में तैनात रहे। समाज कल्याण के कौन अधिकारी उस मियाद में वैसे जिलों में तैनात थे जहां के शेल्टर होम्स की जांच टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (टिस) ने की थी।

सबके अपने-अपने आकलन हैं। इस मामले में अधिकारियों के नाम की पुष्टि के लिए जब सीबीआइ मुख्यालय दिल्ली फोन किया गया तो सूत्रों ने जानकारी दी कि सीबीआइ की ओर से सर्वोच्च न्यायालय को बंद लिफाफे में अनुशंसा सौंपी गई है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद ही इस प्रकरण में शामिल जिलाधिकारियों के साथ ही दूसरे पदाधिकारियों और कर्मचारियों के नाम सार्वजनिक किए जा सकते हैं। उन्होंने इस बारे में अन्य कोई जानकारी देने से साफ इन्कार कर दिया।

बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने 28 नवंबर, 2018 को मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के अतिरिक्त बिहार के दूसरे 16 शेल्टर होम की जांच के आदेश सीबीआइ को दिए थे। बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के अलावा एक दर्जन अन्य केस दर्ज किए थे। इन सभी मामलों की सीबीआइ ने दोबारा जांच की। जांच के दौरान 25 डीएम समेत दूसरे अफसरों की लापरवाही सामने आई थी। इसी आधार पर सीबीआइ ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है।

मकर संक्रांति 15 को, पूरे दिन स्नान-दान

प्रमोद यादव, वाराणसी

- भगवान सूर्य का सुबह 8.24 बजे मकर राशि में होगा प्रवेश
- एक मास से चले आ रहे खरमास को हो जाएगा समापन
- सूर्योदय के साथ मकर संक्रांति जन्य पुण्यकाल शुरू हो जाएगा जो सूर्यास्त तक रहेगा

सनातन धर्म में सूर्य आराधना का महापर्व मकर संक्रांति लोक मंगल को समर्पित है। स्नान-दान और खानपान का यह पर्व इस बार 15 जनवरी को पड़ रहा है। दीर्घायुष्य -आरोग्य, धन-धान्य, ऐश्वर्य समेत सर्व मंगल के कारक प्रत्यक्ष देव सूर्य धनु से मकर राशि में सुबह 8.24 बजे प्रवेश कर जाएंगे। इससे भी पहले सूर्योदय के साथ मकर संक्रांति जन्य पुण्यकाल शुरू हो जाएगा जो सूर्यास्त तक रहेगा। ऐसे में सुबह से शाम तक पर्व विशेष के स्नान-दान विधान पूरे किए जा सकेंगे।

स्नान दान, पूजन विधान : ज्योतिषाचार्य पं. ऋषि द्विवेदी के अनुसार, तिथि विशेष पर गंगा, प्रयागराज संगम समेत नदी, सरोवर, कुंड आदि में स्नान के साथ अर्घ्य और दान का विशेष महत्व है। स्नानोपरांत सूर्य सहस्त्रनाम, आदित्य हृदय स्त्रोत, सूर्य चालीसा, सूर्य मंत्रादि का पाठ कर सूर्य की आराधना करनी चाहिए। साथ ही गुड़, तिल, कंबल, खिचड़ी, चावल आदि पुरोहितों या गरीबों को दान करना चाहिए। वायु पुराण में मकर संक्रांति पर तांबूल दान का भी विशेष महत्व बताया गया है।

उत्तरायण सूर्यदेव : ज्योतिष शास्त्र में संक्रांति का शाब्दिक अर्थ सूर्य या किसी भी ग्रह का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश या संक्रमण बताया गया है। मकर संक्रांति पर्व भगवान सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण होने का संधि काल है। उत्तरायण में पृथ्वीवासियों पर सूर्य का प्रभाव तो दक्षिणायन में चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है। सूर्यदेव छह माह उत्तरायण (मकर से मिथुन राशि तक) व छह माह दक्षिणायन (कर्क से धनु राशि तक) रहते हैं। उत्तरायण देवगण का दिन तो दक्षिणायन रात्रि मानी जाती है। ज्योतिष के अनुसार किसी की कुंडली में आठों ग्रह प्रतिकूल हों तो उत्तरायण सूर्य आराधना मात्र से सभी मनोनुकूल हो जाते हैं।

शुरू हो जाएंगे मांगलिक कार्य : सूर्यदेव के 15 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश के साथ ही एक मास से चले आ रहे खरमास का समापन हो जाएगा। इसी दिन से शादी-विवाह समेत मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। इसके बाद बाजारों में खरीदारों की भीड़ बढ़ने की भी उम्मीद है। खास बात यह कि इस बार जनवरी से लेकर जून तक 67 लगन-मुहूर्त मिल रहे हैं। इसमें जनवरी में नौ, फरवरी में 17, मार्च में आठ, अप्रैल में पांच, मई में 19 व जून में नौ हैं। चातुर्मास्य के बाद नवंबर में दो व दिसंबर माह में आठ लगन मिलेंगी।

एक माह तक पशुशाला में छिपा था पुलिस भर्ती फर्जीवाड़े का मुख्य आरोपित

संवाद सूत्र, जवाली (कांगड़ा)

पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा फर्जीवाड़े का मुख्य आरोपित विक्रम चौधरी अक्टूबर से नवंबर तक जवाली की लाहडू पंचायत में एक माह तक पशुशाला में रहा था। पुलिस मंगलवार को आरोपित को लेकर पशुशाला पहुंची और पंचायत प्रधान की मौजूदगी में एक बैग बरामद किया। बैग से एक लाख 28 हजार रुपये नकद, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस व टूथब्रश बरामद किया है।

लाहडू पंचायत के तहत एक माता के मंदिर मार्ग पर किसी व्यक्ति की पशुशाला है और इसका मालिक विक्रम चौधरी का परिचित था। जंगल का रास्ता होने के कारण विक्रम इसी पशुशाला में एक माह तक रहा था। पशुशाला का मालिक ही आरोपित के खान पान सहित अन्य जरूरतें पूरी करता था। आरोपित ने पिछले माह ही पुलिस अधीक्षक कांगड़ा के पास आत्मसमर्पण किया था और इन दिनों वह पुलिस रिमांड पर है।

यह था मामला : 11 अगस्त, 2019 को पुरुष व महिला कांस्टेबलों के 1063 पदों के लिए प्रदेशभर में लिखित परीक्षा ली गई थी। सत्संग भवन परौर में कांगड़ा जिले के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया था। इस दौरान सीआइडी व पुलिस टीम ने चार युवकों को दूसरे का पेपर देते रंगेहाथ पकड़ा था, जबकि दो युवकों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ लिखित परीक्षा देते हुए गिरफ्तार किया था। बाद में पूछताछ में जवाली निवासी विक्रम चौधरी को भर्ती फर्जीवाड़े का मुख्य आरोपी घोषित किया था। विक्रम की तलाश में पुलिस ने जिला कांगड़ा सहित उसके अन्य संभावित ठिकानों पर दबिश दी थी, लेकिन आरोपित हर बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता था। इस मामले में मुख्य आरोपित समेत 34 लोगों को गिरफ्तार किया था।

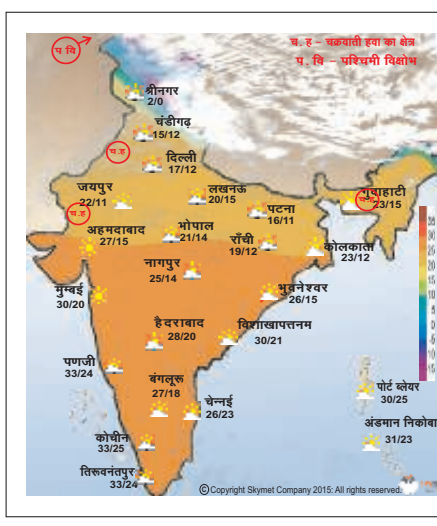

मौसम विशेष

जम्मू-कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में मध्यम से भारी वर्षा व हिमपात होगा। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व उत्तरी राजस्थान में घने बादल छाये रहेंगे। अनेक स्थानों पर गरज के साथ हल्की वर्षा होगी। एक-दो स्थानों पर ओलावृष्टि संभव है।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	30/18/व	अहमदाबाद	28/12/आंबा
कोलकाता	24/14/आंबा	बड़ौदा	29/12/सा
चेन्नई	30/22/आंबा	नागपुर	26/15/व
हैदराबाद	29/21/आंबा	इन्दौर	28/13/आंबा
बंगलूरू	28/17/आंबा	रांची	25/15/आंबा
त्रिवेन्द्रम	33/23/सा	पटना	22/11/आंबा
गुवाहाटी	23/14/व	जमशेदपुर	27/17/आंबा
गंगटोक	05/-9/आंबा	पुणे	30/19/व

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 8 जनवरी 2020
आजकल
16
www.jagran.com

पाकिस्तान ने शेख मुजीबुर्रहमान को किया रिहा

आज ही के दिन 1972 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के नेता शेख मुजीबुर्रहमान को रिहा किया था। भारत से 1971 का युद्ध हारने और अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते जुल्फिकार अली भुट्टो ने उनकी रिहाई के आदेश दिए। मार्च 1971 में गिरफ्तार किया गया था।

पहली बार दुनिया के सामने आई मोनालिसा

आज ही के दिन 1963 में लियोनार्डो द विंची की सुप्रसिद्ध कलाकृति मोनालिसा दुनिया के सामने आई थी। इसे वाशिंगटन की राष्ट्रीय कला दीर्घा में प्रदर्शित किया गया। 16वीं शताब्दी की इस तस्वीर को चेहरे के भावों के कारण आज तक सराहा जाता है।

स्टीफन हॉकिंग ने खोले थे ब्लैक होल्स के राज

सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का जन्म आज ही 1942 में इंग्लैंड में हुआ था। 1962 में उन्होंने भौतिक विज्ञान में डिग्री ली। 1963 में कैंब्रिज विश्वविद्यालय में ब्रह्मांड विज्ञान में रिसर्च की। इसी साल उन्हें एम्योट्रॉफिक लैटरल सेलेरोसिस नाम की बीमारी हो गई, जिसमें अंग धीरे-धीरे काम करना बंद कर देते हैं। 1974 में रॉयल सोसायटी के सबसे कम उम्र के सदस्य बने। 1988 में उनकी पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम प्रकाशित हुई। उन्होंने ब्लैक होल्स और बिग बैंग सिद्धांत को समझाने में अहम भूमिका निभाई है। 14 मार्च 2018 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया।

इधर-उधर की

पॉपकॉर्न ने अस्पताल में कराया भर्ती

लंदन, एजेंसी : दोस्तों के बीच गप्पे लड़ाते, फिल्म देखते और ऐसे ही कई बहाने हैं, जिनमें हम पॉपकॉर्न को शामिल कर लेते हैं। हालांकि ब्रिटेन में पॉपकॉर्न के कारण एक शख्स की जान पर बन आई। दरअसल, 41 साल के एडम मार्टिन के दांत में एक पॉपकॉर्न अटक गया। इसे निकालने के लिए मार्टिन ने पेन के ढक्कन, तार के टुकड़े और यहां तक की धातु की कील की मदद ली। इन चीजों को डालने से उनके मुंह में संक्रमण हो गया, जो बाद में हृदय तक पहुंच गया। इसे एंडोकार्डिटिस कहा जाता है। यह रक्त के जरिए फैलने वाले बैक्टीरिया के कारण होता है। सप्ताह भर बाद ही उन्हें रात में पसीने आने लगे, थकान और सिरदर्द होने लगा। इस पर उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के जरिए पैर से रक्त के थक्के को हटाया और हृदय के वाल्व को बदला गया। मार्टिन ने अब कभी पॉपकॉर्न ने खाने की बात कही है।

शोध अनुसंधान

कैंसर की दवा से हो सकता है फेफड़ों के रोग का इलाज

शोधकर्ताओं को कैंसर के इलाज में काम आने वाली कुछ खास दवाओं में फेफड़ों के रोग क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) के उपचार की भी संभावना दिखी है। उनका दावा है कि आने वाले समय में इस बीमारी के उपचार में इन दवाओं का उपयोग हो सकता है। सीओपीडी में श्वसन नली में सूजन हो जाती है और पीड़ित को सांस लेने में तकलीफ होती है। शोधकर्ताओं के अनुसार, कैंसर के उपचार में काम आने वाली कुछ दवाओं की सूजन पर प्रतिक्रिया का परीक्षण किया गया। इससे निष्कर्ष निकाला गया है। ब्रिटेन की शेफील्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता लिन प्रिंस ने कहा, 'सीओपीडी का आमतौर पर स्टेरॉयड और एयरवे मसल रिलैक्सेंट से इलाज किया जाता है, लेकिन इस समस्या का अभी कोई प्रभावी उपचार नहीं है। हमारे अध्ययन में कुछ दवाओं में इस तरह की समस्या के उपचार की संभावना दिखी है।' -आइएएनएस

ई-सिगरेट से बढ़ सकता है स्ट्रोक का खतरा

ई-सिगरेट के साथ ही पारंपरिक सिगरेट का भी इस्तेमाल करने वाले युवा संभल जाएं। नए अध्ययन में पाया गया है कि दोनों प्रकार की सिगरेट के सेवन से स्ट्रोक का उच्च खतरा हो सकता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, पारंपरिक सिगरेट के साथ ही ई-सिगरेट भी पीने वालों में स्ट्रोक का खतरा दोगुना ज्यादा पाया गया। शोधकर्ता तरंग पारेख ने कहा, 'यह लंबे समय से ज्ञात है कि सिगरेट का सेवन स्ट्रोक के खतरे का प्रमुख कारक होता है। अध्ययन से जाहिर होता है कि ई-सिगरेट भी पीने वाले युवा खुद को बड़े खतरे में डाल रहे हैं। यह धूमपान करने वाले उन युवाओं के लिए संदेश है, जो ई-सिगरेट को कम नुकसानदेह और सुरक्षित विकल्प समझ लेते हैं।' -एएनआइ

गगनयान में अंतरिक्ष यात्रियों को मिलेगा देसी खाना

- मैसुरु की डिफेंस फूड रिसर्च लैबोरेटरी ने तैयार किया भारतीय भोजन
- मिलेगा एग रोल, वेज रोल, इडली, मूंग दाल का हलवा और वेज पुलाव

मैसुरु, एएनआइ : इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (इसरो) के महात्वाकांक्षी गगनयान मिशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भारतीय भोजन ही मिलेगा। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्वादिष्ट, पौष्टिक और हल्के भोजन के रूप में विशेष रूप से एग रोल, वेज रोल, इडली, मूंग दाल का हलवा और वेज पुलाव तैयार किया जाएगा।

डिफेंस फूड रिसर्च लैबोरेटरी (डीएफआरएल) ने मंगलवार को मैसुरु में बताया कि अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले देश के पहले मानव अभियान के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन यहीं से भेजा जाएगा। इस तैयार भोजन को गर्म करने के लिए हीटर भी दिए जाएंगे। यह भोजन पैक्ड है और जब अंतरिक्ष यात्री को भूख लगे, वह इन्हें खोलकर गर्म करके खा लेगा। इतना ही नहीं डीएफआरएल ने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए विशेष कंटेनर भी बनाए हैं, जिसे वह पानी और जूस पीने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। चूंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण शून्य होता है, इसलिए वहां पर कुछ भी पीना-खाना आसान नहीं होता, इसके लिए डीएफआरएल ने विशेष कंटेनर तैयार किए हैं। बता दें कि भारतीय वायुसेना के चार पायलटों के अंतरिक्ष यात्री का प्रशिक्षण देने के लिए रूस मदद करेगा। इंसानों को ले जाने वाले भारत के पहले गगनयान मिशन के लिए रूस ना केवल भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को गगनयान अभियान के लिए प्रशिक्षित करेगा, बल्कि वो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को लाइफ सपोर्ट सिस्टम और स्पेसक्राफ्ट को गर्म रखने वाला सिस्टम भी मुहैया कराएगा। दिसंबर 2021 में लांच किए जाने वाले इस गगनयान मिशन की लागत तकरीबन 10 हजार करोड़ रुपये आएगी।

लाइफ सपोर्ट सिस्टम कई डिवाइसों को मिलाकर तैयार किया जाने वाला एक सिस्टम है जो किसी व्यक्ति को अंतरिक्ष में जिंदा रखने के लिए जरूरी है। यह सिस्टम अंतरिक्ष यात्री को पानी, हवा और भोजन प्रदान करता है। शरीर का उचित तापमान बनाए रखता है और ह्यूमन वेस्ट प्रोडक्ट्स का निपटान करता है।

डिफेंस फूड रिसर्च लैबोरेटरी द्वारा तैयार किया गया भोजन। फाइल

एस्पिरिन कम कर सकती है आंत के कैंसर का खतरा

स्पेक्ट्रम

- शोधकर्ता इसकी सही खुराक को लेकर अब कर रहे हैं अध्ययन
- उपचार के लिए नई थेरेपी विकसित करने में भी मिल सकती है मदद

वाशिंगटन, प्रेट्र : डॉक्टर यूं तो एस्पिरिन दवा की सलाह बुखार होने की स्थिति में देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यह कैंसर जैसी बीमारी के खतरे को कम करने में भी मददगार साबित हो सकती है। हालिया अध्ययन की मानें, तो यह आंत के कैंसर के ट्यूमर को बढ़ने से रोकता है। उसके दोबारा होने की संभावना को भी एक हद तक कम करता है। नए शोध से इस खतरनाक बीमारी के लिए उपचार के लिए नई थेरेपी विकसित करने में भी मदद मिल सकती है। अमेरिका के एक गैर-लाभकारी क्लिनिकल शोध केंद्र सिटी ऑफ होप के शोधकर्ताओं के अनुसार, एस्पिरिन में कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसन और गठिया जैसी बीमारियों की रोकथाम की क्षमता है।

इस अध्ययन के सह-लेखक अजय गोयल ने बताया, 'फिलहाल इन बीमारियों की रोकथाम के लिए एस्पिरिन प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि किसी भी अधिक एंटी-इन्फ्लेमेटरी दवा का अधिक इस्तेमाल करने से गैस और अन्य तरह की दिक्कतें आने लगती हैं।' उन्होंने कहा, 'हम बिना किसी भयावह साइड इफेक्ट के आंत के कैंसर की रोकथाम और उसके इलाज के लिए एस्पिरिन की उचित खुराक का पता लगाने के करीब हैं।' वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के दौरान चूहों पर प्रयोग किया। साथ ही, गणितीय मॉडलिंग के जरिये यह पता लगाने की कोशिश की कि एस्पिरिन की कितनी खुराक उचित होगी। उन्होंने पाया कि एस्पिरिन की खुराक बढ़ाने पर कोशिकाओं की मृत्यु दर बढ़ जाती है, जबकि कोशिकाओं के बंटने की दर घट जाती है।

शोधकर्ताओं ने इस आधार पर अनुमान लगाया कि एस्पिरिन के प्रभाव से ट्यूमर कोशिका के बढ़ने की जगह मरने की संभावना अधिक है। गोयल ने बताया, 'हम आंकड़ों का अध्ययन करने के लिए इंसानों पर प्रयोग करने वाले कुछ लोगों के साथ काम कर रहे हैं। इस गणना के लिए हम गणितीय मॉडलिंग का प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रक्रिया से भविष्य के लिए अच्छे नतीजे मिलने की उम्मीद है।' उन्होंने बताया कि वैश्विक रूप से सभी प्रकार के कैंसर में हर साल सबसे अधिक आंत के कैंसर का ही पता चलता है। इस लिहाज से भी यह अध्ययन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बढ़ सकता है गंगा के डेल्टा का जलस्तर

ग्लोबल वार्मिंग का असर ▸ इस सदी के अंत तक 1.4 मीटर तक हो सकती है वृद्धि

पीएनएएस नामक पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में सामने आई बात

लंदन, प्रेट्र : पूर्वी भारत और बांग्लादेश के इलाके में बहने वाली गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना के डेल्टा का जलस्तर इस सदी के अंत तक 1.4 मीटर तक बढ़ सकता है। जलस्तर में वृद्धि और भूस्खलन के क्षेत्रीय अनुमानों को बताने वाला यह अध्ययन सोमवार को पीएनएएस नामक जर्नल में प्रकाशित किया गया। अध्ययन में कहा गया है कि इसके निष्कर्षों पर काम करके हम भारत और बांग्लादेश में बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं।

फ्रांस के सीएनआरएस इंस्टीट्यूट सहित विभिन्न देशों के शोधकर्ताओं के मुताबिक, यह क्षेत्र ना केवल दुनिया में सबसे बड़ा है बल्कि यह सबसे घनी आबादी वाला डेल्टा है। यह जलवायु परिवर्तन के लिए संवेदनशील स्थानों में से भी एक है। हालांकि अपने निष्कर्षों में शोधकर्ताओं ने यह जरूर कहा है कि जलस्तर बढ़ने की सीमा और उससे पड़ने वाले प्रभाव के बारे में अब भी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। बांग्लादेश के दो-तिहाई और पूर्वी भारत के इलाके के इस डेल्टा में पहले से ही बाढ़ का खतरा रहता है। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में अक्सर तीव्र मानसूनी बारिश, समुद्र के बढ़ते जलस्तर और भूस्खलन का भी असर पड़ता रहता है। वैज्ञानिकों ने कहा, अब तक लगाए गए पूर्वानुमान जल स्तर के अत्यधिक क्षेत्रीय मापों पर आधारित हैं। वर्तमान अध्ययन के तहत डेल्टा की 101 जगहों पर पानी और समुद्र के स्तर की मासिक रीडिंग का विश्लेषण किया गया। इसके लिए उन्होंने भौगोलिक क्षेत्रों पर इस डाटा को एकत्र करते हुए स्थानीय प्रभावों को अलग कर उसकी गुणवत्ता मापी और समय के साथ-साथ जल स्तर में आए बदलावों का अनुमान लगाया।

2012 तक तीन मिलीमीटर हुई वृद्धि : अध्ययन से पता चलता है कि 1968 और 2012 के बीच जलस्तर में औसतन तीन मिलीमीटर प्रति वर्ष की वृद्धि हुई है। यह समुद्र के स्तर में होने वाली वैश्विक वृद्धि की तुलना में अधिक है, जो इसी समयावधि में दो मिमी प्रति वर्ष है। वैज्ञानिकों ने कहा, हालांकि इनका मान ढाका, बांग्लादेश में कुछ स्थानीय मापों से कम है, जिनका उपयोग अब तक एक संदर्भ के रूप में किया जाता था। लेकिन यह चिंताजनक जरूरत है।

जलस्तर में 85-140 सेमी तक की हो सकती है बढ़ोतरी : इसके बाद शोधकर्ताओं ने इस क्षेत्र में होने वाले भूस्खलन का अनुमान लगाया तो पता चला कि 1993 और 2012 के बीच डेल्टा में अधिकतम भूस्खलन एक और सात मिमी प्रति वर्ष के बीच था। अध्ययन में कहा गया है कि यदि इसी दर से भूस्खलन जारी रहा तो सदी के अंत तक जलस्तर में 85-140 सेमी तक वृद्धि हो सकती है।

बाढ़ की त्रासदी को किया जा सकता है कम : यह आंकड़ा हाल ही में प्रकाशित आइपीसीसी रिपोर्ट में उपलब्ध कराए गए अनुमानों से दोगुना है, जो कि चिंता का विषय है। शोधकर्ताओं के अनुसार, यह अध्ययन से गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना डेल्टा में जल स्तर के बेहतर पूर्वानुमान लगाने और बाढ़ की त्रासदी कम करने में देशों देशों की मदद कर सकता है।

बांग्लादेश का तटीय क्षेत्र, जहां गंगा नदी का डेल्टा है। फाइल

सफलता को लेकर पांच में चार मेडिकल के छात्र रहते हैं आशंकित

न्यूयॉर्क, प्रेट्र : एक अध्ययन के अनुसार, लगभग 80 फीसद मेडिकल छात्रों को आशंका रहती है कि भविष्य में उन्हें बड़ी उपलब्धि मिलेगी भी या नहीं? शोधकर्ताओं ने कहा कि पेशे में आने से पूर्व ही इस तरह की आशंकाएं व्यक्ति को और कमजोर बना सकती हैं। उनका दावा है कि इस अध्ययन के निष्कर्ष लोगों को डॉक्टर बनने के लिए प्रशिक्षण के दौरान में मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।

अमेरिका की ओहियो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अध्ययन के लिए 385 मेडिकल छात्रों को सर्वेक्षण में शामिल कर उनके बर्नआउट स्तर का आकलन किया। बर्नआउट एक मनोवैज्ञानिक सिंड्रोम है जो तनावपूर्ण कार्यों से उभर कर सामने आता है। द जर्नल ऑफ द अमेरिकन ओस्टियोपैथिक एसोसिएशन में छपे अध्ययन के मुताबिक, बर्नआउट के तीन आयाम होते हैं - भावनात्मक थकावट, अवैयक्तिकरण और व्यक्तिगत उपलब्धि की कमी महसूस होना।

ओहियो यूनिवर्सिटी की शोधकर्ता और इस अध्ययन की सह-लेखक एलिजाबेथ बेवर्ली ने कहा, 'यह विडंबना है कि 80 फीसद लोग व्यक्तिगत उपलब्धियों की कमी महसूस करते हैं। हालांकि, लगभग सभी छात्र पढ़ाई के बाद अपने क्षेत्र में सर्वोच्च प्रदर्शन कर सकते हैं।

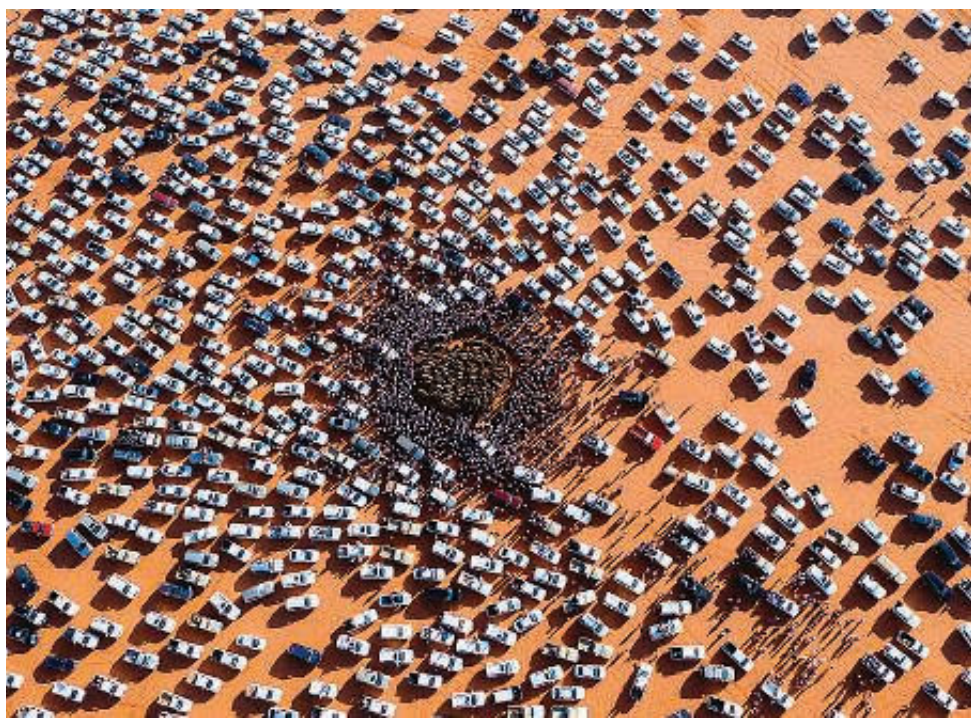

कारों से खरीदने पहुंचे ऊंट...

ये सऊदी अरब में ऊंट के दीवानों की कारें हैं। यहां राजधानी रियाद से 160 किलोमीटर दूर रूमा में किंग अब्दुलअजीज ऊंट महोत्सव चल रहा है। मंगलवार को ऊंट खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग कारों से यहां पहुंचे। इस दौरान ऊंटों को घेरे लोग। यह उत्सव दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला है। इस दौरान कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम और ईनामी प्रतियोगिताएं भी होती हैं। एएफपी

स्क्रीन शॉट

'शिकारा' में कश्मीरी पंडितों का दर्द

करीब 13 साल बाद विधु विनोद चोपड़ा ने फिल्म 'शिकारा' से निर्देशन में वापसी की है। इससे पहले वर्ष 2007 में रिलीज फिल्म 'एकलव्य : द रॉयल गार्ड' का उन्होंने निर्देशन किया था। मंगलवार को मुंबई में 'शिकारा' के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर विधु विनोद चोपड़ा ने बताया कि इस फिल्म को बनाने में उन्हें 11 साल का समय लगा। 19 जनवरी 1990 को लाखों कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया गया था। फिल्म की कहानी का आगाज वहीं से होकर वर्तमान में आता है। विधु के मुताबिक, यह फिल्म कश्मीरी युगल की कहानी है। इसमें उनकी तीस साल के सफर को दिखाया गया है। यह कहानी उन सभी लोगों की है, जो पिछले तीन दशक से अपने ही देश में रिफ्यूजी के तौर पर रह रहे हैं। बॉलीवुड द्वारा कश्मीरी पंडितों के मुद्दे को नजरअंदाज करने के सवाल पर विधु ने कहा, 'मैं कहीं आता-जाता नहीं हूं, अपने अवार्ड लेने भी नहीं जाता। लिहाजा इंडस्ट्री में लोग क्या बना रहे हैं, मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता हूं। मैं इतना कह सकता हूं कि मैंने जो फिल्म बनाई है, उसमें चार हजार असल कश्मीरी पंडितों ने काम किया है।' विधु ने बताया, 'पोस्टर में दिखाए गए लोग असली रिफ्यूजी हैं। एक दृश्य में रजिस्ट्रेशन का सीन है। शूटिंग के दौरान एक महिला रजिस्ट्रेशन के लिए आती है और रोने लगती है। हमने कहा कि दूसरा टेक लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि अब नहीं होगा। उन्होंने कहा कि दो बार हो चुका है, तीसरी बार उसी सीन को नहीं कर सकती। मैंने कहा कि यह दूसरा टेक है, तो वह बोलीं कि पहली बार तीस साल पहले किया था। इसी तरह कैंसर से पीड़ित बंसी लाल ने काम किया है। उन्होंने कैंसर होने की बात बताई नहीं थी। अब उनका निधन हो चुका है। तब उन्हें खाने के लिए पूछते तो कहते थे कि भूख नहीं है। जबकि वह खाना खा नहीं सकते थे। उस हालत में उन्होंने काम किया। उन्हें लगा कि उनके मरने के बाद ऐसी कोई बात रह जाए।' फिल्म का संगीत एआर रहमान ने तैयार किया है। फिल्म सात फरवरी को रिलीज होगी।

जन्मदिन पर 'अंग्रेजी मीडियम' में इरफान का लुक रिलीज

इरफान ने मंगलवार को 53वां जन्मदिन मनाया। उनके जन्मदिन पर फिल्म 'अंग्रेजी मीडियम' के निर्माता दिनेश विजन की प्रोडक्शन कंपनी मेडॉक फिल्म्स ने उनके फैन्स को तोहफा देने के लिए फिल्म अंग्रेजी मीडियम का लुक रिलीज किया। तस्वीर में इरफान के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान है। उन्होंन शर्ट पर स्वेटर और ऊपर से हाफ जैकेट पहन रखा है। यह फिल्म 2017 में रिलीज हुई फिल्म 'हिंदी मीडियम' की सीक्वल होगी। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, 'हमारे बेहतरीन कलाकारों में से एक इरफान को जन्मदिन की शुभकामनाएं। ट्रीट के तौर पर हम आप सभी के लिए अंग्रेजी मीडियम को मार्च में लेकर आ रहे हैं।' फिल्म का निर्देशन होमी अदजानिया ने किया है। इस फिल्म में इरफान के साथ पहली बार करीना कपूर खान स्क्रीन साझा करेंगी। फिल्म में राधिका मदान भी अहम भूमिका में हैं। अभिनेत्री बिपाशा बसु भी इरफान खान के साथ अपना जन्मदिन साझा करती हैं। सात जनवरी को बिपाशा ने अपना 41वां जन्मदिन मनाया। उनके पति करण सिंह ग्रोवर ने उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि 'तुम हम सभी के लिए भगवान की तरफ से एक तोहफा हो'।

'द फॉरगॉटन आर्मी' में डबिंग के लिए शाह रुख खान ने नहीं ली फीस

'काबुल एक्सप्रेस', 'बजरंगी भाईजान' और 'एक था टाइगर' जैसी फिल्मों का निर्देशन करने वाले कबीर सिंह ने 'द फॉरगॉटन आर्मी' से डिजिटल डेब्यू किया है। यह वेब सीरीज आजाद हिंद फौज के गठन को लेकर है, उसमें सनी कौशल और शारवरी प्रमुख भूमिका में हैं। वेब शो में शाह रुख खान ने भी वॉयसओवर किया है। कबीर सिंह के मुताबिक, 'हर एपीसोड से पहले चालीस सेकेंड का परिचय है। शो ऐतिहासिक है और सत्य घटनाओं से प्रेरित है तो उसके बारे में बताना जरूरी है। शाह रुख के साथ मैं इस आइडिया को पहले साझा कर चुका हूं। तब इस पर फिल्म को लेकर बात हुई थी। शाह रुख से मैं फिल्म इंडस्ट्री में आने के पहले से परिचित हूं। वह दिल्ली में मेरे सीनियर रहे हैं। उनके नोट्स अपनी परीक्षा देने के लिए पढ़ चुका हूं। उनकी पत्नी गौरी दोस्त हैं। हमने एक स्टेज प्रोडक्शन साथ में किया था। शाह रुख खान का आजाद हिंद से जुड़ाव रहा है। उनके पिता आजाद हिंद फौज के जनरल शाहनवाज खान के करीबी थे। मैंने शाह रुख से वॉयसओवर कराने के बारे में सोचा। मैंने उन्हें फोन किया। दो दिन के भीतर उन्होंने स्वीकृति दे दी। वरना उनके साथ फिल्म करने वालों को पता है कि शाह रुख खान फिल्म करने से पहले उस पर चर्चा करने में काफी समय लेते हैं। उन्होंने दो दिन में पूरी रिकॉर्डिंग कर दी। मुझे नहीं पता कि यह बात बतानी चाहिए या नहीं, लेकिन उन्होंने इसके लिए फीस लेने से भी इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने यह डबिंग इसलिए की है, क्योंकि यह प्रेरणादायक कहानी है।'

रहस्यमय ब्रह्मांड

कहा- वे मनुष्यों की तरह कार्बन से नहीं बने हो सकते, इसीलिए हम उन्हें देख नहीं पाते, रूसी मॉड्यूलर अंतरिक्ष स्टेशन मीर के मिशन में भाग लेकर शर्मन ने रचा था इतिहास

अंतरिक्ष यात्री का दावा, एलियन का है अस्तित्व

लंदन आइएएनएस : यह सवाल हमेशा से ही लोगों की जिज्ञासा का विषय रहा है कि क्या ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसा कोई ग्रह मौजूद है? क्या एलियंस की भी एक दुनिया है? विज्ञान से जुड़ी कई फिल्मों में हमने एलियंस देखे हैं। दुनियाभर के वैज्ञानिक भी एलियंस के अस्तित्व को लेकर अलग-अलग तरह की बातें कहते रहे हैं। इस बारे में विभिन्न धर्मों की अपनी अलग-अलग राय है। लेकिन पुख्ता जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। इसका उत्तर खोजने के लिए वैज्ञानिक शोध में लगे हुए हैं।

अब ब्रिटेन की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हेलेन शर्मन ने दावा किया है कि एलियन होते हैं। वे पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों पर भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे ब्रह्मांड में लाखों ग्रह, उपग्रह और तारे हैं। हर खगोलीय पिंड का अपना एक अलग वातावरण है और पृथ्वी का वातावरण और जीवन अन्य से जुदा है। शायद, इसीलिए हम उन्हें नहीं जान पाते। एक ब्रिटिश पत्रिका में शर्मन के दावे सामने आए हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि एलियंस मनुष्यों की तरह कार्बन और नाइट्रोजन से नहीं बन सकते हैं।

ब्रिटेन की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हेलेन। फाइल

ब्रिटेन की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री : बता दें कि 56 वर्षीय शर्मन ने मई 1991 में रूसी मॉड्यूलर अंतरिक्ष स्टेशन मीर के एक मिशन में भाग लेकर इतिहास रचा था। एक साक्षात्कार में अंतरिक्ष यात्री ने बताया कि उस समय उन्हें बेहद खुशी होती है, जब लोग आपको केवल एक ब्रिटिश नागरिक के बजाय ब्रिटेन की पहली महिला अंतरिक्ष के तौर पर जानते हैं। उन्होंने कहा अब जब भी ब्रिटेन के अंतरिक्ष यात्रियों की चर्चा होगी तो उन्हें भी देश के पहले अंतरिक्ष यात्री टिम पीक के साथ याद किया जाएगा।

धरती का दौर कर चुके हैं एलियन : इनसे पहले अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के इंटेलिजेंट सिस्टम डिवीजन के वैज्ञानिक सिल्वानो पी. कोलंबानो का भी मानना था कि हो सकता है कि एलियंस धरती का बहुत पहले ही दौरा कर चुके हों। एक अध्ययन में उन्होंने दावा किया था कि एलियंस की जिंदगी इंसानों से काफी अलग हो सकती है। उन्होंने कहा, 'यह जरूरी नहीं कि दूसरी दुनिया के जीव जिन्हें हम खोज रहे हैं या जो हमें खोज रहे हैं, वे हमारी तरह कार्बन के बने हों।' कोलंबानो ने कहा कि बाहरी दुनिया के प्राणी काफी बुद्धिमान हो सकते हैं। हो सकता है उन्होंने उस तकनीक का भी पता लगा लिया हो, जिस बारे में हम अभी सोच भी नहीं सकते।

हॉकिंग ने भी माना था होते हैं एलियंस : अंतरिक्ष वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने भी माना था कि एलियन का अस्तित्व है। पर उनका यह भी मानना था कि एलियंस को खोजने के चक्कर में हम अपने लिए ही परेशानी खड़ी कर लेंगे। यह सदी खत्म होते-होते इंसानों के सामने कई परेशानियां खड़ी होने लगेंगी। लिहाजा, हमें दूसरे ग्रहों पर कॉलोनियां बनाने के काम में अभी से जुट जाना चाहिए।